



वार्षिक रिपोर्ट

2020–2021



भारतीय लोक
प्रशासन संस्थान
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट,
रिंग रोड, नई दिल्ली
iipa.org.in



गाँधीजी का तिलिस्म

“मैं तुम्हें एक तिलिस्म दूँगा। जब भी तुम्हें संदेह हो अथवा तुम्हारा अहम् प्रबल होता दिखाई दे, तो यह कसौटी आजमा कर देखो:

तब उस सबसे गरीब और निर्बल व्यक्ति का चेहरा याद करो जिसे तुमने देखा है और फिर अपने आप से पूछो कि तुम जो कदम उठाने का विचार कर रहे हो क्या वह उस आदमी के लिए उपयोगी होगा? क्या उससे उसको कुछ लाभ होगा? क्या उससे वह अपने जीवन और भाग्य पर नियंत्रण रख सकेगा? दूसरे शब्दों में, क्या उससे उन करोड़ों भूखे और अतृप्त लोगों को स्वराज्य मिलेगा?

तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम् समाप्त हो रहा है।”



mkgandhi
मोहनदास
करमचंद गाँधी

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली- 110002



**67वीं
वार्षिक रिपोर्ट
2020-2021**

**1 नवंबर, 2021 को आम सभा
की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत**

केंद्र और राज्य स्तर पर शासन के कार्यों के प्रबंधन के लिए अपेक्षित ज्ञान, कौशल और व्यवहार के साथ प्रशिक्षण और अनुसंधान के माध्यम से लोकसेवकों के बीच क्षमता निर्माण के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की गई थी। सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अधिकारियों के नेतृत्व, प्रबंधन और प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाने के अपने प्रयासों में संस्थान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर काम करता है। संस्थान के प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रम इसके विशाल सूचना प्रबंधन और अनुभव साझाकरण गतिविधियों से जुड़े हुए हैं।

अपने संस्थापकों के सपनों को साकार करते हुए भा.लो.प्र.सं का उद्देश्य लोक प्रशासन, नीति निर्माण और कार्यान्वयन के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी शैक्षणिक विचार केंद्रों में से एक बनना है (ताकि शासन प्रणालियां नागरिकों की जरूरतों और आकांक्षाओं के प्रति अधिक उत्तरदायी बन सकें और लोकतांत्रिक समाज में मानवीय मूल्यों के साथ तालमेल बैठा सकें।

कार्यकारी परिषद्
(01.4.2020 से 31.03.2021 तक)

अध्यक्ष

श्री. एम. वेंकय्या नायडू
भारत के माननीय उपराष्ट्रपति
6, मौलाना आज़ाद रोड
नई दिल्ली- 110011

सभापति

डॉ. सी. चंद्रमौलि
सचिव
कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय,
भारत सरकार
कमरा नं. 112, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली- 110001
(11.01.2020 से 30.09.2020 तक)

डॉ. जितेन्द्र सिंह
माननीय राज्यमंत्री
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय,
भारत सरकार
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली- 110001
(अक्टूबर 2020 से आज तक)

कार्यकारी परिषद् के सदस्य

श्री शेखर दत्त
(छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल)
फ्लैट सं. सी-805, 8वीं मर्जिल, कीनवुड टॉवर,
चार्मवुड विलेज,
सूरजकुंड रोड, फरीदाबाद- 121009 (हरियाणा)

प्रो. जोसेफ के. अलेकजेंडर
अध्यक्ष
भा.लो.प्र.सं. केरल क्षेत्रीय शाखा
मार्फत, एलेक्सी जोस, टी.सी., 41/1950 (1)
ए-56, पंडित कॉलोनी, कॉडीयार
थिरुवनंतपुरम- 695003

प्रो. राजकुमार
कुलपति
पंजाब विश्वविद्यालय
चंडीगढ़- 160014

डॉ. संजीव चोपड़ा
निदेशक, लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी,
मसूरी- 248179 (उत्तराखण्ड)

श्री एस. एस. क्षत्रिय
अध्यक्ष
भा.लो.प्र.सं. महाराष्ट्र क्षेत्रीय शाखा
भूतल, महाराष्ट्र बैंक के साथ, मुख्य मंत्रालय
हुतात्मा राजगुरु चौक, मैडम कामा रोड,
मुंबई-400032

प्रो. एन. लोकेन्द्र सिंह अध्यक्ष भा.लो.प्र.सं. मणिपुर क्षेत्रीय शाखा मार्फत मणिपुर विश्वविद्यालय काँचीपुर, इंफाल- 795003	प्रो. के.के. पाण्डेय भा.लो.प्र.सं. नई दिल्ली- 110002
श्री एस.सी. मिश्रा अध्यक्ष भा.लो.प्र.सं. ओडिशा क्षेत्रीय शाखा क्वाटर नंबर वी आईसी, 2/1 इकाई-1, भुवनेश्वर-751009	श्रीदीपक खांडेकर सचिव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रलय, भारत सरकार कक्ष संख्या -112, नार्थ ब्लॉक नई दिल्ली-110001
डॉ. टी. वी. सोमनाथन सचिव, व्यव विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार कक्ष संख्या-129-अ, नार्थ ब्लॉक नई दिल्ली-110001	श्री अमिताभ कांत मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीति आयोग, भारत सरकार नीति भवन, संसद मार्ग नई दिल्ली- 110001

सदस्य सचिव

श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी
महानिदेशक
भारतीय लोक प्रस्थान संस्थान,
आई.पी. एस्टेट, रिंग रोड,
नई दिल्ली- 110002

डॉ जितेन्द्र सिंह

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार),
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय;
राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय;
राज्य मंत्री कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय;
राज्य मंत्री परमाणु ऊर्जा विभाग तथा
राज्य मंत्री अंतरिक्ष विभाग
भारत सरकार



Dr. JITENDRA SINGH

Minister of State (Independent Charge)
of the Ministry of Science and Technology;
Minister of State (Independent Charge)
of the Ministry of Earth Sciences;
Minister of State in the Prime Minister's Office;
Minister of State in the Ministry of Personnel,
Public Grievances and Pensions;
Minister of State in the Department of Atomic Energy and
Minister of State in the Department of Space
Government of India

संदेश



भा.लो.प्र.सं. के 67 साल पुराने प्रतिष्ठित प्रकाशन-इसकी वार्षिक रिपोर्ट के लिए यह संदेश लिखते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। यह रिपोर्ट वर्ष 2020-21 के दौरान संस्थान की वर्ष भर की गतिविधियों का एक सक्षिप्त संस्करण है।

वर्ष 2020-21 में कोविड-19 ने दुनिया पर हमला बोला और हर जगह इसकी वजह से संकट छाया रहा। फिर भी भा.लो.प्र.सं. को इस बात का श्रेय जाता है कि इसने बहुत शोध्रता से खुद को डिजिटल प्रशिक्षण में अनुकूलित कर लिया। जिस समय कोरोना और लॉकडाउन अपने चरम पर थे (उस दौरान भी संस्थान द्वारा डिजिटल आधारभूत संरचना के साथ ही डिजिटल पाठ्य सामग्री भी तैयार की गई।

महामारी के दौरान भा.लो.प्र.सं. ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के लिए बड़ी संख्या में अनुसंधान परियोजनाएं पूरी कीं। न्यूनतम उपस्थिति, अधिकतम कार्यनिष्पादन के मंत्र का अनुसरण करते हुए भा.लो.प्र.सं. के शिक्षकों एवं अधिकारियों ने घर से ही अथक परिश्रम किया और उम्मीद से अधिक कार्य निष्पादन को अंजाम दिया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं निर्देशों के अनुसार सरकार ने मिशन कर्मयोगी (जन सेवाओं में क्षमता निर्माण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम) का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य जनसेवाओं की क्षमता निर्माण में आमूलचूल परिवर्तन लाना था। हम नियम आधारित प्रणाली से भूमिका आधारित प्रणाली की ओर बढ़ रहे हैं। भा.लो.प्र.सं. ने अपने अंदर एक मिशन कर्मयोगी प्रकोष्ठ की स्थापना की है। अब भा.लो.प्र.सं. डिजिटल प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक ऐसा अग्रणी संस्थान है जिसने आईजीओटी मंच पर बहुत सारे पाठ्यक्रमों को अपलोड किया है। इसके अलावा भा.लो.प्र.सं. अपने खुद के एल.एम. के लिए भविष्य के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु पाठ्यक्रम की तैयारी करता रहा है। भा.लो.प्र.सं. की आमसभा ने 31 अक्टूबर 2020 को आयोजित वार्षिक बैठक में भा.लो.प्र.सं की कार्यकारी परिषद को छोटा, प्रभावी, कुशल और अधिक प्रतिनिधिक बनाने के लिए भा.लो.प्र.सं. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और नियमों में संशोधन को मजूरी दी।

भा.लो.प्र.सं. की कार्यकारी परिषद के सभापति का पद-भार संभालने के बाद मैं बैठक में शामिल हुआ। बैठक में लिए गए सबसे पहले निर्णयों में से एक था-लंबी रोक के बाद एक जनवरी 2021 से भा.लो.प्र.सं. की आजीवन सदस्यता को दुबारा से शुरू करना। मुझे यह जानकर हर्ष हो रहा है कि भा.लो.प्र.सं. ने अब सदस्यता अधियान शुरू किया है और सेवारत जनसेवकों के साथ ही साथ शिक्षाविदों को भी आजीवन सदस्य के रूप में पंजीकृत करने का प्रयास कर रहा है। इससे निःसंदेह समस्त हित धारकों के बीच जन प्रशासन के ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रचार में मदद मिलेगी।

अधिक से अधिक एकीकरण और डी-सिलोसेशन प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा।

मैं संस्थान की भावना को बनाए रखने में उनके प्रयासों के लिए भा.लो.प्र.सं. की टीम को बधाई देता हूं।


डॉ जितेन्द्र सिंह
एमबीबीएस (स्टैनले, चेन्नई)
एमडीमेडिसिन, फैलोशिप (अ.भा.आ.सं., एनडीएल)
एमएनएमएस (मधुमेह एवं अंतः स्नावी विज्ञान)

अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग

नई दिल्ली-110001

दूरभाष: 011-23316766, 23714230

फैक्स: 011-23316745

साउथ ब्लॉक नई दिल्ली-110011

दूरभाष: 011-23010191 फैक्स: 011-23017931

नार्थ ब्लॉक नई दिल्ली-110001

दूरभाष: 011-23092475 फैक्स: 011-23092716

महानिदेशक की ओर से

वर्ष 2020-21, भा.लो.प्र.सं. के लिए कई तरह से ऐतिहासिक रहा है। माननीय केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय; राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय) राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय से डीओपीटी के प्रभारी राज्य मंत्री की हैसियत से भा.लो.प्र.सं. की कार्यकारी परिषद के सभापति का पदेन प्रभार ग्रहण करने के लिए अनुरोध किया गया था। माननीय केंद्रीय मंत्री ने भा.लो.प्र.सं. की कार्यकारी परिषद के पदेन सभापति के रूप में उत्तरदायित्व को स्वीकार करके महान कृपा की।

2020-21 भा.लो.प्र.सं. के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। इसी वर्ष 31 अक्टूबर 2020 को आयोजित अपनी वार्षिक बैठक में भा.लो.प्र.सं. ने भा.लो.प्र.सं. मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशन और नियमों में व्यापक संशोधन किए हैं। जिसके अनुसार कार्यकारी परिषद छोटी, प्रभावी, कुशल और अधिक प्रतिनिधिक बन सकेगी। ये संशोधन तभी से लागू कर दिए गए हैं।

संशोधनों को लागू करने के पश्चात भा.लो.प्र.सं. ने 1 जनवरी, 2021 से आजीवन सदस्यता को भी पुनः बहाल कर दिया है, जो कि पीछे काफी लंबे समय से बंद पड़ी थी। इसके लिए आंचलिक एवं स्थानीय शाखाओं तथा इच्छुक सदस्यों द्वारा कई बार अनुरोध किया गया था। तभी से भा.लो.प्र.सं. ने सभी लंबित आवेदनों की छंटनी की है और पात्र आवेदकों को सदस्यता प्रदान की है। भा.लो.प्र.सं. ने सदस्यता अभियान भी शुरू किया है और समस्त आंचलिक तथा स्थानीय शाखाओं से आवेदन भी आमंत्रित किए हैं।

वर्ष 2020-21 को केवल भारत वर्ष में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में कोविड-19 के खतरनाक फैलाव के लिए भी याद किया जाएगा। इस भयंकर महामारी के कारण तथा उसके परिणाम स्वरूप होने वाले लॉक-डाउनों की वजह से हर जगह संकट उत्पन्न हो गया था। भा.लो.प्र.सं. की गतिविधियां भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुईं। शारीरिक प्रशिक्षण का कार्य धीरे-धीरे पूरी तरह जाम हो गया। सामान्य कामकाज ठप्प हो गए और संसाधन निर्माण बंद हो गया। फिर भी भा.लो.प्र.सं. ने हिम्मत नहीं हारी और सच्चाई तो यह है कि मई, 2020 से संस्थान की शैक्षणिक गतिविधियां और अधिक सघन हो गईं। भा.लो.प्र.सं. को डिजिटल प्रशिक्षण के रूप में मानो एक नया सहयोगी मिल गया था।

ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भा.लो.प्र.सं. ने नए यंत्रों एवं तकनीकों को अपनाने के लिए खुद को बड़ी फुर्ती से बदला। भा.लो.प्र.सं. ने ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए कई वी सी एवं डिजिटल रूप से सुसज्जित कक्षाओं की स्थापना के साथ ही साथ डिजिटल प्रशिक्षण मॉड्यूलों और पाठ्यक्रमों को तैयार किया। वित्तीय वर्ष 2020-21 में भा.लो. प्र.सं. ने भारतीयों के साथ ही साथ विभिन्न देशों के विदेशी सरकारी अधिकारियों के लिए 66 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इन देशों में वियतनाम, कंबोडिया, भूटान, अर्जेन्टीना, किंगडम ऑफ एस्वाटीनी (पूर्व में स्वाजीलैंड), कॉस्ट रीका, केन्या और मॉरीशस आदि शामिल हैं। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (आईटीईसी) के तहत चलाया गया था।

भा.लो.प्र.सं. के लिए यह पहली बार था कि संस्थान को जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम में गंगा को पुर्जीवित करने के लिए लोगों की सहभागिता को एकीकृत करके नेतृत्व देने का कार्य सौंपा गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है – क्षमता, जन जागरूकता तथा हित धारकों की भागीदारी के साथ बहु-क्षेत्रीय समन्वय को बढ़ाना। यह तीन वर्ष चलने वाला कार्यक्रम है।

भा.लो. प्र.सं. ने इस परियोजना के तहत एल.एम.एस. मंच पर वेब आधारित प्रशिक्षण के लिए मिली जुली अधिगम सामग्री का निर्माण किया है।

भा.लो.प्र.सं. ने 80 से ज्यादा विद्यालयों के 9177 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया है और वर्ष 2020-21 में 672 मास्टर प्रशिक्षक तैयार किए हैं।

भा.लो.प्र.सं. के लिए यह भी पहली बार है कि संस्थान राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान (एनटीआरआई) की स्थापना एवं परिपोषण में भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय की मदद कर रहा है। एनटीआरआई को भा.लो.प्र.सं. परिसर के अंदर भा.लो.प्र.सं सौध भवन में स्थापित किया जा रहा है और भा.लो.प्र.सं. एनटीआरआई का मार्गदर्शन कर रहा है।

कोविड-19 महामारी के दौरान भा.लो.प्र.सं. ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के लिए बड़ी संख्या में अनुसंधान परियोजनाएं पूरी कीं। भा.लो.प्र.सं. के अनुसंधान स्कंध ने चिंता के विशिष्ट शासन क्षेत्रों में गुणात्मक उत्थान प्राप्त किया है। भा.लो.प्र.सं. के शिक्षकों ने विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के लिए लगभग 60 अनुसंधान अध्ययन पूरे किए हैं। वैश्वक संकट के इस दौर में यह अद्भुत उपलब्धि रही है।

भा.लो.प्र.सं. ने मौजूदा प्रासंगिकताओं के विषयों पर मई, 2020 से वेबिनार श्रृंखला शुरू की। इसके विषय थे - मिशन कर्म योगी, पोस्ट कोविड-19 शासन सुधार, कृषि में सुधार, महामारी के बाद की अवधि में शासन का डिजिटल परिवर्तन, राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली, स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, आयुष्मान भारत, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीतियां, जलवायु परिवर्तन, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (ए एम आर यू टी), राष्ट्रीय विरासत शहर विकास आदि। वित्तीय वर्ष 2020-21 में भा.लो.प्र.सं. ने 66 वेबिनारों का आयोजन किया। सरकार से संकेत लेते हुए भा.लो.प्र.सं. ने इस मिशन मोड कार्यक्रम से संबंधित सभी गतिविधियों को संकाय और बाहरी संगठनों के साथ समन्वित करने के लिए समर्पित मिशन कर्म योगी संसाधन केंद्र की स्थापना की। भा.लो.प्र.सं.कार्यक्रमों, मॉड्यूलों और आईजीओटी मंच हेतु पाठ्यक्रमों के विकास के लिए वाधवानी फाउंडेशन, जे-पीएएल, बिल एवं मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, सीटीआईज और एटीआईज जैसे विभिन्न संस्थानों के साथ सहयोग कर रहा है। मिशन कर्म योगी का अभिन्न अंग फ्रेसिंग (फेमवर्क ऑफ रोल्स, एक्टिविटीज एंड कंपीटेंसीज) भी भा.लो.प्र.सं. की गतिविधियों में सबसे आगे है।

46वां लोक प्रशासन में उन्नत व्यावसायिक कार्यक्रम (अप्पा) 1 जुलाई, 2020 को ऑनलाइन माध्यम से शुरू हुआ। इसका उद्घाटन डॉ. जितेंद्र सिंह, माननीय केंद्रीय मंत्री, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा किया गया। यह कोविड-19 महामारी एवं लॉकडाउन के बीच शुरू हुआ था। यह पहला मिड-करियर कार्यक्रम था जो स्फलतापूर्वक सही समय पर शुरू हुआ और अपनी पूरी 10 महीने की कालावधि में ऑनलाइन मोड में चला। भा.लो.प्र.सं. ने 16 सितंबर, 2020 को हिंदी दिवस मनाया। इसमें श्री सुमीत जैरथ, भा.प्र.से., सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विशेष व्याख्यान दिया गया।

ज्ञान प्रसार के मोर्चे पर भा.लो.प्र.सं. पुस्तकालय के डिजिटल भंडार के संचालन तथा दूरस्थ स्थानों से भा.लो.प्र.सं. पुस्तकालय के विशाल संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने से भा.लो.प्र.सं. को अब अकादमिक दुनिया के कोने-कोने तक अपने पंख फैलाने में मदद मिली है।

संस्थान, भा.लो.प्र.सं.में प्रशिक्षण, अनुसंधान, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों एवं अन्य गतिविधियों के समर्थन और ज्ञान के आधार को लगातार उन्नत करने तथा सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने की गुणवत्ता में सुधार करने के सरकारी

प्रयासों में सहायता करने के लिए केंद्र और राज्यों के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा अन्य मंत्रालयों के प्रति आभार व्यक्त करता है। हम भारत के माननीय उपराष्ट्रपति एवं भा.लो.प्र.सं. के अध्यक्ष (माननीय केंद्रीय मंत्री एवं भा.लो.प्र.सं. के सभापति) ई सी, एवं कार्यकारी परिषद के सदस्यों द्वारा प्रदान किए गए निरंतर समर्थन के लिए अपना आभार और प्रशंसा दर्ज करते हैं।

संस्थान आंचलिक और स्थानीय शाखाओं के सभी पदाधिकारियों, संकाय सदस्यों, अधिकारियों और संस्थान के कर्मचारियों को संस्थान के समग्र विकास में उनके ईमानदार प्रयासों के लिए धन्यवाद देता है। हम भा.लो.प्र.सं. के अंदर एवं बाहर उन सभी के आभारी हैं, जिन्होंने हमारी सहायता की है और 2020-21 के दौरान हमारी गतिविधियों और प्रयासों की सफलता में योगदान दिया है। हम उनसे आगे भी इसी तरह के सहयोग की आशा करते हैं।

(सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी)

महानिदेशक

विषय सूची

	पृष्ठ
माननीय केंद्रीय मंत्री एवं भा.लो.प्र.सं. के सभापति का संदेश	v
महानिदेशक की कलम से-	vi
सिंहावलोकन	1
प्रशिक्षण/शैक्षिक कार्यक्रम	1
सूचना प्रबंधन	5
प्रकाशन	5
पुस्तकालय	5
सहयोगी गतिविधियां	6
आम सभा की 66वीं वार्षिक बैठक	7
सदस्यों का 64वां वार्षिक सम्मेलन	9
कार्यकारी परिषद	9
सदस्यता	9
पॉल एच एप्पलबार्ड पुरस्कारों से सम्मानित भा.लो.प्र.सं. के विशिष्ट सदस्य	10
भारतीय लोकप्रशासन पत्रिका (आईजेपीए) में छपे सर्वोत्तम लेख हेतु वर्ष 2019 के लिए श्री टी.एन. चतुर्वेदी पुरस्कार	10
आंचलिक एवं स्थानीय शाखाएं तथा सदस्यों की गतिविधियां	11
दूरगामी पहुंच वाली गतिविधियां	11
निबंध प्रतियोगिता	11
केस स्टडी प्रोग्राम	12
ढांचागत सुधार	12
संस्थान की वित्त व्यवस्था	13
महत्वपूर्ण घटनाएं	13
संगोष्ठियां/सम्मेलन/कार्यशालाएं/व्याख्यान	13
संस्थान के विशिष्ट आगंतुक	27
अकादमिक केंद्र/पीठ	27
प्रशासकीय एवं कार्मिक मामले	36
आभार प्रदर्शन/कृतज्ञता ज्ञापन	37
2020-21 के दौरान भुगतान किए गए टीए/डीए और मानदेय का विवरण	38
01-04-2020 से 31-03 -2021 तक कार्यकारी परिषद् तथा अन्य समितियों की बैठकों/ शाखाओं के पदाधिकारियों के टीए/डीए का विवरण	38
2020-21 के दौरान संकाय सदस्यों को भुगतान किए गए मानदेय एवं वेतन का विवरण	38

वित्त और लेखा	39
च संलग्नक	
च.1 (क) अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक पूरी की गई शोध परियोजनाएं	42
च.1 (ख) अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक चल रही शोध परियोजनाएं	47
च. 2 अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं	49
च. 3 शाखाओं की गतिविधियां (2020-2021)	58
च. 3.1 30-03-2021 तक आंचलिक और स्थानीय शाखाओं के सभापति और मानद सचिवों की सूची	67
च. 3.2 30-03-2021 तक आंचलिक एवं स्थानीय शाखाओं से संबद्ध सदस्यों की सूची	68
च. 4 अकादमिक/शिक्षण केंद्र 2020-21	71
च. 5 भा.लो.प्र.सं. के संकाय एवं अन्य के शैक्षणिक/अकादमिक योगदान (प्रशिक्षण एवं अनुसंधान अध्ययनों के अलावा)	72
च. 6 2020-21 के दौरान शाखाओं को दी गई वित्तीय सहायता का विवरण-पत्र	137
च. 7 31-03-2021 तक भा.लो.प्र.सं. की आंचलिक शाखाओं से संबद्ध संकाय सदस्य	140
च. 8 31-03-2021 को संकाय एवं अन्य वरिज्ञ अधिकारी	141
च. 9 शहरी अध्ययन के लिए केंद्र की गतिविधियां	143
च. 10 उपभोक्ता अध्ययन के लिए केंद्र की गतिविधियां	148
च. 11 2020-2021 के दौरान संकाय सदस्यों को भुगतान किए गए मानदेय एवं वेतन का विवरण	163
वर्ष 2020-21 के लिए तुलन-पत्र और खातों का लेखा-परीक्षित विवरण	164

संस्थान की गतिविधियों की रिपोर्ट

(2020-2021)

सिंहावलोकन

भा.लो.प्र.सं. की यह रिपोर्ट वर्ष 2020-2021 से संबंधित है। संस्थान मौलिक एवं समकालीन मुद्दों के साथ ही साथ सरकार, राष्ट्रीय संगठनों एवं अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा प्रायोजित विशिष्ट क्षेत्रों में शोध का कार्य करता है। यह सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को परिचालन क्षेत्र में सलाहकार सेवाएं भी प्रदान करता है। यह लोक प्रशासन और प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं और पक्षों पर बड़ी संख्या में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है और हर साल भारत एवं विदेशों के लगभग 5000 अधिकारियों एवं नागरिक समाज के सदस्यों को प्रशिक्षित करता है। यह विशेष प्रकाशनों और पत्रिकाओं के माध्यम से लोक प्रशासन से संबंधित साहित्य का प्रकाशन और प्रचार भी करता है।

यह रिपोर्ट निम्नलिखित चार प्रमुख शीर्षों के तहत संस्थान की गतिविधियों को प्रस्तुत करती है :

- प्रशिक्षण
- अनुसंधान गतिविधियां
- सूचना प्रबंधन
- सहयोगी एवं दूरगामी पहुंच वाली गतिविधियां

इस रिपोर्ट में निम्नलिखित के बारे में जानकारी शामिल है :

- संस्थान की वित्त व्यवस्था
- शैक्षणिक कार्यक्रम जैसे, संगोष्ठियां, सम्मेलन, व्याख्यान, यात्राएं, पुस्तक विमोचन आदि।
- भा.लो.प्र.सं. के विभिन्न केंद्रों और समितियों की गतिविधि रिपोर्ट
- संकाय की शैक्षणिक गतिविधियाँ
- प्रशासकीय एवं कार्मिक मामले

प्रशिक्षण/शैक्षिक कार्यक्रम

संस्थान ने बड़ी संख्या में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं :

1. **दीर्घकालिक कार्यक्रम** : इसमें वरिष्ठ अधिकारियों के लिए लोक प्रशासन में उन्नत व्यावसायिक कार्यक्रम (अप्पा) शामिल है जो भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के प्रशिक्षण प्रभाग के लिए आयोजित किया जाता है।
2. **प्रायोजित कार्यक्रम** : इनमें मुख्यतः वे कार्यक्रम शामिल हैं, जो-
 - अ) कार्मिक प्रशिक्षण विभाग
 - ब) शहरी विकास मंत्रालय
 - स) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
 - द) उपभोक्ता मामले विभाग
 - य) अन्य मंत्रालयों/ विभागों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, आदि के द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं।
3. **शुल्क आधारित कार्यक्रम** : उपयोगकर्ता संगठन के आदेश के साथ ही साथ अपनी पहल पर संस्थान द्वारा डिजाइन एवं पेश किए जाने वाले ।

46 वां उन्नत व्यावसायिक लोक प्रशासन कार्यक्रम '2020-21

संक्षिप्त रिपोर्ट

46वां उन्नत व्यावसायिक लोक प्रशासन कार्यक्रम भा.लो.प्र.सं. और भारत के इतिहास में सुनहरे पन्नों में दर्ज होगा। यह भा.लो.प्र.सं. के इतिहास में पहला डिजिटल कार्यक्रम होगा। अप्पा अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक उच्च-अंत-अनुकूलित 10 महीने का कार्यक्रम है।

यह कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है और इसे भा.लो.प्र.सं. द्वारा प्रत्येक वर्ष की 1 जुलाई से शुरू किया जाता है।

इस वर्ष का अप्पा बहुत ही अनोखा-भा.लो.प्र.स./देश में अपनी तरह का पहला

कोविड-जनित उपद्रव के साथ ही यह साल कई तरह से अनोखा रहा। कार्यक्रम 1 जुलाई , 2020 को शुरू हुआ। 29 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया। इनमें से ज्यादातर तीनों सेनाओं में से थे और अन्य आई टी एस, सैन्य अभियंता सेवा, (एम ई एस) व एम ओ ई एफ तथा दूसरे नागरिक अधिकारी थे।

कार्यक्रम के उद्देश्य

इस अप्पा पाठ्यक्रम की समाप्ति पर प्रतिभागी-गण निम्नलिखित योग्यताएं प्राप्त कर लेंगे :

- सामाजिक विज्ञान, लोकनीति एवं शासन की प्राथमिक धारणाओं को समझना
- भारत में लोक प्रशासन और शासन-सदाचार के सामयिक मुद्दों पर अपने विचार विकसित करना
- नीतियों और तौर-तरीकों के अनुप्रयोग को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण करना
- निर्णय लेने में विश्लेषणात्मक कौशलों का अनुप्रयोग करना
- प्रशासनिक सुधार एवं सुशासन के लिए फेम वर्क डिजाइन करना
- जनता की जरूरतों के प्रति संवेदनशीलता एवं अंतर्वैयक्तिक कौशलों को विकसित करना

उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु कार्यक्रम को इस तरह डिजाइन किया गया था कि इसमें नैतिकता, जीवन-मूल्य, समीक्षात्मक सोच और रचनात्मकता के विकास के लिए गैर क्रेडिट इनपुट के अलावा शैक्षणिक प्रशिक्षण मॉड्यूल, अनुभवात्मक अधिगम, शोध-निबंध लेखन, और मौखिक परीक्षा समाहित थी। इस वर्ष शैक्षणिक मॉड्यूल्स में 33 स्ट्रीम शामिल थे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह एक सर्वव्यापी कवरेज

है (इसमें कई संस्करण और वृद्धियां भी सम्मिलित थीं।

46वें डिजिटल अप्पा का क्रियान्वयन

कार्यक्रम की शुरुआत 1 जुलाई, 2020

इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र का माननीय केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह द्वारा डिजिटल रूप से उद्घाटन किया गया। अपने भाषण में उन्होंने उल्लेख किया कि एपीपीपीए ने विभिन्न सेवाओं और सशस्त्र बलों के प्रतिभागियों को (एक दूसरे को जानने, समझने तथा पृष्ठभूमि, सीमाओं और एक दूसरे की कठिनाइयों को जानने और उनकी सराहना करने का अवसर प्रदान किया है। इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इस विशिष्ट रूप से डिजाइन किए गए डिजिटल कार्यक्रम ने प्रतिभागियों को अपने ज्ञान को अद्यतन करने और नागरिक-केंद्रित-सेवा-वितरण के सभी पहलुओं में सुधार के लिए आवश्यक गुणों को विकसित करने हेतु जीवन भर का अवसर प्रदान किया है।

कार्यक्रम का संचालन

(जुलाई, 2020-अप्रैल, 2021)

इस बैच में विभिन्न शैक्षणिक मॉड्यूल्स को कवर किया गया। ये मॉड्यूल्स चार व्यापक क्षेत्रों के गिर्द घूमते हुए 33 विभिन्न बहु-विषयक ज्ञान क्षेत्रों से संबंधित थे। सिद्धांत और अवधारणाओं पर एक बुनियादी मॉड्यूल था। नीति, प्रशासन और शासन पर एक विषय गत मॉड्यूल था। तीसरा मॉड्यूल शासन में गंभीर लचताओं पर था। हर एक विषय को मिश्रित मोड में पढ़ाया गया। भालोप्रस संकाय द्वारा रिकार्ड किए गए “माय आई आई पी ए वीडियो” के साथ ही उपलब्ध ऑनलाइन मॉड्यूल का इस्तेमाल हुआ। भा.लो.प्र.सं. के परिसर में मौजूद ऑनलाइन तथा कुछ ऑनलाइन प्रतिभागियों के साथ लाइव चर्चा भी हुईं।

अ) शैक्षणिक माड्डूल्स

पांच महीने तक चले अप्पा के पूर्वार्ध भाग में अवधारणाओं और अनुप्रयोगों पर फोकस रहा। स्ट्रीम्स को शासन तथा अध्ययन के संबंधित क्षेत्रों में हालिया

विकास के मुद्दों की प्रारंभिकता के आधार पर निर्धारित किया गया था। इन स्ट्रीम्स को पुनः तीन भागों में विभाजित किया गया, जो निम्नलिखित हैं :

- (अ.1) बुनियादी मॉड्यूल : सिद्धांत एवं अवधारणाएं
- (अ.2) विषयगत मॉड्यूल : नीति, प्रशासन एवं शासन
- (अ.3) लोकनीति मॉड्यूल : शासन में गंभीर लचताएं

ब) अनुभव के माध्यम से अधिगम

कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने एक दूसरे से संबंधित नौकरियों में दिलचस्प अनुभवों के साथ ही साथ विभिन्न स्थानों की यात्राओं के माध्यम से सीखा। इन यात्राओं/दौरों का उद्देश्य प्रतिभागियों को, उद्योग तथा चयनित ग्रामीण और शहरी केंद्रों/ सुविधाओं में मार्गदर्शित अध्ययन यात्राओं के माध्यम से विभिन्न विकासात्मक सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और वितरण से संबंधित जमीनी हकीकत से अवगत कराना था। 46 वें अप्पा के दौरान इन का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है :

ब.1) अनुभवजन्य प्रस्तुतीकरण :

यह बहुत ही सार्थक और आनंद पूर्ण अभ्यास था। अनुभवात्मक प्रस्तुतियां प्रतिभागियों के बीच अनुभव और विशेषज्ञता के आपसी आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए थी। हर एक प्रतिभागी ने अपनी सेवा के दौरान कभी न कभी जिस विशिष्ट स्थिति का सामना किया था उस पर केंद्रित करते हुए अपनी प्रस्तुति तैयार की थी। ये प्रस्तुतियां आंतरिक प्रशासन या क्षेत्र की स्थितियों में नवाचारों, संगठनात्मक नेतृत्व में सर्वोत्तम परंपराओं या परियोजना नियोजन और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण शिक्षाओं को उजागर करने के लिए थीं।

ब.2) ग्रामीण क्षेत्र का अध्ययन :

संदर्भ में ग्रामीण विकास एवं प्रशासन का अध्ययन करने के लिए, इस घटक का उद्देश्य प्रतिभागियों को ग्रामीण जीवन की सामाजिक एवं आर्थिक वास्तविकताओं के प्रति संवेदनशील बनाना था। प्रतिभागियों को भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों जैसे स्वच्छ भारत अभियान, जन धन योजना, पीएमजे-एवाई, स्किल इंडिया आदि पर

केंद्रित एक विषय आधारित अध्ययन सौंपा गया था। उनसे वितरण तंत्र की प्रभावशीलता की जांच करने और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभाव का आकलन करने की उम्मीद की गई थी। प्रतिभागियों ने छोटे-छोटे समूहों में देश के विभिन्न भागों में चयनित ग्रामीण इलाकों का दौरा किया और ग्राम स्तर के पदाधिकारियों एवं पंचायत सदस्यों से बातचीत की। ये दौरे और बातचीत संकाय सदस्य के पूर्ण मार्गदर्शन में हुईं। इन समूहों ने अपने इन दौरों की क्षेत्र अध्ययन रिपोर्ट साझा की। यह भविष्य के नीति संदर्भ के लिए उपयोगी थी। ग्रामीण क्षेत्र अध्ययन रिपोर्टों को बाद में भा.लो.प्र.स. में प्रस्तुत किया गया। इस साल पंसारी नामक आदर्श गांव और तेजगढ़ नामक आदिवासी गांव की यात्रा की गई। पंसारी गुजरात के सबर कांता जिले में स्थित है और तेजगढ़ बड़ोदरा शहर से पूर्व में 90 कि.मी. की दूरी पर गुजरात के ही छोटा उदयपुर जिले में स्थित है।

ब.3) शहरी क्षेत्र अध्ययन :

स्मार्ट शहरों तथा भारत सरकार की अन्य प्रमुख शहरी विकास पहलों के विशेष संदर्भ में शहरी विकास एवं प्रशासन का अध्ययन करने के लिए यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में प्रतिभागियों को शहरी प्रशासन एवं प्रबंधन की समस्याओं को तथा उनका समाधान करने में आने वाली चुनौतियों को समझने का मौका मिला। प्रतिभागियों ने विभिन्न शहरी विकास योजनाओं तथा लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं पर पड़ने वाले उनके असर के बारे में जाना। खासकर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों पर। इस अध्ययन में नगर पालिका एवं अन्य विकास एजेंसियों के पदाधिकारियों के साथ बातचीत भी शामिल थी। ग्रामीण क्षेत्र अध्ययन की ही तरह इस समूह ने उन विशिष्ट शहरों/ कस्बों का दौरा किया जिन्हें विशिष्ट मुद्दों के आधार पर चुना गया था। ये चुनिंदा शहर/ कस्बे गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर, भुज और कच्छ जिलों के विभिन्न अंचलों में स्थित थे। शहरी अध्ययन रिपोर्टों को भी समूह द्वारा साझा किया गया। इन रिपोर्टों ने अच्छे नीति इनपुट के रूप में काम किया।

अग्रिम क्षेत्र का दौरा :

प्रतिभागियों को सीमावर्ती राज्यों और जिलों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थित भारतीय सेना एवं स्थानीय सरकारों के प्रतिष्ठानों के साथ ही साथ अन्य संस्थानों के प्रतिष्ठानों की यात्राओं के माध्यम से जमीनी हकीकत से भी अवगत कराया गया। अग्रिम क्षेत्रों के दौरे के लिए प्रतिभागियों को सिकिम तथा बंगल के दार्जिलिंग जिले में ले जाया गया।

स) विशेष व्याख्यान/ वेबिनार :

प्रतिभागियों को लोकप्रिय विषयों पर आयोजित वेबिनारों में प्रशासकों, विचारकों और प्रेरकों को सुनने और उनसे बातचीत करने का अवसर मिला। अप्पा टाउन हॉल चर्चा का आयोजन किया गया। इसमें शिक्षाविदों की मंडली के साथ नीति निर्माताओं को प्रासंगिक राष्ट्रीय लचताओं पर बहस करने तथा ‘सचिव भाषण श्रृंखला’ में वरिष्ठ नौकरशाहों के रणनीतिक परिप्रेक्ष्य को सुनने के लिए एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया गया था। सद्गुरु जग्गी वासुदेव द्वारा सुख सेहत के लिए ‘आंतरिक इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी’ विषय पर एक विशेष सत्र भी आयोजित किया गया।

दीक्षांत समारोह

46वें अप्पा के दीक्षांत समारोह का वेब एक्स वीडियो कान्फ्रेसिंग सुविधा का इस्तेमाल करते हुए वर्चुअल माध्यम के द्वारा 30 अप्रैल, 2021 को आयोजन किया गया। इसमें डीओपीटी के सचिव श्री दीपक

खांडेकर ने सम्मानित मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की अध्यक्षता करने हेतु और पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राजकुमार ने कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए अपनी-अपनी कृपा पूर्ण सहमति दे दी थी।

कार्यक्रम की शुरूआत में भा.लो.प्र.सं. के महानिदेशक श्री एस.एन. त्रिपाठी ने अपने विजन और कार्यक्रम की अमिट छाप को साझा किया। इस कार्यक्रम के निदेशकों की उन्होंने विशेष रूप से प्रशंसा की। इसके पश्चात कार्यक्रम की निर्देशिका डॉ चारु मल्होत्रा ने कार्यक्रम की सक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की। अपने मुख्य दीक्षांत भाषण में श्री दीपक खांडेकर ने देश में लोक प्रशासन के प्रतिमान को धार देने में भा.लो.प्र.सं. द्वारा उठाए गए महान कदमों और योगदान पर जोर दिया। इसी तरह से प्रो. राजकुमार ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान शिक्षा क्षेत्र के सामने आने वाली अभूतपूर्व चुनौतियों को रेखांकित किया और यह बताया कि भा.लो.प्र.सं. ने 46वें अप्पा का सफलतापूर्वक संचालन करके इनसे कैसे निपटा। डिजिटल अप्पा की यह खूबसूरत गाथा इसके सह निदेशक डॉ पवन तनेजा द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम

दीर्घकालिक अप्पा कार्यक्रम से अलग, संस्थान द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान 65 अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इनका व्यौरा इस प्रकार है :

पाठ्यक्रम	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
मंत्रालयों/विभागों द्वारा आयोजित	11	301
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (अप्पा सहित)	1	29
राज्य सरकार	1	25
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	6	174
उपर्योक्ता मामलों का मंत्रालय	35	7001
शहरी विकास मंत्रालय	3	73
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	1	14
अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम	3	94
अन्य	5	642
कुल योग	66	8353

इस प्रकार आयोजित पाठ्यक्रमों की कुल संख्या 66 थी। इसमें अप्पा भी शामिल है। वर्ष के दौरान कुल मिलाकर 8353 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इसमें 46वें अप्पा के प्रतिभागी भी शामिल हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण एफ-2 पर दिया गया है।

उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा भा.लो.प्र.सं. में इस अवधि के दौरान 45 ऑनलाइन वेबिनारों/स्मारक व्याख्यानों का भी आयोजन किया गया।

सूचना प्रबंधन

संस्थान अपने नियमित प्रकाशनों के माध्यम से लोक प्रशासन, शासन, नीति, और विकास से संबंधित सूचना, विश्लेषण, दृष्टिकोण और ज्ञान का प्रसार करता है। इन प्रकाशनों के नाम इस प्रकार हैं :

भालोप्रस के मासिक न्यूज़ लेटर के डिजिटल संस्करण, सेज प्रकाशन के सहयोग से भारतीय लोक प्रशासन पत्रिका आई जे पी ए के त्रैमासिक संस्करण, नगर लोक के त्रैमासिक संस्करण, लोक प्रशासन में प्रलेखन।

(डीपीए) के त्रैमासिक संस्करण, लोक प्रशासन (हिंदी) पत्रिका के अर्धवार्षिक संस्करण और भालोप्रस डाइजेस्ट के त्रैमासिक संस्करण।

आई.जे.पी.ए के अलावा सभी पत्रिकाओं के डिजिटल संस्करण भालोप्रस की वेबसाइट पर निःशुल्क उपलब्ध हैं। आई जे पी ए के सभी पिछले और मौजूदा संस्करण सेज /आई.जे.पी.ए की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। भारतीय लोक प्रशासन पत्रिका (आई.जे.पी.ए) नए यूजीसी केरेयर ग्रुप 1 के तहत सूचीबद्ध है।

प्रकाशन

प्रकाशन अनुभाग द्वारा वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित साहित्य का प्रकाशन किया गया :

1. भारतीय लोक प्रशासन पत्रिका (आई जे पी ए) के चार संस्करण
2. लोक प्रशासन (हिंदी) के दो संस्करण
3. नगर लोक के चार संस्करण

4. लोक प्रशासन में प्रलेखन (डीपीए) के चार संस्करण
5. भा.लो.प्र.सं. डाइजेस्ट के चार संस्करण
6. भा.लो.प्र.सं. के डिजिटल न्यूज़लेटर के बारह प्रकाशन

भा.लो.प्र.सं. द्वारा पिछले वर्ष एजीएम 2020-21 के दौरान निम्नलिखित साहित्य प्रकाशित और जारी किया गया :

1. श्री टी. एन. चतुर्वेदी स्मारक (अनुसंधान एवं मूल्यांकन)
2. डॉ यू. सी. अग्रवाल स्मारक (लेख एवं पत्र)
3. प्रो. सी. शीला रेड्डी द्वारा डॉ बी आर अंबेडकर फिलॉसफी ऑ कांस्टीट्यूशनलिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस, सोशल एंड पुलिटिकल
4. पांचवां राकेश हूजा स्मारक व्याख्यान, प्रो. सी. शीला रेड्डी एवं श्रीमती मीनाक्षी हूजा द्वारा संपादित

इस सप्ताह भा.लो.प्र.स. समाचार का शुभारंभ

इस सप्ताह भा.लो.प्र.सं. द्वारा दृश्य श्रव्य समाचारों के समाचार खंड का शुभारंभ किया गया है। इसमें भा.लो.प्र.सं. एवं उसकी शाखाओं के संस्थागत समाचारों के साथ-साथ सरकार की नई योजनाओं और नीतियों से संबंधित जानकारी मौजूद रहती है। सरकारी योजनाओं और भा.लो.प्र.सं. की गतिविधियों के प्रचार प्रसार के लिए इस हफ्ते भा.लो.प्र.सं. की खबरों के चार विडियो यूट्यूब पर अपलोड किए गए हैं।

ये विडियो निम्नलिखित विषयों पर थे :

1. मिशन कर्म योगी
2. गरीब कल्याण रोजगार योजना
3. पढ़ना लिखना अभियान
4. सरकारी भर्ती हेतु राष्ट्रीय भर्ती अभिकरण

पुस्तकालय

समीक्षाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां की गई :

संग्रह विकास

वर्ष 2020-21 के दौरान पुस्तकालय के भंडार में 1910 पुस्तकें और 499 जिल्द बंद पत्रिकाओं को जोड़ा गया। इनमें से 101 पुस्तकें खरीदी गईं और 1809 पुस्तकें निःशुल्क प्राप्त हुईं। लगभग 85 दस्तावेज सार्वजनिक दस्तावेज अनुभाग में जोड़े गए। 31 मार्च 2021 को पुस्तकालय के पास 2.28 लाख किताबें एवं जिल्द बंद पत्रिकाएं मौजूद हैं। इस वर्ष के दौरान पुस्तकालय ने 99 वर्तमान पत्रिकाओं एवं 21 समाचार पत्रों की सदस्यता ली और 132 पत्रिकाएं ‘निःशुल्क एवं विनिमय’ के आधार पर प्राप्त की।

टी. एन. चतुर्वेदी संग्रह

पुस्तकालय को स्व. श्री. टी. एन. चतुर्वेदी के परिवार के सदस्यों से तकरीबन 27 सौ पुस्तकें मानार्थ अनुपूरक आधार पर प्राप्त हुई हैं। पुस्तकालय ने इन पुस्तकों को प्र-संस्कृत एवं संसाधित किया है और पुस्तकालय के संर्भ क्षेत्र में अलग से एक “टी. एन. चतुर्वेदी संग्रह” बनाया है।

ऑनलाइन सेवाएं

सब्सक्राइब्ड ऑनलाइन डेटा बेस

भालोप्रस की वेबसाइट के जरिए 21 से भी ज्यादा पत्रिकाओं तक ऑनलाइन पहुंच की सुविधा दी जा रही है। इन पत्रिकाओं में हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, इकॉनामिस्ट, टाइम और इकॉनामिक एंड पुलिटिकल वीकली आदि शामिल हैं। इसके अलावा पुस्तकालय ने ए बी आई इनफोर्म की सदस्यता जारी रखी है। इससे करीब 4000 शीर्षकों तक पहुंच की सुविधा मिलती रही। इनमें से 3000 शीर्षक अपने पूर्ण पाठ में हैं। इसके अलावा यह डेटाबेस तकरीबन 25000 से भी अधिक शोध निबंधों तक पहुंच की सुविधा देता है। पुस्तकालय ने जेएसटी और की सदस्यता जारी रखी है। यह लाभ न कमाने वाला संगठन है। यह संगठन विद्वानों के समुदाय को एक विश्वसनीय डिजिटल संग्रह में बौद्धिक सामग्री की एक श्रृंखला को खोजने, उपयोग करने और बनाने में मदद करने के लिए समर्पित है। यह तकरीबन 2700 शैक्षणिक पत्रिकाओं के संपूर्ण पाठ की खोज प्रदान करता है।

आंतरिक पुस्तकालय ऑनलाइन डेटाबेस

कंप्यूटरीकृत पुस्तकालय डेटाबेस में पुस्तकों और रिपोर्टों से संबंधित 1.38 लाख रिकॉर्ड्स और आवधिक लेखों से संबंधित 1.23 लाख रिकॉर्ड्स मौजूद हैं।

इन सभी ऑनलाइन पत्रिकाओं और डेटाबेस को रिमोट एक्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से दुनियाभर में 24×7 एक्सेस किया जा सकता है।

डिजिटल ज्ञान भंडार :

पुस्तकालय ने संस्थान के अनुसंधान आउटपुट और प्रकाशित संसाधनों को प्रदर्शित करते हुए डिजिटल ज्ञान भंडार (डीकेआर) बनाया है। संस्थान की बौद्धिक पूँजी, अनुसंधान आउटपुट और प्रकाशित संसाधनों को सुगम्य में बनाने में जीकेआर अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका उद्देश्य संस्थान की शैक्षणिक और अनुसंधान गतिविधि से उत्पन्न बौद्धिक कार्यों को संग्रहित और संरक्षित करना है जिससे कि इसे खुली पहुंच के माध्यम से इसमें प्रसारित किया जा सके।

संसाधनों को विभिन्न प्रकारों के लिए बनाए गए समुदायों के रूप में दर्शाया जाता है (जैसे कि वार्षिक आम सभा की बैठक, अध्यक्षीय संबोधन, संकाय प्रकाशन, दुर्लभ पुस्तकें, वार्षिक रिपोर्ट, विशेष रिपोर्ट, विषय गत पेपर, वर्किंग पेपर और इसी तरह के अन्य। इनमें ए पी पी ए के प्रतिभागियों द्वारा अपनी एम फ़िल डिग्री के लिए लिखे गए शोध प्रबंध (थीसिस) और शोध निबंध भी शामिल हैं। भंडार में अब तक 3379 दस्तावेज अपलोड किए जा चुके हैं। इनमें सत्र 2008-09 से 2019-20 तक के 10 सर्वोत्तम अप्या के शोध निबंधों का पूर्ण पाठ भी शामिल है। अप्या व्याख्यानों को भी इस भंडार में अपलोड किया गया है। इनमें 34 मॉड्यूल शामिल हैं। इन मॉड्यूलों में वीडियो, पीपीटी, प्रश्नोत्तरी और पठन सामग्री शामिल है।

पुस्तकालय सेवाएं :

पुस्तकालय द्वारा 31 मार्च 2021 तक 1202 दस्तावेज उधार दिए गए और दस्तावेजों के 1120 खंड वापस प्राप्त किए गए थे। कंप्यूटरीकृत डेटाबेस में पुस्तकों

और रिपोर्ट से संबंधित 1.38 लाख और आवधिक लेखों से संबंधित 1.23 लाख रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। पुस्तकालय का उपयोग 3166 उपयोगकर्ताओं ने किया। इनमें संस्थान के संकाय सदस्य, भा.लो.प्र.सं. सदस्य और लोक प्रशासन में उन्नत व्यावसायिक कार्यक्रम सहित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागी शामिल हैं। इसके अलावा तकरीबन 1670 वास्तविक शोधकर्ताओं ने शुल्क आधारित परामर्श कार्यक्रम के तहत पुस्तकालय के संसाधनों का इस्तेमाल किया। पुस्तकालय ने सदस्यों को फोटोकॉपी एवं इंटरनेट की सुविधा देना जारी रखा। वर्ष के दौरान 14885 पृष्ठों की फोटो कॉपी उपलब्ध करवाई गई तथा उपयोगकर्ताओं को ग्रंथ सूची सेवाएं प्रदान की गई।

मूल्य संवर्धित सेवाएं

पुस्तकालय वर्तमान जागरूकता, अनुक्रमण और सार सेवाओं की सुविधा प्रदान करता है। पुस्तकालय नियमित रूप से आने वाली पुस्तकों की अग्रिम सूचना जारी करता है। ये अग्रिम सूचनाएं संस्करणों की वार्षिक सूची, साप्ताहिक समाचार अलर्ट और वर्तमान विषयों से संबंधित नए शीर्षकों के बारे में होती हैं।

इन अलर्ट्स का उद्देश्य है - पाठकों को सन्निकट भविष्य में प्रकाशित होने वाले दस्तावेजों और अधुनातन सूचना से वाकिफ रखना। अनुक्रमण एवं सार लेखन की त्रैमासिक पत्रिका “लोक प्रशासन में दस्तावेज लेखन” (डीआईपीए) शीर्षक से प्रकाशित की जा रही है। इसमें आवधिक लेखों का अनुक्रमण, सार-सारांश, पुस्तक समीक्षा एवं पुस्तक नोट्स शामिल होते हैं। वर्ष के दौरान 2040 आवधिक लेख, 125 पुस्तक समीक्षाएं और 69 बुक नोट्स डीआईपीए में जोड़े गए। वर्ष 2020 के लिए डीआईपीए के सभी चारों संस्करण निश्चित समय पर प्रकाशित हुए थे। इसके अलावा पुस्तकालय अपने सदस्यों और विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रतिभागियों को ग्रंथसूची सेवाएं प्रदान करता है।

राष्ट्रीय पुस्तकालय नेटवर्क में भागीदारी

संस्थान का पुस्तकालय विकासशील पुस्तकालय नेटवर्क (डेलनेट) का सक्रिय सदस्य है और अंतर

पुस्तकालय ऋण, ग्रंथ सूची के संकलन और साहित्य खोज के लिए, नेटवर्क की सुविधाओं का काफी उपयोग कर रहा है। इस नेटवर्क प्रयास के भाग के रूप में भा.लो.प्र.सं. पुस्तकालय अन्य सहयोगी नेटवर्क सदस्यों के लिए अपने समृद्ध संसाधनों के उपयोग में भी पारस्परिक सहयोग कर रहा है। वर्ष के दौरान भालोप्रस पुस्तकालय में उपयोगकर्ताओं के लिए अंतर पुस्तकालय ऋण पर 27 दस्तावेज उधार लिए गए थे और 97 दस्तावेज अन्य पुस्तकालयों द्वारा (डेलनेट) सुविधा के माध्यम से उधार लिए गए थे। हमारी पारस्परिक कुशल सेवाओं के एक भाग के रूप में भा.लो.प्र.सं. पुस्तकालय को 7000 पुस्तकालयों में से सर्वोत्तम पुस्तकालय के रूप में चुना गया है और डेलनेट द्वारा प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया है।

भा.लो.प्र.सं. पुस्तकालय के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन

- i) पुस्तकालय सदस्यों के इस्तेमाल के लिए पुस्तकालय परिसर के अंदर वाई फाई सुविधाएं प्रदान करना जारी है।
- ii) संसाधनों की खोज हेतु उपयोगकर्ताओं के इस्तेमाल के लिए पुस्तकालय के संदर्भ एवं परिसंचरण क्षेत्र में भूतल पर दो नए संगणक उपलब्ध करवाए गए हैं।

संघ की गतिविधियां

आम सभा की 66वीं वार्षिक बैठक

संस्थान की आम सभा की 66वीं बैठक शनिवार, 31 अक्टूबर, 2020 को अपराह्न 4:00 बजे आयोजित की गई। भा.लो.प्र.सं. के अध्यक्ष व भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की तथा भा.लो.प्र.सं. कार्यकारी परिषद के सभापति एवं डीओपीटी के माननीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आम सभा की बैठक के द्वितीय सत्र की अध्यक्षता की। भा.लो.प्र.सं. के अध्यक्ष एवं भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से एजीएम की अध्यक्षता की। उन्होंने सेवा प्रदान करने

में, न्याय देने में और सामान्य जन की जरूरतों के प्रति सरकारी मशीनरी के प्रत्युत्तर देने के तौर तरीकों में परिवर्तन लाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, “यही वह परिवर्तन है जिसकी ओर आज का भारत टकटकी लगाए देख रहा है।” उन्होंने राय व्यक्त की कि लोक प्रशासन का प्रमुख संस्थान होने के कारण भा.लो.प्र.सं. को यह परिवर्तन लाने में निर्णयक भूमिका निभानी चाहिए।

उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भालोप्रस ने महामारी के दौरान भी डिजिटल बुनियादी संरचना का निर्माण करके अपनी गतिविधियों को जारी रखा है। उन्होंने भा.लो.प्र.सं. द्वारा नई वेबसाइट का शुभारंभ किए जाने की भी प्रशंसा की। श्री नायडू ने भा.लो.प्र.सं. के पुस्तकालय में भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री सरदार श्री वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण किया। महानिदेशक एवं अधिकारियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि मूर्ति सभी को प्रेरणा प्रदान करती रहेगी।

वर्तमान और उभरती हुई चुनौतियों के आलोक में भा.लो.प्र.सं. की कार्यकारी परिषद द्वारा इसे पुनः स्थापित करने के लिए शुरू किए गए कदमों को संज्ञान में लेते हुए श्री नायडू ने कहा, “हमें संस्थागत सुधारों के लिए ठोस रणनीति के साथ आना होगा और देश में शासन सुधारों की नई लहर को उत्प्रेरित करने के लिए भा.लो.प्र.सं. को एक उपयुक्त संगठन बनाना होगा।” उन्होंने कार्यकारी परिषद को छोटा, कुशल, लागत प्रभावी और अधिक प्रतिनिधिक बनाने के लिए भा.लो.प्र.सं. के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड रूल्स में किए गए संशोधनों एवं बदलावों की सराहना की। उन्होंने भा.लो.प्र.सं. के सभापति के रूप में प्रभार ग्रहण करने के लिए केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह का स्वागत किया और आशा व्यक्त की कि उनका अनुभव एवं क्षमता भा.लो.प्र.सं. के कद को और अधिक बढ़ाएगी। उन्होंने भा.लो.प्र.सं. के पूर्व सभापति श्री. टी. एन. चतुर्वेदी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, जिनका जनवरी 2020 में निधन हो गया था।

भा.लो.प्र.सं. के सभापति डॉ जितेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में उल्लेख किया कि पिछले पाँच वर्षों में

सरकार द्वारा कई सुधार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने सिविल सेवाओं को स्टील फेम के रूप में परिभाषित किया है। मिशन कर्म योगी भारत की प्राथमिकताओं और राष्ट्र की आवश्यकताओं के आधार पर हमारी सेवाओं को समय-समय पर पुनः स्थापित करने के लिए जीते हैं। वास्तव में मिशन कर्म योगी “नियम के अभ्यास से भूमिका के अभ्यास” में स्थानांतरण करने का एक प्रयास है ताकि जनसेवक द्वारा ली गई किसी भी नौकरी में क्षमता निर्माण का प्रावधान हो और वह भी आधुनिकतम तकनीकी तरीकों-ऑनलाइन तथा ऐप्स के माध्यम से।

उन्होंने भा.लो.प्र.सं. के कामकाज में बड़ा डिजिटल बदलाव करने के लिए महानिदेशक और उनकी टीम की सराहना की। आज ऑनलाइन तंत्र के बिना किसी व्यवधान के कार्य कर रहा है। इसका प्रमाण कोविड-19 के दौरान उस समय मिला जब संस्थान का शो तब भी चला जब अन्य संगठनों के अधीन चलने वाली सभी गतिविधियां बुरी तरह बाधित हो गई थी। वह इसके साक्षी स्वयं बने क्योंकि भालोप्रस द्वारा आयोजित अप्पा पाठ्यक्रम का डिजिटल उद्घाटन इस साल 1 जुलाई को उन्हीं के द्वारा उस समय किया गया था जब कोविड-जनित यह तबाही अपने चरम पर थी। इसी तरह भा.लो.प्र.सं. द्वारा बड़ी संख्या में शोध अध्ययन और अन्य पाठ्यक्रम संचालित किए गए हैं।

भा.लो.प्र.सं. के महानिदेशक श्री सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने अपने उद्घाटन भाषण में संस्थान की उन उपलब्धियों और ताकतों के बारे में संक्षेप में बताया जिनके लिए भा.लो.प्र.सं. के कर्मचारियों ने कड़ी मेहनत की है। इस कोविड-19 के होते हुए भी भा.लो.प्र.सं. आगे बढ़ता रहा है और इसकी नियमित गतिविधियां सामान्य स्थिति में लौट रही हैं। भा.लो.प्र.सं. ने संपूर्ण आवश्यक डिजिटल अवसंरचना तैयार की है और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए डिजिटल सामग्री तैयार की है। यह विभिन्न विभागों के साथ ही साथ वेबिनारों के लिए भी नियमित रूप से ऑनलाइन प्रशिक्षण कर रहा है। भा.लो.प्र.सं. का संकाय महामारी के दौरान भी अनुसंधान एवं मूल्यांकन अध्ययन कर रहा है। भा.लो.प्र.सं. के कुलसचिव/ रजिस्ट्रार श्री अमिताभ रंजन ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

सदस्यों का 64 वां वार्षिक सम्मेलन

संस्थान के सदस्यों का 64 वां वार्षिक सम्मेलन ऑनलाइन/ वर्चुअल माध्यम से 2 नवंबर, 2020 को पूर्वाह्न 10:00 बजे आयोजित किया गया।

सम्मेलन का विषय था- महामारियों का प्रबंधन

डॉ सचिन चौधरी ने विषय पत्र प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने महामारियों के प्रबंधन की अवधारणा पर प्रकाश डाला। अपने स्वागत भाषण में भा.लो.प्र.सं. के महानिदेशक श्री एस. एन. त्रिपाठी ने थीम के महत्व पर प्रकाश डाला। आंचलिक एवं स्थानीय शाखाओं के प्रतिनिधियों ने विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। चर्चा के अलावा सम्मेलन के दौरान विषय पर, पत्र भी प्रस्तुत किए गए। वार्षिक सम्मेलन के आयोजन से पहले आंचलिक और स्थानीय शाखाओं द्वारा थीम के मुख्य विषय पर अपने अपने मुख्यालय पर प्रस्तावना सम्मेलनों/गोष्ठियों का आयोजन किया गया। आंचलिक और स्थानीय शाखाओं द्वारा आयोजित सम्मेलनों/गोष्ठियों की सिफारिशों और टिप्पणियों को इस सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया।

कार्यकारी परिषद

कार्यकारी परिषद की बैठकें

वर्ष के दौरान 16 सितंबर, 2020 तथा 21 अक्टूबर, 2020 को कार्यकारी परिषद की दो बैठकें आयोजित की गईं।

मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड रूल्स में संशोधन

आम सभा ने 31 अक्टूबर 2020 को अपराह्न 4:00 बजे आयोजित अपनी वार्षिक बैठक में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड रूल्स में प्रस्तावित संशोधनों का अनुमोदन किया। इन संशोधनों का समय से सदस्यों में व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया। इनमें निम्नलिखित अनुपूरक संकल्प भी शामिल थे :

- चुनाव सहित अध्यक्ष की भूमिका को बढ़ाने के लिए नियम आठ में संशोधन किया जा रहा है।

- भा.लो.प्र.सं. की कार्यकारी परिषद के सभापति की भूमिका को बढ़ाने हेतु इसे 'पदेन' करने के लिए नियमों में संशोधन किया जा रहा है।
- कार्यकारी परिषद के नियम 13 (1) को 16 सदस्यों के लिए युद्धिसंगत बनाया जा रहा है।
- उपरोक्त के अलावा नियम 13 (2)- ई सी बैठक; 13 (3)-कोरम; नियम 17 (2) viii - ई सी की शक्ति; नियम 21- आमसभा की विशेष बैठक; नियम 22-एजीएम की बैठक; नियम 36 (1) - एम ओ ए को संशोधित करने की शक्ति; और निदेशक को महानिदेशक करने से संबंधित नियम को संशोधित किया गया।
- इसके अलावा कुछ नियम/खंड हटा दिए गए थे। अर्थात् नियम 19 (अ), 10, 10 (अ), 11, 14, 15, 18 (अ) और (ब) तथा 30 (2)। इन नियमों उपर्युक्तों का संबंध स्थायी समिति, शैक्षणिक समिति, चुनावों तथा बहुत-सी दूसरी बातों से था। प्रासारिक खंडों में 'निदेशक' को 'महानिदेशक' से स्थानापन्न किया जाएगा।
- यह भी अनुमोदित किया गया कि नियमों को पुनः नई संख्या दी जाए। वाक्यों की व्याकरणिक त्रुटियां ठीक की जाएं; पर इससे संशोधनों की मूल भावना अक्षुण्ण रहे। इसके अलावा अन्य आवश्यक कार्यवाहियां की जाएं।

कार्यकारी परिषद को छोटा, लागत प्रभावी और आंचलिक प्रतिनिधित्व युक्त बनाए रखने के साथ ही कुशल बनाने के लिए नियमों में संशोधन आवश्यक थे। नए नियम 21 वह सदी की बदलती हुई दुनिया में भा.लो.प्र.सं. को नई दिशा देने और मजबूत करने में मदद करेंगे।

सदस्यता

वर्ष के दौरान 215 आजीवन सदस्यों, 37 एसोसिएट सदस्यों और 14 विद्यार्थी सदस्यों को शामिल किया गया। जिन पर सदस्यता शुल्क का एसियर बकाया था, ऐसे 13 वार्षिक सदस्यों और दो कार्पोरेट सदस्यों के नाम, संस्थान के नियम संख्या 35 (1) के अंतर्गत सदस्यता पंजिकाओं से काट दिए गए। वर्ष के दौरान 22 आजीवन सदस्यों का निधन हो गया।

सदस्यता का श्रेणी वार विवरण सारणी-बद्ध रूप में तालिका क्रमांक 1 में दिया गया है।

पॉल एच एप्पलबार्ड अवार्ड से सम्मानित भा.लो.प्र.सं. के विशिष्ट सदस्य

निम्नलिखित सदस्यों को

भा.लो.प्र.सं. तथा लोक प्रशासन के क्षेत्र में विशिष्ट सेवाएं देने के लिए एजीएम में पॉल एच एप्पल बार्ड पुरस्कार से नवाजा गया :

1. श्री ईश्वर चंद्र द्विवेदी, भा.पु.से. (अवकाश प्राप्त)
2. प्रो के मुनि रत्नम् नायदू
3. श्री शरत् चंद्र मिश्र, भा.पु.से. (अवकाश प्राप्त)
4. श्री बी एन मखीजा भा.प्र.से. (अवकाश प्राप्त)

भारतीय लोक प्रशासन पत्रिका (आईजेपीए) में सर्वोत्तम लेख के लिए वर्ष 2019 का श्री टी. एन. चतुर्वेदी पुरस्कार

आईजेपीए में प्रकाशित सर्वोत्तम लेख के लिए वर्ष 2019 का श्री टी एन चतुर्वेदी पुरस्कार, सुश्री अभिलाषा बहुगुणा और श्री जी प्रसन्ना रामास्वामी को उनके लेख 'हाइलैंड टू हाई फैशन: द डिवेलपमेंट ऑफ अ विमिन कोऑपरेटिव इन लद्दाख' के लिए प्रदान किया गया।

सारणी 1

	वार्षिक सदस्य	आजीवन सदस्य	एसोसिएट सदस्य	विद्यार्थी सदस्य	कॉर्पोरेट सदस्य (वार्षिक)	कॉर्पोरेट सदस्य (20 वर्ष)	कुल योग
1. 31.03.20 को सदस्यता	33	10642	143	07	06	63	10894
2. 2020-21 के दौरान भर्ती सदस्य	--	215	37	14	
3. 2020-21 के दौरान रूपांतरण	--	--	-(54)	
4. 2020-21 में हटाए गए सदस्य	-(13)	--	-(02)	
5. 2020-21 में मृत सदस्य	--	-(22)	
31.03.2021 को कुल सदस्यता	20	10835	126	21	06	61	11069

लोक सेवा में उत्कृष्टता के लिए श्री टीएन चतुर्वेदी पुरस्कार

भा.लो.प्र.सं. एवं भा.लो.प्र.सं. पूर्व छात्र संघ के सहयोग से लोक सेवा में उत्कृष्टता के लिए श्री टी. एन. चतुर्वेदी पुरस्कार की स्थापना की है। इस पुरस्कार में एक लाख रुपए नकद, प्रशस्ति पत्र और पट्टिका प्रदान की जाती है। इस वर्ष यह पुरस्कार विकासशील पुस्तकालय नेटवर्क (डेलनेट) को प्रदान किया गया।

श्री टी. एन. चतुर्वेदी स्मारक प्रमाण पत्र

वर्ष 2019-20 में किसी भा.लो.प्र.सं. संकाय के द्वारा अधिकतम शोध अध्ययन पूरे करने के लिए भा.लो.प्र.सं. के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ साकेत बिहारी को श्री टी. एन. चतुर्वेदी स्मारक प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया। इसमें एक प्रमाण पत्र और पांच हजार रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है।

डॉ यू. सी. अग्रवाल स्मारक प्रमाण पत्र

वर्ष 2019-20 में किसी भा.लो.प्र.सं. कर्मी द्वारा सर्वाधिक लेख लिखने के लिए भा.लो.प्र.सं. की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ चारू मल्होत्रा को डॉ यू. सी. अग्रवाल स्मारक प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। इसमें एक प्रमाण पत्र और पांच हजार रुपए का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

भा.लो.प्र.सं. की शाखाओं को पुरस्कार

भा.लो.प्र.सं. के अध्यक्ष ने इच्छा व्यक्त की थी कि 24 आंचलिक और 43 स्थानीय शाखाओं के साथ बेहतर नेटवर्क स्थापित करने और उन्हें प्रेरित करने के लिए पुरस्कृत किया जाए। इस क्रम में सबसे पहला पुरस्कार वर्ष 2019 में सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन हेतु पुद्भुच्चेरी स्थानीय शाखा को प्रदान किया गया। इसमें शाखा को एक प्रमाण पत्र और दस हजार रुपए का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जम्मू और कश्मीर तथा बिहार की आंचलिक शाखाओं को सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन में क्रमशः द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने के लिए प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया है।

आंचलिक और स्थानीय शाखाएं तथा सदस्यों की गतिविधियां

31 मार्च, 2021 को संस्थान की आंचलिक एवं स्थानीय शाखाओं की संख्या क्रमशः 24 और 43 है। आंचलिक एवं स्थानीय शाखाओं तथा उनके पदाधिकारियों के नाम, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान उनके द्वारा की गई गतिविधियां और उनसे संबंधित सदस्यों की संख्या को अनुलग्नक च-3 में दर्शाया गया है।

शाखाओं की बहुत-सी गतिविधियों को भा.लो.प्र.सं. के मासिक पत्र में भी छापा गया है।

आंचलिक एवं स्थानीय शाखाओं के सभापतियों की एक बैठक 31 अक्टूबर 2020 को ऑनलाइन/ वर्चुअल तरीके से आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता संस्थान के महानिदेशक श्री सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने की। बैठक में शाखाओं के विकास तथा भालोप्रस की गतिविधियों को मजबूती प्रदान करने से संबंधित बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हई। इस बैठक में निम्नलिखित आंचलिक एवं स्थानीय शाखाओं का प्रतिनिधित्व रहा :

आंचलिक शाखाएं

दिल्ली, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, करेल, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, राजस्थान तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल।

स्थानीय शाखाएं

बर्दवान, धारवाड़, गुलबर्गा, करीम नगर पाटलिपुत्र, पुदुच्चेरी, पुणे और तिरुपति ।

बैठक में आंचलिक शाखाओं से संबद्ध संकाय सदस्यों ने भी शिरकत की। आंचलिक शाखाओं से संबद्ध संकाय सदस्यों की सूची अनुलग्नक च-7 में दी गई है।

वर्ष के दौरान शाखाओं को अपने कार्यक्रम एवं गतिविधियां चलाने के लिए 753013/- रुपए की धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में दी गई।

इसमें आजीवन सदस्यता पूंजी निधि में जमा रकम पर मिलने वाले ब्याज का 50 प्रतिशत हिस्सा भी शामिल है। संस्थान ने वित्त वर्ष के दौरान आंचलिक शाखा को 30000/-रुपए तथा स्थानीय शाखा को 15000/- रुपए की वित्तीय सहायता संगोष्ठी/सम्मेलन/पूर्व गोष्ठी आदि आयोजित करने के लिए प्रदान की बशर्ते वह शाखा -

अ) नियमित चुनाव करवाती हो
ब) नियमित रूप से लेखा परीक्षित खाते प्रस्तुत करती हो

स) अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट जमा करवाती हो

इसके अलावा ब्याज के 50 प्रतिशत हिस्से और वार्षिक सदस्यता शुल्क के 50 प्रतिशत हिस्से का भी शाखाओं को भुगतान किया जाता है। वर्ष 2020-21 के दौरान शाखाओं को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा अनुलग्नक च-6 में दिया गया है।

वार्षिक आम सभा की बैठक और सदस्यों का वार्षिक सम्मेलन भी सदस्योन्मुख गतिविधियां हैं। इनके लिए सभी शाखाओं के साथ ही साथ भा.लो.प्र.सं. के समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए विषय पत्र भेजा जाता है।

भा.लो.प्र.सं. की शाखाओं द्वारा आयोजित वेबिनार

दूरगामी पहुंच वाली गतिविधियां

निबंध प्रतियोगिता

वार्षिक निबंध पुरस्कार प्रतियोगिता 2020 के लिए निम्नलिखित विषय निर्धारित किए गए :

क्र. संख्या	शाखा	शीर्षक	संकाय समन्वयक	दिनांक
1.	असम	सामाजिक वानिक : आत्मनिर्भर होने का तरीका	डॉ. श्यामली सिंह	13, जनवरी, 2021
2.	बिहार	राष्ट्रीय विरासत शहर विकास एवं वृद्धि योजना	डॉ. नुपुर तिवारी	27, जनवरी, 2021
3.	दिल्ली	पुनरुज्जीवन एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन (एएमआरयूटी)	प्रो. सुरेश मिश्रा	10, फरवरी, 2021
4.	गुजरात	अटल पेंशन योजना	प्रो. अशोक विशनदास	24, फरवरी, 2021
5.	हरियाणा	बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ	डॉ. नीतू जैन	10, मार्च, 2021
6.	हिमाचल प्रदेश	प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत)	डॉ. साकेत बिहारी	24, मार्च, 2021

- कोविड-19 सार्वजनिक स्वास्थ्य-तंत्र
- पलायन एवं रोजगार सृजन
- एक राष्ट्र एक राशन कार्ड- पीडीएस सुधार

प्राप्त हुए कुल 16 निबंधों में से 11 अंग्रेजी में थे और 5 हिंदी में। इनका मूल्यांकन निर्णयिकों की एक समिति द्वारा किया गया। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे :

प्रो. सुरेश मिश्रा

प्रो. सी शीला रेड्डी

प्रो. अशोक विशनदास

डॉ. गदाधर मोहापात्र

डॉ. पवन कुमार तनेजा

डॉ. ममता पठानिया

10000/-रुपए का प्रथम पुरस्कार नई दिल्ली के डॉ विवेक दीक्षित को उनकी प्रविष्टि 'कोविड-19 और सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र' के लिए प्रदान किया गया। 7000/-रुपए का द्वितीय पुरस्कार कर्मवीर विद्यापीठ, आनंद नगर, खंडवा, मध्य प्रदेश के श्री संदीप भाट को उनके निबंध 'एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड- पीडीएस सुधार' के लिए दिया गया और 5000/-रुपए का तृतीय पुरस्कार दिल्ली के श्री हरीश कुमार को उनके निबंध 'पलायन और रोजगार सृजन' पर मिला।

केस अध्ययन कार्यक्रम

संस्थान उच्च गुणवत्ता की ऐसी केस स्टडी को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक केस स्टडी पुरस्कार प्रतियोगिता आयोजित करता है (जिसका उपयोग प्रारूप अधिगम को शिक्षण/ प्रशिक्षण के माध्यम से या स्वयं सीखने हेतु किया जा सके। वर्ष 2020-21 के लिए सभी चारों केस स्टडीज का विशेषज्ञों के पैनल द्वारा मूल्यांकन किया गया। सभी केस स्टडीज अंग्रेजी में थे। पुरस्कार वितरण 31 अक्टूबर, 2020 को आयोजित वार्षिक आम सभा की बैठक में वर्चुअल तरीके से हुआ। पैनल को 10000/- के प्रथम पुरस्कार हेतु कोई उपयुक्त केस स्टडी नहीं मिली। सिर्फ द्वितीय पुरस्कार सुश्री कंचन गुप्ता और सुश्री स्मिता निमसरकर को उनकी प्रविष्टि 'मैना टाउन प्लैलनग स्कीम्स - लैंड ओनर्स मीट इन कोविड-19 एंड पोस्ट कोविड टाइम्स'" के लिए संयुक्त रूप से दिया गया।

ढांचागत सुधार

भा.लो.प्र.स. ऐसा अग्रणी संस्थान है जिसके परिसर में उसका खुद का छात्रावास भवन है। इसमें अप्पा सहित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागियों, बाहरी सदस्यों, अतिथियों, सरकारी विभागों और शैक्षिक संस्थानों के वास्तविक शोधकर्ताओं एवं अधिकारियों को बोर्डिंग और लॉजिंग की सुविधा प्रदान की जाती है। छात्रावास के अंदर 89 कमरे और 8 अप्पा पारिवारिक सुरुई हैं।

छात्रावास के सभी कमरे वातानुकूलित हैं। इनमें संलग्न स्नानागार हैं। प्रसाधन एवं केबल टीवी हैं। छात्रावास को लकड़ी के पैनलिंग से पुनर्निर्मित किया गया है।

संस्थान की वित्त व्यवस्था

जैसा कि प्राप्ति एवं भुगतान खातों (अनुसूची-ए) में दर्शाया गया है (वर्ष 2020-21 के दौरान संस्थान की आय 33.03 करोड़ रुपए थी जबकि व्यय 33.01 करोड़ रुपए था। 33.03 करोड़ रुपए की कुल आय में से संस्थान को 28 करोड़ रुपए का अनुदान/वेतन/सामान्य/पूंजी सरकार से प्राप्त हुआ है।

इस प्रकार पिछले वर्ष से आगे लाए गए 7.33 लाख रुपए की संचयी कमी को समायोजित करने के बाद वर्ज के अंत में अनुसूची- ए के अनुसार संचयी कमी 5.54 लाख रुपए है।

वर्ष के दौरान आंतरिक संसाधनों से प्राप्त कुल आय 5.04 करोड़ रुपए थी जबकि यह पिछले वर्ष में 24.86 करोड़ रुपए थी। 5.04 करोड़ रुपए की प्राप्तियों में मुख्य रूप से निम्नलिखित मद शामिल थे :

प्रशिक्षण शुल्क (1.83 करोड़ रुपए), अनुसंधान कार्यों से शुद्ध आय (2.11करोड़ रुपए), उपयोगकर्ता प्रभार (47.00 लाख रुपए), प्रकाशनों की बिक्री (0.25 लाख रुपए) आदि। 33.01 करोड़ रुपए के कुल भुगतान में से संस्थान के वेतन और भत्ते 10.95 करोड़ और पेंशन 7.08 करोड़ रुपए थी। व्यय के अन्य मुख्य मद इस प्रकार थे - परिसर रखरखाव (2.41 करोड़ रुपए), प्रशासकीय एवं विविध खर्च (51.48 लाख रुपए), प्रशिक्षण कार्यक्रम (1.05 करोड़ रुपए)।

संस्थान को पूंजी प्रकृति की विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए सरकार से 10.50 लाख रुपए का अनुदान (पूंजी) भी प्राप्त हुआ। इसके विरुद्ध 10.50 लाख रुपए खर्च किए गए थे। व्यय के मुख्य मद इस प्रकार थे -

आईसीटी गतिविधियां (73.96 लाख रुपए), पुस्तकालय (18.46 लाख रुपए), आंचलिक/स्थानीय शाखाओं को मजबूत करना (5.05 लाख रुपए), संरचनात्मक विकास कार्य/नवीकरण कार्य (952.53 लाख रुपए)। संस्थान की विस्तृत वित्तीय स्थिति बैलेंस

शीट और आय एवं व्यय खाते में दी हुई है।

महत्वपूर्ण घटनाएं

‘संगोष्ठियां/सम्मेलन/कार्यशालाएं/व्याख्यान’

संस्थान ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित गोष्ठियों/सम्मेलनों/ व्याख्यानों/ वेबिनारों का आयोजन किया :

प्रशिक्षक कार्यशाला का पायलट प्रशिक्षण

टीओटी मॉड्यूल्स को अंतिम रूप देना :

जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल को अंतिम रूप देने हेतु 3 मार्च, 2020 को गंगटोक में प्रशिक्षक कार्यशाला के पायलट प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इसमें प्रमुख हित धारकों यानी वन, पर्यावरण और वन्यजीव प्रबंधन विभाग, खाद्य सुरक्षा और कृषि विकास विभाग, शिक्षा विभाग और इसी तरह के दूसरे प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। कार्यशाला का उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रमुख हित धारकों की क्षमताओं को बढ़ाना था। कार्यशाला का आयोजन श्री भुवन प्रधान, मुख्य वन संरक्षक (वन, पर्यावरण एवं वन्य जीवन प्रबंधन विभाग, सिक्किम सरकार के सभापतित्व में किया गया। प्रो विनोद के शर्मा और डॉ श्यामली सिंह कार्यक्रम के समन्वयक थे।

उपभोक्ता संरक्षण में समसामयिक चुनौतियों पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

भा.लो.प्र.स. के उपभोक्ता अध्ययन केंद्र ने यशवंतराव लॉ कॉलेज, पुणे के सहयोग से 2-3 मार्च 2020 से ‘उपभोक्ता संरक्षण में समकालीन चुनौतियां’ विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। इसे भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग ने प्रायोजित किया था। 80 से भी अधिक शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों, विद्यार्थियों, विशेषज्ञों, चिकित्सकों, कार्यपालकों और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने इसमें शिरकत की। संगोष्ठी में सभी हितधारकों को भाग लेने तथा क्षेत्र की नई चुनौतियों पर चर्चा करने और उपभोक्ताओं के लिए एक सुरक्षित व्यवस्था के लिए आगे बढ़ने का अवसर मिला। प्रो सुरेश मिश्रा और डॉ सपना चड्डा ने इसका संचालन किया।

डॉ बी. आर. अंबेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि

डॉ बी. आर. अंबेडकर की 129 वीं जयंती के अवसर पर भालोप्रस के महानिदेशक श्री एस एन त्रिपाठी, कुलसचिव श्री अमिताभ रंजन, डॉ सी. शीला रेड्डी, चेयर प्रोफेसर, डॉ बी. आर. अंबेडकर सामाजिक न्याय पीठ, डॉ चारु मल्होत्रा, एसोसिएट प्रोफेसर, ई-गवर्नेंस और आई सी टी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कोविड-19 की वजह से सामाजिक दूरी का पालन करते हुए उपस्थित संकाय एवं स्टाफ ने, भारतीय संविधान के निर्माता डॉ अंबेडकर के आदर्शों और विचारों को याद किया। श्री एस एन त्रिपाठी ने कहा कि डॉ अंबेडकर ने जाति मुक्त भारत की कल्पना की थी। उनका अटल विश्वास था कि जाति व्यवस्था केवल श्रम का विभाजन ही नहीं करती बल्कि श्रमिकों का विभाजन भी करती है। उन्होंने भालोप्रस में डॉ अंबेडकर सामाजिक न्याय पीठ प्रायोजित करने के लिए, डॉ अंबेडकर प्रतिष्ठान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का धन्यवाद व्यक्त किया। इस अवसर पर श्री अमिताभ रंजन द्वारा डॉ अंबेडकर के बहुमुखी व्यक्तित्व और उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया। डॉ सी. शीला रेड्डी ने भारतीय समाज में व्याप्त अंतर्विरोधों का पता लगाने के लिए डॉ अंबेडकर की अमूल्य अंतदृष्टि, आदर्शों और दर्शन पर फिर से विचार करने की आवश्यकता पर बल दिया। डॉ. चारु मल्होत्रा ने डॉ. अंबेडकर के मिशन एवं विरासत को संक्षेप में साझा किया।

अप्पा के 45वें दीक्षांत समारोह का ऑनलाइन आयोजन

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (भा.लो.प्र.सं.) के इतिहास में पहली बार भा.लो.प्र.स. के सर्वोत्कृष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम 45वें उन्नत व्यावसायिक लोक प्रशासन कार्यक्रम (अप्पा) का दीक्षांत समारोह 30 अप्रैल, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपन्न हुआ। 2 जुलाई, 2019 को शुरू हुए इस कार्यक्रम को कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (डीओपीटी) द्वारा प्रायोजित किया गया था। डॉ जितेंद्र सिंह, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

तथा राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग एवं अंतरिक्ष विभाग (इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। डॉ सी. चंद्रमौलि, सभापति, भा.लो.प्र.सं. एवं सचिव, डीओपीटी ने भी इस अवसर की शोभा बढ़ाई। श्री सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी, निदेशक (अब महानिदेशक) ने अतिथियों के साथ ही साथ प्रतिभागियों का भी स्वागत किया। प्रो गोविंद भट्टाचार्यजी निदेशक, 45वां अप्पा, ने पाठ्यक्रम का सिंहावलोकन प्रस्तुत किया और डॉ नीतू जैन, सह-कार्यक्रम निदेशक ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा।

कोविड-19 के बाद शासन सुधारों पर वेबिनार श्रृंखला में प्रथम

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान भा.लो.प्र.सं. ने 'कोविड-19 के बाद शासन सुधार' विषय पर 14 मई, 2020 को एक वेबिनार का आयोजन किया। श्री वी. श्रीनिवास, (भा.प्र.से.), अतिरिक्त सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय तथा निदेशक राष्ट्रीय सुशासन केंद्र- इस वेबिनार के मुख्य वक्ता थे। डॉ यामिनी अय्यर, सीईओ एवं अध्यक्ष, नीति अनुसंधान केंद्र, नई दिल्ली चर्चाकार थीं। सत्र की अध्यक्षता भा.लो.प्र.सं. के महानिदेशक, श्री एस. एन. त्रिपाठी भा.प्र.से. (अवकाश प्राप्त) ने की। सभी क्षेत्रों से लगभग 90 लोगों ने संगोष्ठी में शिरकत की। और उन्हें प्रश्नोत्तर सत्र में प्रश्न पूछने का अवसर भी प्रदान किया गया। भा.लो.प्र.सं. के कुलसचिव श्री अमिताभ रंजन ने धन्यवाद ज्ञापन किया। सत्र का संचालन प्रो गीतांजलि नटराज, प्रोफेसर अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र, भा.लो.प्र.सं. ने किया।

'भारत में कृषि मंडियों में सुधार पर वेबिनार'

18 मई, 2020 को 'भारत में कृषि मंडियों में सुधार' पर वेबिनार चर्चा का आयोजन किया गया। डॉ अशोक दलवाई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण तथा निर्वर्तमान सभापति कृषक आय-द्विगुणीकरण पर अंतर-मंत्रालय समिति; इस सेमिनार के अग्रणी चर्चाकार थे। श्रीमती नीलकमल दरबारी, एम डी, लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ

(एस एफ ए सी) दूसरी चर्चाकार थीं। श्री सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी, महानिदेशक, भा.लो.प्र.सं. ने चर्चा को आगे बढ़ाया, अवलोकन किए और दर्शकों/श्रोताओं के प्रश्नों को मॉडरेट किया। श्री अमिताभ रंजन, कुलसचिव, भा.लो.प्र.सं. द्वारा प्रस्तावित हार्दिक धन्यवाद प्रस्ताव के साथ चर्चा संपूर्ण हुई। प्रो अशोक विशन दास, प्रोफेसर, अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र, भा.लो.प्र.सं. ने सत्र का संचालन किया।

‘कोविड-19 महामारी के दौरान भावनात्मक लचीलापन बनाने में नेतृत्व की भूमिका पर वेबिनार’

‘कोविड महामारी के दौरान भावनात्मक लचीलापन बनाने में नेतृत्व की भूमिका’ पर 20 मई, 2020 को एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इसमें आमंत्रित अतिथि थे - श्री वी. के. सिंह, निदेशक, कार्मिक पावर ग्रिड और श्री डी. वी. शास्त्री, कार्यकारी निदेशक, ‘गैल’ (जी ए आई एल) प्रशिक्षण संस्थान, गैल (इंडिया) तिमिटेड। श्री एस एन त्रिपाठी महानिदेशक, भा.लो.प्र.सं. सत्र के मॉडरेटर थे। श्री अमिताभ रंजन, कुलसचिव, भा.लो.प्र.सं. ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। डॉ नीतू जैन, एसोसिएट प्रोफेसर, संगठन एवं व्यवहार विज्ञान क्षेत्र, भा.लो.प्र.सं. ने सत्र का संचालन किया।

‘कोविड-19: उपभोक्ता संरक्षण के लिए उभरती चुनौतियां पर वेबिनार’

26 मई, 2020 को ‘कोविड-19 : उपभोक्ता संरक्षण के लिए उभरती चुनौतियां’ - विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार को श्री एस. एन. त्रिपाठी, महानिदेशक, भा.लो.प्र.सं. ने मॉडरेट किया। इसमें अग्रणी वक्ता थे - श्री अविनाश के श्रीवास्तव, निवर्तमान सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार तथा मुख्य चर्चाकार थे - प्रो श्री रामकृष्ण, वाणिज्य प्रोफेसर (निवर्तमान), दिल्ली विश्वविद्यालय तथा जाने-माने उपभोक्ता कार्यकर्ता। इसमें प्रतिभागियों की अच्छी खासी उपस्थिति रही। इनमें नीति निर्माता, शिक्षाविद, शोधकर्ता, उपभोक्ता निवारण प्राधिकरण के सदस्य तथा गैर सरकारी संगठन शामिल हुए। वेबिनार

का संचालन प्रो सुरेश मिश्रा, पीठ प्रोफेसर, उपभोक्ता मामले, उपभोक्ता अध्ययन केंद्र, भा.लो.प्र.सं. ने किया।

‘कोरोना संकट में भारत में स्थानीय सरकारों की उभरती हुई भूमिका पर वेबिनार’

‘कोरोना संकट में भारत में स्थानीय सरकारों की उभरती हुई भूमिका’-विषय पर 27 मई, 2020 को एक वेबिनार आयोजित की गई। डॉ वी. एन. आलोक ने सभी का स्वागत किया और इस विषय पर अपने पृष्ठभूमि पत्र के आधार पर परिचयात्मक टिप्पणी प्रस्तुत की। डॉ एम रामचंद्रन, निवर्तमान सचिव, शहरी विकास केंद्रीय मंत्रालय तथा श्री एस एम विजयानंद, सभापति, छठा केरल राज्य वित्त आयोग ने अपना प्रस्तुतीकरण दिया। बहुत ही सजीव पर चर्चा हुई। कई राज्यों के प्रतिभागियों ने प्रश्न उठाए। श्री एस. एन. त्रिपाठी, महानिदेशक, भा.लो.प्र.सं. ने सत्र को मॉडरेट किया। डॉ आलोक, एसोसिएट प्रोफेसर, शहरी वित्त, भा.लो.प्र.सं. ने वेबिनार का संचालन किया।

‘कोविड-19 : लचीलापन कलंक और लैंगिक समानता पर वेबिनार’

29 मई, 2020 को एक वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार का शीर्षक था - ‘कोविड-19 : लचीलापन कलंक और लैंगिक समानता’। सुश्री वृद्धा कारत, राज्यसभा सदस्य एवं सीपीआई (एम) पोलित व्यूरो की पहली महिला सदस्य तथा डॉ रंजना कुमारी, जानी-मानी सामाजिक कार्यकर्ता एवं उर्वर शिक्षाविद -वेबिनार की अग्रणी वक्ता थीं। उन्होंने विभिन्न व्यवसायों में महिलाओं के व्यावसायिक स्वास्थ्य के लिए बढ़ती हई चुनौतियों पर बात की। उन्होंने कहा कि इस महामारी में इस बात को पहचान दिलाने की जरूरत है। उन्होंने इस पर भी बात की कि महिलाओं से परामर्श करना और निर्णय लेने में लिंग संतुलन बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण है। श्री एस. एन. त्रिपाठी, महानिदेशक, भा.लो.प्र.सं. इस कार्यक्रम के सभापति और मॉडरेटर थे। डॉ नूपुर तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर

एवं अध्यक्ष, जनजातीय मामले उत्कृष्टता केंद्र (सी ओ ई), (जनजातीय मामले मंत्रालय, भारत सरकार), भा.लो.प्र.सं. ने सत्र का संचालन किया।

‘समावेशी शासन’ विषय पर वेबिनार

भा.लो.प्र.सं. ने 18 जून, 2020 को एक वेबिनार का आयोजन किया। आयोजित वेबिनार का विषय था-“समावेशी शासन: पोस्ट कोविड चुनौतियां”। सुश्री ललिता, निदेशक, इंडिया फाउंडेशन तथा निवर्तमान चेयर पर्सन राष्ट्रीय महिला आयोग और प्रो अमिता सिंह, प्रोफेसर, कानून एवं शासन तथा संस्थापक चेयरपर्सन, विशेष आपदा अनुसंधान केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय- वेबिनार की प्रमुख वक्ता थी। श्री एस एन त्रिपाठी, महानिदेशक, भा.लो.प्र.सं. ने सत्र को मॉडरेट किया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने कोविड- उत्तर चुनौतियों पर प्रकाश डाला और कहा कि समग्र विकास प्राप्त करने के लिए समावेशी शासन ही मुख्य कारक है। प्रो सी शीला रेड्डी ने वेबिनार का संचालन किया।

‘महामारी के बाद की अवधि में शासन का डिजिटल परिवर्तन’ विषय पर सेमिनार

9 जून, 2020 को ‘महामारी के बाद की अवधि में शासन का डिजिटल परिवर्तन’- विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। श्री जे सत्यनारायण भा.प्र.से. (अवकाश प्राप्त) मुख्य सलाहकार, चतुर्थ औद्योगिक क्रांति का भारतीय केंद्र, विश्व आर्थिक फोरम,- वेबिनार के अग्रणी वक्ता थे। डॉ लवनीश चानना, उपाध्यक्ष, डिजिटल सरकार, एशिया प्रशांत और जापान, एस ए वी-मुख्य चर्चाकार थे। वेबिनार में 170 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल हुए। इन सभी ने वेबिनार-पूर्व सर्वेक्षण में प्रतिभागिता की। प्रतिभागियों के समूह में सरकारी, शिक्षा- विदों, आई टी/उद्योग के साथ ही साथ विद्यार्थियों का भी स्वस्थ प्रतिनिधित्व था। डॉ चारू मल्होत्रा कार्यक्रम की संचालक थीं।

‘साइबर सुरक्षा : सोशल डिस्टेंसिंग के दौरान सोशल इंजिनियरिंग’ विषय पर वेबिनार

24 जून, 2020 को ‘साइबर सुरक्षा : सोशल डिस्टेंसिंग के दौरान - सोशल इंजिनियरिंग’- विषय पर एक वेबिनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम के समन्वयक डॉ सुरेश पांडेय ने परिचयात्मक टिप्पणी प्रस्तुत की। श्री एस. एन. त्रिपाठी, महानिदेशक, भा.लो.प्र.सं. ने स्वागत भाषण दिया और परिचर्चा को मॉडरेट किया। वेबिनार के प्रख्यात पैनलिस्ट थे - लेफ्टिनेंट जनरल (डॉ) राजेश पंत, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत सरकार तथा श्री एस के भल्ला, निदेशक (साइबर एवं सूचना सुरक्षा), गृह मंत्रालय, भारत सरकार। वक्ताओं ने हमारे देश के सामने आने वाली अड़चनों/चुनौतियों पर बात की।

‘शासन और बुनियादी ढांचे के लिए नव सामान्य’ विषय पर वेबिनार

5 जून, 2020 को ‘शासन एवं बुनियादी ढांचे के लिए नव सामान्य’ विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार में दो प्रख्यात पैनलिस्टों द्वारा विशेषज्ञ प्रस्तुतीकरण दिया गया। इनके नाम हैं-- श्री हितेष वैद्य, निदेशक, राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान और श्री शैलेश पाठक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं स्वतंत्र निदेशक, एल एंड टी इन्फ्राट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। श्री एस. एन. त्रिपाठी, महानिदेशक, भा.लो.प्र.सं. ने वेबिनार को मॉडरेट किया। सत्र के दौरान इस बात पर बल दिया गया कि मुख्य शहरों के माध्यम से कोविड-19 का विस्तार हो रहा है। परिवहन, आवास, आपूर्ति- शृंखला, कम आय वाले निपटान और शासन प्रथाएं एक संक्रमण के दौर से गुजर रही हैं, जो एक नव सामान्य बना रही है। इस संदर्भ में शहर-सरकार पहलों के केंद्र में है। अंतर-सरकारी संदर्भ में सक्रियकरण और सुविधा के साथ शहर की सरकारों की भूमिका को मजबूत करने की आवश्यकता है। इस संबंध में दोनों वक्ताओं द्वारा वर्तमान परिदृश्य में नवाचारों पर भी प्रकाश डाला गया। अंततः यह महसूस किया गया कि महामारी के खिलाफ लड़ाई को सफल बनाने की कुंजी शहरी क्षेत्र के पास है। प्रो के के पांडेय कार्यक्रम के समन्वयक थे।

‘आदिवासी समुदायों के लिए डिजिटल कौशल और मेंटरशिप’ विषय पर वेबिनार

जनजातीय मामले एवं फेसबुक मंत्रालय के साथ साझेदारी में 26 जून, 2020 को ‘आदिवासी समुदायों के लिए डिजिटल कौशल और मेंटरशिप’ विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार के दौरान ‘गोल’ ‘जी ओ ए एल) कार्यक्रम के बारे में चर्चा हुई। यह कार्यक्रम जनजातीय मामले एवं फेसबुक मंत्रालय, भारत सरकार की एक पहल है। इसके साथ ही जनजातीय-प्रतिभा-पूल-योजना पर भी चर्चा हुई। इन पहलों की सफलता के लिए नया सीखने एवं अपने सुझाव देने के लिए भारत के विभिन्न भागों से आए हुए तकरीबन 900 जनजातीय विद्वानों ने इस वेबिनार में भाग लिया। डॉ नूपुर तिवारी ने सत्रों का समन्वय किया।

‘कोविड-19 के बाद में लोक सेवा वितरण’ विषय पर वेबिनार

10 जून, 2020 को ‘कोविड-19 के बाद में लोक सेवा वितरण’- विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार में दो प्रमुख वक्ता थे --प्रो थनकोम अरूण, प्रोफेसर, वैश्विक विकास एवं उत्तरदायित्व, एसेक्स विश्वविद्यालय और डॉ विक्रम चंद, निवर्तमान अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र विशेषज्ञ, विश्व बैंक। श्री एस. एन. त्रिपाठी, महानिदेशक, भा.लो.प्र.सं., कार्यक्रम के समन्वयक थे।

नव सामान्य में नौकरियों का पुनर्निर्माण और पुनः सृजन

29 जुलाई, 2020 को ‘नव सामान्य में नौकरियों का पुनर्निर्माण और पुनः सृजन- सृजन’- विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया। श्री विनोद जुत्ती भा.प्र.से. (अवकाश प्राप्त), निवर्तमान सचिव, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार और श्री के.के. जालान, भा.प्र.से. (अवकाश प्राप्त), निवर्तमान सचिव, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार (इस वेबिनार के प्रमुख वक्तागण थे। श्री एस.एन. त्रिपाठी, महानिदेशक, भा.लो.प्र.स. ने स्वागत भाषण दिया और डॉ साकेत बिहारी ने कार्यक्रम का समन्वयन किया।

डेटा विश्लेषण एवं कृत्रिम इंटेलिजेंस पर कार्यशाला

नेशनल अकैडमी ऑफ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स, नई दिल्ली के लिए 27 जुलाई, 2020 को ‘डेटा विश्लेषण और कृत्रिम इंटेलिजेंस’ - विषय पर एक कार्यशाला ऑनलाइन शुरू की गई।

समकालीन भारत में प्रवास और रोजगार सृजन पर वेबिनार

22 जुलाई, 2020 को एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इसका विषय था- ‘समकालीन भारत में प्रवास और रोजगार सृजन: संभावनाएं और चुनौतियाँ।’ प्रो बिनोद खादरिया, निवर्तमान प्रोफेसर, अर्थशास्त्र, शिक्षा एवं प्रवास, जेएनयू, नई दिल्ली तथा प्रो संतोष मेहरोत्रा, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर एवं सभापति श्रम अध्ययन केंद्र जे.एन.यू; वेबिनार के प्रमुख वक्ता गण थे। श्री एस.एन. त्रिपाठी, महानिदेशक, भा.लो.प्र.सं. ने स्वागत भाषण दिया। डॉ गदाधर महापात्रा ने कार्यक्रम का समन्वयन किया।

तनाव प्रबंधन एवं बढ़ी हुई उत्पादकता पर सेमिनार

14 अगस्त, 2020 को ‘तनाव प्रबंधन एवं बढ़ी हुई उत्पादकता’- विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। डॉ नूपुर कोहली, सलाहकार, हेल्थ केयर नीदरलैंड्स; इस अवसर पर प्रमुख वक्ता थीं। श्री एस. एन. त्रिपाठी, महानिदेशक, भा.लो.प्र.सं. ने स्वागत भाषण दिया और डॉ नूपुर तिवारी ने इस कार्यक्रम का समन्वयन किया। श्री अमिताभ रंजन, कुलसचिव, भा.लो.प्र.सं. ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

किसानों के कल्याण एवं कृषि के लिए नई पहलों पर वेबिनार

10 अगस्त, 2020 को ‘किसानों के कल्याण एवं कृषि के लिए नई पहलों’- विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। श्री संजय अग्रवाल, भा.प्र.से., सचिव, कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग और डॉ त्रिलोचन महापात्र, सचिव, कृषि, अनुसंधान एवं शिक्षा तथा महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद; इस अवसर पर प्रब्ल्यात वक्तागण थे।

श्री एस. एन. त्रिपाठी, महानिदेशक, भा.लो.प्र.सं. ने सत्र को मॉडरेट किया। प्रो अशोक विशन दास ने इस कार्यक्रम का समन्वय किया। श्री अमिताभ रंजन, कुलसचिव, भा.लो.प्र.सं. ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकीय तंत्र पर वेबिनार

6 अगस्त, 2020 को ‘भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकीय तंत्र’ -विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया। श्री पवन श्रीवास्तव, सीएसआई एवं सचिव, एम ओ एस पी आई, भारत सरकार तथा श्री राज गौतम मित्रा, निवर्तमान आई एस एस अधिकारी; इस अवसर पर प्रख्यात वक्तागण थे। श्री एस. एन. त्रिपाठी, महानिदेशक भा.लो.प्र.सं. ने सत्र को मॉडरेट किया और प्रो अशोक विशन दास ने इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया। श्री अमिताभ रंजन, कुलसचिव, भा.लो.प्र.सं. ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा।

ई-कॉमर्स : नव सामान्य में लोच रणनीतियां पर वेबिनार

4 अगस्त, 2020 को ‘ई-कॉमर्स : नव सामान्य में लोच रणनीतियां’ - विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। श्री राहुल सुंदरम्, वरिष्ठ कारपोरेट वकील, एमेज़ॉन इंडिया तथा श्री गौरव लूंबा, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट, (गवर्नमेंट रिलेशंस एंड एडवोकेसी), एनपीसीआई; प्रमुख वक्तागण थे। श्री एस. एन. त्रिपाठी, महानिदेशक, भा.लो.प्र.सं. ने सत्र को मॉडरेट किया। डॉ सपना चड्डा ने कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया और श्री अमिताभ रंजन, कुलसचिव भा.लो.प्र.सं. ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

जलवायु भिन्नता एवं परिवर्तन : भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए चुनौतियां पर वेबिनार

20 अगस्त, 2020 को “जलवायु भिन्नता एवं परिवर्तन: भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) के लिए चुनौतियां”- विषय पर एक

वेबिनार का आयोजन किया गया। डॉ के. जे. रमेश, निवर्तमान महानिदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग तथा श्री कमल किशोर, सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण; वेबिनार में प्रख्यात वक्तागण थे। श्री एस. एन. त्रिपाठी, महानिदेशक, भा.लो.प्र.सं. ने सत्र को मॉडरेट किया। डॉ श्यामली सिंह ने कार्यक्रम का समन्वयन किया।

माननीय केंद्रीय मंत्री जनजातीय मामले भालोप्रस द्वारा आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन में सम्मिलित हुए

श्री अर्जुन मुंडा, माननीय मंत्री, जनजातीय मामले, भारत सरकार; भा.लो.प्र.सं. के उत्कृष्टता केंद्र द्वारा 3-4 सितंबर, 2020 को आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन में सम्मिलित हुए। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए माननीय केंद्रीय मंत्री, जनजातीय मामले ने कहा कि मंत्रालय भा.लो.प्र.सं. के सहयोग से व्यावहारिक मॉडल के ऐसे डिजाइन पर विचार कर रहा है जो समस्या की पहचान, समाधान खोजने और परियोजना निष्पादन जैसे क्रियात्मक अनुसंधान के हिस्से के रूप में एंड टु एंड समाधान प्रस्तुत करता है, जिनका नीतिगत पहलों द्वारा कार्यान्वयन किया जा सकता है। श्री दीपक खांडेकर, सचिव, एम ओटीए ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि पूर्व में जनजातीय अनुसंधान का कार्य जनजातीय मामलों के मंत्रालय में एक प्रयोजित कार्य की तरह किया जा रहा था परंतु अब इसे मिशन मोड में चलाया जा रहा है। श्री एस. एन. त्रिपाठी, महानिदेशक, भा.लो.प्र.सं. ने सत्र की अध्यक्षता की और डॉ नूपुर तिवारी ने कार्यक्रम का समन्वयन किया।

मिशन कर्म योगी पर वेबिनार

11 सितंबर, 2020 को “मिशन कर्मयोगी : परिकल्पना एवं संभावनाएं”- विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार के प्रख्यात वक्तागण थे- डॉ सी. चंद्रमौलि, सचिव, डीओपीटी एवं सभापति भा.लो.प्र.सं. तथा श्रीमती रश्मि चौधरी, अतिरिक्त सचिव, प्रशिक्षण, डीओपीटी। श्री एस. एन. त्रिपाठी, महानिदेशक भा.लो.प्र.सं. ने बैठक की अध्यक्षता

की। इस कार्यक्रम का आयोजन मिशन कर्मयोगी की कार्यान्वयन रणनीति का विश्लेषण करने एवं समझने के लिए किया गया था। श्री अमिताभ रंजन, कुलसचिव भा.लो.प्र.सं. ने भी सत्र में शिरकत की और धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। डॉ चारु मल्होत्रा ने कार्यक्रम का समन्वय किया।

रणनीतिक एवं लोक हितकारी सीएसआर पर वेबिनार

2 सितंबर 2020 को “रणनीतिक एवं लोक हितकारी सीएसआर : सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए महामारी के बाद की चुनौतियां एवं अवसर”- विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। श्री संजय कुमार जैन, संयुक्त सचिव, लोक उद्यम विभाग, (डीपीई) एवं श्री विश्वजीत राय, निदेशक, मानव संसाधन और व्यवसाय विकास, अॅयल इंडिया लिमिटेड; इस वेबिनार के प्रमुख वक्ता थे। डॉ रोमा देबनाथ ने कार्यक्रम का समन्वयन किया।

आपदा जोखिम में कमी के अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय परिपेक्ष्य पर वेबिनार

“आपदा जोखिम में कमी के अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय परिपेक्ष्य”- विषय पर 28 सितंबर, 2020 को एक वेबिनार का आयोजन किया गया। डॉ राजीव शौ, प्रोफेसर, ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मीडिया एंड गवर्नेंस, कियो विश्वविद्यालय, जापान; श्री कृष्ण एस. वत्स, सदस्य, एनडीएमए और श्री अनिल कुमार सिन्हा, भा.प्र. से. (अवकाश प्राप्त), व वरिष्ठ सलाहकार एवं मेंटर; वेबिनार के मुख्य वक्तागण थे। वेबिनार का समन्वयन प्रो वी के शर्मा और डॉ श्यामली सिंह द्वारा किया गया।

शिक्षण एवं निर्णय लेने के लिए केस स्टडी विधि पर वेबिनार

इस वेबिनार का आयोजन 26 अक्टूबर, 2020 को किया गया। वेबिनार ने भा.लो.प्र.सं. के केस स्टडी कार्यक्रम में सुधार पर विचार विमर्श करने एवं चर्चा करने का अवसर प्रदान किया। उन सभी लेखकों को इस

वेबिनार में आमंत्रित किया गया था जिन्होंने अपने केस स्टडीज को भा.लो.प्र.सं. की वार्षिक निर्णय लेने/ केस स्टडी प्रतियोगिता में पिछले 5 वर्षों (2016-2020) के दौरान जमा करवाया था। प्रो सी. शीला रेड्डी, पीठ प्रोफेसर, डॉ अंबेडकर सामाजिक न्याय पीठ तथा सदस्य सचिव, केस स्टडीज समिति ने अपने उद्घाटन भाषण में शिक्षण, प्रशिक्षण एवं निर्णय लेने में केस स्टडी विधि के महत्व पर प्रकाश डाला। श्री एस. एन. त्रिपाठी महानिदेशक, भा.लो.प्र.सं. ने इस बात पर जोर दिया कि यह विधि निर्णय लेने और महत्वपूर्ण सोच कौशल के एकीकरण के लिए एक व्यापक परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा देती है जिससे प्रशासक अपने स्वयं के कार्यों और निष्क्रियताओं की समीक्षा कर सकते हैं। वेबिनार के मुख्य रिसोर्स पर्सन प्रो नंद धर्मीजा, संकायाध्यक्ष एवं प्रोफेसर, प्रबंध अध्ययन संकाय, (एफ एम एस) मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान एवं अध्ययन संस्थान फरीदाबाद; ने “केस विधि और केस विश्लेषण” पर एक व्यापक और अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण प्रस्तुति दी। प्रो अशोक विशनदास, प्रोफेसर अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र ने “मिशन कर्मयोगी” पर एक परिपेक्ष्य प्रस्तुत किया। “मिशन कर्मयोगी” भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम “नियम आधारित” मानव संसाधन प्रबंधन के “भूमिका आधारित” में परिवर्तन का समर्थन करता है जिससे कि लोक सेवा के सभी पदों को भूमिकाओं के सांचे में ढाला जा सके। डॉ वी एन आलोक, एसोसिएट प्रोफेसर, सार्वजनिक वित्त; ने चर्चा का समापन करते हुए करते हुए भा.लो.प्र.सं. के केस स्टडी प्रोग्राम को मजबूत करने पर जोर दिया। प्रो सी. शीला रेड्डी ने कार्यक्रम का समन्वयन किया और धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

सीपीएसई का सिंहावलोकन

“केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का सिंहावलोकन: विनिवेश और प्रदर्शन का मूल्यांकन” विषय पर 26 अक्टूबर, 2020 को एक वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार के प्रख्यात वक्ता थे : श्री प्रवीण कांत पांडेय, सचिव, निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। श्री एस. एन. त्रिपाठी,

महानिदेशक, भा.लो.प्र.सं. ने परिचय भाषण दिया। डॉ सुरभि पांडेय ने वेबिनार का कार्यान्वयन किया।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम - 2019 पर वेबिनार

“20 अक्टूबर, 2020 को छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय, पनवेल, नवी मुंबई और उपभोक्ता अध्ययन केंद्र भा.लो.प्र.सं. के संयुक्त सहयोग से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 : एक खेल परिवर्तक” विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इसका आयोजन सेंट विलफ्रेड्स कॉलेज ऑफ लॉ, पनवेल के सहयोग से किया गया। डॉ मृत्युंजय पांडेय, प्राचार्य, सेंट विलफ्रेड्स कॉलेज ऑफ लॉ ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। प्रो सुरेश मिश्रा, पीठ प्रोफेसर, सी सी एस, भा.लो.प्र.सं. ने परिचयात्मक टिप्पणी प्रस्तुत की। प्रो ए. के. सिन्हा, कुलपति, सीएसएमयू, ने विशेष संबोधन किया अध्यक्ष ने अध्यक्षीय भाषण दिया। प्रो सुरेश मिश्रा और डॉ सपना चड्डा ने कार्यक्रम का समन्वयन किया।

लोक सेवा वितरण प्रणाली में आरटीआई अधिनियम की भूमिका

‘लोक सेवा वितरण प्रणाली में सूचना अधिकार अधिनियम की भूमिका’ विषय पर 1 अक्टूबर, 2020 को एक वेबिनार का आयोजन किया गया। श्री विमल जुल्का, भा.प्र.से., (अवकाश प्राप्त), निवर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त, नई दिल्ली और सुश्री अंजलि भारद्वाज, सह-संयोजिका, नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इनफार्मेशन (एनसीपीआरआई) व संस्थापक सदस्य, एस एन एस - सर्टक नागरिक संगठन (सोसायटी फॉर सिटीजंस विजिलेंस इनीशिएटिव) वेबिनार में प्रभ्यात वक्ता थे। भा.लो.प्र.सं. के महानिदेशक श्री एस. एन. त्रिपाठी ने सत्र की अध्यक्षता की। प्रो अशोक विश्वन दास और डॉ सपना चड्डा ने कार्यक्रम का समन्वयन किया।

शासन में डिजिटल परिवर्तन पर वेबिनार

राज्य ए टी आईज के माध्यम से जिला अधिकारियों

के लिए ‘जागरूकता और कौशल विकास कार्यक्रम’ परियोजना के तहत ‘शासन में डिजिटल परिवर्तन’ पर 12 से 15 अक्टूबर, 2020 तक एक तीन दिवसीय आभासी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसका प्रायोजन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया था। श्री एस. एन. त्रिपाठी, महानिदेशक, भा.लो.प्र.सं. ने सत्र की अध्यक्षता की। इस वेबिनार में प्रभ्यात वक्ता थे; डॉ राजेंद्र कुमार, भा.प्र.से. ,अतिरिक्त सचिव, एमईआईटीवाई (श्री अभिषेक सिंह, सीईओ व अध्यक्ष एनईजीडी) (डॉ जयदीप कुमार मिश्र, संयुक्त सचिव, एमईआईटीवाई (डॉ लवनीश चानना, उपाध्यक्ष ‘सरकारी मामले- एशिया प्रशांत और जापान’ एसएपी (डॉ अविक सरकार, संकाय, भारतीय व्यवसाय विद्यालय (श्री शोभेंद्र बहादुर निदेशक, ई-गाँव व माइगाँव (श्री गोलोक स्मिली, प्रधान परामर्शदाता एवं प्रौद्योगिकी प्रमुख, एम ई ए; श्री दीपक महेश्वरी, लोकनीति प्रोफेशनल और श्री दीपेंद्र सिंह, फ्रीलांसर, ई-शासन विशेषज्ञ। डॉ चारू मल्होत्रा ने वेबिनार का समन्वयन किया।

भा.लो.प्र.सं. में आयोजित आभासी जनजातीय प्रतिभा पूल सम्मेलन

जनजातीय मामले मंत्रालय के अंतर्गत जनजातीय मामलों के उत्कृष्टता केंद्र ने 13 अक्टूबर, 2020 को आभासी जनजातीय प्रतिभा पूल सम्मेलन आयोजित किया। इसमें प्रभ्यात वक्तागण थे -प्रो. विनय कुमार श्रीवास्तव, निदेशक, एनएसआई एवं प्रो. रजनीश जैन, सचिव, यूजीसी एवं सीवीओ। डॉ नूपुर तिवारी ने कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया।

भारत में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना : कोविड बाद का परिदृश्य

भारत में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने पर एक वेबिनार

“भारत में स्वास्थ्य प्रणाली का मजबूती करण-पोस्ट-कोविड परिदृश्य” विषय पर 13 अक्टूबर, 2020 को एक वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार के प्रभ्यात वक्तागण थे- डॉ इंदु भूषण, सीईओ, आयुष्मान भारत (एडी - पीएमजेएवाई) और राष्ट्रीय

स्वास्थ्य प्राधिकरण; श्री मनोज झालानी, आईएएस, निदेशक (स्वास्थ्य प्रणाली विकास), विश्व स्वास्थ्य संगठन और प्रो सुरेखा किशोर, कार्यकारी निदेशक, एम्स गोरखपुर। वेबिनार का संचालन डॉ पवन तनेजा ने किया।

भा.लो.प्र.सं. में संविधान दिवस समारोह

डॉ. अम्बेडकर सामाजिक न्याय पीठ, भा.लो.प्र.सं. ने भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में 71वां संविधान दिवस मनाया। कार्यक्रम की शुरूआत डॉ. अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुई। प्रो. सी. शीला रेड्डी, पीठ आचार्या, डॉ. अम्बेडकर सामाजिक न्याय पीठ ने प्रस्तावना में परिलक्षित भारतीय संविधान के दर्शन को साझा करके राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाने के महत्व को समझाया। इस अवसर पर भा.लो.प्र.सं. बिरादरी ने श्री एस.एन. त्रिपाठी, महानिदेशक, भा.लो.प्र.सं. के नेतृत्व में संकल्प पारित किया और संविधान की प्रस्तावना पढ़कर स्वयं को संविधान के आदर्शों के प्रति पुनः समर्पित करने की शपथ ली। इसके बाद, भा.लो.प्र.सं. के संकाय और कर्मचारियों ने डॉ अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की।

संविधान निर्माण पर डॉ अम्बेडकर के विचार पर वेबिनार

भा.लो.प्र.सं. ने 'संविधान निर्माण पर डॉ अम्बेडकर के विचार' विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार के मुख्य वक्ता थे- डॉ. राजा शेखर वुंदू, भा.प्र.स., प्रधान सचिव, भारत सरकार। डॉ. वुंदू ने अम्बेडकर, जाति, अस्पृश्यता, दलित इतिहास और साहित्य पर विस्तार से लिखा है। वह 'अंबेडकर, गांधी और पटेल' पुस्तक के लेखक भी हैं। प्रो. सी. शीला रेड्डी, पीठ आचार्या, डॉ. अम्बेडकर सामाजिक न्याय पीठ, ने वक्ता और प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने उल्लेख किया कि बाबासाहेब अम्बेडकर ने संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष की हैसियत से भारत के लोगों के लिए एक व्यापक और व्यावहारिक संविधान तैयार किया। श्री एस.एन. त्रिपाठी, महानिदेशक, भा.लो.प्र.सं. ने अपने उद्घाटन भाषण में

इस बात पर जोर दिया कि भारतीय संविधान के निर्माण में डॉ. अम्बेडकर का योगदान अभूतपूर्व था। डॉ. वुंदू ने अपने संबोधन में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार तथा सीमित मताधिकार से मौलिक अधिकार बनने तक की मतदान यात्रा का विस्तृत वर्णन किया। उन्होंने रियासतों के एकीकरण पर अपने शोध और डॉ. अम्बेडकर पर कुछ रोचक और महत्वपूर्ण तथ्य भी साझा किए। 46वें "लोक प्रशासन में उन्नत व्यावसायिक कार्यक्रम" (अप्पा) के प्रतिभागी और अन्य आमंत्रित लोग वेबिनार का हिस्सा थे। प्रो. सी. शीला रेड्डी ने वेबिनार का समन्वयन किया और धन्यवाद प्रस्ताव रखा।

माननीय मंत्री जनरल वी. के. सिंह का भा.लो.प्र.सं. में राष्ट्रीय सुरक्षा संवाद पर वक्तव्य

माननीय मंत्री जनरल वी के सिंह, परम वशिष्ठ सेवा मेडल (पीवीएसएम), अति वशिष्ठ सेवा मेडल (एवीएसएम), युवा सेवा मंडल (वाईएसएम), एडीसी, केंद्रीय राज्यमंत्री; राज्य मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा पूर्व थल सेना प्रमुख ने 25 नवंबर, 2020 को 'राष्ट्रीय सुरक्षा संवाद' पर एक भाषण दिया। अपने व्याख्यान के दौरान, माननीय मंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक समान दृष्टिकोण और राष्ट्र की समग्र संरक्षा और सुरक्षा में प्रत्येक व्यक्ति को कैसे कुछ भूमिका निभानी है; इस बात पर जोर दिया। उन्होंने रक्षा खरीद, साइबर स्पेस सुरक्षा और प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता पर प्रकाश डालने के अलावा समग्र सुरक्षा पहलुओं से निपटने के दौरान प्रौद्योगिकी के उपयोग, नवाचार और कुशल दृष्टिकोण के बारे में बात की। इसके अलावा, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया। डॉ. सुरभि पांडे, स्ट्रीम प्रभारी, साइबर और राष्ट्रीय सुरक्षा, भा.लो.प्र.सं. ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया और माननीय मंत्री जनरल वी. के. सिंह को भा.लो.प्र.सं. के निदेशक श्री एस. एन. त्रिपाठी का परिचय दिया। श्री एस. एन. त्रिपाठी ने परिचयात्मक टिप्पणी प्रस्तुत की और सत्र का संचालन किया। श्री अमिताभ रंजन, कुलसचिव, भा.लो.प्र.सं. ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। भा.लो.प्र.सं. के संकाय और वरिष्ठ कर्मचारियों ने सत्र में

भाग लिया। लोक प्रशासन में 46वें उन्नत व्यावसायिक कार्यक्रम के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ-साथ भा.लो.प्र.सं. की क्षेत्रीय और स्थानीय शाखाओं के सदस्यों ने अँनलाइन मोड के माध्यम से सत्र में भाग लिया। पूर्व थल सेनाध्यक्ष ने भा.लो.प्र.सं. में महात्मा गांधी और सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उसके बाद भा.लो.प्र.सं. के प्रशिक्षु अधिकारियों और संकाय सदस्यों की एक सामूहिक तस्वीर का आयोजन किया गया।

स्व. डॉ यू.सी. अग्रवाल स्मृति व्याख्यान

भा.लो.प्र.सं. ने 19 नवंबर, 2020 को “नैतिकता और शासन” विषय पर प्रथम स्व. डॉ यू.सी. अग्रवाल स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया।

श्री एस.एन. त्रिपाठी, महानिदेशक, भा.लो.प्र.सं. ने उद्घाटन भाषण प्रस्तुत किया। डॉ. सी. चंद्रमौलि भा.प्र.से (सेवानिवृत्त), भारत सरकार के पूर्व सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने व्याख्यान दिया। श्री ओम प्रकाश अग्रवाल, भा.प्र.से (सेवानिवृत्त), भारत सरकार में पूर्व संयुक्त सचिव और डॉ. यू.सी. अग्रवाल के सुपुत्र ने भी इस अवसर पर बात की। भा.लो.प्र.सं. संकाय, डॉ. चारू मल्होत्रा को भा.लो.प्र.सं. के एक संकाय द्वारा प्रकाशित और लिखित सबसे अधिक लेखों के लिए डॉ. यू.सी. अग्रवाल स्मारक पुरस्कार प्रदान किया गया। इसी तरह इस कार्यक्रम के दौरान डॉ. यू.सी. अग्रवाल अग्रवाल स्मारक पुस्तक का विमोचन किया गया। इसमें भालोप्रसं के सभी संकाय सदस्यों द्वारा प्रकाशित लेखों का संकलन है। श्री अमिताभ रंजन, कुलसचिव, भा.लो.प्र.सं. ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। कार्यक्रम का समन्वयन प्रो. सुरेश मिश्रा ने किया।

भारत के परमाणु सिद्धांत पर वेबिनार

10 नवंबर, 2020 को “भारत के परमाणु सिद्धांत” पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। श्री एस.एन. त्रिपाठी, महानिदेशक, भा.लो.प्र.सं. ने उद्घाटन भाषण प्रस्तुत किया। डॉ. राजीव नयन, वरिष्ठ अध्ययेता, रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान और प्रो. संजय भारद्वाज, दक्षिण एशियाई अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विद्यालय,

जेएनयू.-वेबिनार के मुख्य वक्ता थे। कार्यक्रम का समन्वयन डॉ. मनन द्विवेदी ने किया।

अच्छे केस स्टडीज़ विकसित करने के तौर-तरीकों की अंतदृष्टि पर वेबिनार

जनजातीय मामले मंत्रालय, भारत सरकार के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित “उद्यमिता और कौशल विकास के माध्यम से जनजातीय महिलाओं का सशक्तिकरण: संभावनाएं और चुनौतियाँ” विषय पर एक 5-6 नवंबर, 2020 को एक वेबिनार आयोजित किया गया था। श्री एस.एन. त्रिपाठी, महानिदेशक, भा.लो.प्र.सं. ने उद्घाटन भाषण दिया। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री नवल जीत कपूर और एनएसटीएफडीसी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक असित गोपाल वेबिनार के मुख्य वक्ता थे। इस अवसर पर एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन श्रीमती रेखा शर्मा मुख्य अतिथि थीं। श्री अमिताभ रंजन, कुलसचिव, भा.लो.प्र.सं. ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। कार्यक्रम का संचालन डॉ. गदाधार महापात्र ने किया।

आत्मनिर्भर प्रौद्योगिकियों पर वेबिनार

3 नवंबर, 2020 को एपीपीपीए के तहत “आत्मनिर्भर प्रौद्योगिकियों पर टाउनहॉल चर्चा” विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। श्री एस.एन. त्रिपाठी, महानिदेशक, भालोप्रसं ने उद्घाटन भाषण दिया। डॉ. आर.एस. शर्मा, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त); ट्राई के पूर्व अध्यक्ष, लेफ्टिनेंट जनरल, राजेश पतं; राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक, पीएमओ; डॉ. संजय बहल, महानिदेशक, सीईआरटी-इन और डॉ. भट्टाचार्य, संस्थापक एवं सीईओ, जीरेन माइक्रोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड- वेबिनार के प्रमुख वक्ता थे। कार्यक्रम का समन्वयन 46वें अप्पा की कार्यक्रम निदेशक डॉ. चारू मल्होत्रा और 46वें अप्पा के सह-कार्यक्रम निदेशक डॉ. पवन तनेजा ने किया।

अच्छे केस स्टडीज़ विकसित करने के तौर-तरीकों की अंतदृष्टि पर वेबिनार

18 नवंबर, 2020 को “अच्छे केस स्टडीज विकसित करने के तौर-तरीकों की अंतर्दृष्टि” पर एक वेबिनार आयोजित किया गया था। श्री एस.एन. त्रिपाठी, महानिदेशक, भा.लो.प्र.सं. ने उद्घाटन टिप्पणी प्रस्तुत की। प्रो. राज कुमार, कुलपति, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़, इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। प्रो. स्विंदर सिंह, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ और प्रो. सी. शीला रेड्डी, भा.लो.प्र.सं. संकाय- मुख्य चर्चाकार थे। प्रो. अशोक विशनदास ने कार्यक्रम का समन्वयन किया।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की नई विशेषताओं पर वेबिनार

भा.लो.प्र.सं. के उपभोक्ता अध्ययन केंद्र ने; उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस-2020 के अवसर पर 24 दिसंबर, 2020 को “उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की नई विशेषताएं” विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय केंद्रीय मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, श्री पीयूष गोयल ने किया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से अपील की कि वे हमारे प्रधान मंत्री की अपील के अनुसार स्वदेशी उत्पादों और सेवाओं को प्राथमिकता देने के लिए स्थानीय के लिए मुखर हों। मंत्री ने गुणवत्ता, मानकों और आत्मनिर्भर भारत के प्रति अधिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता पर बल दिया। मंत्रीजी ने कहा कि अगले वर्ष, भारत को मानक और उत्पादकता में गुणवत्ता के वर्ष का जश्न मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह उपभोक्ताओं और व्यवसाय के हित में होगा क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धियों के खिलाफ अच्छी स्थिति में खड़ा होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि भारत के उत्पादों और सेवाओं को अंतरराष्ट्रीय और घरेलू बाजार में स्वीकार्यता प्राप्त हो। मंत्री ने भाषण का समापन ‘जागो और जागते रहो’ कहकर किया, जिसका अर्थ है कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए और उन्हें जागरूक रहना चाहिए।

तथा सामान और सेवाओं की खरीद करते समय सतर्क रहना चाहिए। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर मंत्रीजी ने सीसीएस, भा.लो.प्र.सं. द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को भी सम्मानित किया और ई-बुक (उपभोक्ता पुस्तिका) का विमोचन किया। उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री श्री रावसाहेब पाटिल दानवे ने अपने मुख्य भाषण में कहा कि ‘उपभोक्ता देवो भव’ अर्थात् उपभोक्ता ही ईश्वर है। उन्होंने ई-कॉमर्स और सीधी बिक्री को विनियमित करने की आवश्यकता पर जोर दिया क्योंकि ऑनलाइन खरीदारी हर दिन बढ़ रही है। मंत्री जी ने उपभोक्ता शिकायतों के समाधान में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन और क्षेत्रीय हेल्पलाइनों द्वारा शिकायत निवारण की प्रक्रिया का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या शिकायत दर्ज करने के लिए उपभोक्ता ऐप का उपयोग कर रही है और यह एक बड़ी सफलता है। मंत्रालय में इस ऐप की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम सभी को उपभोक्ताओं के सशक्तिकरण और जागरूकता की दिशा में काम करना चाहिए। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव श्रीमती लीना नंदन ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि नए अधिनियम की कई अनूठी विशेषताएं उपभोक्ता के लिए फायदेमंद हैं। उन्होंने कहा कि जागरूकता फैलाने और शिक्षित करने के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां उपभोक्ता शोषण के प्रति अधिक संवेदनशील हैं, उपभोक्ता मामले विभाग सामान्य सेवा केंद्रों, पंचायतों और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से कार्यक्रमों को लागू करने में राज्य सरकारों के साथ प्रमुख रूप से जुड़ रहा है। मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्षों तथा सदस्यों एवं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कई अन्य हितधारकों ने आभासी रूप से इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर भा.लो.प्र.सं. के महानिदेशक श्री एस. एन. त्रिपाठी ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का संचालन डॉ. सपना चड्डा और डॉ. ममता पठानिया ने किया।

भारत के संघवाद के बदलते स्वरूप पर वेबिनार

23 दिसंबर, 2020 को छठे डॉ. राकेश हूजा स्मृति व्याख्यान के अवसर पर एक वेबिनार आयोजित किया गया था। 'भारत के संघवाद के बदलते स्वरूप: राजनीति, शासन और उसके परे' विषय पर डॉ संदीप शास्त्री, प्रो. वाइस चांसलर, जैन विश्वविद्यालय, बैंगलुरु, कर्नाटक, द्वारा व्याख्यान दिया गया। व्याख्यान का आयोजन डॉ. राकेश हूजा के सम्मान और स्मृति में किया गया, जिन्होंने 06 अगस्त, 2010 से 07 सितंबर, 2012 तक भालोप्रसं के निदेशक के रूप में कार्य किया था। श्री एस.एन. त्रिपाठी, महानिदेशक, भा.लो.प्र.सं. ने अपने उद्घाटन भाषण में शिक्षा और प्रशासन के क्षेत्र में डॉ राकेश हूजा के समृद्ध योगदान का स्मरण किया। डॉ. संदीप शास्त्री ने अपने व्याख्यान में भारतीय संघवाद के बदलते स्वरूपों के प्रक्षेपक्र को प्रस्तुत किया, जो लोकतंत्र को प्रगाढ़ करने और लोकतांत्रिक स्थान के विस्तार में प्रकट हुआ। श्रीमती मीनाक्षी हूजा ने डॉ. राकेश हूजा की यादें साझा कीं और स्मारक व्याख्यान को संस्थागत बनाने पर संतोष व्यक्त किया। व्याख्यान में डॉ राकेश हूजा के परिवार और दोस्तों, भा.लो.प्र.सं. के संकाय और वरिष्ठ प्रशासनिक कर्मचारियों, शिक्षाविदों और देश भर के शोध विद्वानों ने भाग लिया। प्रो. सी. शीला रेड्डी, पीठाचार्या, डॉ. अम्बेडकर सामाजिक न्याय पीठ, ने कार्यक्रम का समन्वयन किया।

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में भ्रांतियां तोड़ने पर वेबिनार

30 दिसंबर, 2020 को 7वें प्रो.एस सरोजा स्मारक व्याख्यान के अवसर पर "सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में भ्रांतियां तोड़ना : चुनौतियां और हस्तक्षेप" विषय पर एक वेबिनार आयोजित किया गया था। यह व्याख्यान भा.लो.प्र.सं. के निवर्तमान विशिष्ट संकाय प्रो.एस सरोजा के सम्मान और स्मृति में आयोजित किया गया था। श्री एस एन त्रिपाठी, महानिदेशक, भा.लो.प्र.सं. ने उद्घाटन भाषण प्रस्तुत किया। डॉ अलका मित्तल, निदेशक (एचआर), ओएनजीसी, दिल्ली वेबिनार की मुख्य

वक्ता थीं। कार्यक्रम का संचालन डॉ नीतू जैन ने किया।

डिजिटल इंडिया 3.0 पर वेबिनार

17 दिसंबर, 2020 को "डिजिटल इंडिया 3.0 : भारत के शासन में डिजिटल परिवर्तन" पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया था। श्री अजय प्रकाश साहनी, भा.प्र.से., सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, भारत सरकार- इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता थे। श्री एस. एन. त्रिपाठी, महानिदेशक, भा.लो.प्र.सं. ने सत्र का संचालन किया। कार्यक्रम का संचालन डॉ चारू मल्होत्रा और डॉ पवन के तनेजा ने किया।

जनजातीय प्रतिभा पूल पर वेबिनार

एनएफएसटी स्कॉलर्स के लिए 4 दिसंबर, 2020 को "जनजातीय विद्वान और विकास योजनाएं" की थीम पर "जनजातीय प्रतिभा पूल" पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का संचालन डॉ नूपुर तिवारी ने किया।

मिशन कर्मयोगी पर वेबिनार

1 दिसंबर, 2020 को मिशन कर्मयोगी-द्वितीय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। श्री एस.एन. त्रिपाठी, महानिदेशक, भा.लो.प्र.सं. ने उद्घाटन टिप्पणी प्रस्तुत की। प्रो अशोक विशनदास और डॉ अमित सिंह द्वारा मिशन कर्मयोगी पर एक हवाई दृश्य प्रस्तुत किया गया था। प्रो. वी.के. शर्मा, भा.लो.प्र.सं. फैकल्टी द्वारा नमामि गंगे परियोजना पर एक सिंहावलोकन भी प्रस्तुत किया गया। सत्र के दौरान मिशन कर्मयोगी और फ्रेसिंग (Fracing) प्रक्रिया पर चर्चा की गई। डॉ अमित सिंह ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा।

भारत की एकट ईस्ट नीति पर वेबिनार

28 दिसंबर, 2020 को "इंडियाज एकट ईस्ट पॉलिसी : द चॉइस बेटविक्स्ट रीजनल कॉम्प्रैहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड ट्रांसपेसिफिक पार्टनरशिप?" पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया था। डॉ सुधीर सिंह, फैकल्टी, दयाल सिंह कॉलेज, डीयू और डॉ प्रीतम बनर्जी, विश्व बैंक सलाहकार- इस वेबिनार

के प्रमुख वक्ता थे। श्री एस. एन. त्रिपाठी, महानिदेशक, भा.लो.प्र.सं. ने सत्र का संचालन किया। कार्यक्रम का संचालन डॉ मनन द्विवेदी ने किया।

आंतरिक इंजीनियरिंग पर वेबिनार

आंतरिक इंजीनियरिंग : आरोग्य के लिए प्रौद्योगिकी-विषय पर भालोप्रसं द्वारा 9 जनवरी, 2021 को ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु के साथ एक ऑनलाइन बातचीत सत्र का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए, श्री सदगुरु ने भारत राष्ट्र से विश्व के सांस्कृतिक नेतृत्व का जिम्मा लेने का आह्वान किया, जो विश्व स्तर पर संघर्ष के समाधान का सौहार्दपूर्ण मार्ग प्रशस्त करे। उन्होंने नेताओं को आनंद का माहात्म बनाने के महत्व के बारे में भी बताया ताकि वे स्थायी प्रभाव के साथ सबसे प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। ईशा फाउंडेशन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के माध्यम से अधिकारियों के लिए आंतरिक इंजीनियरिंग कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। माननीय केंद्रीय मंत्री, डीओपीटी और भालोप्रसं के अध्यक्ष डॉ. जितेंद्र सिंह ने भी कार्यक्रम में शामिल होकर इस अवसर की श्री वृद्धि की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एम एन भंडारी, छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल श्री शोखर दत्त, श्री सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी, भा.लो.प्र.सं. के महानिदेशक तथा श्री अमिताभ रंजन, कुलसचिव भा.लो.प्र.सं. ने भी भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. सुरभि पांडेय ने किया। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया और भा.लो.प्र.सं. की क्षेत्रीय/स्थानीय शाखाएं, एटीआई और देश के विभिन्न हिस्सों के सदस्य इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर वेबिनार

28 जनवरी, 2021 को उपभोक्ता अध्ययन केंद्र, भालोप्रसं द्वारा “राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : छात्र सशक्तिकरण” पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया था। श्री सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी, महानिदेशक, भा.लो.प्र.सं., ने सत्र का संचालन किया। इस अवसर पर प्रख्यात वक्ताओं में थे - एमजी केंद्रीय विश्वविद्यालय

के कुलपति प्रो संजीव के शर्मा, बीपीएस महिला विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो सुषमा यादव, डॉ डी. एस.एन. कुमार, कुलपति, सुशांत विश्वविद्यालय, डॉ कमलेश मिश्र, कुलपति, श्रीषिंहुड विश्वविद्यालय और प्रो हरि कृष्ण मारम, कुलपति, ग्लोबल डिजिटल यूनिवर्सिटी, यूएसए। कार्यक्रम का संचालन प्रो सुरेश मिश्रा और डॉ ममता पठानिया ने किया।

राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और विस्तार योजना पर वेबिनार

27 जनवरी, 2021 को “राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना : नीति प्रक्रिया” पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। श्री एस. एन. त्रिपाठी, महानिदेशक, भा.लो.प्र.सं. ने उद्घाटन भाषण प्रस्तुत किया। श्री विजय प्रकाश, भा.प्र.से (सेवानिवृत्त), अध्यक्ष, बिहार विद्यापीठ, पटना व भा.लो.प्र.सं. की बिहार क्षेत्रीय शाखा के अध्यक्ष ने अतिथियों का स्वागत किया। बिजॉय कुमार चौधरी, कार्यकारी निदेशक, बिहार विरासत विकास समिति, बिहार सरकार, - वेबिनार के मुख्य वक्ता थे और प्रो राश बिहारी सिंह, भूगोल के प्रोफेसर और पटना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति-विशेषज्ञ पैनलिस्ट थे। कार्यक्रम का संचालन डॉ नुपुर तिवारी ने किया।

जनजातीय सतत विकास के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण पर आभासी सम्मेलन

“बहुविषयक” पर एक आभासी सम्मेलन

“राष्ट्रीय टीआरआई के सहयोग से जनजातीय सतत विकास के लिए बहु-विषयक दृष्टिकोण” विषय पर- उत्कृष्टा केंद्र, जनजातीय मामले, भा.लो.प्र.सं. द्वारा 28 से 30 जनवरी, 2021 तक एक आभासी सम्मेलन आयोजित किया गया था। पद्म श्री (2020), राहीबाई सोमा पोपेरे ने सम्मेलन को संबोधित किया। पोपेरे एक स्व-शिक्षित आदिवासी महिला हैं, जो कृषि जैव-विविधता संरक्षण में, खासकर स्वदेशी किस्मों के मामले में अपने काम के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हैं। सम्मेलन का संचालन डॉ नुपुर तिवारी ने किया।

भारत के ऊर्जा मिश्रण और विदेश नीति के निहितार्थ पर वेबिनार

25 फरवरी, 2021 को “भारत के ऊर्जा मिश्रण और विदेश नीति के निहितार्थ”- विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। श्री एस.एन. त्रिपाठी, महानिदेशक, भा.लो.प्र.सं. ने स्वागत भाषण दिया। वेबिनार के प्रख्यात वक्ता थे- श्री उत्तम कुमार सिन्हा, शोध अध्येता, मनोहर परिंकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान और डॉ भूपेंद्र कुमार सिंह, निदेशक और प्रमुख, ऊर्जा सुरक्षा, भारतीय उद्योग परिसंघ, नई दिल्ली। कार्यक्रम का संचालन डॉ. मनन द्विवेदी ने किया।

अटल पेंशन योजना पर वेबिनार

24 फरवरी, 2021 को अटल पेंशन योजना पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। श्री एस.एन. त्रिपाठी, महानिदेशक, भा.लो.प्र.सं. ने अपनी उद्घाटन टिप्पणी प्रस्तुत की। श्री पी.के. लाहेरी, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त), गुजरात क्षेत्रीय शाखा के अध्यक्ष ने अतिथियों का स्वागत किया। भा.लो.प्र.सं. फैकल्टी, प्रो अशोक विश्वनाथस ने परिचयात्मक विषय प्रस्तुत किया और साथ ही कार्यक्रम का समन्वयन किया। डॉ मदनेश कुमार मिश्र, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय- मुख्य चर्चाकार थे। वेबिनार के अन्य वक्ता थे- गुजरात के प्रो संजय वनानी और श्री पी.एन. जैन, अवैतनिक सचिव, गुजरात क्षेत्रीय शाखा। भा.लो.प्र.सं. के कुलसचिव श्री अमिताभ रंजन ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया।

कलाकार की नजर से जीवन पर वेबिनार

46वें अप्पा के प्रतिभागियों के लिए 12 फरवरी, 2021 को ‘तरन्नुम’- कलाकार की नजर से जीवन- पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री सुश्री सादिया सिद्दीकी मुख्य वक्ता थीं। श्री एस. एन. त्रिपाठी, महानिदेशक, भा.लो.प्र.सं. ने परिचयात्मक टिप्पणी दी। कार्यक्रम का संचालन डॉ चारू मल्होत्रा ने किया। इस कार्यक्रम के दौरान डॉ पवन के तनेजा भी मौजूद रहे।

67वां स्थापना दिवस

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (भा.लो.प्र.सं.) का 67वां स्थापना दिवस 26 मार्च, 2021 को संस्थान की दूसरी मंजिल पर नव-उद्घाटित टी एन सी स्मारक हॉल में लोक प्रशासन की प्रासारिकता विषय पर आयोजित किया गया था। श्री एस एन त्रिपाठी महानिदेशक, भा.लो.प्र.सं. ने अध्यक्षीय टिप्पणी दी। डॉ चारू मल्होत्रा ने अतिथियों का परिचय दिया। प्रो सुरेश मिश्र ने संक्षेप में भा.लो.प्र.सं. के इतिहास के बारे में बताया। डॉ आर एस शर्मा, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त), सीईओ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा व्याख्यान दिया गया। श्री अमिताभ रंजन कुलसचिव भा.लो.प्र. सं. ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में 46वें अप्पा के प्रतिभागियों, भा.लो.प्र.सं. के संकाय और कर्मचारियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया और भा.लो.प्र.सं. की क्षेत्रीय/स्थानीय शाखाएं और देश के विभिन्न हिस्सों के सदस्य भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद भा.लो.प्र.सं. स्टाफ द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर वेबिनार

24 मार्च, 2021 को “आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना” पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। श्री एस.एन. त्रिपाठी, महानिदेशक, भा.लो.प्र.सं. ने उद्घाटन भाषण प्रस्तुत किया। श्री विनोद जुत्सी, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त), पूर्व सचिव, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार और डॉ विपुल अग्रवाल, भा.पु.से., उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण- प्रमुख वक्ता थे। श्री अमिताभ रंजन, कुलसचिव, भा.लो.प्र.सं. ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. साकेत बिहारी ने किया।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ पर वेबिनार

10 मार्च, 2021 को भा.लो.प्र.सं. की हरियाणा

आंचलिक शाखा के सहयोग से “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। श्री एस.एन. त्रिपाठी, महानिदेशक, भा.लो.प्र.सं. ने उद्घाटन भाषण प्रस्तुत किया। भा.लो.प्र.सं. की एसोसिएट प्रो डॉ नीतू जैन ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर के दौरान प्रख्यात वक्ता थे- श्री एम.सी. गुप्ता, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त), अध्यक्ष, हरियाणा आंचलिक शाखा; डॉ वागेश्वरी देशवाल, एक नारीवादी; सुश्री वसुंधरा, प्रबंध निदेशक, वैकल्पिक देखभाल उत्कृष्टता केंद्र; डॉ राजीव ढाका, अवैतनिक सचिव, हरियाणा आंचलिक शाखा और हरियाणा आंचलिक शाखा से डॉ जी. प्रसन्न कुमार भा.प्र.से. से (सेवानिवृत्त) श्री अमिताभ रंजन कुलसचिव भा.लो.प्र.सं. ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021

उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार के सहयोग से भा.लो.प्र.सं. के उपभोक्ता अध्ययन केंद्र ने 15 मार्च, 2021 को “प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना” विषय पर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 आभासी रूप में आयोजित किया और मनाया। उपभोक्ता अध्ययन केंद्र के समन्वयक प्रो सुरेश मिश्रा ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। सुश्री लीना नंदन, सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार ने उद्घाटन भाषण दिया। प्रो. सी.के. वार्ष्ण्य, पूर्व संकायाध्यक्ष, पर्यावरणीय अध्ययन विद्यालय, जेएनयू ने “प्लास्टिक वेस्ट- एन एनवार्यनमेंटल हैर्जर्ड” पर बात की। सुश्री पुष्पा गिरिमाजी, वरिष्ठ पत्रकार, उपभोक्ता कार्यकर्ता और स्तंभकार ने “प्लास्टिक कचरे से निपटना - उपभोक्ता उत्तरदायित्व” पर बात की। डॉ सपना चड्ढा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

संस्थान के विशिष्ट आगंतुक

राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, नेपाल के अध्यक्ष लेफिटनेंट जनरल बाला नंदा शर्मा के नेतृत्व में उच्च पदस्थ नागरिक और सैन्य अधिकारियों सहित नेपाल से एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 15 मार्च, 2021

को भा.लो.प्र.सं. का दौरा किया। श्री अमिताभ रंजन, कुलसचिव, भा.लो.प्र.सं. ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। डॉ. सुरभि पांडेय ने भालोप्रसं के बारे में एक प्रस्तुति दी।

शैक्षणिक केन्द्र पीठ

प्रत्येक अकादमिक केंद्र में संबंधित अध्ययन क्षेत्र में रुचि, अनुभव और विशेषज्ञता रखने वाले संकाय सदस्यों का एक समूह शामिल है। ये निम्नलिखित कार्यों के लिए समय-समय पर मिलते हैं-

- (अ) अनुसंधान और प्रशिक्षण के अपने संबंधित क्षेत्रों में कार्य की वार्षिक योजना तैयार करते हैं, और उसकी समय-समय पर समीक्षा करने के लिए
- (ब) कार्यवाई की व्यक्तिगत योजनाओं पर चर्चा, समन्वय और समीक्षा करने के लिए
- (स) सदस्यों के अकादमिक आदान-प्रदान और व्यावसायिक विकास के लिए एक मंच के रूप में कार्य करने के लिए
- (द) अंतर- विषयक गतिविधियों को बढ़ावा देने में अन्य शैक्षणिक समूहों के साथ समन्वय करने के लिए

केंद्र समन्वयकों को निदेशक द्वारा नामित किया जाता है। संस्थान की तंग वित्तीय स्थिति के कारण प्रत्येक अकादमिक केंद्र को अपनी गतिविधियों के लिए धन की तलाश करनी पड़ती है। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार शैक्षणिक केंद्रों की सदस्यता संरचना अनुलग्नक च. 4 में दर्शाई गई है।

(भा.लो.प्र.सं. के भीतर आयोजित प्रशिक्षण और अनुसंधान के अलावा) विभिन्न भा.लो.प्र.सं. संकाय के अकादमिक योगदान का लेखा-जोखा अनुलग्नक च. 5 में दिया गया है।

शहरी अध्ययन के केंद्र

अनुलग्नक च-10 के अनुसार

उपभोक्ता अध्ययन केंद्र

अनुलग्नक च-11 के अनुसार

जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और सूखा प्रशासन केंद्र

कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रम समन्वयक	दिनांक	प्रतिभागियों की संख्या
तकनीकी कार्मिकों के लिए 15वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम (2 हफ्ते)	प्रो. विनोद के शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	11-12 जनवरी, 2021	27
जल संसाधान प्रबंधन एवं चिरस्थायी पर्यावास पर प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम (वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीविद्) (1 सप्ताह)	प्रो. विनोद के शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	01-05 फरवरी, 2021	25
विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं शासन में उभरते रूझान पर दसवां प्रशिक्षण कार्यक्रम (वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विद्) (1 सप्ताह)	प्रो. विनोद के शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	08-12 फरवरी, 2021	28

नमामि गगे के तहत गंगा नदी के हित धारकों के लिए मिश्रित क्षमता संवर्धन कार्यक्रम

मास्टर प्रशिक्षकों की कुल संख्या : 672

विद्यार्थियों की कुल संख्या : 9177

प्रशिक्षण संख्या	प्रशिक्षक	कार्यक्रम समन्वयक	दिनांक	प्रतिभागी विद्यालय	प्रतिभागियों की संख्या
1.	टीओटीज़	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	6 अप्रैल, 2021	• श्री दशमेश स्कूल • दीप असिस्टेंट स्टूडेंट नेस्ट सीनियर-सेकंडरी स्कूल	90
2.	स्कूली छात्र	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	7-8 अप्रैल, 2021	• महाप्रभु पब्लिक स्कूल, प्रयागराज • एथेनिया हाई स्कूल • डालिमस् सनबीम स्कूल	1454
3.	टीओटीज़	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	7 अप्रैल, 2021	• श्री श्री एकेडमी, वेस्ट बंगाल	19
4.	स्कूली छात्र	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	8-9 अप्रैल, 2021	• बक्शी मेमोरियल पब्लिक स्कूल, उत्तर प्रदेश • एल जे डी पब्लिक स्कूल, वेस्ट बंगाल	218
5.	टीओटीज़	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	8 अप्रैल, 2021	• दिल्ली पब्लिक स्कूल, एटा	20
6.	स्कूली छात्र	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	9-10 अप्रैल, 2021	• अमृत विद्यालय दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल • होली किड्स इंटरनेशनल स्कूल, बिहार	186

7.	टीओटीज़	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	15 अप्रैल, 2021	• इंडियन पब्लिक स्कूल, मधुबनी, बिहार • प्रारंभिक, पटना, बिहार	20
8.	स्कूली छात्र	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	16-17 अप्रैल, 2021		1297
9.	टीओटीज़	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	19 अप्रैल, 2021	• द परसिस्टेंट स्टूडेंट नेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल	21
10.	टीओटीज़	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	22 अप्रैल, 2021	• जवाहर नवोदय विद्यालय, पौरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड	34
11.	स्कूली छात्र	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	23-24 अप्रैल, 2021	• महर्षि विद्या मंदिर, कानपुर, यूपी • भारत अकैडमी एंड साइंसेस, हावड़ा, वेस्ट बंगाल • डीएवी मॉडल स्कूल, असनसोल, वेस्ट बंगाल	292
12.	टीओटीज़	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	26 अप्रैल, 2021	• दून कान्वेंट स्कूल, उत्तराखण्ड	28
13.	स्कूली छात्र	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	27-28 अप्रैल, 2021	• चिल्ड्रन्स एकेडमी, बिजनौर, यूपी • बद्रीनाथ तिवारी इंटर कॉलेज, इलाहाबाद	356
14.	टीओटीज़	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	27 अप्रैल, 2021	• बंजारवाला देहरा पब्लिक इंटर कॉलेज, देहरादून	35
15.	स्कूली छात्र	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	28-29 अप्रैल, 2021	• दिल्ली पब्लिक स्कूल पटना, बिहार • बी एल एम एकेडमी, नैनीताल, उत्तराखण्ड	285
16.	टीओटीज़	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	5 मई, 2021	• जी.डी. गोयंका पब्लिक स्कूल डागापुर, सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल	86
17.	स्कूली छात्र	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	6-7 मई, 2021		753
18.	टीओटीज़	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	10 मई, 2021	• ग्रिफिंस, इंटरनेशनल स्कूल, वेस्ट बंगाल • आर.ए.एन पब्लिक स्कूल, रुद्रपुर, उत्तराखण्ड	21
19.	स्कूली छात्र	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	11-12 मई, 2021		377

20.	टीओटीज़	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	13 मई, 2021	• एस.आर. विद्यापीठ खुसरूपुर, पटना, बिहार	57
21.	स्कूली छात्र	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	14-15 मई, 2021	• मदर टेरेसा विद्यापीठ, मुजफ्फरपुर, बिहार • शुगर सिंह एकेडमी, कानपुर, उत्तर प्रदेश • संस्कार पब्लिक स्कूल, शेखपुरा, बिहार	332
22.	टीओटीज़	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	17 मई, 2021	• दिल्ली पब्लिक स्कूल, हावड़ा, वेस्ट बंगाल	105
23.	स्कूली छात्र	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	18-19 मई, 2021	• द माउंट स्कूल पटना, बिहार • टेक्नो इंडिया ग्रुप पब्लिक स्कूल, नाभाग्राम, हुगली, वेस्ट बंगाल • बाल भारती पब्लिक स्कूल, औरंगाबाद, बिहार	682
24.	टीओटीज़	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	19 मई, 2021	• शर्मा इंटरनेशनल स्कूल, देहरादून, उत्तराखण्ड	13
25.	स्कूली छात्र	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	20-21 मई, 2021	• दिल्ली पब्लिक स्कूल, लखनऊ, यूपी	348
26.	टीओटीज़	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	20 मई, 2021	• दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिरोजाबाद, यूपी	92
27.	स्कूली छात्र	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	21-22 मई, 2021	• दिल्ली पब्लिक स्कूल, एनटीपीसी, विद्युत नगर, यूपी • सीजी डी ए वी सेनेटनरी पब्लिक स्कूल, मेरठ, यूपी • टैगोर पब्लिक स्कूल, प्रयागराज, यूपी	1151
28.	टीओटीज़	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	24 मई, 2021	• दिल्ली पब्लिक स्कूल, सीतापुर, यूपी	13
29.	स्कूली छात्र	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	25-26 मई, 2021		305
30.	टीओटीज़	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	27 मई, 2021	• दिल्ली पब्लिक स्कूल, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	18
31.	स्कूली छात्र	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	28-29 मई, 2021	• सी.एल. गुप्ता वर्ल्ड स्कूल, मुरादाबाद, यूपी .	491

32.	गंगा नदी के हित धारकों के लिए मिश्रित क्षमता निर्माण कार्यक्रम	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	4-5 जून, 2021	• गंगा संवाद	650
-----	--	---	------------------	--------------	-----

अनुसंधान परियोजनाएं

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	परियोजना समन्वयक	अवधि
1.	गंगा नदी के हित धारकों के लिए मिश्रित क्षमता निर्माण कार्यक्रम	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	जुलाई 2020-जून 2023
2.	कोविड-19 का प्रलेखीकरण : भारत सरकार का उत्तर	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	अक्टूबर 2020-नवंवर 2021
3.	ओडीएम योजना का तृतीय पक्ष मूल्यांकन	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	अप्रैल 2020-जुलाई 2020
4.	लघु जोत वाले चावल किसानों का चरम जलवायु के प्रति स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय नाजुकपन : कृषि परिस्थितिको एवं परंपरागत कृषि का तुलनात्मक अध्ययन	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	मार्च 2019-मार्च 2020
5.	सिक्किम के चुनिंदा जिलों में जैव विविधता के संरक्षण के लिए क्षमताओं एवं प्रशिक्षण आवश्यकता के विश्लेषण का मूल्यांकन करना	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	दिसंबर 2018-सितंबर 2020
6.	जलवायु स्मार्ट शासन	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	मार्च 2017-मार्च 2020
7.	जलवायु परिवर्तन के सामने जटिल आपदाओं के प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	मार्च 2017-मार्च 2020

प्रकाशन

1. श्यामली सिंह, ओवमनी ओलिव कागवेजा, “लंबेंगो, युगांडा में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, एशिया और अफ्रीका में जलवायु मुद्दे- जलवायु की जांच, इसके प्रवाह, परिणाम और समाज की प्रतिक्रिया; 29 जून 2021 को प्रकाशित हुई।
2. वी.के. शर्मा और श्यामली सिंह, “चैलेंज इन डिजास्टर मैनेजमेंट इन हिल एरियाज़: ए स्टडी ऑफ सिक्किम”, द जर्नल ऑफ गवर्नेंस, आईसी सेंटर फॉर गवर्नेंस, नई दिल्ली, वॉल्यूम 22, पृष्ठ 248-268, जनवरी 2021
3. वी. हाउ, एन.ए.एम. अहरुदीन, श्यामली सिंह, एच-आर गुओ, क्यूटी. डांग, आर. चोकेली और एस.एस. युसवीर, “एसोसिएशन ऑफ ब्लड कॉलिनेस्टरेज विद सेक्सुअल डिफरेंसेस इन मेटाबोलिक हेल्थ रिस्क्स इन विलेजर्स फ्रॉम

पेस्टिसाइड-ट्रीटेड फार्मिंग विलेजिज”, जर्नल ऑफ एक्सोफिजियोलॉजी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ, वॉल्यूम 20 (1 और 2), जनवरी- जून 2020

4. वी. हाउ, एन.ए.एम. अहरुदीन, श्यामली सिंह, एच-आर गुओ, क्यूटी. डांग, आर. चोकेली और एस.एस. युसवीर, “द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ्लाइमेट एक्स्ट्रीम्स ऑन फिजियोलॉजिकल हेल्थ अमंग एग्रोइकोलॉजी एंड कन्वेशनल स्मॉलहोल्डर राइस फार्मर्स”, एनवायर्नमेंटल जस्टिस, वॉल्यूम 13 (2), अप्रैल 2020

आर्थिक विकास और प्रबंधन अध्ययन केंद्र प्रशिक्षण कार्यशाला

संकाय के व्यक्तिगत योगदान में शामिल

जनजातीय अनुसंधान और अन्वेषण केंद्र (COTREX)

(जनजातीय मामले मंत्रालय, भारत सरकार के तहत उत्कृष्टता केंद्र (सीओई))

उत्कृष्टता केंद्र- आदिवासी मामले-की गतिविधियां 20-21

उत्कृष्टता केंद्र के बारे में

जनजातीय कल्याण के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण और सक्रिय अनुसंधान को मजबूत करने के कार्य के साथ जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तत्वावधान में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। अपनी स्थापना के बाद से, सीओई का यह लगातार प्रयास रहा है कि वह दिए गए विषय अर्थात् आदिवासी समुदायों के बहिष्करण, समावेश, हाशिए पर आदि से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 'जनजातीय अनुसंधान और अन्वेषण' पर काम करे। एमओटीए और सीओई गुणवत्ता प्रकाशनों के आदेश के अनुसार, मूल्य वर्धित कार्यशालाएं, स्मारक व्याख्यान 'राष्ट्रीय सेमिनार, संवाद/चर्चा, जागरूकता और विस्तार कार्यक्रम, अंतर-सीओई सहयोग कार्यक्रम नियमित- रूप से आयोजित किए जाने हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के इस उत्कृष्टता केंद्र का एक विशेष महत्व है क्योंकि यह लोक प्रशासन के एक ऐसे प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान में स्थित जिसकी प्रशासन को संवेदनशील बनाने के अलावा नीति निर्माण और शासन के लिए इनपुट प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका है।

उत्कृष्टता केंद्र का दायरा और उद्देश्य

राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष संस्थान के रूप में संचालित करने के लिए केंद्र को एमओटीए द्वारा कुछ उद्देश्य सौंपे गए हैं जिसमें शामिल हैं :

- जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) और जनजातीय कल्याण कार्यक्रमों में लगे कर्मियों को उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करना और व्यवस्थित करना;
- टीआरआई के मौजूदा कौशल, ज्ञान और तकनीकी जानकारी को बढ़ाना और उन्नत करना, जिससे कि वे देश की अनुसूचित जनजातियों की सांस्कृतिक

विविधता और उनके सशक्तिकरण को बनाए रखने में सक्षम हो सकें।

- जनजातीय समुदायों पर गुणात्मक, कार्योन्मुखी और नीतिगत अनुसंधान करना;
- आदिवासियों के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में जागरूकता फैलाने और तकनीकी विशेषज्ञों और लोकप्रिय नेताओं के बीच संचार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सेमिनार आयोजित करना;
- जनजातीय विकास पर समसामयिक समस्याओं पर विशेष सम्मेलनों और अध्ययन समूहों की व्यवस्था करना;
- भारत में जनजातीय विकास की विभिन्न सरकारी समस्याओं पर अनुसंधान को बढ़ावा देना; तथा
- भारत और विदेशों में जनजाति-संबंधित मुद्दों में कुशल और अद्यतन सूचना और प्रलेखन सेवाओं का विकास करना और सूचना का प्रसार तथा जागरूकता पैदा करना।

उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की गतिविधि

उत्कृष्टता केंद्र टीआरआई अधिकारियों, जिला अधिकारियों, राज्य आदिवासी कल्याण अधिकारियों और एसटी पीआरआई सदस्यों को प्रशिक्षण देने के लिए कई गतिविधियों का आयोजन करता है। सीओई, भा.लो.प्र.सं. जनजातीय अनुसंधान विद्वानों के लिए अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है। वर्ष 2020-21 के दौरान, सीओई, आईआईपीए ने 20 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, अभिविन्यास कार्यक्रम, सेमिनार/सम्मेलन और कार्यशालाएं आयोजित की हैं। ये कार्यक्रम मुख्य रूप से आदिवासी समग्र विकास से संबंधित हैं। सीओई, भा.लो.प्र.सं. ने जनजातीय मामलों के मंत्रालय को नीतिगत इनपुट भी प्रदान किए। सीओई, भा.लो.प्र.सं. विभिन्न सरकारी योजनाओं का अनुसंधान और मूल्यांकन भी करता है।

गतिविधियों की सूची

1. जनजातीय प्रतिभा पूल

जनजातीय प्रतिभा पूल के बारे में

जनजातीय विद्वानों का प्रशिक्षण और परामर्श

1. जनजातीय सतत् विकास पर बहु-विषयक दृष्टिकोण- विषय पर अंतर्राष्ट्रीय आभासी सम्मेलन 28-30 जनवरी, 2021
2. जनजातीय प्रतिभा पूल पर राष्ट्रीय आभासी सम्मेलन, विषय “आदिवासी विद्वान् और विकासात्मक योजनाएं” 4 दिसंबर, 2020, उत्कृष्टता केंद्र, भा.लो.प्र.सं.
3. एनएफएसटी विद्वानों के अनुसंधान की गुणवत्ता उन्नत करने हेतु क्षमता निर्माण ढांचा, पर वेबिनार 30 नवंबर, 2020, एमओटीए और उत्कृष्टता केंद्र
4. भा.लो.प्र.सं. जनजातीय प्रतिभा पूल सम्मेलन, 13 अक्टूबर 2020 , उत्कृष्टता केंद्र, भा.लो.प्र.सं.
5. राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति के साक्षात्कार, 23-24 सितंबर, 2020
6. जनजातीय प्रतिभा पूल पर राष्ट्रीय परामर्श, 13-14 अगस्त 2020
7. जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रायोजित “अनुसंधान पद्धति पर दो दिवसीय कार्यशाला”, 28 और 29 फरवरी 2020

2. जनजातीय अनुसंधान संस्थान का पुनरुद्धार एवं सुदृढ़ीकरण

जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के बारे में आंचलिक प्रशिक्षण में सुधार और सुदृढ़ीकरण के लिए गतिविधियाँ

1. टीआरआई की समीक्षा बैठक, 21 सितंबर-27 सितंबर 2020, उत्कृष्टता केंद्र, भा.लो.प्र.सं.
2. राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन: जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई), उत्कृष्टता केंद्र, अनुसंधान संगठन, 3- 4 सितंबर, 2020, भा.लो.प्र.सं.
3. जनजातीय अनुसंधान संस्थान के पुनरुद्धार और सुदृढ़ीकरण के लिए राष्ट्रीय परामर्श और राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का रोड मैप, जनजातीय मामले मंत्रालय और उत्कृष्टता केंद्र, जनजातीय मामले, भा.लो.प्र.सं., 10 सितंबर, 2020

4. जनजातीय अनुसंधान संस्थानों की क्षमता निर्माण और सुदृढ़ीकरण पर दो दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श। दिनांक: 29-30 जनवरी, 2020 भारतीय लोक प्रशासन संस्थान

क्षमता निर्माण ढांचे का विकास : बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षण प्रक्रिया (जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के लिए एक व्यवस्थित प्रशिक्षण मॉड्यूल) राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान

3. अनुसंधान एवं मूल्यांकन

- जनजातीय महोत्सव का तृतीय पक्ष मूल्यांकन, अनुसंधान सूचना और जन शिक्षा योजना, निगरानी और मूल्यांकन।
- जनजातीय डिजिटल दस्तावेज भंडार : एनएफएसटी विद्वानों के अनुसंधान थीसिस का मूल्यांकन, विश्लेषण और टीआरआई का ओसीआर रूपांतरण।
- जनजाति-कोंप्रित चिरस्थायी आजीविका सृजन और नवाचारी व्यवहार

4. उत्कृष्टता केंद्र की अन्य गतिविधियाँ

पैनल परिचर्चा

- 5.1.1 “जनजाति-कोंप्रित चिरस्थायी आजीविका सृजन और नवाचारी प्रथाएं”- पर पैनल चर्चा, 20 मार्च 2020 भा.लो.प्र.सं.

कार्यशालाएं/सम्मेलन

- जीओएएल (लीडर के रूप में ऑनलाइन जाना) जनजातीय समुदायों के लिए डिजिटल कौशल और मेंटरशिप पर वेबिनार, 25 जून 2020
- “कोविड -19, लचीलापन कलंक और लैंगिक समानता” पर वेबिनार, 29 मई 2020
- “पीएफएमएस ईट मॉड्यूल” पर गैर सरकारी संगठनों के साथ परामर्श कार्यशाला, 25-26 फरवरी 2020 भा.लो.प्र.सं.।

संगोष्ठियाँ

ज्ञान साझाकरण प्रतिफल के लिए संघ का विकास करना

- जनजातीय प्रतिभा पूल विद्वानों के लिए क्षमता निर्माण
- टी आर आई गतिविधियों के सुधार और सदृढ़ीकरण के परिणाम

प्रकाशन

प्रकाशनों की सूची

1. जनजातीय चिरस्थायी विकास पर बहु-विषयक दृष्टिकोण पर जनजातीय प्रतिभा पूल अंतर्राष्ट्रीय आभासी सम्मेलन पर रिपोर्ट, 28-30 जनवरी, 2021
2. जनजातीय प्रतिभा पूल जनजातीय विद्वानों और सरकारी योजनाओं पर विकास रिपोर्ट, 4 दिसंबर 2020
3. जनजातीय प्रतिभा पूल जनजातीय सम्मेलन पर रिपोर्ट, 13 अक्टूबर, 2020
4. ‘अनुसंधान पद्धति: सीएपीआई का इस्तेमाल करते हुए गुणात्मक एवं मात्रात्मक और डेटा संग्रह विधियां- पर टीटीपी वर्कशॉप पर रिपोर्ट, 13 अक्टूबर 2020
5. ‘राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन: जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई), उत्कृष्टता केंद्र, अनुसंधान संगठन’ पर रिपोर्ट, 3-4 सितंबर, 2020
6. ‘जनजातीय प्रतिभा पूल पर राष्ट्रीय परामर्श’- पर रिपोर्ट, 13-14 अगस्त, 2020
7. ‘कोविड-19, लचीलापन कलंक और लैंगिक समानता’ पर वेबिनार पर रिपोर्ट, जून 2020
8. भा.लो.प्र.सं. में 20 मार्च, 2020 को ‘भारत में जनजाति-केंद्रित चिरस्थायी आजीविका सृजन और नवाचार प्रथाएं’- पर पैनल चर्चा पर रिपोर्ट, 20 मार्च 2020, भा.लो.प्र.सं.
9. ‘जनजातीय विकास और परंपराओं पर लाल गलियारे में हिंसा के प्रभाव’ पर सार की एक पुस्तक।
10. ‘द स्टेट ऑफ आर्ट ऑफ ट्राइबल स्टडीज’ नामक पुस्तक - एक एनोटेट ग्रंथ सूची’।
11. ‘वेपनाइजिंग कल्चर: माओवादी इंसर्जेंसी एंड ट्राइबल सेल्फ-रूल’ नामक पुस्तक।
12. ‘जनजातीय विकास हेतु विभिन्न एजेंसियों के बीच संवाद के लिए एक मंच का निर्माण’ पर पैनल चर्चा और विचार-मंथन पर रिपोर्ट, फरवरी, 2020
13. ‘क्षमता निर्माण ढांचा: बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षण प्रक्रिया’ पर रिपोर्ट। (टीआरआई के लिए एक व्यवस्थित प्रशिक्षण मॉड्यूल) 29-30 जनवरी, 2020
14. ‘राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्तीय विकास निगम को समर्थन’ पर मूल्यांकन अध्ययन रिपोर्ट।
15. ‘कोविड -19, लचीलापन कलंक और लैंगिक समानता’ पर वेबिनार पर रिपोर्ट, जून 2020
16. भा.लो.प्र.सं. में 20 मार्च, 2020 को ‘भारत में जनजाति-केंद्रित चिरस्थायी आजीविका सृजन और नवाचार प्रथाएं’- पर पैनल चर्चा पर रिपोर्ट, 20 मार्च 2020, भा.लो.प्र.सं.

एनटीआरआई गतिविधियों की सूची (2021 - अब तक)

क्रम सं.	गतिविधियां	गतिविधियों की संख्या
1.	<ul style="list-style-type: none"> • डिजाइन रिक्विटों के लिए परिपत्र • प्रशासनिक-सह-लेखा अधिकारी • प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सलाहकार • आईटी सलाहकार • अनुसंधान एवं मूल्यांकन सलाहकार • अनुसंधान अधिकारी • पीए-सह-कार्यालय सहायक • मल्टी-टालस्किंग स्टाफ (एमटीएस) 	7

2.	<p>तैयार मॉड्यूल</p> <ul style="list-style-type: none"> अनुसूचित जनजाति पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के लिए मास्टर प्रशिक्षकों का क्षमता निर्माण प्रशिक्षण एसटीपीआरआई पर टीआरआई के लिए टीओटी एसटी पीआरआई पर मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए टीएसपी क्षेत्रों में ग्राम पंचायत विकास योजना-जीपीडीपी की तैयारी और कार्यान्वयन की आवश्यकता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारियों के लिए) अभिसरण मोड में टीआरआई के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम (मॉड्यूल-1) टीआरआई के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम (मॉड्यूल-2) टीआरआई के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम (मॉड्यूल-3) 	6
3.	<p>प्रशिक्षण मॉड्यूल</p> <ul style="list-style-type: none"> जनजातीय अनुसंधान संस्थान के लिए व्यवस्थित प्रशिक्षण मॉड्यूल क्षमता निर्माण ढांचा : बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षण प्रक्रिया (3 मॉड्यूल) टीआरआई के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम जीपीडीपी की तैयारी और कार्यान्वयन पर टीआरआई के लिए टीओटी 	4
4.	एनटीआरआई रोड मैप - डिजाइन और प्रस्तुति	1
5.	एनटीआरआई कैलेंडर और कार्यक्रम -	-
6.	समीक्षा बैठकें -	.
7.	<p>निम्नलिखित तैयार किए :</p> <ul style="list-style-type: none"> श्रम सुधार और पीपीटी पर एक हाइलाइट तैयार किया एनटीआरआई की पहली प्रस्तुति पडोस कार्यक्रम (विदेश मंत्रालय) एनटीआरआई दिशानिर्देश ट्राई का पुनरुद्धार प्रो. जॉन ग्रीस द्वारा जनजातीय प्रतिभा पूल एसटी पीआरआई सदस्यों के लिए मास्टर ट्रेनर्स के क्षमता निर्माण प्रशिक्षण पर प्रशिक्षण (16-18 जून, 2021) 	7
8.	<p>ओडिशा और यूएनडीपी के साथ एनटीआरआई की बैठकें (चल रही)</p> <ul style="list-style-type: none"> 13 मई, 2021 को टीआरआई ओडिशा के साथ एनटीआरआई गतिविधियां और कार्यान्वयन योजना 17 मई, 2021 को एमओटीए, टीआरआई ओडिशा और यूएनडीपी के साथ एनटीआरआई गतिविधियां और कार्यान्वयन योजना 28 मई, 2021 को टीआरआई ओडिशा और यूएनडीपी के साथ एनटीआरआई गतिविधियां और कार्यान्वयन योजना 	3

9.	अन्य बैठकों का विवरण <ul style="list-style-type: none"> • 28 मई, 2021 को पीरामल फाउंडेशन के साथ सिक्कल सेल रोगों पर चर्चा • भारत /75 जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत अनुसूचित जनजाति पंचायती राज संस्थाओं के मास्टर ट्रेनर के लिए सीबी कार्यक्रम पर टीआरआई, सांसद के साथ चर्चा 8 जून, 2021 • टीआरआई को सहायता योजना के तहत 1 जुलाई, 2021 को उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) और परियोजना प्रगति रिपोर्ट (पीपीआर) प्रस्तुत करना। 	3
----	--	---

भा.लो.प्र.सं. की गतिविधियों के साथ एनटीआरआई की सूची

क्रम सं.	गतिविधियां	दिनांक	कार्य विवरण
1.	श्रम सुधार	3 जून, 2021	भा.लो.प्र.सं.
2.	फ्रेसिंग/Fracing	16 मई, 2021	भा.लो.प्र.सं.
3.	एपीपीपीए (संशोधित पीपीटी)	2 जून, 2021 को अंतिम बार अपडेट किया गया	भा.लो.प्र.सं.
4.	बैठकें <ul style="list-style-type: none"> • जनजातीय मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार के साथ भा.लो.प्र.सं. के महानिदेशक की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान (एनटीआरआई) की कार्यान्वयन योजना पर चर्चा करने के लिए। 31 मई, 2021 को, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली, में आयोजित 		भा.लो.प्र.सं.
5.	एसटी पीआरआईज़ सदस्यों के लिए मास्टर प्रशिक्षकों हेतु क्षमता निर्माण प्रशिक्षण पर प्रशिक्षण	16-18 जून, 2021	एनटीआरआई

प्रशासनिक और कार्मिक मामले

अ. नियुक्तियां

- प्रो. सुरेश मिश्रा को, 31.12.2021 तक विशुद्ध रूप से संविदा के आधार पर लोक प्रशासन (उपभोक्ता मामलों में विशेषज्ञता के साथ) के प्रोफेसर के रूप में अनुबंधित किया गया है।
- प्रो. वी. के. शर्मा को, 02.02.2022 तक विशुद्ध रूप से संविदा के आधार पर आपदा प्रबंधन के प्रोफेसर के रूप में अनुबंधित किया गया है।
- प्रो. के. के. पाण्डेय को, 02.02.2022 तक विशुद्ध रूप से संविदा के आधार पर शहरी विकास के प्रोफेसर के रूप में अनुबंधित किया गया है।

ब. सेवा का विस्तार

- अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र के प्रोफेसर, प्रो. अशोक कुमार

विशनदास का कार्यकाल 01.11.2021 तक बढ़ा दिया गया है।

- श्री ओ. पी. चावला, उप कुलसचिव (वित्त एवं प्रशासन) के कार्यकाल की अवधि 31.01.2022 तक बढ़ा दी गई है।
- शहरी विकास के सहायक प्रोफेसर डॉ. अमित सिंह का कार्यकाल 23.10.20 से बढ़ाकर 22.04.21 कर दिया गया है।

स. निम्नलिखित संकाय और कर्मचारी सदस्य संस्थान की सेवाओं से सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त हुए :

- प्रो. सुरेश मिश्रा, लोक प्रशासन के प्रोफेसर (उपभोक्ता मामलों में विशेषज्ञता के साथ) 30.11.2020 को सेवानिवृत्त हुए।

- श्री सुखबीर सिंह, एमटीएस 31.12.2020 को सेवानिवृत्त हुए।
- श्री हुकुम चंद यादव, कार्यवाहक पुस्तकालयाध्यक्ष, 31.03.2021 को सेवानिवृत्त हुए।

द. संस्थान की सेवाओं से त्यागपत्र

- प्रो. गोविंदा भट्टाचार्जी अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र (सार्वजनिक वित्त एवं कराधान) के प्रोफेसर ने 18.06.2020 को इस्तीफा दे दिया और उन्हें 18.06.2020 से सेवा-मुक्त कर दिया गया।
- प्रो. गीतांजलि नटराज, अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र के प्रोफेसर ने इस्तीफा दे दिया और उन्हें 26.06.2020 से सेवा-मुक्त कर दिया गया।
- शहरी प्रबंधन के सहायक प्रोफेसर डॉ. सुजीत कुमार पूर्सेथ ने 20.07. 2020 को इस्तीफा दे दिया और उन्हें 20.07.2020 से सेवा-मुक्त कर दिया गया।

ध. फैकल्टी स्टाफ को संस्थान की सेवाओं से मुक्त किया गया

- प्रो. सी. शीला रेड्डी, पीठाचार्या, डॉ अंबेडकर सामाजिक न्याय पीठ को श्री बेंकटेश्वर कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राचार्य के रूप में ज्वाइन करने के लिए 18.01.2021 को 2 वर्ष की अवधि के लिए लियन पर सेवाओं से मुक्त किया गया।

न. तकनीकी इस्तीफा

- लोक नीतियां और लोक प्रशासन की प्रोफेसर प्रो सुषमा यादव को 30.08.2020 (अपराह्न) को भा.लो.प्र.सं. उनका लियन पूरा होने के बाद 31. 08.2020 (पूर्वाह्न) को संस्थान की सेवाओं से कार्यमुक्त कर दिया गया है।
- डॉ. प्रदीप कुमार परिदा, सहायक प्रोफेसर (ग्रामीण विकास) को दिनांक 11.12.2017 की दोपहर से संस्थान की सेवाओं से कार्यमुक्त किया गया है।

हिन्दी का प्रगतिशील उपयोग

महानिदेशक की अध्यक्षता में संस्थान की राजभाषा

कार्यान्वयन समिति ने, समन्वयक के रूप में प्रो. के. के. पांडेय के साथ संस्थान के कामकाज में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देना जारी रखा। इस दिशा में किए गए कुछ उपाय इस प्रकार थे :

संस्थान ने 16 सितंबर, 2020 को हिंदी में एक सार्वजनिक व्याख्यान का आयोजन किया।

डॉ सुमित जैरथ, सचिव, राजभाषा विभाग, भारत सरकार ने “राष्ट्रीय शिक्षा नीति और हिंदी भाषा” - विषय पर व्याख्यान दिया। श्री सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी, महानिदेशक, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली ने समारोह की अध्यक्षता की और स्वागत भाषण दिया। प्रो. के. के. पांडेय ने कार्यक्रम का संचालन किया। श्री अमिताभ रंजन, कुलसचिव, भा.लो.प्र.सं. ने धन्यवाद ज्ञापित किया। व्याख्यान की कार्यवाही हिन्दी में आयोजित की गई।

संस्थान हर साल वार्षिक निबंध पुरस्कार प्रतियोगिता आयोजित करता है। इस प्रतियोगिता के लिए संस्थान ने हिंदी लेख प्रतियोगिता 2020 का आयोजन किया।

संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित की जा रही है।

आभार प्रदर्शन/कृतज्ञता ज्ञापन

हम भारत के माननीय उपराष्ट्रपति और भालोप्रसं के अध्यक्ष श्री एम बेंकैया नायडू को उनके निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन के लिए अपना गहरा आभार व्यक्त करते हैं।

संस्थान के पूर्व अध्यक्ष श्री टी एन चतुर्वेदी को अपने जीवन की अंतिम सांस तक संस्थान की विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन में उनके निरंतर समर्थन के लिए हमारा धन्यवाद। हम डॉ. जितेंद्र सिंह, माननीय केंद्रीय कार्मिक, लोक शिक्षायत और पेंशन राज्य मंत्री, भारत सरकार और मंत्रालय के सभी अधिकारी, विशेष रूप से श्री दीपक खांडेकर, सचिव

डीओपीटी, डॉ. सी. चंद्रमौलि, पूर्व सचिव डीओपीटी और पूर्व सभापति भा.लो.प्र.सं. ईसी, श्रीमती रश्म चौधरी, अतिरिक्त सचिव, डीओपीटी और उप सचिव (प्रशिक्षण), डीओपीटी, श्री ए एन नारायणन को उनके निरंतर समर्थन के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं।

इसके अलावा हम नीति आयोग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार; भारत सरकार के आवास और शहरी मामले, उपभोक्ता मामले, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विदेश, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, सूचना प्रौद्योगिकी तथा जनजातीय मामले मंत्रालयों और प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के

साथ-साथ विदेशी सरकारों सहित अन्य सभी विभागों के प्रति भा.लो.प्र.सं. की गतिविधियों में उनकी निरंतर रुचि के लिए विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं। संस्थान के संकाय सदस्यों, अधिकारियों और सहयोगी स्टाफ के प्रति भी हमारा आभार है।

2020-21 के दौरान भुगतान किए गए टीए/डीए और मानदेय का विवरण

2020-2021 के दौरान संकाय सदस्यों को भुगतान किए गए मानदेय और वेतन का विवरण।

अनुलग्नक च. 11 देखें

वित्त और लेखा राजस्व खाता (नकद आधार पर)

प्राप्तियां

अपने स्वयं के संसाधान उत्पन्न करने के अलावा, संस्थान ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार और अन्य से अनुदान प्राप्त किया। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान ऐसी प्राप्तियों का विवरण इस प्रकार है :

राशि (रु. लाख में)

अ. सरकारी अनुदान		ब्रेक-अप निम्नानुसार (रु. लाख में)
1. वेतन	950.00	(1) विभिन्न शुल्क आधारित प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों से शुल्क
2. सामान्य	800.00	(2) उपयोगकर्ता शुल्क
3. पूँजी	1050.00	(3) अनुसंधान कार्यों से शुद्ध आय
बी. भा.लो.प्र.सं. द्वारा उत्पन्न	503.54	(4) सदस्यता शुल्क (सदस्यता निधि पर ब्याज सहित) (5) प्रकाशनों की बिक्री
आंतरिक प्राप्तियां		(6) विविध प्राप्तियां
		कुल
		503.54

इस प्रकार 2020-21 के दौरान संस्थान को कुल प्राप्तियां 3303.54 रुपये थीं।

व्यय

3301.75 लाख रुपये की राजस्व प्राप्तियों की तुलना में, रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान भुगतान 3301.75 लाख था, जो निम्नलिखित ब्रेक-अप के साथ था :

	(रु. लाख में)
1. स्थापना (वेतन और भत्ते)	1094.99
2. शुल्क आधारित और प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन	104.90
3. पुस्तकालय पुस्तकों और पत्रिकाएं	4.49
4. प्रकाशन	6.41
5. पेंशन	700.80
6. शाखा गतिविधियों को बढ़ावा देना	1.19
7. छात्रावास के सामान्य शुल्क सहित परिसर का रखरखाव, पानी और बिजली शुल्क, किराया, दरें और कर	240.93
8. प्रशासनिक और विविध खर्च	51.48
9. आस्तियों की खरीद	5.53
11. सीजीएचएस को भुगतान की गई राशि	15.98
12. जीएसटी सेवा कर व्यय	1.60
13. पूँजीगत व्यय	1050.00
14. आईआईपीए आरक्षित निधि में अंतरित राशि	21.11
15. अनुसंधान बंदोबस्ती निधि में अंतरित राशि	2.34
कुल	3301.75

वर्ष के अंत में यानी 2019-20 में संचयी कमी 7.33 लाख रुपये थी। हालाँकि, संस्थान वर्ष 2020-21 के अंत में केवल 5.54 लाख रुपये की संचयी कमी का प्रबंधन करने में सक्षम था।

शहरी अध्ययन केंद्र (सीयूएस)

रिपोर्टर्धीन वर्ष के दौरान शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से 334.39 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त हुए। इसके अलावा 0.08 लाख रुपये की राशि सीयूएस प्रकाशनों की बिक्री से प्राप्त हुए। रिपोर्टर्धीन वर्ष के दौरान पिछले वर्ष से 109.96 लाख रुपये की कमी को आगे लाया गया।

224.43 लाख रुपये की कुल धनराशि के खिलाफ। (रु. 109.96 लाख की पिछली कमी के समायोजन के बाद), 258.09 लाख रुपये का व्यय किया गया था :

	(रु. लाख में)
1. वेतन और भत्ते	208.16
2. पुस्तकें और पत्रिकाएं	5.98
3. यात्रा व्यय	5.42
4. इंफास्ट्रक्चर	0.25
5. प्रकाशन का मुद्रण	0.77
6. अन्य आकस्मिकताएं और विविध खर्च	2.94
7. कंप्यूटर सुविधा, सुरक्षा, टेलीफोन सहित परिसर का रखरखाव	6.39
8. पानी और बिजली	4.14
9. ओवरहेड चार्ज	22.70
10. मुद्रण और स्टेशनरी	1.34
कुल	258.09

33.66 लाख रुपए की कमी को अगले वर्ष (2021-22) के समायोजन के लिए आगे बढ़ाया गया है।

प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अनुसंधान अध्ययन आदि पर विशिष्ट अनुदान और व्यय

प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनुसंधान अध्ययन और संगोष्ठियों आदि के आयोजन के लिए प्रायोजित मंत्रालयों विभागों से 1489.39 लाख रुपये की राशि का अनुदान शुल्क निम्नानुसार प्राप्त हुआ :

	(रु. लाख में)
1. 46वां अप्पा (विभिन्न प्रायोजक मंत्रालयों विभागों से)	218.25
2. विभिन्न मंत्रालयों विभागों से क्षेत्रीय दौरों निबंधों आदि के लिए,	147.94
अप्पा प्रतिभागियों द्वारा	
3. मंत्रालयों विभागों (डीओपीटी के अलावा) और अन्य संगठनों से	723.20
अनुसंधान असाइनमेंट, सेमिनारों के लिए	
4. उपभोक्ता मामले मंत्रालय उपभोक्ता अध्ययन केंद्र के लिए	400.00
कुल	1489.39

पिछले वर्ष की तुलना में रु.1094.83 लाख की अव्ययित शेष राशि को भी आगे लाया गया। इस प्रकार कुल उपलब्ध धनराशि रु. 2584.22 लाख थी।

उपरोक्त के विपरीत, विभिन्न कार्यक्रमों, शोध अध्ययनों आदि पर व्यय 1244.88 लाख रु. व्यय हुआ, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है :

	(रु. लाख में)
1. 46वां अप्पा	55.90
2. अप्पा प्रतिभागियों द्वारा क्षेत्र का दौरा निबंध आदि	28.45
3. भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों और अन्य संगठन द्वारा प्रायोजित विशेष कार्यक्रम, अनुसंधान अध्ययन अनुसंधान सत्रीय कार्य और संगोष्ठी आदि	535.02
4. उपभोक्ता मामले मंत्रालय, उपभोक्ता अध्ययन केंद्र के लिए	625.53
कुल	1244.90

1339.34 लाख रुपये की शेष राशि को उपयोग के लिए अगले वर्ष में ले जाया गया है।

विदेशी अंशदान (एफसीआरए)

कुछ विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों और शोध अध्ययनों आदि के संचालन के लिए रु.0.58 लाख का विदेशी योगदान प्राप्त हुआ। (इस खाते में अर्जित और जमा किए गए रु.0.58 लाख के ब्याज सहित)

35.14 लाख रु. का अव्ययित शेष पिछले वर्ष से आगे लाया गया था। इस प्रकार, उपलब्ध कुल धनराशि

35.72 लाख रु थी, जिसके मुकाबले रु.18.50 की राशि का उपयोग वर्ष के दौरान किया गया था।

17.22 लाख रुपये की अव्ययित शेष राशि को अगले वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया है।

इन अनुदानों से शेष व्यय को 2021-22 के दौरान उपयोग समायोजन के लिए ले जाया गया है।

मेसर्स जीएसए एंड एसोसिएट्स ने रिपोर्ट के तहत वर्ष के लिए संस्थान के खातों की लेखा परीक्षा की।

संस्थान ने अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए संसाधन जुटाने का प्रयास जारी रखा।

अनुसंधान अध्ययन परियोजनाएं

वर्ष के दौरान, संस्थान ने निम्नलिखित 60 शोध अध्ययनों को पूरा किया, जिनका विवरण अनुलग्नक च.1 (क) में दिया गया है।

इनके अलावा, 20 अनुसंधान परियोजनाएं चल रही थीं जो अनुलग्नक च.1 (ख) में सूचीबद्ध हैं।

अनुलग्नक-च.1 (क)

अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक पूरी हो चुकीं परियोजनाएं

क्रम संख्या	परियोजना	परियोजना समन्वयक	एजेंसी
1.	प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजीटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडीआईएसएचए) योजना का प्रभाव आकलन और मूल्यांकन	डॉ चारू मल्होत्रा	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीकी मंत्रालय
2.	संभावित लाभार्थियों के जीवन पर डॉ अम्बेडकर फाउंडेशन की अंतर जातीय विवाह योजना का प्रभाव	प्रो. सी. शीला रेड्डी	डॉ अम्बेडकर फाउंडेशन
3.	नई उड़ान नया सवेरा	प्रो. सी. शीला रेड्डी डॉ साकेत बिहारी	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय
4.	राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम (आरवाईएसके) का मूल्यांकन अध्ययन	डॉ साकेत बिहारी	युवा मामले और खेल मंत्रालय
5.	एमएसडीई “1396 सरकार का उन्नयन, पीपीपी के माध्यम से” के अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्र योजना का तीसरा पक्ष मूल्यांकन	डॉ साकेत बिहारी	कौशल विकास एवं उद्यमशिलता मंत्रालय (आर्थिक एवं नीति खंड)
6.	एमएसडीई “जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) के अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्र योजना का तीसरा पक्ष मूल्यांकन	डॉ साकेत बिहारी	कौशल विकास एवं उद्यमशिलता मंत्रालय (आर्थिक एवं नीति खंड)
7.	एमएसडीई “वामपंथी अतिवादियों (एसडीएलडब्ल्यूई) से प्रभावित 47 जिलों में कौशल विकास” के अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्र योजना का तीसरा पक्ष मूल्यांकन	डॉ साकेत बिहारी	कौशल विकास एवं उद्यमशिलता मंत्रालय (आर्थिक एवं नीति खंड)
8.	एमएसडीई “प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)” के अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्र योजना का तीसरा पक्ष मूल्यांकन	डॉ साकेत बिहारी	कौशल विकास एवं उद्यमशिलता मंत्रालय (आर्थिक एवं नीति खंड)
9.	ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के लिए राष्ट्रीय स्तरीय निगरानी (एनएलएम)	डॉ साकेत बिहारी	ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
10.	राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) का मूल्यांकन अध्ययन	डॉ साकेत बिहारी डॉ कुसुम लता	युवा मामले और खेल मंत्रालय
11.	मानव संसाधन प्रबन्धन के लिए तीसरा पक्ष मूल्यांकन	डॉ कुसुम लता डॉ साकेत बिहारी	संचार मंत्रालय डाक विभाग
12.	विदेश में अध्ययन के लिए अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए योजना छात्रवृत्ति का मूल्यांकन	डॉ गदाधर मोहपात्रा	जनजातीय मामले मंत्रालय

13.	अनुसूचित जनजाति की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप और छात्रवृत्ति	डॉ गदाधर मोहपात्रा	जनजातीय मामले मंत्रालय
14.	जलवायु स्मार्ट शासन, डीएसटी के जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम के अंतर्गत मानव क्षमता निर्माण कार्यक्रम	प्रो विनोद शर्मा डॉ श्यामली सिंह	डीएसटी (भारत सरकार)
15.	जलवाय परिवर्तन की स्थिति में जटिल आपदाओं के प्रबन्धन के लिए क्षमता निर्माण रणनीतियां	प्रो विनोद शर्मा डॉ श्यामली सिंह	एमओईएफ (भारत सरकार), एनएमएचएस
16.	सुरक्षित हिमालय परियोजना परिदृश्य और सिक्किम के सभी जिलों में प्रमुख हितधारकों की क्षमता बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक प्रभावी जैव विविधता संरक्षण विकास और क्षमता निर्माण ढांचे के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख हितधारकों की क्षमता और प्रशिक्षण की आवश्यकता का आंकलन	प्रो विनोद शर्मा डॉ श्यामली सिंह	यूएनडीपी/एमओईएफसीसी
17.	निर्माण उद्योग विकास परिषद (सीआईडीसी) के माध्यम से पीएफसी की सीएसआर पहल के अंतर्गत 2000 व्यक्तियों के लिए समाज के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिलाओं और ईडब्ल्यूएस के लिए रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम का प्रभाव	डॉ पवन कुमार तनेजा डॉ रोमा देबनाथ	विद्युत वित्त निगम लि.
18.	पूर्ववर्ती आईईसी कार्यक्रम के स्वस्थ नागरिक अभियान (एसएएन) का त्वरित मूल्यांकन	डॉ पवन कुमार तनेजा डॉ रोमा देबनाथ	नीति आयोग
19.	आईएसटीएम में आईएसटीएम की योजना प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि का तीसरा पक्ष मूल्यांकन	डॉ पवन कुमार तनेजा डॉ रोमा देबनाथ	आईएसटीएम (डीओपीटी)
20.	सीमा प्रबन्धन, एमएचए के लिए तटीय सुरक्षा सेवाओं (सीएसएस) चरण-II का तीसरा पक्ष मूल्यांकन	डॉ सुरभि पांडेय	गृह मामले मंत्रालय
21.	सीमा प्रबन्धन, एमएचए के लिए सीमा अवसरंचनात्मक ढांचे (बीआईएम) योजना का तीसरा पक्ष मूल्यांकन	डॉ सुरभि पांडेय	गृह मामले मंत्रालय
22.	सीमा प्रबन्धन, एमएचए के लिए सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) योजना का तीसरा पक्ष मूल्यांकन	डॉ सुरभि पांडेय	गृह मामले मंत्रालय
23.	भारतीय साइबर क्राइम समन्वयन केन्द्र (14सी) योजना, एमएचए का तीसरा पक्ष मूल्यांकन	डॉ सुरभि पांडेय	गृह मामले मंत्रालय

24.	पीआरआईज (2018) के संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपायों पर अनुसंधान अध्ययन	डॉ वी.एन. आलोक	नीति आयोग
25.	एनआरपी योजना का तीसरा पक्ष मूल्यांकन	डॉ सुरभि पांडेय	शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
26.	आरजीएनआईवाईडी का मूल्यांकन	प्रो के.के. पांडेय डॉ सचिन चौधरी	युवा मामले मंत्रालय
27.	एमएसएमई को पेशेवर सहायता (एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 में परिवर्तन की आवश्यकता का अध्ययन करने के लिए कार्य समूह)	प्रो के.के. पांडेय डॉ सचिन चौधरी डॉ सपना चड्डा	एमएसएमई मंत्रालय
28.	आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) के अधीन सूचना के सक्रिय खुलासे का तीसरा पक्ष लेखा परीक्षा	डॉ सपना चड्डा	एनटीपीसी लिमिटेड
29.	आरटीआई अधिनियम 2005-एनईपीसीओ की धारा 4 (1) के अधीन सूचना के सक्रिय खुलासे का तीसरा पक्ष लेखा परीक्षा	डॉ सपना चड्डा	पूर्वोत्तर इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
30.	आरटीआई अधिनियम 2005-बीईई की धारा 4 (1) के अधीन सूचना के सक्रिय खुलासे का तीसरा पक्ष लेखा परीक्षा	डॉ सपना चड्डा	ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड
31.	आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) के अधीन सूचना के सक्रिय खुलासे का तीसरा पक्ष लेखा परीक्षा	डॉ सपना चड्डा	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विकास मंत्रालय
32.	आरटीआई अधिनियम 2005-आईआईएसईआर कोलकाता की धारा 4 (1) के अधीन सूचना के सक्रिय खुलासे का तीसरा पक्ष लेखा परीक्षा	डॉ सपना चड्डा	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान-कोलकाता
33.	आरटीआई अधिनियम 2005-आईआईएसईआर मोहाली की धारा 4 (1) के अधीन सूचना के सक्रिय खुलासे का तीसरा पक्ष लेखा परीक्षा	डॉ सपना चड्डा	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान-मोहाली
34.	आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) के अधीन सूचना के सक्रिय खुलासे का तीसरा पक्ष लेखा परीक्षा	डॉ सपना चड्डा	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय
35.	आरटीआई अधिनियम 2005-की धारा 4 (1) के अधीन सूचना के सक्रिय खुलासे का तीसरा पक्ष लेखा परीक्षा	डॉ सपना चड्डा	आईएसटीएम
36.	आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) के अधीन सूचना के सक्रिय खुलासे का तीसरा पक्ष लेखा परीक्षा	डॉ सपना चड्डा	एमएसएमई

37.	आरटीआई अधिनियम 2005- की धारा 4 (1) के अधीन सूचना के सक्रिय खुलासे का तीसरा पक्ष लेखा परीक्षा	डॉ सपना चड्डा	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान-तिरुवनन्तपुरम
38.	सीबीआई की चल रही योजना का तीसरा पक्ष मूल्यांकन	डॉ सपना चड्डा डॉ अमित कुमार सिंह	केन्द्रीय जांच ब्यूरो
39.	स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना का तीसरा पक्ष मूल्यांकन	डॉ सपना चड्डा डॉ अमित कुमार सिंह	गृह मामले मंत्रालय
40.	विदेशी प्रशिक्षण के घरेलू वित्त पोषण का तीसरा पक्ष मूल्यांकन (डीएफएफटी)	डॉ अमित कुमार सिंह	डीओपीएंडटी
41.	केन्द्रीय क्षेत्र की योजना अन्य आपदा प्रबन्धन योजना (ओडीएमएस) का तीसरा पक्ष मूल्यांकन	प्रो. वी.के. शर्मा डॉ श्यामली सिंह	गृह मामले मंत्रालय
42.	चरम जलवायु के लिए छोटी जोत वाले चावल किसानों की स्वास्थ्य और पर्यावरणीय कमज़ोरी (भेदता): कृषि परिस्थितिकी और पारंपरिक रूप पर एक सहयोगी अध्ययन	डॉ श्यामली सिंह	धीमी गति से शुरू होने वाली जलवायु आपदा के लिए प्रणालीगत प्रयास के साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण संस्थान (एआई-एसओसीडी)
43.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, शिमला का 'पारदर्शिता लेखा परीक्षा' (आईआईएएस)	प्रो. अशोक विशनदास	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, शिमला (आईआईएएस)
44.	भारत की विदेश नीति: नेहरूवादी काल से अब तक	डॉ मनन द्विवेदी	आईसीएसएसआर
45.	कोविड-19 का प्रलेखन	प्रो. वी.के. शर्मा डॉ श्यामली सिंह	गृह मामले मंत्रालय, यूएनडीपी
46.	पूर्वोत्तर की विज्ञापन और प्रचार योजना का तीसरा पक्ष मूल्यांकन	डॉ वी.एन. आलोक डॉ साकेत बिहारी	गृह मामले मंत्रालय
47.	"पूर्वोत्तर क्षेत्र में नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम" योजना का तीसरा पक्ष मूल्यांकन	डॉ वी.एन. आलोक डॉ साकेत बिहारी	गृह मामले मंत्रालय
48.	"पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम" योजना का तीसरा पक्ष मूल्यांकन	डॉ वी.एन. आलोक डॉ साकेत बिहारी	गृह मामले मंत्रालय
49.	"पूर्वोत्तर क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवा" का तीसरा पक्ष मूल्यांकन	डॉ वी.एन. आलोक डॉ साकेत बिहारी	गृह मामले मंत्रालय
50.	14वें वित्त आयोग से परे आईसी योजना की निरंतरता के लिए इस मंत्रालय की सर्वेक्षण, अध्ययन ओर नीति अनुसंधान योजना के अधीन एमएमई मंत्रालय की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) योजना का मूल्यांकन अध्ययन	डॉ सचिन चौधरी प्रो. के.के. पाडेय	एमएसएमई मंत्रालय

51.	तमिलनाडु के यूएलबी इंजीनियर्स के प्रशिक्षण आवश्यकता आकलन	प्रो. के.के. पांडेय डॉ सचिन चौधरी	नगर प्रशासन आयुक्तालय, तमिलनाडु सरकार
52.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन का मूल्यांकन	डॉ पवन के तनेजा डॉ रोमा देबनाथ	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
53.	पेट्रो-रसायन की नई योजनाओं का मूल्यांकन (i) प्लास्टिक पार्क की स्थापना की योजना और (ii) उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना की योजना (सीओई)	प्रो. अशोक विशनदास डॉ साकेत बिहारी	रसायन और उर्वरक मंत्रालय और रसायन विभाग
54.	“प्रशासनिक सुधार” के लिए योजना का मूल्यांकन अध्ययन	डॉ नीतू जैन डॉ सुरभि पांडेय	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, प्रशासन सुधार और पीजी विभाग
55.	‘मादक पदार्थों नियंत्रण के लिए राज्यों की सहायता’ का तीसरा पक्ष मूल्यांकन	डॉ सुरभि पांडेय	गृह मामले मंत्रालय
56.	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा के मेधावी छात्रों के लिए डॉ अम्बेडकर राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार योजना का मूल्यांकन	प्रो. शीला रेड्डी	डॉ अम्बेडकर पीठ
57.	“पेंशनभोगी पोर्टल” योजना का तीसरा पक्ष मूल्यांकन	डॉ पवन के तनेजा	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग
58.	“जनजातीय पर्व, अनुसंधान, सूचना और जन शिक्षा” और “निगरानी और मूल्यांकन” योजनाओं का मूल्यांकन	डॉ नूपुर तिवारी	जनजातीय मामले मंत्रालय (एमओटीए)
59.	सूचना और जन जागरूकता कार्यक्रम का तीसरा पक्ष मूल्यांकन	डॉ वी.एन. आलोक	नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय (आईएंडपीए प्रभाग)
60.	महिला और बच्चों के विरुद्ध साइबर क्राइम नियंत्रण का तीसरा पक्ष मूल्यांकन	डॉ सुरभि पांडेय	गृह मंत्रालय

अनुलग्नक-च.1 (ख)

अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक पूरी हो चुकीं परियोजनाएं

क्रम संख्या	परियोजना	परियोजना समन्वयक	एजेंसी
1.	राष्ट्रीय जनजातीय कोष परियोजना	डॉ नूपुर तिवारी	जनजातीय मामले मंत्रालय
2.	टीआरआईएफईडी बन धन मूल्यांकन	डॉ नूपुर तिवारी	जनजातीय मामले मंत्रालय
3.	ओडिशा के केबीके जिलों में महिला सशक्तिकरण में मिशन शक्ति के प्रभाव का मूल्यांकन	डॉ गदाधर मोहपात्रा	राष्ट्रीय महिला आयोग
4.	नमामि गंगा कार्यक्रम के अधीन गंगा नदी के हितधारकों के लिए मिश्रित क्षमता निर्माण कार्यक्रम	प्रो. वी.के. शर्मा डॉ श्यामली सिंह	जल संसाधान विभाग, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय गंगा जीर्णोद्धार मिशन
5.	एमएसएमई को पेशेवर सहयोग (भारत में एमएसएमई के लिए राष्ट्रीय नीति की तैयारी)	प्रो. के.के. पांडेय डॉ सचिन चौधारी डॉ सपना चड्डा	एमएसएमई मंत्रालय
6.	भारत में प्रशिक्षण संस्थान का मूल्यांकन	प्रो. अशोक विशनदास डॉ नीतू जैन	नीति आयोग
7.	सीएपीएफ में दुर्घटना (एट्रीशन) और आत्महत्या संबंधी मामले का तुलनात्मक विश्लेषण और सुधारात्मक उपाय	डॉ नीतू जैन	पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो
8.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास योजनाओं का मूल्यांकन	प्रो. सी. शीला रेड्डी	डॉ अम्बेडकर पीठ (एनबीसीएफडीसी द्वारा प्रायोजित, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण)
9.	चयनित राज्यों में उपभोक्ता अधिकारों पर कोविड-19 के प्रभाव का अध्ययन	डॉ ममता पठानिया	उपभोक्ता अध्ययन केन्द्र (सीसीएस)
10.	जिला उपभोक्ता के कामकाज का मूल्यांकन-कर्नाटक में सूचना केन्द्र और उपभोक्ता के बीच संतुष्टि का स्तर	प्रो. सुरेश मिश्रा	उपभोक्ता अध्ययन केन्द्र (सीसीएस)
11.	एनसीआर में उपभोक्ता संरक्षण और आवास शिकायत निवारण में रियल स्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 का प्रभाव	डॉ सपना चड्डा	उपभोक्ता अध्ययन केन्द्र (सीसीएस)
12.	“विशेषज्ञ जांचकर्ता सृजनता” का तीसरा पक्ष मूल्यांकन	डॉ सुरभि पांडेय	गृह मंत्रालय बीपीआएंडडी
13.	एसएपी इंडिया प्रा. लि. का प्रभाव मूल्यांकन	डॉ चारू मल्होत्रा डॉ पवन के तनेजा	एसएपी इंडिया प्रा. लि.

14.	“प्रशिक्षण संस्थानों की सहायता” (एटीआई) का मूल्यांकन अध्ययन	डॉ साकेत बिहारी	एमएमएमई मंत्रालय
15.	एलबीएसएनएए में पंजी और राजस्व योजना का तीसरा पक्ष मूल्यांकन	डॉ सुरभि पांडेय	एलबीएसएनएए, मसूरी
16.	डाक विभाग की आईटी आधुनिकीकरण परियोजना का तीसरा पक्ष मूल्यांकन	डॉ साकेत बिहारी	डाक विभाग कॉर्पोरेट योजना प्रभाग
17.	डाक विभाग की योजनाओं का तीसरा पक्ष मूल्यांकन	डॉ रोमा देबनाथ डॉ कुसुम लता	डाक विभाग कॉर्पोरेट योजना प्रभाग
18.	राहतगंज/आराम गंज, रोशनारा रोड, पुलबंगश में जनकपुरी पश्चिम से आर.के. आश्रम गलियारे के संबंध में डीएमआरसी परियोजना के सामाजिक प्रभाव का आकलन	प्रो. के.के. पांडेय	राष्ट्रीय राजधानी सरकार, दिल्ली क्षेत्र
19.	उपभोक्ता अध्ययन केन्द्र	प्रो. सुरेश मिश्रा डॉ सपना चड्ढा डॉ ममता पठानीया	उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार
20.	राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के माध्यम से एकीकृत उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली	प्रो. सुरेश मिश्रा डॉ ममता पठानीया	उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार

अनुलग्नक- च.2

अप्रैल 2020 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला

क्रम संख्या	कार्यक्रम का नाम	तिथि/तिथियां	व्यक्तियों की संख्या	संकाय का नाम
1.	सिक्किम के अधिकारियों के लिए “क्लाइमेट स्मार्ट गवर्सनेंस” (डीएसटी, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	जून 1-5, 2020	25	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ श्यामली सिंह
2.	लोक प्रशासन में 46वां अग्रिम पेशेवर कार्यक्रम (डीएसटी, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	जुलाई 1, 2020 से अप्रैल 2021	29	डॉ चारू मल्होत्रा डॉ पवन तनेजा
3.	श्री दुर्गा मल्लेश्वरा सिद्धार्थ महिला कलाशाला वाणिज्य विभाग (कृष्ण विद्यालय) के सहयोग से “उपभोक्ता संरक्षण में कोविड-19 की नई चुनौतियां और रणनीतियां” विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय एफडीपी वेबिनार	जुलाई 04, 2020	103	प्रो. सुरेश मिश्रा
4.	कोविड-19 मीडिया और उपभोक्ता सशक्तिकरण विषय पर वेबिनार, उपभोक्ता अध्ययन केन्द्र, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (भा.लो.प्र.सं.), नई दिल्ली	जुलाई 07, 2020	130	डॉ ममता पठानिया
5.	एनएडीपी अधिकारियों के लिए लोक प्रशासन और स्थापना मॉड्यूल, (एनएडीपी, रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित)	जुलाई 13-15, 2020	34	प्रो. सी. शीला रेड्डी डॉ ममता पठानिया
6.	राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी के लिए “डाटा एनालिटिस्ट एंड आर्टिफिशियल इन्टरलीजेंस” विषय पर कार्यशाला	जुलाई 27-30, 2020	46	डॉ सुरभि पांडेय
7.	“ई-कॉर्मस रेसिलिएंस स्ट्रेटिजी इन न्यू नॉर्मल”, उपभोक्ता अध्ययन केन्द्र, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (भा.लो.प्र.सं.), नई दिल्ली विषय पर वेबिनार	अगस्त 4, 2020	308	डॉ सपना चड्डा
8.	जी.जे अडवाणी कॉलेज, मुम्बई, महाराष्ट्र के सहयोग से कोविड-19 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 विषय पर वेबिनार	अगस्त 8, 2020	217	प्रो. सुरेश मिश्रा

9.	बैच-2019 के आईपीएंडटीएफएसओटी का ऑनलाइन अटैचमेंट (राष्ट्रीय वित्त संचार संस्थान द्वारा प्रायोजित)	अगस्त 10-21 , 2020	04	प्रो. सी. शीला रेड्डी डॉ ममता पठानिया
10.	एमईएस कार्यकारी इंजीनियर्स के लिए 'वरिष्ठ प्रबन्धन पाठ्यक्रम' (मिलिट्री अभियंता सेवा, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	अगस्त 30 से 5 सितम्बर, 2020 तक	57	डॉ नीतू जैन
11.	सिक्किम में जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (यूएनडीपी द्वारा प्रायोजित)	सितम्बर 9-11 , 2020	29	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ श्यामली सिंह
12.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लोक प्रशासकों से उन्नत डाटा विश्लेषण (योजना विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा प्रायोजित)	सितम्बर 21-25 , 2020	25	डॉ रोमा देबनाथ मित्रा
13.	"लोक सेवा वितरण प्रणाली में आरटीआई अधिनियम की भूमिका", भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, (भा.लो.प्र.सं.) , नई दिल्ली	अक्टूबर 01 , 2020	153	डॉ सपना चड्डा
14.	एमईएस के मुख्य अभियंताओं के लिए मानव संस्थान प्रबन्धन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	अक्टूबर 5-16 , 2020	30	डॉ नीतू जैन
15.	राज्य एटीआई के माध्यम से जिलाधिकारियों के लिए "परियोजना जागरूकता और कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत" विषय पर तीन दिवसीय आभासी शिखर सम्मेलन	अक्टूबर 13-15 , 2020	25	डॉ चारू मल्होत्रा
16.	सटिफेन विलफ्रेड्स कॉलेज ऑफ लॉ, पनवेल, महाराष्ट्र (उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019) के सहयोग से "ए गेम चेंजर"	अक्टूबर 20 , 2020	174	डॉ सपना चड्डा
17.	वैल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनीवर्सिटी, वैल्लोर, तमिलनाडु के सहयोग से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-ए गेम चेंजर	अक्टूबर 22 , 2020	577	डॉ सपना चड्डा
18.	प्रभावी शासन और प्रशासन (एसईजीए) जयपुर (सीसीएस) के लिए उपभोक्ता संरक्षण और सशक्त समाज	अक्टूबर 28 , 2020	562	डॉ ममता पठानिया

19.	डिजीटल माध्यम से क्षेत्रीय हेल्पलाइन परामर्शदाता	नवम्बर 2-6, 2020	36	डॉ ममता पठानिया सुश्री दीपिका सुर
20.	महिला राष्ट्रीय आयोग (एनसीडब्ल्यू) द्वारा प्रायोजित “उद्यमशीलता और कौशल विकास के माध्यम से जनजातीय महिलाओं का सशक्तिकरण” विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय आभासी सम्मेलन	नवम्बर 5-6, 2020	28	डॉ गदाधर मोहपात्रा
21.	एनजीओ/वीओसी के प्रमुखों के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	नवम्बर 4-6, 2020	40	प्रो. सुरेश मिश्रा डॉ ममता पठानिया
22.	संकाय सदस्याओं/प्रशिक्षुओं के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	नवम्बर 9-11, 2020	37	प्रो. सुरेश मिश्रा डॉ ममता पठानिया
23.	महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, मुम्बई के सहयोग से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019-ए गेम चेंजर	नवम्बर 17, 2020	224	डॉ सपना चड्डा
24.	जेएसएस लॉ कॉलेज, मैसूरु, कर्नाटक के सहयोग से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019-ए गेम चेंजर	नवम्बर 18, 2020	683	डॉ सपना चड्डा
25.	उपभोक्ता जागरूकता पर ऑनलाइन राष्ट्रीय पोस्टर प्रतियोगिता	नवम्बर 22, 2020	244	डॉ ममता पठानिया
26.	जिला आयोग के अध्यक्षों/सदस्यों के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 पर तीन दिवसीय ऑनलाइन उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम	नवम्बर 23-25, 2020	120	प्रो. सुरेश मिश्रा डॉ सपना चड्डा
27.	वैज्ञानिकों और तकनीकियों के लिए वैज्ञानिक संगठनों में वित्त प्रबन्धन पर 9वां टी.पी.	नवम्बर 23-27, 2020	33	डॉ पवन के. तनेजा
28.	“आत्मनिर्भर (एलईएन) भारत के लिए नेतृत्व उत्कृष्टता” (सभी पीएसयू के लिए) 9वां उन्नत नेतृत्व कार्यक्रम	नवम्बर 23, 2020 से दिसम्बर 11, 2020 तक	14	डॉ नीतू जैन डॉ सचिन चौधरी
29.	“उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019” पर राज्य सरकारों के अधिकारियों/ऑफिशियलों के लिए दो दिवसीय ऑनलाइन उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम	नवम्बर 26-27, 2020	92	प्रो. सुरेश मिश्रा डॉ सपना चड्डा

30.	वेल टेक रंगराजन डॉ सगुंथला आरएंडडी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवाड़ी-वेल टेक रोड, पुनमअल्ली-अवाड़ी हाइ रोड, वेल नगर, चैन्नई, तमिलनाडु, 600062 के सहयोग से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019-ए गेम चेंजर	दिसम्बर, 2, 2020	360	डॉ ममता पठानिया
31.	खाद्य, जन आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण, विंग 'डी', प्रथम तल, विंद्याचल भवन, भोपाल, मध्य प्रदेश के जिला स्तरीय अधिकरियों/ऑफिशियल्स के लिए "उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019" विषय पर दो दिवसीय ऑनलाइन उन्मुख कार्यक्रम	दिसम्बर 3-4, 2020	66	डॉ सपना चड्डा
32.	खाद्य, जन आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण, विंग 'डी', प्रथम तल, विंद्याचल भवन, भोपाल, मध्य प्रदेश के जिला स्तरीय अधिकरियों/ऑफिशियल्स के लिए "उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019" विषय पर दो दिवसीय ऑनलाइन उन्मुख कार्यक्रम	दिसम्बर 7-8, 2020	68	डॉ सपना चड्डा
33.	ग्रामीण सोसाइटियों, वैज्ञानिकों और तकनीकविदों (1-सप्ताह) के लिए विज्ञान और तकनीक पर तीसरा टीपी (डीएसटी द्वारा प्रायाजित)	दिसम्बर 07-11, 2020	34	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ चारू मल्होत्रा
34.	खाद्य, जन आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण, विंग 'डी', प्रथम तल, विंद्याचल भवन, भोपाल, मध्य प्रदेश के जिला स्तरीय अधिकरियों/ऑफिशियल्स के लिए "उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019" विषय पर दो दिवसीय ऑनलाइन उन्मुख कार्यक्रम	दिसम्बर 10-11, 2020	68	डॉ सपना चड्डा
35.	नगर निगम और तमिलनाडु सरकार की श्रेणी 'क' नगर पालिकाओं के नगर आयुक्तों के लिए शहरी शासन विषय पर दिवसीय डिजीटल प्रशिक्षण कार्यक्रम	दिसम्बर 14-16, 2020	20	प्रो. के.के. पांडेय डॉ अमित कुमार सिंह

36.	सभी सीपीआईओ के लिए आरटीआई पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा प्रायोजित)	दिसम्बर 21, 2020	35	डॉ सपना चड्डा
37.	राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2020 रूपरेखा: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की नई विशेषताएं	दिसम्बर 24, 2020	986	डॉ सपना चड्डा डॉ ममता पठानिया
38.	एसएआरडी, केन्द्रीय तिब्बतियन प्रशासन, धर्मशाला के लिए “नेतृत्व और लोक प्रशासन” विषय पर तीन दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	जनवरी 04-06, 2021	20	डॉ सुरभि पांडेय
39.	ग्रामीण सोसाइटियों के लिए विज्ञान और तकनीक पर 9वां टी.पी (महिला घटक) (सभी स्तर के वैज्ञानिक तथा तकनीकीविद) (डीएसटी द्वारा प्रायोजित)	जनवरी 04-08, 2021	27	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ चारू मल्होत्रा
40.	तकनीकी कार्मिकों (तकनीकी अधिकारी, तकनीकी कर्मचारी, टेकनीशियन, वरिष्ठ टेकनीशियन, अवर विश्लेषक) के लिए 15वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम (डीएसटी द्वारा प्रायोजित)	जनवरी 11-22, 2021	27	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ श्यामली सिंह
41.	जेवियर लॉ कॉलेज, सिफन जेवियर्स यूनीवर्सिटीज, कोलकाता के सहयोग से प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019	जनवरी 15, 2021	420	डॉ सपना चड्डा
42	हिमाचल प्रदेश (बैच-1) में एसएलटीसी (राज्यस्तरीय तकनीकी कक्ष) और सीएलटीसी (सिटी स्तरीय तकनीकी प्रकोष्ठ) में विशेषज्ञों/स्पेशिलिस्टों के लिए पीएमएवाई-एचएफए पर एक दिवसीय विशेष ऑनलाइन कार्यक्रम	जनवरी 19, 2021	27	प्रो. के.के. पांडेय डॉ अमित कुमार सिंह
43.	हिमाचल प्रदेश (बैच-II) में एसएलटीसी (राज्यस्तरीय तकनीकी कक्ष) और सीएलटीसी (सिटी स्तरीय तकनीकी प्रकोष्ठ) में विशेषज्ञों/स्पेशिलिस्टों के लिए पीएमएवाई-एचएफए पर एक दिवसीय विशेष ऑनलाइन कार्यक्रम	जनवरी 21, 2021	26	प्रो. के.के. पांडेय डॉ अमित कुमार सिंह

44.	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019: आगे का रास्ता-अध्यक्ष सदस्य पर एनसीडीआरसी और राज्य आयोगों का आभासी क्षेत्रीय सम्मेलन	जनवरी 27, 2021	23	प्रो. सुरेश मिश्रा डॉ सपना चड्डा
45.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: विद्यार्थियों को सशक्त करना	जनवरी 28, 2021	200	प्रो. सुरेश मिश्रा डॉ ममता पठानिया
46.	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019: आगे का रास्ता विषय पर एनसीडीआरसी और राज्य आयोगों का आभासी क्षेत्रीय सम्मेलन	जनवरी 29, 2021	17	प्रो. सुरेश मिश्रा डॉ सपना चड्डा
47.	उपभोक्ता आयोगों के आर्थिक क्षेत्राधिकार पर ऑनलाइन हितधारकों के परामर्श का आयोजन करना	फरवरी 1, 2021	115	प्रो. सुरेश मिश्रा डॉ सपना चड्डा
48.	वैज्ञानिकों और तकनीकीविदों के लिए जल संसाधन प्रबन्धन और सतत आवास पर पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम (ऑनलाइन)	फरवरी 1-5, 2021	25	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ श्यामली सिंह
49,	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019: आगे का रास्ता विषय पर एनसीडीआरसी और राज्य आयोगों का आभासी क्षेत्रीय सम्मेलन	फरवरी 3, 2021	22	प्रो. सुरेश मिश्रा डॉ सपना चड्डा डॉ ममता पठानिया
50.	विज्ञान, तकनीक और शासन में उभरता रुझान विषय पर 10वां टीपी (सभी स्तर के वैज्ञानिक और तकनीकीविद) (1-सप्ताह)	फरवरी 08-12, 2021	28	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ श्यामली सिंह
51.	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019: आगे का रास्ता विषय पर एनसीडीआरसी और राज्य आयोगों का आभासी क्षेत्रीय सम्मेलन	फरवरी 8, 2021	16	प्रो. सुरेश मिश्रा डॉ सपना चड्डा
52.	भारतीय रक्षा संपदा सेवा के परिवीक्षाधीनों के लिए लोक प्रशासन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	फरवरी 08-12, 2021	03	डॉ ममता पठानिया
53.	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019: आगे का रास्ता विषय पर एनसीडीआरसी और राज्य आयोगों का आभासी क्षेत्रीय सम्मेलन	फरवरी 9, 2021	16	प्रो. सुरेश मिश्रा डॉ सपना चड्डा
54.	एनजीओ/वीसीओ प्रमुखों के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पर तीन दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	फरवरी 10-12, 2021	30	प्रो. सुरेश मिश्रा डॉ ममता पठानिया
55.	लर्निंग एंड डेवलपमेंट एलीसियम 2021 समिट	फरवरी 16-20, 2021	400	डॉ रोमा देबनाथ मित्रा

56.	जिला फोरमों के अध्यक्षों/सदस्यों के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 विषय पर तीन दिवसीय ऑनलाइन 111वां उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम	फरवरी 22-24, 2021	46	डॉ सपना चड्डा
57.	सहायक प्रशासनिक अधिकारियों (एएओ) और एलआईसी, भारत के एलओसी के लिए 101वां एडवांस टाइम मैनेजमेंट इन न्यू नॉर्मल विषय पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	फरवरी 24-26, 2021	34	डॉ कुसुम लता डॉ साकेत बिहारी
58.	6वां जेडसीएच ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम (एनसीएच द्वारा प्रायोजित)	मार्च 1-5, 2021	39	प्रो. सुरेश मिश्रा डॉ ममता पठानिया सुश्री दीपिका सुर
59.	भारतीय डाक सेवा (आईपीओएस) के प्रशिक्षुओं के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पर तीन दिवसीय उन्मुख कार्यक्रम	मार्च 3-5, 2021	14	प्रो. सुरेश मिश्रा डॉ ममता पठानिया
60.	“गैर-वित्तीय पृष्ठभूमि वाले नेतृत्व के लिए वित्त” ई-आईटीईसी विषय पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	मार्च 8-12, 2021	40	डॉ पवन के. तनेजा डॉ रोमा देबनाथ मित्रा
61.	“डेवलेपमेंट अँक लीडरशिप क्वालिटी इन न्यू नॉर्मल” (एलआईसी) विषय पर तीन दिवसीय ऑनलाइन टीपी	मार्च 10-12, 2021	35	डॉ कुसुम लता डॉ साकेत बिहारी
62.	लॉ कॉलेज चैनर्सी (प्रो. सुब्रामणियम) (सीसीएस द्वारा प्रायोजित)	मार्च 10, 2021	63	प्रो. सुरेश मिश्रा डॉ सपना चड्डा
63.	वैश्विक उपभोक्ता अधिकार दिवस का आयोजन	मार्च 15, 2021	369	प्रो. सुरेश मिश्रा डॉ सपना चड्डा
64.	जिला फोरमों (आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना) के अध्यक्षों/सदस्यों के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 विषय पर तीन दिवसीय ऑनलाइन 112वां उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम	मार्च 22-24, 2021	70	प्रो. सुरेश मिश्रा डॉ सपना चड्डा
65.	भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार	मार्च 22-26, 2021	25	डॉ रोमा देबनाथ मित्रा डॉ पवन तनेजा
66.	लॉ कॉलेज चैनर्सी (प्रो. सुब्रामणियम) (सीसीएस द्वारा प्रायोजित)	मार्च 26, 2021	460	डॉ सपना चड्डा
			8353	

क्रम संख्या	वेबिनार का विषय	तिथि	वेबिनार समन्वयक
1.	कोविड-19 के बाद शासन सुधार	14 मई 2020	प्रो. गीतांजलि नटराज
2.	भारत में कृषि बाजारों में सुधार	18 मई 2020	प्रो. अशोक विशनदास
3.	कोविड-19 महामारी के दौरान भावनात्मक लचीलता निर्माण में नेतृत्व भूमिका	20 मई 2020	डॉ नीतू जैन
4.	कोविड-19: उपभोक्ता संरक्षण के लिए उभरती चुनौतियां	26 मई 2020	प्रो. सुरेश मिश्रा
5.	कोरोना-संकट के दौरान भारत में स्थानीय सरकारों की उभरती भूमिका	27 मई 2020	डॉ वी.एन. आलोक
6.	कोविड-19: द फ्लेक्सिबिलिटी स्टिग्मा एंड जेंडर इक्वेलिटी	29 मई 2020	डॉ नूपुर तिवारी
7.	महामारी-बाद की अवधि में शासन का डिजीटल रूपांतरण	जून 9, 2020	डॉ चारू मल्होत्रा
8.	कोविड-19 के दुष्परिणाम में लोक सेवा का वितरण	जून 10, 2020	डॉ सचिन चौधरी
9.	शहरी शासन और अवसंरचनात्मक ढांचे के लिए न्यू नॉर्मल	जून 15, 2020	प्रो. के.के. पांडेय
10.	समावेशी शासन: कोविड बाद-चुनौतियां	जून 18, 2020	प्रो. सी. शीला रेड्डी
11.	साइबर सिक्योरिटी: सोशल इंजीनियरिंग इन द टाइम ऑफ सोशल डिस्ट्रेसिंग	जून 24, 2020	डॉ सुरभि पांडेय
12.	नदी आर्द्धभूमि लिंकेज़: सतत जल प्रबन्धन और गंगा बेसिन के कायाकल्प के लिए प्रकृति आधारित दृष्टिकोण	जुलाई 3, 2020	प्रो. वी.के. शर्मा
13.	कोविड 19: मीडिया और उपभोक्ता सशक्तिकरण	जुलाई 7, 2020	डॉ ममता पठानिया
14.	भारत में फर्टिलाइजर का रूपांतरण	जुलाई 8, 2020	प्रो. अशोक विशनदास
15.	पैनडेमिक रेसिलिएंट मेट्रो सिटीज	जुलाई 16, 2020	डॉ कुसुम लता
16.	समकालीन भारत में प्रवास और रोजगार सूजन	जुलाई 22, 2020	डॉ गदाधार मोहपात्रा
17.	कोविड-19 महामारी के दौरान कचरा प्रबन्धन	जुलाई 27, 2020	डॉ अमित कुमार सिंह
18.	रि-बिल्डिंग एंड रि-क्रिएटिंग जॉब इन न्यू नॉर्मल	जुलाई 29, 2020	डॉ साकेत बिहारी
19.	“ई-कॉर्मस: रेजीलिएंस स्ट्रेटिजीस् इन न्यू नॉर्मल”	अगस्त 4, 2020	डॉ सपना चड्डा
20.	“भारत में राष्ट्रीय सांख्यकीय प्रणाली”	अगस्त 6, 2020	प्रो. अशोक विशनदास
21.	“किसान कल्याण और कृषि के लिए नई पहल”	अगस्त 10, 2020	प्रो. अशोक विशनदास
22.	“तनाव प्रबन्धन और बढ़ती उत्पादकता”	अगस्त 14, 2020	डॉ नूपुर तिवारी
23.	“जलवायु परिवर्तनशीलता और परिवर्तन-भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए चुनौतियां”	अगस्त 20, 2020	डॉ श्यामली सिंह
24.	सामरिक और परोपकारी सीएसआर: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए महामारी के बाद की चुनौतियां और अवसर	सितम्बर 2, 2020	डॉ रोमा देबनाथ मित्रा

25.	आपदा जोखिम न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दृष्टिकोण	सितम्बर 28, 2020	प्रो. वी.के. शर्मा डॉ श्यामली सिंह
26.	आरटीआई अधिनियम-मुद्दे और चुनौतियां	अक्टूबर 1, 2020	प्रो. अशोक विशनदास डॉ सपना चड्डा
27.	कोविड-बाद परिदृश्य-भारत में स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	अक्टूबर 13, 2020	डॉ पवन तनेजा
28.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) का अवलोकन-विनिवेश और प्रदर्शन मूल्यांकन	26 अक्टूबर, 2020	डॉ सुरभि पांडेय
29.	भारत का परमाणु सिद्धांतः समकालीन संदर्भ	10 नवम्बर, 2020	डॉ मनन द्विवेदी
30.	‘नैतिकता और शासन’ विषय पर पहला स्वर्गीय डॉ यू. सी. अग्रवाल मेमोरियल व्याख्यान	नवम्बर 19, 2020	प्रो.सुरेश मिश्रा
31.	उत्तम केस अध्ययन विकास के तौर-तरीकों पर अंतर्दृष्टि	18 नवम्बर, 2020	प्रो. सी. शीला रेड्डी
32.	राष्ट्रीय सुरक्षा संवाद	नवम्बर 25, 2020	डॉ सुरभि पांडेय
33.	“संविधान निर्माण पर डॉ अम्बेडकर के विचार”	26 नवम्बर, 2020	प्रो. सी. शीला रेड्डी
34.	“भारत के संघवाद के बदलते स्वरूपः राजनीति, शासन और इससे परे” विषय पर 6वां डॉ राकेश हूजा मेमोरियल व्याख्यान	23 दिसम्बर, 2020	प्रो. सी. शीला रेड्डी
35.	भारत की एक ईस्ट नीतिः क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी और ट्रांस-पेसिफिक भागीदारी के बीच चुनाव (सोमवार)	28 दिसम्बर, 2020	डॉ मनन द्विवेदी
36.	“ब्रेकिंग द ग्लास सिलिंग इन पीएसयू'जः चैलेंज एंड इन्टरवेंशन्स” विषय पर सातवां प्रोफेसर एस.सरोज मेमोरियल व्याख्यान	30 दिसम्बर, 2020	डॉ नीतू जैन
37.	आत्मनिर्भर होने के मार्ग के रूप में सामाजिक वानिकी	13 जनवरी, 2021	डॉ श्यामली सिंह
38.	राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और विस्तार योजना	27 जनवरी, 2021	डॉ नूपुर तिवारी
39.	मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत फ्रेसिंग	29 जनवरी, 2021	प्रो. अशोक विशनदास डॉ अमित कुमार सिंह
40.	पुनरुद्धार और रूपांतरण (अमृत) के लिए अटल मिशन	10 फरवरी, 2021	प्रो. सुरेश मिश्रा
41.	अटल पेंशन योजना	24 फरवरी, 2021	प्रो. अशोक विशनदास
42.	भारत का ऊर्जा सम्मिलिकरण और विदेश नीति के लिए निहितार्थ	25 फरवरी, 2021	डॉ मनन द्विवेदी
43.	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	10 मार्च, 2021	डॉ नीतू जैन
44.	प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत)	24 मार्च, 2021	डॉ साकेत बिहारी
45.	लोक प्रशासन की प्रासंगिकता पर व्याख्यान	26 मार्च, 2021	डॉ आर.एस. शर्मा सीईओ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण

अनुलग्नक च. 3

शाखा की गतिविधियाँ (2020-21)

असम

वेबिनार/सेमिनार/सम्मेलन

- “असम के आंतकवाद” विषय पर एक वार्ता (अक्टूबर 14, 2020)
- महामारी प्रबन्धन विषय पर चर्चा के लिए प्रस्तावना सम्मेलन (अक्टूबर 25, 2020)
- “आत्मनिर्भर बनने के एक तरीके के रूप में सामाजिक वानिकी” विषय पर चर्चा के लिए भा.लो.प्र.सं. द्वारा समन्वित राष्ट्रीय वेबिनार (जनवरी 13, 2021)
- “वित्तीय निरीक्षण और संबंधित मामलों” पर एक चर्चा (मार्च 26, 2021)

अनुसंधान अध्ययन

वर्ष 1926 की अवधि (यांदाबू की संधि) (मेघालय का निर्माण) को समायोजित करते हुए अविभाजित असम के प्रशासनिक इतिहास को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय शाखा द्वारा किए गए अनुसंधान परियोजना को पूरा करने का काम मुद्रण की प्रक्रिया में है, जो शीघ्र ही जारी होगा।

बिहार

वेबिनार/सेमिनार/सम्मेलन

- “कोविड-19, प्रशासन और राजनीति” पर राष्ट्रीय वेबिनार (मई 14, 2020)
- कोविड-19 पर राष्ट्रीय वेबिनार: प्रकृति और पर्यावरण (विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित), (जून 5, 2020)
- “महामारी का प्रबन्धन” पर एजीएम और प्रस्तावना सेमिनार (अक्टूबर 29, 2020)
- “राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और उन्नयन

योजना: नीति प्रक्रिया पर राष्ट्रीय वेबिनार (जनवरी 27, 2021)

व्याख्यान बैठक

- “समकालीन भारतीय परिदृश्य में महिलाएं” विषय पर एक पैनल चर्चा (अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर), (मार्च 15, 2021)
- “राजनीतिक प्रशासन: मुद्रे एवं चुनौतियाँ” विषय पर एक चर्चा (मार्च 26, 2021)

व्याख्यान अध्ययन

“कोविड-19, नीति प्रक्रिया और प्रवासी मजदूर: बिहार के विशेष संदर्भ के साथ।

प्रकाशन

- लोक प्रशासन की बिहार पत्रिका खंड XVII, संख्या 1, जनवरी-जून, 2020
- लोक प्रशासन की बिहार पत्रिका खंड XVII, संख्या प्रस्तावना नवम्बर, 2020
- लोक प्रशासन की बिहार पत्रिका खंड XVII, संख्या 2, जुलाई-दिसम्बर, 2020

अन्य गतिविधियाँ

- शाखा की वेबसाइट www.iipabiharbranch.org का रखरखाव और विकास
- इंक्यूबेशन सेन्टरों और सृजनात्मक शिक्षा पर अध्ययन करने के लिए प्रस्ताव पर अटल इंक्यूबेशन सेंटर, बिहार (नीति आयोग द्वारा समर्थित) के साथ चर्चा- मार्च 5, 2021

ગुजरात

वेबिनार/सेमिनार/सम्मेलन

- “अटल पेंशन योजना” विषय पर चर्चा (फरवरी 02, 2021)

- “भारत कौशल फोरम-2020” (आत्मनिर्भर भारत के लिए कौशल) विषय पर वेबिनार (सितम्बर 15, 2020)
- “कोविड-19 संकट के दौरान सरकार और लोगों के बीच सहयोग और समन्वयन” विषय पर वेबिनार (जून 29, 2020)

जम्मू और कश्मीर क्षेत्रीय शाखा

सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशालाएं/संगोष्ठियां

- “महामारी का प्रबन्धन” विषय पर संगोष्ठी सम्मेलन (अक्टूबर 23, 2020)

व्याख्यान/चर्चा

- “प्रबन्धन तनाव और कोविड-19 से मुकाबला” विषय पर वेबिनार (मई 5, 2020)
- “अगली पीढ़ी के लिए शिक्षा, शिक्षा-विज्ञान पर पुनर्विचार: कोविड-19 से शिक्षा” विषय पर एक वेबिनार पैनल चर्चा: (मई 8, 2020)
- “संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को दोबारा शुरू करना: एमएसएमई के लिए प्रोत्साहन पैकेज बढ़ाना” विषय पर 7वें श्री राम सहाय मेमोरियल व्याख्यान (जून 6, 2020)
- “साइबर सुरक्षा” विषय पर ऑनलाइन पैनल चर्चा (जुलाई 11, 2020)
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और समग्र शिक्षा और भारतीय जन प्रशासन संस्थान, क्षेत्रीय शाखा के माध्यम से जम्मू और कश्मीर में इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए रोडमैप तैयार करने के विषय पर आज ऑनलाइन पैनल चर्चा हुई थी (सितम्बर 18, 2020)
- “घर की राय में, कक्षा संबंधी शिक्षा के रूप में आभासी (वर्चुअल) मॉडल एक घटिया विकल्प है” विषय पर 19वीं वार्षिक वीरना ऐवल्ली स्मारक वाद-विवाद प्रतियोगिता (जून 6, 2020)
- आईआईपीए जेकेआरबी की 42वीं वार्षिक आम बैठक के दौरान राष्ट्रीय सुशासन केन्द्र, भारत सरकार,

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) नई दिल्ली और आईआईपीए, जम्मू और कश्मीर की क्षेत्रीय शाखा के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

- “सोशल मीडिया: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या शान्ति और सद्भावना को खतरा” विषय पर 11वें सत पॉल साहनी मेमोरियल व्याख्यान का आयोजन किया गया (मार्च 3, 2021)

प्रकाशन

- आईआईपीए जम्मू और कश्मीर क्षेत्रीय शाखा समाचार-पत्रिका खंड: XI, जुलाई, 2020 संख्या 1
- आईआईपीए जम्मू और कश्मीर क्षेत्रीय शाखा समाचार-पत्रिका खंड: XI, दिसम्बर, 2020 संख्या 2

अन्य गतिविधियां

72वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए, परिस्थिर में ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया गया था (जनवरी 26, 2021)

कर्नाटक

वेबिनार/सेमिनार/सम्मेलन

- “नागरिक हितैषी प्रशासन: उभरते मुद्दे” विषय पर वेबिनार (जुलाई 24, 2020)
- “पर्यावरण और विकास” विषय पर वेबिनार (सितम्बर 23, 2020)
- “महामारी का प्रबन्धन” विषय पर प्रस्तावना सम्मेलन (अक्टूबर 29, 2020)
- भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) की निष्पादन लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर कर्नाटक में 74वें संवैधानिक संशोधन का क्रियान्वयन: कर्नाटक सरकार: वर्ष 2020 की रिपोर्ट संख्या 2” विषय पर वेबिनार (दिसम्बर 5, 2020)
- “भारत में पुलिस सुधार” विषय पर वेबिनार (जनवरी 30, 2021)

6. “कृषिगत बाजार: समस्याएं और संभावनाएं” विषय पर वेबिनार (मार्च 18, 2021)

व्याख्यान बैठक/चर्चा

- “चीन की सिल्क रोड पहल और भारत के लिए इसका क्रियान्वयन” विषय पर वेब चर्चा (अगस्त 2, 2020)
- “लोक मामलों का इंडेक्स-2020: भारत के राज्यों में प्रशासन” विषय पर अभासी पैनल चर्चा (नवम्बर 21, 2020)
- “भारतीय प्रबन्धन और सुशासन” विषय पर वेब चर्चा (फरवरी 11, 2020)

प्रकाशन

शाखा ने अगस्त 2020 से ('कन्ड में वास्तव स्थितिपत्र' विषय पर) एक मासिक आभासी समाचार पत्रिका का शुभारंभ किया

केरल

सेमिनार/वेबिनार/सम्मेलन

- प्रस्तावना सम्मेलन (अक्टूबर 28, 2020)
- नए स्थानीय निकायों के लिए एक कार्यसूची का निर्धारण (जनवरी 20, 2021)
- केरल विधानसभा चुनाव: मतदाताओं के समक्ष मुद्रे (फरवरी 05, 2021)
- कृषि कानून और कृषि क्षेत्र में उथल-पुथल (फरवरी 15, 2021)

व्याख्यान बैठक/चर्चा

चुनावों में मनी माफिया और पेड़ माफिया (फरवरी 24, 2021)

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़

वेबिनार/सेमिनार/सम्मेलन

- महामारी की चुनौती का सामना (अक्टूबर 12, 2020)

- कोविड का दुष्परिणाम - दृष्टिकोण में परिवर्तन (फरवरी 20, 2021)

अन्य गतिविधियां

- वार्षिक आम बैठक (अक्टूबर 17, 2020)
- कार्यकारणी समिति बैठकें (फरवरी 2021 और सितम्बर 2020 और जनवरी 2021)

महाराष्ट्र

प्रशिक्षण कार्यक्रम

- सूचना का अधिकार 2005 (जनवरी 28, 2020)
- एमसीएस (अवकाश) नियम-1981 (जनवरी 29, 2020)
- एमसीएस (कार्यग्रहण अवधि) नियम-1981 (जनवरी 30, 2020)
- एमसीएस (पेंशन) नियम-1982 एनपीएस (जनवरी 31, 2010)
- सरकार में विधायी कार्य (फरवरी 3, 2020)
- तनाव प्रबन्धन (फरवरी 4, 2020)

अन्य गतिविधियां

- (क) पुस्तकालय: शाखा में सुप्रबन्धित प्रस्तकालय है जिसमें लोक प्रशासन पर विभिन्न विषयों पर 12000 पुस्तकें हैं। इस पुस्तकों में अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, प्रबन्धन, इतिहास, प्रख्यात लोगों की जीवनी और सेवा तथा रक्षा कार्मिकों द्वारा लिखित पुस्तकें भी शामिल हैं।
- (ख) निम्नलिखित विषयों पर स्वर्गीय श्री बी.जी. देशमुख वार्षिक निबन्ध प्रतियोगिता 2019-2020 का आयोजन किया गया:
- जल प्रबन्धन
 - महाराष्ट्र में क्षेत्रीय असमानता को ध्यान में रखते हुए पोषण की स्थिति
- (ग) लोक प्रशासन-2019 में नवाचार के लिए स्वर्गीय डॉ एस.एस. गडकरी मेमोरियल अवार्ड

ओडिशा

सेमिनार/वेबिनार/सम्मेलन

1. “ऑनलाइन शिक्षा” विषय पर वेबिनार (जून 2020)
2. “न्यायिक सुधार” विषय पर वेबिनार (अगस्त 2020)
3. “एन.ई.पी. 2020” विषय पर वेबिनार (सितम्बर 2020)
4. “महामारी प्रबन्धन” विषय पर वेबिनार (अक्टूबर 2020)
5. “कौशल विकास मुद्दे, चुनौतियां और अवसर” विषय पर वेबिनार (नवम्बर 2020)
6. “कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व प्रासंगिकता आज” विषय पर वेबिनार (दिसम्बर 2020)
7. सदस्यों का वार्षिक सम्मेलन (जनवरी 2021)
8. “महामारी के बाद की दुनिया में भारत” विषय पर सेमिनार (फरवरी 2021)
9. “भारत में आपराधिक न्याय सुधार” विषय पर सेमिनार (मार्च 2021)

राजस्थान

वेबिनार/सेमिनार/सम्मेलन

महामारी प्रबन्धन पर क्षेत्रीय सेमिनार (अक्टूबर 25, 202)

व्याख्यान/बैठकें/चर्चाएं

1. भारतीय गणतंत्र के सुदृढ़ीकरण विषय पर संवादात्मक सत्र (जनवरी 26, 2021)
2. गांधी से हम क्या सीख सकते हैं? (जनवरी 31, 2021)
3. केन्द्रीय बजट 2021-2022 की आत्मा
4. सफल नेताओं के गुण (फरवरी 7, 2021)
5. खुशहाली का रहस्य-संवादात्मक बैठक (फरवरी 14, 2021)

6. खुशहाली के आध्यात्मिक नियम: ऋग्वेद से सीखे सबक (फरवरी 21, 2021)
7. खुशहाली और सफलता के लिए तनाव प्रबन्धन (मार्च 1, 2021)
8. रचनात्मकता और नवाचार (मार्च 7, 2021)
9. कबीर: व्यक्तित्व और योगदान-वीडीएस मेमारियल लेक्चर (मार्च 15, 2021)
10. कठिन परिश्रम से सफलता (मार्च 15, 2021)
11. बहुआयामी आसूचना (इंटेलिजेंस) (मार्च 28, 2021)

तमिलनाडु

सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशालाएं

1. उपभोक्ता संरक्षण और जागरूकता विषय पर दो-दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार (अप्रैल 22 और 23, 2019)
2. “सुशासन और संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्य” विषय पर प्रस्तावना सेमिनार (सितम्बर 21, 2019)
3. लोक प्रशासन के स्नातकोत्तर और अनुसंधान विभाग के सहयोग से “पुलिस और सोशल मीडिया” विषय पर सेमिनार (फरवरी 1, 2020)
4. “नेशनल एकता दिवस” विषय पर कार्यशाला (अक्टूबर 3, 2020)
5. “नेशनल एकता दिवस” -संवैधानिक दिवस/कानून दिवस 2019” विषय पर कार्यशाला (नवम्बर 26, 2019)

व्याख्यान/बैठकें/चर्चाएं

“जल प्रबन्धन” विषय पर व्याख्यान (जुलाई 20, 2019)

प्रकाशन

1. समाचार पत्रिका- नया प्रशासन - जून-2019 में समाप्त हो रही तिमाही के लिए
2. समाचार पत्रिका- नया प्रशासन - सितम्बर-2019 में समाप्त हो रही तिमाही के लिए

अन्य गतिविधियां

1. शासन और लोक प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में जन भागीदारी पर व्याख्यानों की एक शृंखला का आयोजन किया गया और उपर्युक्त विषय पर नियत समय पर एक पुस्तक लाने का प्रस्ताव है।
2. शाखा 2015 से लगातार संवैधानिक दिवस मना रही है। इस दिन, बड़ी संख्या में कार्यशालाओं, लघु व्याख्यानों और आकर्षक प्रश्नोत्तरी का आयोजन उपनगरीय विश्वविद्यालयों और शहरों में किया जाता है।
3. आकर्षक प्रश्नोत्तरी में 30 मिनट की अवधि में ही उसी स्थान पर विद्यार्थियों को 20 पुरस्कार दिए गए।
4. संविधान का महत्व विषय पर 20 मिनट की अवधि के लिए लघु व्याख्यान दिया गया।
5. आईआईपीए-टीएनआरबी, चेन्नई के वार्षिक आम निकाय का आयोजन 15.09.2019 को किया गया और इसमें निम्नलिखित नए केन्द्रों के सृजन का संकल्प लिया गया है:
 - महिला सशक्तिकरण केन्द्र
 - गरीबी उन्मूलन केन्द्र
 - पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन केन्द्र
 - प्लास्टिक के उपयोग और फेंके गए प्लास्टिक का उन्मूलन केन्द्र
 - समाज सेवा केन्द्र और जन जागरूकता तथा भागीदारी केन्द्र

तेलंगाना और ए.पी. क्षेत्रीय शाखा

आयोजित सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशालाएं

1. “राजस्व प्रशासन - भूमि स्वामित्व और अधिकारों पर विशेष फोकस के साथ” विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी (जुलाई 15, 2019)
2. “सुशासन और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य” विषय पर संगोष्ठी सम्मेलन (अक्टूबर 10, 2019)
3. “उच्च शिक्षा में ऑनलाइन पहल” पर संगोष्ठी (मार्च 20, 2019)

व्याख्यान/बैठकें/चर्चाएं

1. शाखा के चेयरमैन श्री एम गोपालकृष्णन, आईएएस (सेवानिवृत) द्वारा मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज (एमईएस) के वर्ग-क अधिकारी (परिवीक्षाधीन) के लिए प्रथम फाउंडेशन कोर्स (एफसी) के प्रतिभागियों को “प्रशासन में नैतिकता और मूल्य” विषय पर व्याख्यान दिया गया (अप्रैल 24, 2019)
2. चेयरमैन को हैदराबाद प्रबन्धन संगठन द्वारा “मेस्पर ऑफ द ईयर अवार्ड” दिया गया। यह पुरस्कार भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा दिया गया (जून 8, 2019)
3. शाखा के चेयरमैन श्री एम. गोपालकृष्णा द्वारा आन्ध्र महिला सभा में दुर्गाबाई देशमुख मेमोरियल-2019 में “हेल्पिंग दोज़ हू केनोट हेल्प देमसेल्वज रोल ऑफ एनजीओ” विषय पर व्याख्यान दिया (जुलाई 15, 2019)
4. शाखा के चेयरमैन श्री एम. गोपालकृष्णा ने प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज में “कॉर्पोरेट शासन” विषय पर व्याख्यान दिया (अगस्त 20, 2019)
5. शाखा के अध्यक्ष श्री एम. गोपालकृष्णा ने भारत के प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम-वित्तीय प्रणाली प्रबन्धन और सरकार में जवाबदेही के प्रतिभागियों के लिए “नागरिक-केन्द्रित शासन” पर एक व्याख्यान दिया (सितम्बर 26, 2019)
6. शाखा के अध्यक्ष श्री एम. गोपालकृष्णा ने सिकन्दराबाद में एनटीपीसी कर्मचारियों को सतर्कता सप्ताह विषय पर व्याख्यान दिया (अक्टूबर 28, 2019)

उत्तर प्रदेश

व्याख्यान/बैठकें/चर्चाएं

1. शाखा के इतिहास को तैयार करने पर चर्चा (फरवरी 15, 2021)
2. उत्तर प्रदेश शाखा की गतिविधियों पर चर्चा के लिए आईआईपीए मुख्यालय के साथ ऑनलाइन बैठक (जनवरी 31, 2021)

3. कार्यकारिणी और वार्षिक आम बैठक (ऑनलाइन) (मार्च 23, 2021)

प्रकाशन

1. तिमासिक समाचार पत्रिका “डायनामिक एडमिनिस्ट्रेशन” का दिसम्बर 2020 से अगस्त 2021 तक प्रकाशन
2. मुख्यालय की वेबसाइट में शामिल करने के लिए आईआईपीए, उत्तर प्रदेश का इतिहास लिखा गया था।
3. श्री आर.सी. त्रिपाठी की “इंडिया (हेरिटेज कलचर पॉलिसी (सेलेक्टेड एस्से एंड स्पिचेज़)” नामक पुस्तक इस बात को दर्शाती है कि भारतीय इतिहास, प्राचीन संस्कृति और विरासत को कैसे भावी पीढ़ी को सौंप दिया जाता है और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए क्या किया जा सकता है। यह लोक प्रशासन की ताकत और कमज़ोरियों को उजागर करती है और इसे कैसे सुधारें, इसका भी वर्णन करता है।
4. श्री सुधन चंद्र चंदोला “कॉम्बैटिंग एवरलास्टिंग ट्रेजेडी-यूनाइटेड नेशंस ऑफ इंडिया उपमहाद्वीप” नामक पुस्तक में इस बात का उल्लेख किया गया है कि कैसे एशिया के महाद्वीप अपने नागरिकों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर राशि का निवेश करने के बजाय अपने पड़ोसियों से खुद को बचाने के लिए अत्यधिक राशि को खर्च करते हैं। लेखक एशिया के देशों को यूरोपीय संघ की तरह चौतरफा लाभ (विन-विन सिचूएशन) की स्थिति को अपनाने की सलाह देता है।

अन्य गतिविधियां

9वीं और 12वीं कक्षा के लिए एक निबन्ध प्रतियोगिता- वार्षिक निबन्ध प्रतियोगिता, 2020 का आयोजन किया गया था। निबन्धों के विषय (1) कोविड और जन स्वास्थ्य प्रणाली और (2) प्रवास और रोजगार सृजन थे।

स्थानीय शाखाएं

औरंगाबाद

सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशालाएं

1. “उन्नत गांव-उन्नत भारत -सर्वाच सहभाग-सर्वाच विकास” (उन्नत गांव-उन्नत भारत-सभी की भागीदारी-सभी का विकास) विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला (फरवरी 13, 2020)
2. प्रतियोगिता परीक्षा मार्गदर्शन विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला

बदायूं

सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशालाएं

1. “महिला सशक्तिकरण” के लिए कार्यशाला (मार्च 8, 2021)
2. जरूरतमंद गरीबों के लिए किराना समानों का वितरण (मई और जून 2020)

व्याख्यान/बैठकें/चर्चाएं

1. “कोविड-19 महामारी के विरु” लोगों में जागरूकता लाना” विषय पर आभासी व्याख्यान/ बैठकें (जुलाई, अगस्त, सितम्बर 2020)

प्रशिक्षण कार्यक्रम

1. ग्राम बुरा भद्रोल प्रखंड कादर चौक पर जड़ी-बूटी (हर्बल) फसलों के लिए प्रशिक्षण (मई 2020)
2. ग्राम बुटला दौलतपुर ब्लॉक उज्जैनी में जैविक उर्वरक के लिए प्रशिक्षण (फरवरी 2021)

बरेली

सेमिनार/सम्मेलन

1. “भारत में राष्ट्रीय गौरव बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा की भूमिका” विषय पर शिक्षक दिवस कार्यक्रम (सितम्बर 5, 2019)

- “राष्ट्रीय गौरव और भारत के लोग” विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन (सितम्बर 15, 2019)
- “भारत के संदर्भ में मानवाधिकारों के उभरते रुद्धान” विषय पर मानवाधिकार दिवस (दिसम्बर 10, 2019)
- बजट 2020 पर सम्मेलन (फरवरी 4, 2020)

बर्दवान

सेमिनार

“महामारी का प्रबन्धन” विषय पर प्रस्तावना सेमिनार (अक्टूबर 21, 2020)

व्याख्यान बैठक

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में नवीनतम संशोधन (मार्च 15, 2021)

प्रशिक्षण कार्यक्रम

- सूचना का अधिकार अधिनियम (जनवरी 23, 2021)
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की मुख्य विशेषताएं (जनवरी 23, 2021)

अन्य गतिविधियां

नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में रंगांग जुलूस में स्थानीय शाखा सदस्यों ने भाग लिया (जनवरी 23, 2021)

धारवाड़

सेमिनार/वेबिनार/सम्मेलन

- कर्नाटक में कृषि क्षेत्रों में हाल में हुए सुधारों पर प्रशासन के मुद्दे (अक्टूबर 17, 2020)
- महामारी का प्रबन्धन विषय पर प्रस्तावना सेमिनार (अक्टूबर 28, 2020)

हावड़ा

सम्मेलन/कार्यशाला

- कृषि क्षेत्र में जल प्रबन्धन (जुलाई 27, 2019)

- प्लास्टिक के इस्तेमाल से पर्यावरण को नुकसान (सितम्बर 11, 2019)
- सुशासन पर प्रस्तावना सम्मेलन (सितम्बर 17, 2019)
- “मानवाधिकार संरक्षण के लिए प्रणाली में सुधार” विषय पर विश्व मानव अधिकार (दिसम्बर 10, 2019)

व्याख्यान बैठक

- वार्षिक आम बैठक (जून 11, 2019)
- कार्यकारिणी समिति बैठक (नवम्बर 5, 2019 और जनवरी 11, 2010)
- अनमार्केटेड (अछूते) भारत की मार्केटिंग द्वारा समग्र विकास (फरवरी 10, 2020)

मदुरै

वेबिनार/सेमिनार/सम्मेलन

अभासी माध्यम से “महामारी प्रबन्धन” विषय पर प्रस्तावना सम्मेलन (अक्टूबर 29, 2020)

व्याख्यान/बैठकें/चर्चाएं

- “केन्द्रीय बजट 2021 का प्रभाव” और “प्रेम-जीवन का एक टॉनिक” विषय पर मिलन बैठक” (फरवरी 14, 2021)
- “आईआईपीए मुख्यालय दिल्ली और भारत में सभी शाखा की वर्तमान स्थिति” विषय पर तमिलनाडु में आईआईपीए की सभी शाखा की मिलन बैठक (मार्च 28, 2021)

मुज़फ्फरपुर

सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशाला

- सुशासन और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य विषय पर प्रस्तावना सम्मेलन (अक्टूबर 11, 2019)
- उपभोक्ता अध्ययन केन्द्र, आईआईपीए नई दिल्ली के सहयोग और उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,

भारत सरकार द्वारा प्रायोजित “उपभोक्ता संरक्षण और सशक्तिकरण” विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार (फरवरी 17-18, 2020)

पाटलीपुत्र

सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशालाएं

1. आंतकवाद और लोकतंत्र-एक वैश्विक खतरा” विषय पर सेमिनार (अप्रैल 28, 2019)
2. “भारतीय समाज में लैंगिक समानता-यह कहां खड़ी है?” विषय पर गोलमेज सम्मेलन (जून 23, 2019)
3. “क्या संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है” विषय पर सेमिनार/ गोलमेज सम्मेलन (अगस्त 27, 2019)

व्याख्यान/बैठकें/चर्चाएं

1. “मानव संसाधन-क्या यह भारत के विकास के लिए एक परिसंपत्ति है” विषय पर चर्चा (सितम्बर 22, 2019)
2. “सतत विकास और सुशासन - संभावनाएं और बाधाएं” विषय पर गोलमेज चर्चा (अक्टूबर 13, 2019)
3. ग्लोबल वॉर्मिंग-चर्चा, (मार्च 08, 2020)

पुडुचेरी

सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशालाएं

1. पुडुचेरी सरकार के कोविड-19 के दिशानिर्देशों के अनुसार, अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के दौरान आईआईपीए पुडुचेरी की स्थानीय शाखा द्वारा संचालित पांच हेल्पलाइनों के माध्यम से लोगों को कोविड-19 अस्पतालों, बिस्तरों, चिकित्सा और कोविड-19 से प्रभावित लोगों के बारे में कोविड संबंधी जानकारी

व्याख्यान, बैठकें, चर्चाएं

1. महामारी प्रबन्धन (अक्टूबर 24, 2020)

प्रशिक्षण कार्यक्रम

1. हेल्पलाइन आईआईपीए के माध्यम से पुडुचेरी स्थानीय शाखा ने मेडिकल के छात्रों और आम जनता के लिए कोविड-19 के बारे में नैदानिक मनोविज्ञान का आयोजन किया (अप्रैल 2020 से मार्च 2021)
2. ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों के बीच कोविड-19 टीकाकरण जागरूकता पैदा करना (जनवरी 2021 से मार्च 2021)

अन्य गतिविधियां

कोविड-19 के बारे में विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए ऑनलाइन प्रेरक प्रशिक्षण कार्यक्रम।

तिरुपति

सेमिनार

1. विश्व पर्यावरण दिवस (जून 6, 2020)
2. महामारी प्रबन्धन पर प्रस्तावना सम्मेलन (अक्टूबर 21, 2020)
3. विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस-2021 (प्लास्टिक के प्रदूषण से निपटना) (मार्च 15, 2021)

व्याख्यान बैठक

1. महात्मा गांधी के 151वें जयंती दिवस के अवसर पर व्याख्यान कार्यक्रम (अक्टूबर 2, 2020)
2. केन्द्रीय बजट 2021-22: किसान कल्याण और कॉर्पोरेट खेती का भविष्य विषय पर बहस (मार्च 6, 2021)

प्रकाशन

1. सोनिया गांधी पर पुस्तक का विमोचन (दिसम्बर 19, 2020)
2. भारत में डिजीटलीकरण और आर्थिक सुधारों के प्रसार पर पुस्तक का विमोचन (फरवरी 16, 2021)

तिरुपत्तुर

सेमिनार

- “जल संकट और जल प्रबन्धन विषय पर सेमिनार” (जुलाई 24, 2019)
- “सुशासन और संयुक्त राष्ट्र के सतत लक्ष्य” विषय पर प्रस्तावना सम्मेलन (सितम्बर 23, 2019)

व्याख्यान बैठक

शिक्षा ऋण और छात्रवृत्ति विषय पर जागरूकता (जनवरी 01, 2020)

अन्य गतिविधियां

- एल.एस. अस्पताल में “बोन मिनरल डेंसिटी” विषय पर मुफ्त चिकित्सा कैंप (मई 22, 2019)
- एल.एस. अस्पताल में “बोन मेरौ डेंसिटी” विषय पर मुफ्त चिकित्सा कैंप (नवम्बर 26, 2019)

वडोदरा

सेमिनार

- वडोदरा में आतिशबाजी के कारण “पर्यावरण संरक्षण-शहरी पारिस्थितिकी तंत्र (सीओ2) के बारे में जागरूकता” विषय पर सेमिनार (नवम्बर 1, 2019)
- शुक्रवार फरवरी 7, 2020 को वडोदरा-गुजरात में “विरासत और उसके सांस्कृतिक मूल्यांकन की रक्षा करें” विषय पर सेमिनार। सेमिनार का उद्घाटन श्रीमंत महाराज समरजीत सिंह राव गायकवाड़ी ने किया (फरवरी 7, 2020)

व्याख्यान बैठक

कार्यकारी समिति बैठक (4 मई 2019 और 7 फरवरी 2020)

व्याख्यान बैठक/चर्चा

- वडोदरा चैप्टर की कार्यकारी समिति से महत्वपूर्ण सदस्यों और महाराजा सियाजीराव विश्वविद्यालय के पदेन संकाय अध्यक्ष की एक समिति की नियुक्ति।

अन्य गतिविधियां

गुजरात के 33 जिलों में से नौ जिले रेड जोन में थे और वडोदरा उनमें से एक था। आईआईपीए वडोदरा शाखा की ओर से रोगी और उनके परिजनों को फल और खाने योग्य सामग्री वितरित करने के लिए सरकारी अस्पताल के बाल चिकित्सा अनुभाग का दौरा किया। राज्य में अचानक हुई लॉकडाउन की घोषणा के कारण वडोदरा में फंसे बाहरी श्रमिकों के लिए तीन दिनों के लिए आश्रय की भी व्यवस्था की गई थी।

विल्लुपुरम

वेबिनार/सेमिनार/सम्मेलन

विल्लुपुरम में महिलाओं के लिए डॉ एम.जी.आर गवर्नेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज के साथ महामारी प्रबन्धन पर संयुक्त रूप से एक प्रस्तावना सेमिनार का आयोजन किया (अक्टूबर 28, 2020)

व्याख्यान/बैठकें/चर्चाएं

कृषि संबंध क्षेत्र में महिला स्वयं सहायता समूहों और किसान उत्पादक संगठन की भूमिका (20 नवम्बर, 2020)

प्रशिक्षण कार्यक्रम

महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों को बीज उत्पादन तकनीक पर प्रशिक्षण (दिसम्बर 01, 2020)

प्रकाशन

कुट्डालोर शाखा इकाई के साथ संयुक्त रूप से “सतत कृषि” पर पुस्तिकाएं तैयार की जा रही हैं।

विशाखपत्तनम

सेमिनार

- स्थापना दिवस (जुलाई 10, 2019)
- “सुशासन और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य” विषय पर प्रस्तावना सम्मेलन (अक्टूबर 15, 2019)।

अनुलग्नक च. 3.1

1. क्षेत्रीय और स्थानीय शाखा के अध्यक्ष और मानद सचिवों की सूची
2. आईआईपीए ने अपनी वेबसाइट पर क्षेत्रीय/स्थानीय शाखा के लिए एक अलग पृष्ठ तैयार किया है। एक शाखा के अध्यक्ष और मानद सचिव का ब्योरा इन वेब-पृष्ठों पर उपलब्ध है। ये ब्यौरे निम्नलिखित लिंक से प्राप्त किए जा सकते हैं:

<https://www.iipa.org.in/cms/public/branch/2>

अनुलग्नक च. 3.2

सदस्यों की सूची क्षेत्रीय और स्थानीय शाखा के साथ संलग्न है

31-03-2021 तक

क्रम सं.	क्षेत्रीय	स्थानीय	सक्रिय सदस्य		स्थगन में सदस्य		कुल सदस्यता		कुल (क+ख)
			वार्षिक	आजीवन	वार्षिक	आजीवन	वार्षिक (क)	आजीवन (ख)	
1.	असम			43	1	156	1	199	200
2.	बिहार			167		354		521	521
3.		पाटलीपुत्र		9		29		38	38
4.		मुज़फ्फरपुर		24		14		38	38
5.	दिल्ली			410		1430		1840	1840
6.	गोवा (पश्चिमी तट)		1	9		33	1	42	43
7.	गुजरात			23		112		135	135
8.		वडोदरा		11	1	35	1	46	47
9.		वल्लभ विद्यानगर		5		31		36	36
10.	हरियाणा			76		162		238	238
11.	हिमाचल प्रदेश			39		54		93	93
12.	जम्मू और कश्मीर		1	157	1	197	2	354	356
13.	झारखण्ड			53		127		180	180
14.		जमशेदपुर		3		13		16	16
15.	कर्नाटक		2	93		204	2	297	299
16.		गुलबर्गा		19		21		40	40
17.		धारवाड़		13		10		23	23
18.		मैसूर		8		24		32	32
19.	केरल		1	84	1	121	2	205	207
20.	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)			98	1	166	1	264	265
21.		इंदौर		17		23		40	40

22.		जबलपुर		14		48		62	62
23.	महाराष्ट्र			165		594		759	759
24.		औरंगाबाद		27		30		57	57
25.		नागपुर	1	38		55	1	93	94
26.		नासिक		0		20		20	20
27.		पुणे	1	41	1	120	2	161	163
28.		सांगली		9		9		18	18
29.	मणिपुर			20		40		60	60
30.	मेघालय			14		65		79	79
31.	मिजोरम			25		54		79	79
32.	ओडिशा			81		158		239	239
33.		कटक		19		17		36	36
34.	ਪੰਜਾਬ ਏਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ			68	1	209	1	277	278
35.		ਪਟਿਆਲਾ		17		20		37	37
36.	ਰਾਜਸਥਾਨ		1	105		222	1	327	328
37.		ਸਿਰੋਹੀ		4		4		8	8
38.	ਤਮਿਲਨਾਡੁ			229		441		670	670
39.		ਕੋਯੰਬਟੂਰ		9		22		31	31
40.		ਕੁਝਲੌਰ		35		9		44	44
41.		ਡਿੰਡੀਗੁਲ		7		15		22	22
42.		ਮਦੂਰੈ		50		67		117	117
43.		ਸੈਦਾਪੇਟ		5		18		23	23
44.		ਸਲੇਮ		3		15		18	18
45.		ਤੰਜਾਵੁਰ		6		23		29	29
46.		ਤਿਰੁਨੇਲਵੇਲੀ		9		1		20	20
47.		ਤਿਰੁਪ੍ਤੂਰ		16		3		19	19
48.		ਤਿਰੁਚਿਰਾਪਲਲੀ		6		19		25	25
49.		ਵੇਲ਼ਲੋਰ		18		22		40	40
50.		ਵਿਲੁਪੁਰਮ		17		3		20	20
51.		ਵਿਰੁਢਨਗਰ		6		10		16	16
52.		ਪੁਦੁਚੇਰੀ		21		30		51	51
53.	ਤੇਲਾਂਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਨੁਭ ਪ੍ਰਦੇਸ਼			193	1	332	1	525	526

54.		करीमनगर		9		19		28	28
55.		तिरुपति		36		34		70	70
56.		विशाखापत्तनम		32		53		85	85
57.		वारंगल		41		47		88	88
58.	उत्तराखण्ड			56		197		250	250
59.	उत्तर प्रदेश			266	2	532	2	798	800
60.		आगरा		11		23		34	34
61.		बरेली		17		23		40	40
62.		बदायूँ		47		56		103	103
63.		मेरठ		20		36		56	56
64.		कानपुर		52		21		73	73
65.	पश्चिम बंगाल		2	97		240	2	337	339
66.		बर्द्दगान		14		6		20	20
67.		हावड़ा		13		6		19	19
	अन्य राज्य*			11		45		56	56
	विदेश*			11		108		119	119
	कुल		10	3371	10	7464	20	10835	10855

* कोई आईआईपीए शाखा नहीं

अनुलग्नक च. 4
शैक्षणिक केंद्र (2020-21)

शहरी अध्ययन केन्द्र	उपभोक्ता अध्ययन केन्द्र
1. प्रो. के.के. पांडेय-समन्वयक 2. डॉ कुसुम लता 3. डॉ सचिन चौधरी 4. डॉ अमित कुमार सिंह	1. प्रो. सुरेश मिश्रा-समन्वयक 2. डॉ सपना चड्डा 3. डॉ ममता पठानिया
आर्थिक विकास और प्रबन्धन अध्ययन केन्द्र	जनजातीय अनुसंधान और अन्वेषण केन्द्र
1. डॉ वी.एन. आलोक- समन्वयक 2. डॉ रोमा देबनाथ 3. डॉ पवन कुमार तनेजा	1. डॉ नुपुर तिवारी-समन्वयक 2. डॉ साकेत बिहारी 3. डॉ गदाधर मोहपात्र
सार्वजनिक नीति के लिए डॉ अम्बेडकर केन्द्र और सामाजिक न्याय	जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और सूखा प्रशासन केन्द्र
1. प्रो.सी शीला रेड्डी-समन्वयक 2. डॉ नीतू जैन	1. डॉ श्यामली सिंह-समन्वयक 2. प्रो. वी.के. शर्मा
सुशासन केन्द्र	ई-शासन केन्द्र
1. श्री अमिताभ रंजन-समन्वयक 2. श्री एच.सी. यादव 3. श्री मिथुन बरुआ 4. सुश्री मेघना चुक्कथ	1. डॉ चारू मल्होत्रा-समन्वयक 2. डॉ सुरभि पांडेय
अंतर्राष्ट्रीय संबंध केन्द्र	
1. प्रो. अशोक विशनदास-समन्वयक 2. डॉ मनन द्विवेदी	

* केन्द्रों के संविधान और सदस्य केवल आईआईपीए आंतरिक शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए हैं और इनका प्रत्येक केन्द्र और आईआईपीए वेतन ढांचे के अंतर्गत अनुदान/संसाधन से कोई संबंध नहीं है।

अनुलग्नक च. 5

आईआईपीए संकाय और अन्य का शैक्षणिक योगदान (प्रशिक्षण और अनुसंधान अध्ययन को छोड़कर)

सुरेश मिश्रा

क. शिक्षण/प्रशिक्षण

सीसीएस खंड में प्रशिक्षणों का उल्लेख

क (ii) शिक्षण

व्याख्यानों की संख्या (दोहराए गए विषय)

केवल संख्या

लगभग 75

व्याख्यानों की संख्या (नए विषय)

इसमें पैनल चर्चाएं, समूह चर्चाएं, किसी मामले पर चर्चाएं भी शामिल हैं

क (iii) अन्य कार्य (घंटों की संख्या केवल)

पैनल चर्चाएं

समूह चर्चाएं

अध्यास

किन्हीं मामलों पर चर्चाएं

प्रशिक्षण प्रस्तावों की तैयारी

क (iv) क्या आप शिक्षण में अपने योगदान की मात्र और सामग्री से संतुष्ट हैं?

पूर्ण हो चुकीं अनुसंधान परियोजनाएं

(श्रेणी क) (वित्त पोषित और गैर वित्त पोषित दोनों पर लागू)

क्रम संख्या	नाम	द्वारा प्रायोजित	स्थिति	पूर्ण हुए/ चल रहे
1.	राज्य उपभोक्ता विवादों निवारण आयोगों की रैकिंग	उपभोक्ता मामले मंत्रालय, भारत सरकार	पूर्ण हो चुका है	जनवरी 2020
2.	कोविड-19 लॉकडाउन चरण के दौरान ई-लर्निंग के संबंध में “माता-पिता (अभिवावकों) का अनुभव और सुविधा पर अध्ययन”	उपभोक्ता मामले मंत्रालय, भारत सरकार	पूर्ण हो चुका है	सितम्बर 2019
3.	कर्नाटक में जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्र के कार्य का मूल्यांकन और उपभोक्ताओं के बीच संतुष्टि का स्तर	उपभोक्ता मामले मंत्रालय, भारत सरकार	पूर्ण हो चुका है	

चल रहीं अनुसंधान परियोजनाएं (श्रेणी ख)

क्रम संख्या	नाम	द्वारा प्रायोजित	स्थिति
1.	उपभोक्ता अध्ययन केन्द्र	उपभोक्ता मामले मंत्रालय, भारत सरकार	चल रही है
2.	एनसीएच के माध्यम से एकीकृत शिकायत समाधान प्रणाली	उपभोक्ता मामले मंत्रालय, भारत सरकार	चल रही है

(ग) अनुसंधान संबंधी मार्गदर्शन

क्रम संख्या	नामांकित संख्या	प्रस्तुत शोध पत्र	डिग्री प्रदान की गई
1.	4602-बृज अनुल भदुरिया, आईए	सेना आधार कार्यशालाओं के लिए सरकारी स्वामित्व वाले ठेकेदार संचालित (जीओसीओ) प्रक्रिया की खोज	हां
2.	4606-श्री खगेश गर्ग आईटीएस	शराब पर नीति और कार्यक्रमों का एक अध्ययन (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मामले का अध्ययन)	हां

प्रकाशन

सतत उपभोग और जीवन शैली की ओर (ईडी)
सुरेश मिश्रा और ममता पठानिया

प्रकाशक: कॉन्सेप्ट पब्लिकेशन कॉर्पोरेशन

स्थान: नई दिल्ली

प्रकाशन की तिथि: 2020

उपभोक्ता पुस्तिका, सीसीएस, (लेखक सुरेश मिश्रा और सपना चड्डा)

आईआईपीए, नई दिल्ली, 2020

(iv) संदर्भित पत्रिकाओं/पुस्तकों में प्रकाशित पत्रों का विवरण

- सुरेश मिश्रा, उपभोक्ता संरक्षण बिल 2019, कस्टमर आवाज, खंड 4, अंक, अक्टूबर-दिसम्बर 2019
- डायरेक्ट सेलिंग टूडे में प्रकाशित प्रत्यक्ष बिक्री पर सुरेश मिश्रा इफोकेस साक्षात्कार, अक्टूबर 2019
- सुरेश मिश्रा और ममता पठानिया, (2019) विद्युत क्षेत्र में शिकायत समाधान तंत्र: दिल्ली के एक मामले का अध्ययन, गुरुप्रीत पन्न (ईडी) भारत में

उपभोक्ता संरक्षण चुनौतियां और आगे की राह, प्रकाशन ब्यूरो, पंजाब विश्वविद्यालय, पटियाला, 2019, आईएसबीएन 978-81-302-0509-0

क. विशेष निबन्ध

- सुरेश मिश्रा, उपभोक्ता सीसीएस, आईआईपीए, नई दिल्ली, 2019 पर आईआरए और इसका प्रभाव
- सुरेश मिश्रा, बच्चों पर विज्ञापनों का प्रभाव

आईआईपीए समितियां

- अध्यक्ष आईआईपीए अनुसंधान कर्मचारी चयन समिति
- अध्यक्ष एनसीएच कर्मचारी चयन समिति
- निदेशक की अध्यक्षता में सदस्य परियोजना कर्मचारी चयन समिति
- विभिन्न परियोजनाओं के लिए कर्मचारी के चयन के लिए वर्ष के दौरान 30 से अधिक चयन समितियां संचालित की गई हैं।
- आईआईपीए से बाहर अन्य शैक्षणिक/पेशेवर उपलब्धियां और योगदान

(v) आईआईपीए के बाहर किए गए शैक्षणिक कार्य

- मदुरै कामराज विश्वविद्यालय के विरुद्धनगर जिले में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों की ई-बैंकिंग सेवाओं के तुलनात्मक अध्ययन पर पीएचडी शोध पत्र के लिए बाहरी परीक्षक को नियुक्त किया
- रामनाथपुरम जिला, मदुरै कामराज विश्वविद्यालय के सदर्भ में एक अध्ययन-मच्छुआरों की आर्थिक गतिविधियों के प्रदर्शन पर पीएचडी शोध पत्र के लिए बाहरी परीक्षक नियुक्त किया
- पीएचडी शोध पत्र “पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत समुचित ग्रामीण विकास में जन प्रतिनिधियों की भूमिका: जयपुर जिले की ग्राम पंचायतों के संदर्भ में विश्लेषण” राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के लिए बाहरी परीक्षक नियुक्त किया
- उपभोक्ता संरक्षण और शिक्षा के लिए 08/3/2021 तिथि को व्याख्यान देने के लिए 6वां प्रस्तावना कार्यक्रम (ऑनलाइन), यूजीसी मानव संसाधन विकास केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में आयोजित किया
- कानून, मानवधिकार और सामाजिक परिवर्तन में नए पाठ्यक्रम “वैश्वीकरण, बाजार और उपभोक्ता संरक्षण” विषय पर यूजीसी-मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचआरडीसी) बी.पी.एस. महिला विश्वविद्यालय, कानपुर कलां (सोनीपत), हरियाणा में विशेषता प्रदान की और जानकारी दी
- प्रेरणा और कार्य निष्पादन विषय पर भागीदारों के लिए एलआईसी के एओ और एएओ के लिए तीन दिवसीय “ऑनलाइन एडवांस टाइम मैनेजमेंट इन न्यू नॉर्मल” विषय पर संबोधन
- “उपभोक्ता संरक्षण: एक अवलोकन” विषय पर भारतीय रक्षा परिसंपत्ति सेवा (आईडीईएस) के प्रशिक्षुओं के लिए लोक प्रशासन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारों को फरवरी 11, 2021 को संबोधित किया
- “संचार की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारतीय राजनयिक पहल: दक्षिण चीन सागर का एक अध्ययन,” इंदिगा गांधी राष्ट्रीय मुक्त

विश्वविद्यालय (इग्नू), मैदान गढ़ी, नई दिल्ली पर पीएचडी शोध पत्र के लिए बाहरी परीक्षक की नियुक्ति

- उपभोक्ता संरक्षण और शिक्षा पर 30/01/2021 तिथि को व्याख्यान के लिए यूजीसी-मानव संसाधन विकास केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में तीसरा प्रस्तावना कार्यक्रम
- कन्याकुमारी जिले में मनोनमनियम सुंदरनाद विश्वविद्यालय, तमिलनाडु में “सूक्ष्म उद्यम के विकास के लिए स्वयं सहायता समूहों की भूमिका पर एक अध्ययन” विषय पर पीएचडी शोध पत्र के लिए बाहरी परीक्षक की नियुक्ति
- इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश में “इलाहाबाद शहर में शहरी शासन और नियोजित शहरी विकास” विषय पर पीएचडी शोध पत्र के लिए बाहरी परीक्षक की नियुक्ति
- इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश में “इलाहाबाद शहर में शहरी शासन और नियोजित शहरी विकास” विषय पर पीएचडी शोध पत्र के लिए बाहरी परीक्षक की नियुक्ति
- जून 22, 2020 को “आदिवासियों के मानवाधिकार: लाहौल स्पीति की एक केस स्टडी” विषय पर पीएचडी मौखिक परीक्षा के लिए गांधीवादी ओर शान्ति अध्ययन विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय में एक विशेषज्ञ की नियुक्ति
- प्रो. सुरेश मिश्रा ने 10 फरवरी, 2021 को जिरोद्धार और शहरी रूपांतरण के लिए अटल मिशन, आईआईपीए विषय पर एक सत्र का आयोजन किया

(vi) जागरूकता बढ़ाने और उपभोक्ता को शिक्षित करने के लिए गतिविधियां:

- प्रो. सुरेश मिश्रा ने जून 20, 2020 को स्कूल ऑफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट, पॉडिट दीनदयाल पेट्रोलियम यूनीवर्सिटी (पीडीपीयू), गुजरात द्वारा महामारी के दौरान उपभोक्ता संरक्षण पर आयोजित एक वेबिनार में कोविड-19: सतत जीवनशैली की ओर विषय

- पर एक सत्र का संचालन किया
- प्रो. सुरेश मिश्रा 4 जुलाई, 2020 को श्री दुर्गा मल्लेश्वरा सिद्धार्थ महिला कलसला द्वारा आयोजित “उपभोक्ता संरक्षण में कोविड-19 नई चुनौतियां और रणनीतियां” विषय पर वेबिनार के मुख्य वक्ता थे
 - गांधीवादी शान्ति अध्ययन विभाग द्वारा जुलाई 5, 2020 को “कोविड-19 सतत जीवनशैली की ओर” विषय पर आयोजित वेबिनार का प्रो. सुरेश मिश्रा ने संचालन किया गया
 - भारतीय उपभोक्ता मार्गदर्शन सॉसाइटी के सहयोग से 8 अगस्त, 2020 को एच.एस.एन.सी. बोर्ड के जी.जे. अडवाणी लॉ कॉलेज द्वारा “उपभोक्ता संरक्षण: कानून और नीतियां” विषय पर आयोजित ऑनलाइन कार्यशाला में “कोविड-19 और उपभोक्ता संरक्षण” पर प्रो. सुरेश मिश्रा ने सत्र का संचालन किया
 - सितम्बर 6, 2020 को स्वर्णधरा ग्रुप ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 विषय पर आयोजित एक ऑनलाइन वेबिनार में “उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण” विषय पर प्रो. सुरेश मिश्रा ने भाषण दिया
 - प्रो. सुरेश मिश्रा और सपना चड्डा ने 17 अक्टूबर, 2020 को उपभोक्ता वकालत ग्रुप द्वारा सदस्यों के लिए आयोजित ऑनलाइन उन्मुख कार्यक्रम में भाषण दिया
 - उपभोक्ता कानून, वकालत और अनुसंधान केन्द्र, बी.एम.एस. कॉलेज आफ लॉ और उपभोक्ता अधिकार, शिक्षा और जागरूकता ट्रस्ट (सीआईएसटी) द्वारा नवम्बर 20, 2020 को “कोविड-19 महामारी के दौरान उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण” विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय बहुविषय के सम्मेलन में प्रो. सुरेश मिश्रा मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता थे
 - लीगल इंटर्न्स एंड कन्ज्यूमर कॉर्पोरेशन काउंसिल द्वारा 21 नवम्बर, 2020 को “नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,” विषय पर आयोजित वेबिनार में प्रो. सुरेश मिश्रा मुख्य वक्ता अतिथि थे
- (vii) आईआईपीए के बाहर पेशेवर उपलब्धि**
- सदस्य, अध्ययन बोर्ड, आईआईएस विश्वविद्यालय, जयपुर
 - सदस्य, संपादक बोर्ड, इंटरनेशनल जनरल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, केआईईटी, गाजियाबाद
 - उपभोक्ता विज्ञान पत्रिका, परिवार और उपभोक्ता विज्ञान विभाग, मानव पारिस्थितिकी संकाय, बोगोर एग्रीकल्चर यूनीवर्टी, इंडोनेशिया में समीक्षक के रूप में नामांकित
 - सदस्य, आईएसओ की नेशनल मिरर कमेटी/सीआईओएलसीओ (कमेटी ऑन कन्ज्यूमर पॉलीसी), बीआईएस
 - स्कूल बोर्ड ऑफ स्कूल आफ लॉ, इग्नू, नई दिल्ली में सदस्य के रूप में सहयोजित
 - मैम्बर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, अंसल यूनीवर्सिटी, गुरुग्राम
- ## शाखा के साथ सहयोग
- सौंपी गई ब्रान्च:**
- दिल्ली क्षेत्रीय शाखा अध्यक्ष (त्याग पत्र दिसम्बर 2021)
 - राजस्थान क्षेत्रीय शाखा के साथ जुड़ा हुआ
- (viii) संस्थान में और इससे बाहर (स्थानीय और विदेश) की उपलब्धियां**
- (बाहरी कार्य व्यक्तिगत आधार पर नहीं बल्कि अनिवार्य रूप से आईआईपीए के विस्तार के लिए होने चाहिए)
- # उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार की विभिन्न समितियों की सदस्यता
1. सदस्य, केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार
 2. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार कार्यों की निगरानी के लिए

अंतर-मंत्रालीय निगरानी समिति, सदस्य

3. सदस्य, नेशनल मिर कमेटी ऑफ सीओपीओएलसीओ, बीआईएस, नई दिल्ली
4. सदस्य, उपभोक्ता जागरूकता सृजन, जागो ग्राहक जागो, पर अधिकार प्राप्त समिति, डीसीए, भारत सरकार
5. विशेष रूप से विवाहों/पार्टीयों/कार्यक्रमों के दौरान खाद्यान्नों की बर्बादी रोकने और दिखावटी व्यवहार की रोकथाम पर बनी समिति, डीसीए, सदस्य
6. भ्रामक विज्ञापनों और मुद्रा परिचालन योजनाओं के माध्यम से उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी पर बनी समिति, डीसीए, सदस्य
7. उपभोक्ता जागरूकता सृजन के लिए मल्टी मीडिया सलाहकार समिति, डीसीए, सदस्य
8. विभिन्न कानूनों के अंतर्गत पैकेट बन्द जिंसों पर लेबलिंग संबंधी आवश्यकताओं के सामंजस्य के लिए स्थायी समिति, सदस्य
9. उपभोक्ता जागरूकता के लिए सृजनशील एजेंसियों की सूची में नाम शामिल करने के लिए बनी चयन समिति, डीसीए, भारत सरकार, सदस्य
10. “जागो ग्राहक जागो” अभियान के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक (ऑडियो/वीडियो) की डिजाइनिंग और उत्पादन के लिए उत्पादन एजेंसियों के नाम को सूची में शामिल करने के लिए बनी चयन समिति, सदस्य
11. स्कूल ऑफ लॉ, इन्नू द्वारा उपभोक्ता संरक्षण (सीसीपी) पर सर्टिफिकेट कोर्स के पाठ्यक्रम के निर्माण में योगदान दिया

मीडिया संवाद

- प्रो. सुरेश मिश्रा ने 30 सितम्बर, 2020 को राज्य सभा टीवी पर देश देशन्तरः एफएसएसएआई नये नियम और उपभोक्ता विषय पर पैनल चर्चा में भाग लिया
- विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर राज्य सभा टीवी पर पैनल चर्चा

विनोद के शर्मा

क. शिक्षण/प्रशिक्षण

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	तिथि	कार्यक्रम समन्वयक
1.	ग्रामीण समाजों (सभी स्तरों के वैज्ञानिकों और तकनीकीविदों) के लिए विज्ञान और तकनीक पर तीसरा टी.पी.	दिसम्बर 07-11, 2020	प्रो. विनोद के शर्मा डॉ चारू मल्होत्रा
2.	ग्रामीण समाजों (सभी स्तरों के वैज्ञानिकों और तकनीकीविदों) के लिए विज्ञान और तकनीक पर 9वां टी.पी. (एक-सप्ताह)	जनवरी 04-08, 2021	प्रो. विनोद के शर्मा डॉ चारू मल्होत्रा
3.	तकनीकी कार्मिक (तकनीकी अधिकारी, तकनीकी कार्मिक, तकनीशियन, वरिष्ठ तकनीशियन, कनिष्ठ विश्लेषक) के लिए 15वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम (2-सप्ताह)	जनवरी 11-22, 2021	प्रो. विनोद के शर्मा डॉ श्यामली सिंह
4.	जल संसाधन प्रबन्धन और स्थायी आवास (सभी स्तर के वैज्ञानिक और तकनीकीविद) पर 1 पहला टी.पी. (एक-सप्ताह)	फरवरी 01-05, 2021	प्रो. विनोद के शर्मा डॉ श्यामली सिंह
5.	विज्ञान, तकनीकी और शासन में उभरते रुझानों (सभी स्तर के वैज्ञानिक और तकनीकीविद) पर 10वां टी.पी. (एक-सप्ताह)	फरवरी 08-12, 2021	प्रो. विनोद के शर्मा डॉ श्यामली सिंह

क (ii) शिक्षण	केवल संख्या
आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एपीपीपीए स्ट्रीम (विषय)	10
व्याख्यानों की संख्या (दोहराए गए विषय)	30
व्याख्यानों की संख्या (नए विषय)	15
कुल	55

क (iii) अन्य कार्य (घंटों की संख्या केवल)	
पैनल चर्चाएँ:	20
समूह चर्चाएँ:	04
अभ्यास:	02
केस डिस्कशन (मामलों पर चर्चाएँ):	04
प्रशिक्षण प्रस्तावों की तैयारी:	02

क (iv) क्या आप शिक्षण में अपने योगदान की मात्र और सामग्री से संतुष्ट हैं?
हाँ

अपने योगदान में सुधार के लिए उपाय सुझाएँ।
डीएसटी/एमओईएफएंडसीसी/जल संसाधन मंत्रालय को नये प्रशिक्षण/अनुसंधान गतिविधियों के बारे में प्रस्तावित की जा रही हैं

- क. चल रहीं अनुसंधान परियोजनाएं (श्रेणी क)
- ख. पूरी हो चुकीं अनुसंधान परियोजनाएं (श्रेणी क)
(वित्त पोषित और गैर वित्त पोषित अनुसंधानों पर लागु)
- 1. विषय: जलवायु परिवर्तन की स्थिति में जटिल आपदाओं के प्रबन्धन के लिए क्षमता निर्माण
- 2. अवधि: 3 वर्ष
- 3. वित्त पोषण करने वाली एजेंसी: एनएमएचएस-एमओईएफएंडसीसी
- 4. अनुदान: 86 लाख
- 5. आरंभ की तिथि: मार्च 2017

6. समाप्त होने की तिथि: मार्च, 2020

शोध पत्र

- दो शोध पत्र
- एक सामुदायिक मेले का आयोजन (माघे मेला)
- जलवायु विद्यालय पहल: विद्यालयों को जलवायु के प्रति स्मार्ट बनाना कार्यक्रम ऑल इंडिया रेडियो साइंस वॉच प्रोग्राम में दिखाया गया।
- नई दिल्ली में पूर्वी हिमालय में जटिल आपदा और जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्यशाला
- रिपोर्टें:
 - क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यशाला-उत्तरी और पश्चिम सिक्किम
 - जलवायु विद्यालय पहल
 - आपदा तैयारियों पर आध्यापक पुस्तिका
 - आपदा सुरक्षा पुस्तिका

ग. जटिल अनुसंधान परियोजनाएं (श्रेणी)

1. विषय: जलवायु के प्रति स्मार्ट शासन
2. विषय: सिक्किम के चयनित जिलों में जैव विविधता संरक्षण के लिए क्षमता और प्रशिक्षण की आवश्यकता विश्लेषण का आकलन
3. विषय: अन्य आपदा प्रबन्धन योजनाओं (ओडीएमएस), एमएचए का तीसरे पक्ष से मूल्यांकन
4. विषय: कोविड-19 का दस्तावेजीकरण: भारत सरकार की प्रतिक्रिया

घ. चल रहीं अनुसंधान परियोजनाएं (श्रेणी क)

1. विषय: गंगा नदी के हितधारकों के लिए समिलित क्षमता निर्माण कार्यक्रम
- ख. सेमिनार/ कार्यशालाओं/ सम्मेलनों/ वेबिनारों आदि में शोध पत्र (पेपर) प्रस्तुत किए गए
कोविड के दौरान आईआईपीए, एनआईडीएम, एनडीएमए, राजस्थान विश्वविद्यालय और अन्य संस्थानाओं द्वारा बड़ी संख्या में आयोजित वेबिनारों में भाग लिया

वेबिनारों के अनेक सत्रों की अध्यक्षता की चार शोध पत्र प्रकाशित किए

(क) आईआईपीए के भीतर शैक्षणिक कार्य के अन्य रूपों के साथ जुड़ाव

(क) समिति/अन्य (विभाग और योजना और सलाहकार समिति, समन्वयकत्व, संपादकत्व, संयोजकता आदि की सदस्यता) - भागीदारी का ब्योरा और प्रकृति-आईआईपीए का आजीवन सदस्य

(ख) समन्वयक, महाराष्ट्र क्षेत्रीय शाखा

(ग) समन्वयक, आईआईपीए का डीएसटी प्रकोष्ठ

(ख) आईआईपीए के बाहर के अकादमिक कार्य से जुड़ाव (समितियों/बोर्ड आदि की सदस्यता)

1. अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंध पारिस्थितिकी सोसाइटी के आजीवन सदस्य
2. सदस्य, समाचार पत्र सलाहकार बोर्ड, 'आपदा प्रतिक्रिया और प्रबन्धन', आईएसएसएन संख्या 2347-2553 एलबीएसएनएए, मसूरी
3. सदस्य, संपादक दल, आपदा प्रबन्धन पर स्रोत

पुस्तिका, एलबीएसएनएए, मसूरी

4. सदस्य, संपादक मंडल, मानव अधिकारों पर एनआईयू अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका
5. सदस्य, संपादक मंडल, पौध विकास विज्ञान पत्रिका। आईएसएसएन: 0974-6382, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा प्रकाशित
6. सदस्य, विकास और समाजिक-पर्यावरण प्रबन्धन के लिए पेशेवर संस्था की सलाहकार समिति (पीआरआईएसएम), कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
7. सदस्य, यूएन आईएसडीआर एशिया विज्ञान, तकनीकी और अकादमी सलाहकार युप (2015-2020)
8. उपाध्यक्ष, यूनआईएसडीआर-फिक्की एराइज इंडिया
9. उपाध्यक्ष, सिक्किम राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
10. विशेषज्ञ सदस्य, उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण
11. सदस्य, विज्ञान, तकनीकी और नवाचार नीति 2020- अध्यक्ष विषय गत समूह-क्षमता निर्माण
12. सदस्य, कार्यकारी सदस्य, स्फीयर इंडिया

के.के. पांडेय

क. शिक्षण/प्रशिक्षण

क्रम संख्या	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	नया/पुनावृत्ति	टिप्पणी
1.	हिमाचल प्रदेश के राज्य स्तरीय तकनीकी प्रकोष्ठ (एसएलटीसी) और शहरी स्तरीय तकनीकी प्रकोष्ठ (सीएलटीसी) में विशेषज्ञों/प्रवीणों के लिए पीएमएवाई-एचएफए पर एक-दिवसीय विशेष ऑनलाइन कार्यक्रम	जनवरी 21, 2021	नया	अपनी तरह का पहला-दोहराया जाएगा और विस्तार किया जाएगा
2.	हिमाचल प्रदेश के राज्य स्तरीय तकनीकी प्रकोष्ठ (एसएलटीसी) और शहरी स्तरीय तकनीकी प्रकोष्ठ (सीएलटीसी) में विशेषज्ञों/प्रवीणों के लिए पीएमएवाई-एचएफए पर एक-दिवसीय विशेष ऑनलाइन कार्यक्रम	जनवरी 19, 2021	नया	

3.	तमिलनाडु के निगम आयुक्तों के लिए शहरी शासन पर तीन-दिवसीय विशेष आभासी प्रशिक्षण कार्यक्रम	दिसम्बर 14–16, 2020	नया	
4.	अखिल भारतीय/केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए शहरी शासन पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	सितम्बर, 2020	नया	
5.	एनआईयूए और स्मार्ट सिटी मिशन के साथ बैठक का समन्वयन	सितम्बर 21, 2020	नया	जेएस (एससीएम) और निदेशक एनआईयूए द्वारा भाग लिया गया
6.	शहरी अध्ययन के लिए केन्द्रों की आभासी/वर्तुअल बैठक	17 अगस्त, 2020	नया	भारत सरकार के चारों केन्द्रों और जेएस (यूएलजी) द्वारा भाग लिया गया
7.	शहरी शासन और बुनियादी ढांचे के लिए न्यू नॉर्मल पर वेबिनार	15 जून 2020		मुख्य वक्ता श्री शैलेश पाठक (एलएंडटी) और श्री हितेश वैद्य

क (ii) शिक्षण केवल

व्याख्यान की संख्या (दोहराए गए विषय)	संख्या
व्याख्यान की संख्या (नये विषय)	18
कुल	30

क (iii) अन्य कार्य (घटों की संख्या केवल)

पैनल चर्चाएं	:	7
समूह चर्चाएं	:	5
अभ्यास	:	15
मामलों पर चर्चाएं (केस डिस्कशन)	:	8
प्रशिक्षण प्रस्तावों की तैयारी	:	12

क (iv) शिक्षण के लिए अपने योगदान की मात्रा और विषय को लेकर क्या आप संतुष्ट हैं?

डीजी आईआईपीए ने प्रमुख संस्थानों के बीच आईआईपीए को हमेशा ही आगे बढ़ाने के लिए बदलते पर्यावरण के नियमित अंगीकरण के लिए प्रोत्साहित,

प्रेरित और इस दिशा में कार्य किया है। मैंने अप्पा की शहरी धाराओं को एक नये प्रारूप में समन्वयित किया, जो करने के लिए अनूठी सीख थी और हमने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के लिए एक श्रृंखला में चार कार्यक्रमों का पहला मॉड्यूल शुरू किया है। यह सीयूएस में बड़ी संख्या में कार्यक्रमों का मार्ग प्रशस्त करेगा।

पूरी हुई अनुसंधान परियोजनाएं (श्रेणी क) (वित्त पोषित और गैर वित्त पोषित दोनों पर लागू)

I. विषय:

- एमएसएमई (विकास अधिनियम 2006) में बदलाव की आवश्यकता का अध्ययन के लिए कार्यकारी समूह- सदस्य सचिव के रूप में
- युवा मामलों के राजीव गांधी राष्ट्रीय संस्थान का तीसरा-पक्ष मूल्यांकन
- एमएसएमई मंत्रालय की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) योजना का मूल्यांकन अध्ययन चल रहीं अनुसंधान परियोजनाएं

विषय:

- क. एमएसएमई से एक व्यापक नीति दस्तावेज तैयार करने पर अध्ययन (चल रही)
- ख. तमिलनाडु के यूएलबी इंजीनियर्स प्रशिक्षण आवश्यकता का मूल्यांकन

प्रकाशन

शोध पत्र और लेख

विषय:

- क. शहरी विकास और आर्थिक पर श्री दुर्गा शंकर मिश्रा (आईएएस), सचिव और पीएमएसवीएएनआईडीएचआई पर श्री संजय कुमार (आईएएस), जेस (एनयूएल) के साथ साक्षात्कार/ संवाद- एक बहुगुणक प्रभाव के लिए एक जमीनी संपर्क
- ख. भारत में जलवायु परिवर्तन पर शहरी कार्यसूची पर शोध पत्र
- ग. शहरी गरीबों के आवास के लिए नीति कार्यसूची
- घ. यूएलबी के लिए ब्रिंदिंग स्पेस (जगह)
- ड. प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय कार्रवाई
- च. राजस्व को बढ़ाने के लिए यूएलबी क्षमता को बढ़ाना
- छ. शहरी तस्वीर (बजट 2021 पर लेख)
- ज. भारत में पात्र बस्तियों के नगरीकरण पर शोध पत्र

II. पत्रिका/समाचार पत्र:

- क. आईआईपीए डाईजेस्ट का विशेषांक, खंड संख्या 02 अंक
- ख. निर्माण सारिका
- ग. फाइनेंशियल एक्सप्रेस
- घ. फाइनेंशियल एक्सप्रेस
- ड. फाइनेंशियल एक्सप्रेस

III. तिथि:

क. 03 जुलाई-सितम्बर, 2020

ख. 03 जुलाई-सितम्बर, 2020

ग. जुलाई-सितम्बर 9 (3), 2020

घ. अगस्त, 6, 2020

ड. 18 नवम्बर, 2020

च. दिसम्बर 25, 2020

छ. 3 फरवरी, 2021

ज. वेबिनारों/सेमिनारों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों, आदि में मुख्य वक्ता के रूप में प्रस्तुतीकरण/दस्तावेजों की प्रस्तुति

संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों आदि का विषय:

1. आवास और शहरी अर्थव्यवस्था पर आईटीपीआई वेबिनार (मई 2020)
2. निर्माण श्रमिक अधिनियम 1996 (जून, 2020)
3. निगम वित्त पर हैदराबाद विश्वविद्यालय वेबिनार (अगस्त, 2020)
4. एचएसएमआई पुनर्गठन पर एचयूडीसीओ वेबिनार (नवम्बर, 2020)
5. वित्तीय ढांचे पर एचयूडीसीओ वेबिनार (जनवरी, 2021)
6. प्रवासी श्रमिकों पर आईआईपीए वेबिनार (जनवरी, 2021)

I. आईआईपीए के भीतर शैक्षणिक कार्य के अन्य रूपों के साथ जुड़ाव

(क) समिति/अन्य (विभाग और योजना और सलाहकार समिति, समन्वयकत्व, संपादकत्व, संयोजकत्व आदि की सदस्यता)- भागीदारी का व्योरा और प्रकृति

- (i) आईआईपीए में शहरी अध्ययन के लिए केन्द्रों का समन्वयन
- (ii) आईआईपीए में राज्यसभा समिति का समन्वयन
- (iii) अप्पा में शहरी स्ट्रीम (विषय) का समन्वयन
- (iv) अप्पा में नैतिक स्ट्रीम (विषय) का समन्वयन

- (v) आईआईपीए की कार्यकारी समिति के सदस्य
- (vi) आईआईपीए में अनुसंधान स्टाफ के लिए
चयन समिति के सदस्य
- (vii) संपादक मंडल नागरलोक का सदस्य
- (ख)
- (ग) आईआईपीए के बाहर अकादमिक कार्य के साथ
सहयोग (समितियों/मंडलों, आदि की सदस्यता)
- (i) एचयूडीसीओ विशेषज्ञ समिति का सदस्य
- (ii) लोक प्रशासन की एशिया पुनर्संमीक्षा
- (iii) आकांक्षा-वाईएसएसजी पत्रिका (ग्रामीण
क्षेत्रों में शैक्षिक अंतर्ज्ञान की पुष्टि के
लिए)
- (iv) एनसीआर योजना मंडल, 2021 की
पुनर्संमीक्षा के लिए सदस्य संचालन समिति
- (v) एमडीए के सलाहकार मंडल का सदस्य
(नगर पालिकाओं और विकास प्राधिकरणों
का संगठन)
- (vi) आर्थिक गतिविधि और राजकोषीय नीति
पर एनसीआरपीबी अध्ययन समूह का
अध्यक्ष
- (vii) जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रबन्धन में
भारत के राष्ट्रपति नामित

एच. शाखा के साथ सहयोग

शाखा समुनदेषित: पंजाब और चंडीगढ़

अशोक विशनदास

क. शिक्षण/प्रशिक्षण

क (i) निर्देश

क्रम संख्या	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	नया/ पुनावृति	टिप्पणी
1.	46वां अप्पा	10वां सत्र	नया	नया स्ट्रीम (विषय) 'अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य'
2.	46वां अप्पा	3 महीने	2 अप्पा भागीदारों को उनके शोध प्रबन्ध पर निर्देशित किया जिससे वे एम.फिल के लिए आगे बढ़े	

क (ii) शिक्षण संख्या केवल

क्रम संख्या	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	नया/पुनावृति	टिप्पणी
1.	46वां अप्पा	10वां सत्र	मिश्रित	मेरे द्वारा 'सतत कृषि और जोखिम प्रबन्ध' विषय पर स्ट्रीम (विषय) का आरंभ किया गया

व्याख्यान की संख्या (दोहराए गए विषय) 10

व्याख्यान की संख्या (नये विषय) 10

कुल 20

क (iii) अन्य कार्य (घटों की संख्या केवल)

पैनल चर्चाएं	:	5
समूह चर्चाएं	:	7
अभ्यास	:	12
मामलों पर चर्चाएं (केस डिस्कशन)	:	8
प्रशिक्षण प्रस्तावों की तैयारी	:	9

क (iv) शिक्षण के लिए अपने योगदान की मात्रा और विषय को लेकर क्या आप संतुष्ट हैं?

हाँ

अपने योगदान में सुधार के लिए उपाय सुझाएं

पूरी हो चुकीं अनुसंधान परियोजनाएं (श्रेणी क) (वित्त पोषित और गैर वित्त पोषित दोनों पर लागू)

विषय: नई योजनाओं (i) प्लास्टिक पार्क की स्थापना और (ii) उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना का तीसरे-पक्ष से मूल्यांकन

पूरी हो चुकीं अनुसंधान परियोजनाएं (श्रेणी ख)

विषय: आईआईएस, शिमला की पारदर्शिता लेखा-परीक्षा

चल रहीं अनुसंधान परियोजनाएं (श्रेणी क)

विषय: 'भारत सरकार के अंतर्गत प्रशिक्षण संस्थाओं के उत्पादन और परिणाम का मूल्यांकन' पर अध्ययन

समाचार पत्र और लेख

1. अशोक विशनदास और नितीशा ठकवानी (2020) 'गरीब किसान और उच्च उत्पाद खुदरा मूल्य नया सामान्य' पोलिसी सर्किल तिथि अप्रैल 7, 2020 (<https://www.policycircle.org/economy/impoverished-farmer-and-high-product-prices-the-new-normal/>)
2. अशोक विशनदास और नितीशा ठकवानी (2020) 'कोरोना वायरसः सरकार को सभी के लिए खाद्य सुनिश्चित करना चाहिए, और अधिक लोगों को गरीबी में जाने से रोकना चाहिए', फाइनेंशियल एक्सप्रेस तिथि मई 02, 2020 (<https://www.financialexpress.com/economy/coronavirus-lockdown-food-poor-poverty-govt-agenda-helping-poor-bpl-food-for-all-migrant-workers-labourers-covid-19/1946152/->)

[financialexpress.com/economy/coronavirus-lockdown-food-poor-poverty-govt-agenda-helping-poor-bpl-food-for-all-migrant-workers-labourers-covid-19/1946152/-](https://www.financialexpress.com/economy/coronavirus-lockdown-food-poor-poverty-govt-agenda-helping-poor-bpl-food-for-all-migrant-workers-labourers-covid-19/1946152/-))

3. विशनदास, अशोक और ठकवानी नितीशा 'मोदी का आत्मनिर्भर भारतः पामओयल बागवानी भारत को खाद्य तेल में कैसे आत्मनिर्भर बना सकती है', फाइनेंशियल एक्सप्रेस तिथि जुलाई 28, 2020 <https://www.financialexpress.com/economy/modis-atmanirbhar-bharat-how-palm-oil-cultivation-can-make-india-self-reliant-in-edible-oil/2037185/>
4. त्रिपाठी, सुरेन्द्र नाथ और विशनदास, अशोक, 'किसानों को पसंद की स्वतंत्रता: क्या नए कृषि अधिनियम भारतीय कृषि के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है?', फाइनेंशियल एक्सप्रेस तिथि अक्टूबर 07, 2020 <https://www.financialexpress.com/economy/freedom-of-choice-to-farmers-are-new-farm-acts-a-watershed-moment-for-indian-agriculture/2100216/>

ज. संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों आदि में प्रस्तुत किया गया शोध पत्र

1. सेमिनारों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों आदि का विषय 'भारतीय कृषि में समकालीन मुद्दे'। मुख्य भाषण दिया

(v) प्रस्तुत किए गए शोध पत्र का विषय: 'भारतीय कृषि में समकालीन मुद्दे' पर मुख्य भाषण दिया

ज (II) संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों आदि में प्रस्तुत किया गया शोध पत्र

1. आईआईपीए के भीतर अकादमी कार्य के अन्य स्वरूप के साथ जुड़ाव
 - (क) समिति/अन्य (विभाग और योजना और सलाहकार समिति की सदस्यता)
 - (ख) आईआईपीए के बाहर अकादमिक कार्य के साथ जुड़ाव (समितियों/मंडलों आदि की सदस्यता)

१ - शाखा के साथ सहयोग

प्रदत्त शाखा: जम्मू और कश्मीर, गुजरात गतिविधियों में शामिल

(i) प्रशिक्षण:-

(ii) अनुसंधान/केस स्टडीज (मामले का अध्ययन):-

(iii) सेमिनार/सम्मेलन

(i) मुझे 'नया भारत: आकांक्षी 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था' विषय पर हुए सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था

(ii) सदस्य (नीति आयोग) द्वारा समन्वित एक बैठक में शामिल हुआ

(iii) सचिव (उर्वरक) के नियंत्रण पर, मैंने 24 दिसम्बर, 2020 को आयोजित 'भारतीय सब्सिडी कार्यक्रम के रणनीतिक परिवर्तन' में भाग लिया और योगदान दिया

२. आईआईपीए के बाहर किए गए अन्य अकादमिक कार्य का व्योरा

३. शामिल हुए किसी अन्य अकादमिक अथवा संबंधित गतिविधि जिसका उल्लेख ऊपर नहीं दिया गया

(i) हो 46वें अप्पा भागीदारों को उनके शोध पत्रों के लिए निर्देशित किया, जिससे वे एमफिल

कर सकें

(ii) एफआरएसी किया गया

(iii) मिशन कर्मयोगी का प्रबन्ध किया और इस पर नोट तैयार किए

(iv) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की बैठकों में शामिल हुआ

(v) नीति आयोग की बैठकों में शामिल हुआ

वी.एन. आलोक

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/कार्यशाला

27 मई 2020: आभासी स्वरूप में 'कोरोना-संकट में भारत में स्थानीय सरकारों की उभरती भूमिका' पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला। डॉ एम रामचंद्रन, पूर्व सचिव, शहरी विकास केन्द्रीय मंत्रालय और डॉ एस एम विजयानन्द, अध्यक्ष, 6वां केरल राज्य वित्त आयोग मुख्य वक्ता थे। श्री एस.एन. त्रिपाठी, डीजी, आईआईपीए ने मध्यस्था की।

लोक प्रशासन में 46वें अग्रीम पेशेवर कार्यक्रम में 10 सत्रों के साथ लोक वित्त पर स्ट्रीम

लोक प्रशासन में 46वें अग्रीम पेशेवर कार्यक्रम में 10 सत्रों के साथ सहकारी संघवाद पर स्ट्रीम

पूरी हो चुकी अनुसंधान परियोजना

क्रम संख्या	नाम	द्वारा प्रायोजित	स्थिति	बजट
1.	केन्द्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के 'सूचना और जन जागरूकता कार्यक्रम' का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार	पूरा हो चुका	दिनांक 10 फरवरी 2021 के पत्र संख्या 19/20/2019/आईएंडपीए के द्वारा स्वीकृत रूपये 17,62,684
2.	'पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम' पर केन्द्रीय क्षेत्र की योजना का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन	पुलिस वित्त द्वितीय प्रभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार	पूरा हो चुका	दिनांक 15 दिसम्बर, 2020 के पत्र संख्या II-27011/4/2019/PF.II द्वारा स्वीकृत रूपये 19,83,344

3.	‘पूर्वोत्तर क्षेत्र में विज्ञापन और प्रचार’ पर केन्द्रीय क्षेत्र की योजना का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन	गृह मंत्रालय, भारत सरकार का पूर्वोत्तर विभाग	पूरा हो चुका	दिनांक 10 सितम्बर 2020 के पत्र संख्या 2/4/2020. NEDC द्वारा स्वीकृत रूपये 13,96,648
4.	‘पूर्वोत्तर क्षेत्र में नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम’ पर केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के मूल्यांकन का अध्ययन	गृह मंत्रालय, भारत सरकार	पूरा हो चुका	दिनांक 7 सितम्बर 2020 के पत्र संख्या 6/13/2020. NE.I द्वारा स्वीकृत रूपये 19,83,344
5.	‘पूर्वोत्तर क्षेत्र में हैलीकॉप्टर सेवा’ पर केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के मूल्यांकन का अध्ययन	पूर्वोत्तर विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार	पूरा हो चुका	रूपये 9,73,500

प्रकाशन

पुस्तिका

- भारत में पंचायत वित्तः प्रयोग) मूल्यांकन 2081-19, नई दिल्ली, नीति आयोग और आईआईपीए। आईएसबीएन 978-81-946138-0-0

शोध पत्र

- संघवाद के 50 रुपों में ‘भारत में कोविड-19 और संघवाद’

समाचार पत्र लेख

- 29 जून 2020, इकोनोमिक टाइम्स, सरकार-कोरोना संकट में भारत के राजकोषीय ढांचे में स्थानीय सरकारों का उभरता दायरा <https://government.economictimes.indiatimes.com/news/governance/emerging-scope-of-local-governments-in-indias-fiscal-architecture-in-corona-crises/76638753>
- 6 जून 2020, द पायोनियर- संकट से निपटने में स्थानीय सरकारों की भूमिका बढ़ाएं https://www.dailypioneer.com/2020/columnists/72_Indian_Institute_of_Public_Administration_enlarge-role-of-local-govts-in-handling-crisis_.html
- 1 जून 2020, फाइनेंशियल एक्सप्रेस- ‘कोविड-19 से लड़ाई में स्थानीय सरकारों की मुख्य भूमिका होनी चाहिए।

टीवी चैनलों (चयनित) पर व्याख्यानों/प्रस्तुतियों/पैनल में शामिल लोगों को आमंत्रित किया:

- 12 फरवरी, 2021 (ऑनलाइन) को स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर द्वारा आयोजित “केन्द्रीय बजट 2021 पर पैनल चर्चा” में मुख्य वक्ता के रूप में संवाद किया।
- 11 जनवरी 2021 को दिल्ली में, दिल्ली स्थित प्रशिक्षण निदेशालय में दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार द्वीप लोक सेवा (डीएनआईसीस) के 56 बैच के प्रशिक्षक अधिकारियों को ‘राजकोषीय संघवाद और कोरोना संकट’ पर संवाद किया।
- 15 दिसम्बर 2020 को ‘कोविड-19 और भारतीय संघवाद’ विषय पर हान सिडिएल फाउंडेशन और 50 शेड्स ऑफ फेडरलिज्म द्वारा आयोजित ‘टर्न ऑन फेडरलिज्म’ पर एक वैश्वक ऑनलाइन कार्यक्रम में चर्चा की। सभी महाद्वीपों के विभिन्न देशों के सैकड़ों दर्शकों के लिए इस चर्चा और प्रश्नोत्तरी का साथ के साथ फ्रांसीसी, म्यामार और स्पैनिश भाषाओं में अनुवाद किया गया।
- 12 दिसम्बर 2020 को केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय और केन्द्रीय ग्रामीण प्रबन्धन, कोट्टयम द्वारा 10-14 दिसम्बर 2020 के दौरान ‘कोविड-19 के बाद की दुनिया में स्थानीय सरकारों की भूमिका पर पुनर्विचार’ विषय पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय वेबीनार में “महामारी युग में नेतृत्व वित्त और

- ‘विकेन्द्रीकरण सुधार के मुद्दे’ विषय पर एक तकनीकी सत्र की अध्यक्षता की।
- 26 नवम्बर 2020 को मुम्बई स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स एंड पब्लिक पोलीसी, मुम्बई विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राज्य वित्त आयोगों और ग्रामीण विकास विषय पर आभासी माध्यम से संवाद किया।
 - 31 अगस्त 2020 को वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के लिए जीडीपी अनुपान की घोषणा से पूर्व एनडीए टीवी ने सीधा प्रसारण के दौरान हुई चर्चा में पैनेलिस्ट के रूप में भाग लिया।
 - 30 जुलाई 2020 को ए के एस विश्वविद्यालय, सतना द्वारा आयोजित ‘आत्मनिर्भर भारत के लिए मौद्रिक नीति और वित्तीय नीति का एकीकरण’ विषय पर एक राष्ट्रीय वेबीनार में मुख्य वक्ता था।
 - 27 मई 2020 को आभासी माध्यम से ‘कोरोना संकट में भारत में स्थानीय सरकारों की उभरती भूमिका’ विषय पर हुए एक राष्ट्रीय कार्यशाला में पैनेलिस्ट के रूप में शामिल हुआ। डॉ एम. रामचंद्रन, पूर्व सचिव, केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय और डॉ एस.एम. विजयानन्द, अध्यक्ष, छठा केरल राज्य वित्त आयोग इसमें मुख्य वक्ता थे। श्री एस.एन. त्रिपाठी, डीजी, आईआईपीए इसके संचालक थे।
 - 27 मई 2020 को फॉरम ऑफ फेडरेशन, ओट्टावा और फ्रेंड यूनीवर्सिटी, बर्लिन द्वारा ‘संघवाद और कोरोना-संकट-अंतर्राष्ट्रीय अनुभव’ विषय पर आयोजित एक वेबीनार में पैनेलिस्ट था। जर्मनी के सैक्सोनी राज्य के पूर्व प्रधानमंत्री श्री जॉर्ज मिलब्राइट पैनेल में शामिल लोगों में से एक थे।
 - 13 मई 2020 को कोरोना महामारी से उभरने वाली समस्याओं से राहत प्रदान करने के लिए आर्थिक पैकेज को लेकर केन्द्रीय वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमन द्वारा दी गई प्रस्तुतीकरण के दौरान एनडीटीवी लाइव चर्चा में पैनेलिस्ट था।

अन्य अकामिक कार्य के साथ सहयोग

संयुक्त संपादक के रूप में शहरी मामलों पर प्रकाशित होने वाली एक त्रैमासिक पत्रिका नगरलोक के संपादन में संपादक (महानिदेशक, आईआईपीए) को तकनीकी सहायता प्रदान की

भारतीय लोक प्रशासन पत्रिका के लिए लेखों की पुनर्समीक्षा

भा.लो.प्र.सं. शाखा के साथ सहयोग

उत्तराखण्ड

भा.लो.प्र.सं. के बाहर किए गए अन्य अकादमिक कार्यों का व्यौरा

प्रतियोगी परीक्षा के लिए पेपर तैयार किया

प्रतियोगी परीक्षा के लिए परीक्षक

चारू मल्होत्रा

क. प्रशिक्षण/शिक्षण

क. पिछले एक वर्ष के दौरान अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया

क (i) निवेशन

क्रम संख्या	प्रशिक्षण का नाम	अवधि	नया/पुनरावृत्ति	टिप्पणियां
1.	डिजीटल 46वां अप्पा	10 महीने (जुलाई 2020-अप्रैल 2021)	नया संस्करण (भा.लो.प्र.सं. के इतिहास में अब तक का पहला मिश्रित अप्पा प्रशिक्षण)	डीजी के साथ सह-निरीक्षण किया और डॉ पवन तनेजा के साथ आयोजित किया

2.	शासन में डिजिटल परिवर्तन पर पोस्ट-रेज वर्चुअल शिखर सम्मेलन	3 दिन (अक्टूबर 13-15 2020)	नया	भा.लो.प्र.सं. को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय-रेज 2020 कार्यक्रम (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर) के लिए MeitY के ज्ञान प्रदाता के रूप में चिह्नित किया। यह अद्वितीय पोस्ट-राइज शिखर सम्मेलन राज्य एटीआई, भा.लो.प्र.सं. शाखाओं, अप्पा के पूर्व छात्रों और वर्तमान अप्पा सहित हमारे राष्ट्रीय भागीदारों के लिए अपनी सीख को लॉन्च करने के लिए निर्मित किया गया था।
3.	ग्रामीण सोसाइटियों के लिए विज्ञान और तकनीकी विज्य पर तीसरा प्रशिक्षण कार्यक्रम (ऑनलाइन माध्यम)	5 दिन (दिसम्बर 7-11, 2020)	पुनरावृत्ति	यह कार्यक्रम प्रतिभागियों को ग्रामीण समाज के समाने आने वाली जटिल समस्याओं से अवगत कराने और उन समस्याओं से निपटने में तकनीकी की भूमिका को समझने के लिए बना और संचालित किया गया था
4.	महिलाओं के लिए ग्रामीण सोसाइटियों हेतु विज्ञान और तकनीकी विषय पर नौवां प्रशिक्षण कार्यक्रम	5 दिन (जनवरी 4-8, 2021)	पुनरावृत्ति	कार्यक्रम का आयोजन प्रतिभागियों को विज्ञान और तकनीकी, विशेषरूप से महिला वैज्ञानिकों के लिए, के क्षेत्र में नवाचार युक्त हस्तक्षेपों से अवगत कराने के लिए किया गया था

क (ii) शिक्षण	संख्या केवल
व्याख्यान की संख्या (दोहराए गए विषय) :	10
व्याख्यान की संख्या (नये विषय) :	54
वीडियो रिकॉर्डिंग्स	28
नई प्रस्तुतियों का डिजाइन	50
कुल	142

मामलों पर चर्चाएं
(केस डिस्कशन)
: 10 (पूरी जीटीपी गोवट, टेक नीति कार्यान्वयन की प्रक्रिया में थी)

केस डिस्कशन : 25
प्रशिक्षण प्रस्तावों की तैयारी : 35

अन्य उल्लेखनीय उपलब्धि

1. अध्यक्ष और सीईओ के साथ हमारी चर्चाओं के कुछ दौर के बाद, भा.लो.प्र.सं. को 5 अक्टूबर (सोमवार) से शुरू हुए, एआई पर एक वर्चुअल वैश्विक शिखर सम्मेलन, सामाजिक सशक्तिकरण (रेज) 2020, के लिए प्रतिष्ठित ग्लोबल एआई

क (iii) शिक्षण अन्य कार्य (घटों की संख्या केवल)
पैनल चर्चाएं : 45/वेबीनार
समूह चर्चाएं : 20
अध्यास : 12

- इवेंट-रेज-2020-रिस्पोसिबल एआई के आयोजन के लिए एनईजीडी के साथ नॉलेज पार्टनर के रूप में चयनित किया गया।
2. आईआईपीए के तत्वाधान में रेज-पश्चात कार्यक्रम भी किए गए थे।
 3. मिशन कर्मयोगी पर पहले भा.लो.प्र.सं. वेबीनार की शुरूआत की जिसमें सचिव (डीआपीटी) और अपर सचिव (डीओपीटी) ने मिशन कर्मयोगी की विस्तृत चर्चा की।
 4. 45वें अप्पा के पहले ऑनलाइन वाइबा (मौखिक परीक्षा) के संचालन का सफलतापूर्वक मार्ग प्रशस्त किया।
 5. “कोविड-बाद का शहरी शासन-बुनियादी मुद्रे” विषय पर एक विस्तृत डिजिटल कैप्सूल 74 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का शुभांभ करने के लिए आईआईपीए के लिए पहले आदर्श प्रोसेस शीट को तैयार किया। प्रबन्धन द्वारा इस पहल की दिल से सराहना की गई और इसे “डीजी को ज्ञानरूपी सलाहकार” के रूप में माना गया।
- क (iv) क्या आप शिक्षण के अपने योगदान की मात्र और विषय से संतुष्ट हैं?**
- हाँ, हालांकि, प्रबन्धन द्वारा अपने डोमेन विषय को मान्यता देने अथवा उसकी पुष्टि किए जाने की आवश्यकता है, मैं, अब, अपने अनुसंधान प्रयासों में और अधिक नवीनता का समावेशन करने प्रयास करूँगा।
- ख. पूरी हो चुकीं अनुसंधान परियोजनाएं**
- ख.1 विषय:** तीसरे पक्ष का मूल्यांकन और प्रभाव आकलन तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षाता अभियान (पीएमजीडीआईएसएचए) योजना का मूल्यांकन
- ग. चल रहीं अनुसंधान परियोजनाएं**
- ग.1 परियोजना का विज्ञय:** एसएपी इंडिया प्रा. लि. का संगठनात्मक प्रभाव मूल्यांकन
- ग.2 विज्ञय:** राज्य एटीआई के माध्यम से जिला स्तरीय एससी/एसटी अधिकारियों के लिए जागरूकता और कौशल विकास कार्यक्रम
- MeitY (मैटी) के लिए प्रस्तावित नई परियोजनाएं**
- ग.3 कमजोर समुदायों का डिजिटल सशक्तिकरण: डिजिटल दान, साइबर स्वच्छता और डिजिटल साक्षरता (लगभग 7 करोड़)
- ग.4 वरिष्ठ नागरिकों और पीडब्ल्यूडी की अप्रयुक्त बृद्धिमता का संवर्धन और प्रयोग (लगभग 7 करोड़)
- ग.5 उमंग का प्रभाव आकलन (लगभग 24 लाख)
- घ. केस स्टडीज (मामले का अध्ययन) : 2**
1. **ई-मित्र:** भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गई एक ई-शासन पहल के बारे में नागरिकों के दृष्टिकोण को उजागर करना: इस मामले के अध्ययन का उद्देश्य ई-मित्र (डिजिटल दोस्त) पहल का मूल्यांकन करना है, यह MeitY (मैटी) द्वारा शुरू की गई एक राज्य ई-शासन पहल है। इस पहल का उद्देश्य सभी विभागों की सेवाओं को एक-साथ एक ही छत के नीचे लाना है और राज्य (देश) के नागरिकों को एक “बहु-सेवाएं” “एकाकी-पटल” का अनुभव प्रदान करना है।
 2. **ई-शासन/आईसीटी आधारित परियोजनाओं का जोखिम प्रबन्धन:** अस्पताल प्रबन्धन प्रणाली संबंधी मामले का अध्ययन: अध्ययन का उद्देश्य जोखिम प्रबन्धन रणनीतियों को तैयार करना है और इसे अस्पताल प्रबन्धन प्रणाली के इस मामले के अध्ययन पर विचार कर किया जाता है ताकि यह समझाया जा सके कि कुशल तरीके से जोखिम से बचने के लिए जोखिम प्रबन्धन प्रक्रिया को कैसे लागू किया जाए। इसके अलावा, यह अध्ययन अस्पताल प्रबन्धन में जोखिम प्रबन्धन के लिए डिजाइन संबंधी वास्तविकता अंतर वाले उदाहरण के उपयोग को दर्शाता है।
- ड. प्रकाशन**
- क. पुस्तक:** प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडीआईएसएचए) के प्रभाव का

मूल्यांकन, पृष्ठों की संख्या-219 (आईआईपीए, नई दिल्ली, अभी प्रकाशित की जानी है

ख. समाचार पत्र और लेख

- (2020). ई-शासन/आईसीटी आधारित परियोजनाओं का जोखिम प्रबन्धन: छानबीन (आईटी लेखा परीक्षा पर ट्रिवार्षिकी पत्रिका), अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली और लेखा परीक्षा केन्द्र (आईसीआईएसए), दिसम्बर 2020, अंक संख्या 2, नई दिल्ली
- (2020). भविष्य के समावेशी शहरों का डिजाइन तैयार करना: जॉन आर. वाका, मॉर्गन कॉफ्मेन (एल्सेवियर इंक का कार्य) द्वारा भारतीय संदर्भ में रचित पत्रिका “स्मार्ट सिटी तकनीकी पुस्तिका का उपयोग करते हुए शहरी बुनियादी ढांचे की समस्या का समाधान”, सितम्बर 2020 (ईबुक आईएसबीएन: 9780128168172(पेपरबैक आईएसबीएन 9780128168165 elsevier.com; https://www.researchgate.net/publication/345491802_Designing_inclusive_smart_cities_of_the_future_the_Indian_context-stats
- (2020). जन सेवाओं 4.0 का सृजन-भारत में जन सेवाओं के लिए सतत डिजिटल वास्तुकला। लोक प्रशासन भारतीय पत्रिका (आईजेपीए, सेज पब्लिकेशन, अक्टूबर 2020) <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0019556120957421>
- चारू मल्होत्रा (2020) सरकार 4.0: कोविड-19 के बाद शासन का राजहंस, इकोनोमिक टाइम्स, मई 2020 (<https://government.economictimes.indiatimes.com/news/digital-india/government-4-0-the-white-swan-of-governance-post-covid-19/75527186>)
- चारू मल्होत्रा (2020) कोविड के समय साइबर क्राइम पर अब डिजिटल दूरी और रोकथाम, द पायोनीयर, अप्रैल 2020 (<https://www.dailypioneer.com/443/2020/columnists/now-digital-distancing.html>)

ग. पुस्तिक की समीक्षा की गई: ई-शासन और नागरिक सहभागिता, सेज पब्लिकेशन, अप्रैल 2020

घ. समाचार पत्रों की समीक्षा की गई

- मुक्त सरकारी डाटा आधारभूत ढांचा: तंजानिया में सरकारी वेबसाइटों की एक जांच, भारतीय लोक प्रशासन पत्रिका (2020)
- समुदायों के विकास में ई-शासन कार्यों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण: पंजाब में सुविधा परियोजना की एक केस स्टडी। भारतीय लोक प्रशासन पत्रिका (2020)
- ई-शासन कार्यों के प्रति नागरिकों का दृष्टिकोण: भारत के लखनऊ शहरी समुदाय का एक अध्ययन। भारतीय लोक प्रशासन पत्रिका (2020)

च. संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों आदि में प्रस्तुत किए गए समाचार पत्र

- (2020) भारत में लोक सेवा प्रदान करने में तेजी। कृषि में आईओटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक शासन के सिद्धांत और व्यवहार पर 13वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की कार्यवाही। पृष्ठ 62-69 (<https://doi.org/10.1145/3428502.3428510>)
- (2020) भारत में लिंग-आधारित हिंसा का समाधान करते हुए साइबर-अभियान और ऑनलाइन सक्रियता, जेटीए बहु-विषयक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कार्यवाही, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय स्थान: नई दिल्ली, भारत (www.archives.tponsindia.org/sipn/article/download)
- (2020) साइबर सुरक्षा: स्मार्ट शहरों और औद्योगिक क्रांति 4.0 का एक प्रवर्तक, “एज कंप्यूटिंग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्मारिका, रोबोटिक्स, उद्योग 4.0 और सञ्जानात्मक तकनीकी के माध्यम से प्रक्रिया स्वचालन,” विशाखापत्तनम, भारत

छ. भा.लो.प्र.सं. के भीतर अकादमिक कार्य के अन्य स्वरूपों के साथ सहयोग

- i. भा.लो.प्र.सं. संगठन के भीतर
- समन्वयक, ई-शासन केन्द्र
 - उपाध्यक्ष, अप्पा पूर्व छात्र संघ
- ii. एमफिल निबन्ध शोध पत्रों को निदेशित किया गया (अप्पा अधिकारियों के लिए)-कुल-2
1. साइबरस्पेस के माध्यम से गलत सूचना का मुकाबला करने के साथ प्रभावी सूचना संचालन के लिए भारत में संरचनाओं/संगठनों का निर्माण/पुनर्गठन (2020-21)
 2. भारतीय संदर्भ में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ब्रॉड बैंड की भूमिका (2020-21)
- iii. अकादमी के किसी अन्य योगदान के महत्व को भी निर्दिष्ट किया जा सकता है
1. एक विख्यात अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ श्री पीटर डेविस को-स्मार्ट शहरों और साइबर सुरक्षा पर, मुफ्त, सिनेमा जगत की जानी मानी हस्ती, फिल्म पुरस्कार विजेता और टीवी स्टार हस्ती सुश्री सादिया सिद्दकी के साथ-साथ डॉ परिन सोमानी (यूके) को आमंत्रित किया गया। इन अनूठे सत्रों (यूके) को आमंत्रित किया गया। इन अनूठे सत्रों

iii. भा.लो.प्र.सं. के बाद अकादमिक कार्य के साथ जुड़ाव (समितियों/मंडलों आदि की सदस्यता)

क. अध्यक्ष/सदस्य/जूरी

क्रम संख्या	सदस्यता वाले संगठन का नाम	समिति/परियोजना का नाम
1.	एसोचैम (मार्च 2021)	साइबर में महिलाओं को पुरस्कार: लीक से हटकर
2.	MeitY (मैटी) भारत सरकार, चल रही है	जन कार्यक्रम के लिए आईटी
3.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)-चल रही है	एचईआईएस में साइबर सुरक्षा पर यूजीसी विशेषज्ञ समिति
4.	MeitY (मैटी) भारत सरकार, दिसम्बर 2020	डिजिटल भुगतान के प्रसार के लिए योजनाओं का तीसरे पक्ष से मूल्यांकन
5.	MeitY (मैटी) भारत सरकार, दिसम्बर 2021	सतर्कता जागरूकता पखवाड़ा 2020 के लिए MyGov पर निबन्ध/पोस्टर/स्लोगन के लिए जूरी सदस्य
6.	MeitY (मैटी) भारत सरकार, मार्च 2021	राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन के लिए 'नाम, लोगों और टैगलाइन' के लिए अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग) ग्रुप सदस्य

ने प्रतिभागियों की अकादमिक दिनचर्या में थोड़ा वैश्विक स्वाद और कला/संस्कृति में कुछ नएपन का योगदान दिया। दर्शकों ने इन अनूठे प्रयासों की दिल से सराहना की।

2. डॉ जे. सत्यनारायण के साथ 46वें अप्पा की प्रतिक्रिया को दुबारा से रिकास्ट किया गया
3. बोस्टन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर “मनोहरन, ए., और रंगाराजन, एन. (2021) द्वारा लिखित एक अध्याय के लिए भा.लो.प्र.सं. और अप्पा के ध्वजवाहक (फ्लैगबिर्यर)। प्रशासनिक शिक्षा, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण: डिनिंग, पी (में भारतीय लोक प्रशासन की भूमिका, लोक प्रशासन और प्रबन्धन में शिक्षण और सीख पर बॉटम, के एंड जे डायमंड (ईडीएस) पुस्तिका, एलार (फॉरथकमिंग)’। इस संक्षिप्त अध्याय का प्राथमिक उद्देश्य भा.लो.प्र.सं., इसके कार्यों और संस्थान के अन्य पहलुओं का एक विस्तृत अवलोकन करना है ताकि पाठक प्रशासनिक प्रशिक्षण में संस्थान की भूमिका के संबंध में सामान्य ज्ञान प्रदान कर सकें।

7.	MeitY (मैटी) भारत सरकार, 2020	इलेक्ट्रॉनिक्स/आईटी/सीसीएंडबीटी में केन्द्रीय क्षेत्र की योजना अनुसंधान और विकास के मूल्यांकन के लिए 'स्वतंत्र मूल्यांकन समिति' की अध्यक्षता की
8.	डीएआरपीजी, भारत सरकार, 2020	राष्ट्रीय ई-शासन पुरस्कार के लिए अनुवीक्षण समिति
9.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) 2020	भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए ट्रांस-डिसिप्लिनरी रिसर्च योजना के लिए अनुसंधान प्रस्तावों का मूल्यांकन (एसटीआरआईडीई)

ख. सामान्य अध्ययन के पंजाब राज्य सिविल सेवा अधिकारियों (विज्ञान और तकनीकी, जीवन विज्ञान भाग में आधुनिक रूझान) की भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करने वाला (सैटर)।

ग. इन्हूं में 'स्मार्ट सिटी कार्यक्रम' (ई-कॉर्मस (कॉर्स

कोड: बीसीओस-184); स्मार्ट सिटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, शासन और साइबर सुरक्षा (कॉर्स कोड: एमआई0- 004); शहरी स्थानीय शासन (कॉर्स कोड: बीपीएसी-110) में डिप्लोमा के लिए मुक्त दूरस्थ शिक्षण कार्यक्रम के लिए एमओओसी/स्वयं पाठ्यक्रमों के विकास हेतु विशेषज्ञ और सामग्री डिजाइनर

घ. भा.लो.प्र.सं. के बाहर लिए गए सत्रों की तालिका (बशर्ते बुलाया गया हो)

क्र.सं.	विषय	तिथि	आयोजन
1.	विविधता परिपेक्ष्य को व्यापक बनाने में मदद करती है: साइबर डोमेन के लिए इसे प्रभावी ढंग से कैसे लागू किया जाए"	मई 13, 2021	एसोचैम
2.	नागरिकों की डिजिटल पहचान, बिगेटेक और सरकार की त्रियामी व्यवस्था में व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक की भूमिका	मार्च 27, 2021	भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पोलिसी, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी)
3.	महामारी के प्रति स्मार्ट सिटी की प्रतिक्रिया	मार्च 24, 2021	भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन और एकजीवितान इंडिया ग्रुप
4.	अंतर्राष्ट्रीय साइबर और सूचना सुरक्षा सम्मेलन 2021 में साइबर और सूचना सुरक्षा	मार्च 15, 2021	वैश्विक आंतक रोधी परिषद
5.	साइबर की दुनिया में महिला: कुछ हटकर किया हुआ कार्य	मार्च 02, 2021	एसोचैम
6.	वर्ष 2020 के परे उभरता व्यापार, प्रबन्धन और सतत प्रतिमान	मार्च 29, 2021	नई दिल्ली प्रबन्धन संस्थान (एनडीआईएम) और पूर्वोत्तर प्रबन्धन संगठन (एनईएमए)
7.	उभरते सामाजिक ताने-बाने में डिजिटल संचार की भूमिका	मार्च 25, 2021	नोएडा में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट
8.	जन नीति के लाभ: शासन में डिजिटल परिवर्तन के विशेष संदर्भ में मौलिक पहलू	जनवरी 24, 2021	सेंट स्टिफन कॉलेज, दिल्ली

9.	सुरक्षा अनुसंधान अड़चन... लैब, कार्यक्रम की तैयारी, समस्या संबंधी विवरण, औद्योगिक संपर्क और डाटा सेट	दिसम्बर 14, 2020	डीएससीआई और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय और आईटी (MeiTY), भारत सरकार
10.	शिक्षण शिक्षा पर पुनर्विचार: व्यवहार्यता और चुनौतियां (संकाय प्रस्तावना कार्यक्रम)	नवम्बर 13, 2020	एचआरडीसी, बीपीएस वूमन यूनीवर्सिटी, कानपुर कलां, सोनीपत
11.	एएओएस का प्रस्तावना प्रशिक्षण	नवम्बर 3, 2020	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूनिकेशन फाइनेंस
12.	महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर क्राइम	अक्टूबर 16, 2020	साइबर पुलिसिंग बेस्ट प्रक्रियिंग मीट 2020 पर राष्ट्रीय स्तरीय आभासी सम्मेलन 2.0
13.	भारत में महिला पत्रकारों की सुरक्षा को बढ़ाना	अक्टूबर 16, 2020	यूनेस्को और सीएमएस
14.	टेलीरोबोटिक्स और 5जी, डिजिटल नोमेडिस के लिए मंच का निर्माण	अक्टूबर 7, 2020	रेज 2020
15.	भारत में 'शासन में रूपांतरण: मुद्रे और चिंताएं' पर संकाय विकास कार्यक्रम	सितम्बर 23, 2020	रामलाल आनन्द कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय
16.	उद्योग 4.0	सितम्बर 16, 2020	सीएसआई, इंजीनियरिंग कंप्यूटर विभाग, एफसीआरआईटी, वासी द्वारा आयोजित एंजेल कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट सिपोजियल-2020 (एसीईएसएस-2020)
17.	कोविड युद्ध कक्ष के रूप में स्मार्ट शहर	अगस्त 18, 2020	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय
18.	ई-शासन के आयात और भारत	जून 23, 2020	राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी, फरीदाबाद
19.	वर्तमान अशान्त समय में आदमी/मशीन संवेदनशीलता और आगे बढ़ना	अप्रैल 24, 2020	प्राइम इफोसर्व एलएलपी
20.	शासन में डाटा	अप्रैल 10, 2020	लॉरियेट्स अकादमी
21.	आईसीटी और शासन (पहला सत्र)	अप्रैल 8, 2020	लॉरियेट्स अकादमी
22.	कौशल और क्षमता निर्माण, एआई/मशीनी शिक्षा तथा भाषा	अप्रैल 2020	ई-शासन पर 23वां राष्ट्रीय सम्मेलन, डीएआरपीजी
23.	सोशल मीडिया और राज्य के नियम	दिसम्बर 2020	सिटीजन्स फोरम इंडिया
24.	महामारी के विरुद्ध स्मार्ट सिटी प्रतिक्रिया	मार्च 25, 2021	आईएमएस नोएडा
25.	आईसीटी और शासन: बदलते रुझान	14 अप्रैल 2020	अमेटी सूचना तकनीकी संस्था, अमेटी विश्वविद्यालय, उप्र, नोएडा
26.	2020 से परे उभरता व्यापार, प्रबन्धन और सतत प्रतिमान विज्ञय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	29 मार्च, 2021	न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (एनडीआईएम) और द नॉर्थ ईस्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन (एनईएम)

27.	एसटीईएम शिक्षा में महिलाएं	30 मार्च, 2021	ऑल इंडिया कार्डिनल फॉर रोबोटिक्स एंड ओटोमेशन (एआईसीआरए)
28.	वैश्विक परिदृश्य में स्मार्ट शहरों की स्थिति	जुलाई 11, 2020	जामिया हमदर्द, नई दिल्ली
29.	स्मार्ट शहर और कोविड 19	जून 6, 2020	सीईपीटी विश्वविद्यालय
30.	“खुले समावेशी और सुरक्षित डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाना-संयुक्त राज्य अमेरिका से सबक और इंडो-पैसिफिक राष्ट्र के लिए सहयोग के अवसर”	जून 3, 2020	अमेरिकी व्यापार विकास एजेंसी (यूएसटीडीए) और अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमेरिकी एजेंसी (यूएसएआईडी) के साथ विश्व बैंक

• “‘डाटा विज्ञान के महत्वपूर्ण पहलू’, डाटा की दुनिया शॉ पर राष्ट्रीय टेलीकास्ट, डीडी साइंस (डीडी नेशनल), नई दिल्ली

• एक लोकप्रिय मीडिया हाउस के लिए “डिजिटल साक्षरता और ई-कचरे को कम करने” के बारे में ग्रामीण युवा के लिए एक संदेश रिकॉर्ड किया

1. शाखाओं के साथ सहयोग: पुद्गुच्चेरी किसी अन्य शैक्षणिक या संबंधित गतिविधि का विवरण जिसे पहले शामिल नहीं किया गया है

“डिजीटल स्वच्छता-साइबर जगत में सुरक्षित रहे का प्रबन्धन” विषय पर सीडीएसी के विष्यात साइबर

सुरक्षा प्रशिक्षण को सफलता के साथ पूरा किया। (दिसम्बर 21-26 दिसम्बर 2020)

यह भी

1. तीन प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित
2. भा.लो.प्र.सं. में अधिकतम प्रकाशन लाने के लिए यू.सी. अग्रवाल सर्टिफिकेट ऑफ एप्रीसिएशन’ (भा.लो.प्र.सं. 2021) मिला
3. ग्लोबल स्मार्ट सिटीज लीडर अवार्ड (द वर्ल्ड कांग्रेस और ईटी, 2020)
4. ‘पावर वुमन अवार्ड’ (वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, लंदन, 2021)

कुसुम लता

क. शिक्षण/प्रशिक्षण

क (i) निवेशन

क्रम संख्या	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	नया/ पुनरावृत्ति	टिप्पणियां
1.	एलआईसी के एएओएस और एओएस के लिए नये सामान्य में एडवांस टाइम मैनेजमेंट फरवरी 24-26, 2021	3 दिन	नया	34 भागीदार फीस , रुपये 1000/भागीदार/प्रतिदिन
2.	एलआईसी के एडीएमएस और एओएस नये सामान्य में नेतृत्व क्वालिटी का विकास, मार्च 10-12, 2021	3 दिन	नया	35 भागीदार फीस , रुपये 1000/ भागीदार/प्रतिदिन

3.	<p>46वें अप्पा के लिए 'बुनियादी परियोजनाओं का विकास और प्रबन्धन' विषय पर स्ट्रीम, 28-30सितम्बर, 2020 (1 सत्र/प्रतिदिन) (5,8,9, 12, 13, 14 और 16 अक्टूबर 2020)</p>	10 सत्र	नया	28 भागीदार
----	---	---------	-----	------------

क (ii) शिक्षण	संख्या केवल
व्याख्यान की संख्या (दोहराए गए विषय) :	3
व्याख्यान की संख्या (नये विषय) :	9
कुल	12

क (iii) अन्य कार्य (घटों की संख्या केवल)	
पैनल चर्चाएं	:
समूह चर्चाएं	:
अभ्यास	:
मामलों पर चर्चाएं (केस डिस्कशन)	:

प्रशिक्षण प्रस्तावों की तैयारी/ ऑनलाइन माध्यम से
हुई कक्षाएः 330 घंटे

क (iv) शिक्षण के लिए अपने योगदान की मात्रा
और विषय को लेकर क्या आप संतुष्ट हैं? अपने
योगदान में सुधार के लिए उपाय सुझाएं

शिक्षण के लिए अपने योगदान की मात्रा और विषय को लेकर मैं संतुष्ट हूँ।

मैं अपनी रुचि से संबंधित साहित्य और डाटा का अधिक पठन और विश्लेषण करूँगी और शहरी संदर्भ में भारत सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों से स्वयं को अवगत कराऊँगी।

पूरी हो चुकीं अनुसंधान परियोजनाएं (श्रेणी क)
(वित्त पोषित और गैर वित्त पोषित दोनों अनुसंधानों
पर लाग)

पूरी हो चुकीं अनुसंधान परियोजनाएं (श्रेणी ख)

पहली परियोजना

- विषय: “मानव संसाधन प्रबन्धन” के अंतर्गत चल रही योजनाओं के लिए तीसरे पक्ष से मूल्यांकन

दूसरी परियोजना

- ## 2. विषयः राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) का तीसरे पक्ष से मूल्यांकन

चल रहीं अनुसंधान परियोजनाएं (श्रेणी ख)

- विषय: डाक कार्यों, परिसंपत्ति प्रबन्धन और भारत पोस्ट भुगतान बैंक का का तीसरे पक्ष से मूल्यांकन

(ग) अन्य कोई प्रकाशन

- I. विषय: 'स्मार्ट लिविंग के लिए भू-स्थानिक आसूचना- नई दिल्ली का मामला' (पृष्ठ 145-181)

- II. पुस्तिका/पत्रिका में अध्याय: “स्मार्ट शहरों के लिए स्मार्ट रहन-सहन खंड-2 सामुदायिक अध्ययन, मार्ग और माध्यम”

- ### III. स्थानः स्प्रिंगर नेचर द्वारा प्रकाशित

- IV. तिथि: जून 2020

- I. विषयः 'स्मार्ट वैश्वक महाशहरः चैन्नई सतत विकास खाका'

- ## II. पुस्तक में अध्याय: “स्मार्ट वैश्विक महाशहर”

- ### III. स्थानः प्रकाशक : स्प्रिंगर नेचर

- #### IV. तिथि : 12 फरवरी 2021 (अध्याय को प्रवृष्टि करने की तिथि)

- ज. संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों आदि में प्रस्तुत किए गए शोध पत्र

- ## I. सम्मेलनों का विषय: “आपदा, जोखिम और संवेदनशीलता (वनरेबिलिटी) सम्मेलन-2020”

- II. आयोजक एजेंसी: स्कूल ऑफ इंवायरोनमेंट साइंसेज, एमजी यूनीवर्सिटी, कोटटयम और भूविज्ञान विभाग, केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेंद्रम

III. स्थान और तिथि: कोट्टयम, केरल

IV. वित्त पोज़क एजेंसी:

V. अनुदान:

VI. प्रस्तुत किए गए शोध पत्र का विषय: आपदा प्रबन्धन में विज्ञान और तकनीकी

महामारियों का प्रबन्धन विषय पर आईजेपीए विशेषांक के लिए चार शोध पत्र प्रस्तुत किए

भा.लो.प्र.सं. के भीतर अकादमिक कार्य के अन्य स्वरूपों के साथ जुड़ाव

(क) समितियाँ/अन्य (विभाग और योजना और सलाहकार समिति, समन्वयकत्व, संपादकत्व, संयोजकता आदि की सदस्यता)- भागीदारी का ब्यौरा और प्रकृति। अनुसंधान स्टाफ के लिए चयन समिति और अनुसंधान परियोजना सदस्यता के लिए सलाहकार, जन और खबरखाव कार्य के लिए चयन समिति का सदस्य।

(ख) भा.लो.प्र.सं. के बाहर के अकादमिक कार्य के साथ सहयोग

(समितियों/मंडलों आदि की सदस्यता)

- 1) भा.लो.प्र.सं. की दिल्ली स्थित क्षेत्रीय शाखा का ईसी सदस्य
- 2) बाह्य सदस्य, योजना के लिए बीओएस, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, वाईएसआर आर्किटेक्चर और फाइन आर्ट्स यूनीवर्सिटी, 9

अनुसंधान निर्देशन

अक्टूबर 2020 से शुरू हुई तीन वर्ष की अवधि के लिए कड़पा

ज. शाखाओं के साथ सहयोग

शाखाएं प्रदत्त: मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़

गतिविधियों में शामिल:

I. प्रशिक्षण:

II. अनुसंधान/केस स्टडीज (मामलों की जांच):

III. सेमिनार/सम्मेलन:

ट. संगोष्ठियाँ/कार्यशालाओं/सम्मेलनों आदि में प्रस्तुत शोधपत्र

- 1) 03-08 नवम्बर, 2020 के दौरान “एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस इन अर्बन रेजिलिएंस प्लानिंग” विषय पर पेशेवर विकास कार्यक्रम में 7 नवम्बर 2020 (सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक) को ‘जियो स्पाइयल दिल्ली लि. एंड एनएसडीएल रिसोर्स’ पर विशेषज्ञ व्याख्यान दिया। इसका आयोजन उच्च शिक्षा में क्षमता निर्माण के क्षेत्र में यूरोपीय संघ, फ्रेसमस+ प्रोग्राम के तहत वित्त पोषित एक परियोजना “बिल्डिंग रेजिलिएंट अर्बन कम्युनिटीज (बीआरईयूकॉम) के अंतर्गत स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, विजयवाड़ा द्वारा किया गया।
- 2) किए गए अन्य अकादमिक कार्य अथवा संबंधित कार्यों का ब्योरा जिन्हें उपर्युक्त तथ्यों में शामिल नहीं किया गया

क्रम संख्या	शोध पत्र/प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट	प्रदत्त डिग्री
1.	45वें अप्पा के बिग्रेडियर चरणजीव मंजू द्वारा “भारतीय सेना के युद्धक दस्ते में महिलाएँ: उनकी संभावित नियुक्ति का एक अध्ययन”	एमडीपीए प्रदत्त
2.	45वें अप्पा के डॉ श्रवण कुमार द्वारा “बच्चों की फिल्म सोसाइटी भारत: एक जटिल अध्ययन”	एमडीपीए और एमफिल प्रदत्त
3.	46वें अप्पा के श्री विशाल गर्ग द्वारा “जल संकट: पंजाब में मुद्दे और चुनौतियाँ”	एमडीपीए दिया जाना है

- I. विषय: महामारी का प्रबन्धन, भा.लो.प्र.सं. सदस्यों का वार्षिक सम्मेलन के लिए विषय पत्र, अक्टूबर 2020। नई दिल्ली: आईआईपीए।
- II. पुस्तिकों/पत्रिका में अध्याय:
- III. स्थान: नई दिल्ली
- IV. तिथि: अक्टूबर 2020
- I. भा.लो.प्र.सं. के भीतर अकादमिक कार्य के अन्य स्वरूपों के साथ सहयोग।
- (क) समिति/अन्य (विभाग और योजना और सलाहकार समिति, समन्वयकत्व, संपादकत्व, संयोजकता आदि की सदस्यता)- भागीदारी का ब्यौरा और प्रकृति।
- i. अनुसंधान स्टाफ के लिए चयन समिति का सदस्य
- ii. वार्षिक प्रतियोगिता अध्ययन विषय की प्रवृष्टियों का मूल्यांकन किया।
- iii. 'कोविड-19' के दुष्परिणाम में लोक सेवा की डिलीवरी पर एक्सेस यूनीवर्सिटी के प्रो. अरुण और पूर्व विश्व बैंक विशेषज्ञ डॉ विक्रम चंदके साथ वेबीनार आयोजित किया।
- iv. उत्तम लेख पुरस्कार के लिए आईजेपीए लेखों का मूल्यांकन किया
- v. कर्नाटक में लोक सेवा अधिनियम के अधिकार पर 46वें अप्पा भागीदार ब्रिगेडियर सूरज के शोध पत्र
- का पर्यवेक्षण किया।
- (ख) भा.लो.प्र.सं. के बाहर के कार्य के साथ सहयोग (समितियों/मंडलों आदि की सदस्यता)
- ज. शाखाओं के साथ सहयोग
- प्रदत्त शाखा: मणिपुर
- गतिविधियों में शामिल होना:
- I. प्रशिक्षण:
- II. अनुसंधान/अध्ययन का विज्ञय:
- III. सेमिनार/सम्मेलन:
- ट. भा.लो.प्र.सं. के बाहर किए गए अन्य अकादमिक कार्य का ब्योरा
- ठ. किए गए अन्य अकादमिक कार्य अथवा संबंधित गतिविधि का ब्योरा जिन्हें उपर्युक्त में शामिल नहीं किया गया
1. यूएलबी में पुरुष और महिला पार्षदों की स्थिति पर प्रश्न पर एमओएचयू के लिए मिजोरम और पश्चिम बंगाल यूडी विभागों के साथ समन्वय (जुलाई 20, 2020)।
2. एमएसएमई मंत्रलय के एमएसएमई हेल्पलाइन के लिए प्रस्ताव की तैयारी और उसकी प्रस्तुति।
3. एमएसएमई मंत्रलय की स्वतंत्र पुष्टि एजेंसी के लिए प्रस्ताव की तैयारी और उसकी प्रस्तुति।

नीतू जैन

क. शिक्षण/प्रशिक्षण

क (i) निवेशन

क्रम संख्या	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	नया/पुनरावृत्ति	टिप्पणियां
1.	9वां एडवांस्ड लीडरशिप कोर्स (अग्रिम नेतृत्व पाठ्यक्रम)	3 सप्ताह	नया	निजी क्षेत्र के उद्यमों के अधिकारियों के लिए आयोजित
2.	मानव संसाधान प्रबन्धन पाठ्यक्रम	2 सप्ताह	नया	एमईएस के मुख्य अभियंता श्रेणी के अधिकारियों के लिए

3.	प्रबन्धन विकास कार्यक्रम	10 महीने	नया	अप्पा में दो पाठ्यक्रम शामिल किए गए
4.	लोक प्रशासन में 46 वां एडवांस्ड पेशेवर कार्यक्रम	10 महीने	नया	अप्पा में दो पाठ्यक्रम शामिल किए गए

क (ii) शिक्षण

	केवल संख्या
व्याख्यानों की संख्या (दोहराए गए विषय)	5
व्याख्यानों की संख्या (नए विषय)	7
कुल	12

क (iii) अन्य कार्य (घंटों की संख्या केवल)

पैनल चर्चाएं :	3
समूह चर्चाएं :	4
अध्यास :	10
केस डिस्कशन (मामलों पर चर्चाएं) :	5
प्रशिक्षण प्रस्तावों की तैयारी :	6

पूरी हो चुकीं अनुसंधान परियोजनाएं

(श्रेणी क) (वित्त पोषित और गैर वित्त पोषित दोनों अनुसंधानों पर लागू)

पूरी हो चुकी परियोजना में शामिल की जानी है:

- विषय: डीएआरएंडपीजी की “प्रशासनिक सुधार के लिए योजना” का तीसरे पक्ष से मूल्यांकन।

चल रहीं अनुसंधान परियोजनाएं (श्रेणी क)

- विषय: सीएपीएफ में दुर्घटना और आत्महत्या के मामलों का तुलनात्मक विश्लेषण और सुधारात्मक उपाय।

चल रही परियोजनाएं (श्रेणी ख)

- विषय: भारत में प्रशिक्षण संस्थानों का उत्पादन और परिणाम का मूल्यांकन।

प्रकाशन

शोध पत्र और लेख

वार्षिक रिपोर्ट

- कार्यकारी शिक्षा और आजीविका उन्नयनः सतत रोजगार, राष्ट्रीय शिक्षा योजना और प्रशासन संस्थान, दिल्ली, रुटलेज, 2021 द्वारा लाई गई एक नीति रिपोर्ट में प्रकाशन के अधीन है।
- अध्याय विषय ‘रिविजिटिंग एचआर लेसन’: डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडी और संबंधित लेखन के पाठों ने अनंत गिरी, माइकल जिर्कलर और दिव्या कीर्ति द्वारा संपादित पुस्तक 6न्यू वर्क्स इन कॉन्सियसनेस कॉरिडोर्स’ में योगदान दिया।
- एमएआईएमएस, दिल्ली द्वारा प्रकाशित सम्मेलन कार्यवाही की एक पुस्तक में प्रकाशित की गई ‘ट्रांसफॉर्मिंग एचआर पर्सेपेक्टिव बाइ एचआर एनालिटिक्स’।
- ‘केन्द्रीय सतर्कता आयोग: ऐतिहासिक भारतीय विश्व दृष्टिकोण और राज्य कौशल पर आधारित एक परिप्रेक्ष्य’ विषय का शोधपत्र भारतीय लोक प्रशासन पत्रिका में प्रकाशित हुआ, मार्च, 2021।

ज. सेमिनारों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों आदि में प्रस्तुत शोध पत्र

- नवम्बर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन (एफआईबीसी) 2020 में नए वैश्विक वास्तविकताओं में व्यापार का भविष्य पर फॉर्म स्कूल मैनेजमेंट द्वारा आयोजित ‘कोविड-19 महामारी के दौरान संगठनों के अभिनव मानव संसाधान प्रथाओं का अध्ययन’ विषय पर प्रस्तुत किया गया शोध पत्र।
- एमएआईएमएस, आई.पी विश्वविद्यालय द्वारा लिंकन विश्वविद्यालय, मलेशिया के सहयोग से आयोजित 82 भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में एमएआईएमएस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ‘शिक्षा, प्रबन्धन विज्ञान, आईटी, कानून प्रवर्तन और मीडिया पर डिजीटलीकरण का प्रभाव’ में ‘जेन वाई की

पारस्परिक आवश्यकता प्रोफाइल का आकलन' पर शोध पत्र प्रस्तुत किया।

ज. भा.लो.प्र.सं. के भीतर अकादमिक कार्य के अन्य स्वरूपों के साथ सहयोग

(क) समितियाँ/अन्य (विभाग और योजना और सलाहकार समिति, समन्वयकत्व, संपादकत्व, संयोजकता आदि की सदस्यता)- भागीदारी का ब्योरा और प्रकृति।

- पर्यवेक्षक के रूप में एक अप्पा भागीदार को उसके शोध पत्र के लिए मार्गदर्शन किया।
- 30 दिसम्बर, 2020 को 'ब्रेकिंग द ग्लास सिलिंग इन पीएसयू: चैलेंजस एंड इंटरवेंशन' विषय पर सरोज मेमोरियल व्याख्यान का संचालन किया।
- 20 मई, 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान भावना लोचता निर्माण में 'नेतृत्व भूमिका' विषय पर वेबीनार का आयोजन किया।
- 10 मार्च, 2021 को हरियाणा क्षेत्रीय शाखा के सहयोग से 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' विषय पर

वेबीनार का संचालन किया।

• 9-13 नवम्बर, 2020 के दौरान एआईसीटीई ट्रेनिंग और लर्निंग अकादमी द्वारा आयोजित 'संगठनात्क व्यवहार' विषय पर ऑनलाइन एफडीपी में शामिल हुई।

• 7-11 सितम्बर, 2020 के दौरान एआईसीटीई ट्रेनिंग और लर्निंग अकादमी द्वारा आयोजित 'रिस्पोंस इफेक्टिवनेस, ऑर्गेनाइजिंग सेल, एटीट्यूडनियल शिफ्ट, डिसिजन मेकिंग' विषय पर ऑनलाइन एफडीपी में शामिल हुई।

(ख) भा.लो.प्र.सं. के बाहर के अकादमिक कार्य के साथ सहयोग

(समितियाँ/मंडलों आदि की सदस्यता)

नेशनल एचआरडी नेटवर्क का आजीवन सदस्य कुछ अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं के शोध पत्र की पुनर्समीक्षा की

ग. किसी अन्य शैक्षणिक या संबंधित गतिविधि का विवरण जिसे पहले शामिल नहीं किया गया है

साकेत बिहारी

क. शिक्षण/प्रशिक्षण

क्रम संख्या	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	नया/पुनरावृत्ति	टिप्पणियाँ
1.	एलआईसी एएओएस के लिए संवादात्मक ऑनलाइन कार्यक्रम	फरवरी 24-26, 2021	नया	संचालित
2.	एलआईसी एएओएस के लिए संवादात्मक ऑनलाइन कार्यक्रम	मार्च 10-12, 2021	पुनरावृत्ति	संचालित

क (ii) क्या आप शिक्षण में अपने योगदान की मात्रा और विषय से संतुष्ट हैं?

हां, दिए गए विषय में संतुष्ट हूं

क (iii) शिक्षण संख्या केवल:

व्याख्यानों की संख्या (दोहराए गए विषय) = 8

व्याख्यानों की संख्या (नए विषय) = 4

ख. पूरी हो चुकीं परियोजनाएं (श्रेणी क) (वित्त

पोषित और गैर वित्त पोषित दोनों अनुसंधानों पर लागू)

1. विषय: केवीआईसी, लखनऊ, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित पीएमईजीपी इकाईयों का भौतिक सत्यापन
2. पूर्वोत्तर, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की विज्ञापन और प्रचार योजना का तृतीय-पक्ष मूल्यांकन
3. विषय: 'पूर्वोत्तर क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवाएं' पर

- केन्द्रीय क्षेत्र की योजना का तीसरा-पक्ष मूल्यांकन (डॉ वीएन आलोक के साथ)
4. अध्ययन का नाम: 'पूर्वोत्तर क्षेत्र में नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम पर तीसरा-पक्ष मूल्यांकन (डॉ वी. एन. आलोक के साथ)
 5. अध्ययन का नाम: 'पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम पर केन्द्रीय क्षेत्रों की योजना का तीसरा-पक्ष मूल्यांकन (डॉ वी. एन. आलोक के साथ)
 6. अध्ययन का नाम: केन्द्रीय नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के 'सूचना और जन जागरूकता कार्यक्रम' पर तीसरा-पक्ष मूल्यांकन (डॉ वी. एन. आलोक के साथ)
 1. अध्ययन का नाम: अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय, भारत सरकार की नया सवेरा और नई उड़ान योजनाओं का तीसरा-पक्ष मूल्यांकन (डॉ सी. शीला रेड्डी के साथ)
 2. अध्ययन का नाम: पेट्रोकेमिकल्स की नई योजनाओं (i) प्लास्टिक पार्कों की स्थापना और (ii) केन्द्रीय और उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना का तीसरा-पक्ष मूल्यांकन (प्रो. अशोक विशनदास के साथ)
 3. अध्ययन का नाम: राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम की केन्द्रीय क्षेत्र योजना का तीसरा-पक्ष मूल्यांकन (आरवाईएके)
 4. अध्ययन का नाम: राष्ट्रीय सेवा योजना, एमओवाईएस, भारत सरकार का तीसरा-पक्ष मूल्यांकन (डॉ कुसुम लता के साथ)
 5. अध्ययन का नाम: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमवीवाई), एमएसडीई, भारत सरकार का तीसरा-पक्ष मूल्यांकन
 12. अध्ययन का नाम: जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), एमएसडीई, भारत सरकार का तीसरा-पक्ष मूल्यांकन
 13. अध्ययन का नाम: वामपंथी अतिवादी प्रभावित 47 जिलों में कौशल विकास का तीसरा-पक्ष मूल्यांकन
 14. अध्ययन का नाम: 1393 सरकारी, आईटीआई, एमएसडीई, भारत सरकार के उन्नयन का अध्ययन का तीसरा-पक्ष मूल्यांकन
 15. अध्ययन का नाम: एटीआई योजना, एमओएमएसएमई, भारत सरकार का तीसरा-पक्ष मूल्यांकन
 16. अध्ययन का नाम: डाक विभाग, डीओपी, भारत सरकार की आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 2012 का तीसरा-पक्ष मूल्यांकन
 3. चल रहीं अनुसंधान परियोजनाएं (श्रेणी ख): लागू नहीं
 4. तैयार किया गया अध्ययन का विषय: शून्य
 5. प्रकाशन: शून्य
 6. सेमिनारों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों आदि में प्रस्तुत किए गए शोध पत्र
- समाजशास्त्र विभाग, डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर द्वारा आयोजित 'सामाजिक अनुसंधान में पद्धति' पर दो व्याख्यान दिए
- भा.लो.प्र.सं.** के भीतर अकादमिक कार्य के अन्य स्वरूपों के साथ सहयोग
1. सह-संपादक: लोक प्रकाशन (हिन्दी)
 2. भा.लो.प्र.सं. की विभिन्न आंतरिक समितियों के साथ समन्वयन किया
 3. भा.लो.प्र.सं. के एपीपीपीए कार्यक्रम के अंतर्गत एमफिल शोधपत्र का संचालन किया
 4. सीडीएमपी की तैयारी के लिए बीएसडीएमए पटना में आयोजित कार्यशाला में भाग लिया
 5. भा.लो.प्र.सं. में दो वेबीनारों का समन्वयन किया

रोमा मित्रा देबनाथ

क. शिक्षण/प्रशिक्षण

क (i) निर्देशन

क्रम संख्या	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	नया/पुनरावृति	राजस्व प्राप्त	टिप्पणियां
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लोक प्रशासकों के लिए उन्नत डाटा विश्लेषण पर क्षमता विकास कार्यक्रम	एक सप्ताह सितम्बर 21–25, 2020	नया	6 लाख	जीएनसीटीडी योजना विभाग से 25 प्रशासक
2.	बिगनर्स के लिए डाटा विश्लेषण पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑनलाइन)	एक सप्ताह (मार्च 22 से 26, 2021)	नया	2.55 लाख रुपये	23 देशों के 40 पेशेवरों के लिए ई-आईटीईसी कार्यक्रम
3.	गैर वित्तीय पृष्ठभूमि वाले शीर्ष नेतृत्व के लिए वित्त पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (ऑनलाइन)	एक सप्ताह (मार्च 8 से 12, 2021)	नया	2.55 लाख रुपये	16 देशों के 40 पेशेवरों के लिए ई-आईटीईसी कार्यक्रम
4.	सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों का प्रबन्धन	एक सप्ताह (जनवरी 20–24, 2020)	नया	अप्पा का भाग	आईए, आईएएफ, आईएनएस, आईसीजी, आईईएस, एमईएस और आईटीएस केडर के 29 अधिकारी
5.	सार्वजनिक क्षेत्र के लिए डाटा विश्लेषण	दो सप्ताह (10 सप्त)	नया	अप्पा का भाग	आईए, आईएएफ, आईएनएस, आईसीजी, आईईएस, एमईएस और आईटीएस केडर के 29 अधिकारी
6.	अनुसंधान पद्धति और अनुसंधान के तरीके: मात्रात्मक, गुणात्मक तरीके और निबन्ध प्रोटोकॉल	दो सप्ताह (10 सप्त)	नया	अप्पा का भाग	आईए, आईएएफ, आईएनएस, आईसीजी, आईईएस, एमईएस और आईटीएस केडर के 29 अधिकारी

क (ii) शिक्षण

व्याख्यानों की संख्या (दोहराए गए विषय)

केवल संख्या

30

व्याख्यानों की संख्या (नए विषय)

30

कुल

60

क (iii) अन्य कार्य (घंटों की संख्या केवल)

पैनल चर्चाएं

: 10

समूह चर्चाएं

: 30

अभ्यास

: 30

केस डिस्कशन (मामलों पर चर्चाएं) : 30
प्रशिक्षण प्रस्तावों की तैयारी : 100

हां

अपने योगदान में सुधार के तरीके सुझाएं

क (iv) क्या आप शिक्षण में अपने योगदान की
मात्र और विषय से संतुष्ट हैं?

कक्षा में चर्चा के लिए अधिक ऑनलाइन पाठ्यक्रम
सामग्री के विकास की आवश्यकता

पूरी हो चुकीं अनुसंधान परियोजनाएं (श्रेणी क) (वित्त पोषित और गैर वित्त पोषित दोनों अनुसंधानों पर लागू)

क्रम संख्या	नाम	द्वारा प्रायोजित	अध्ययन दल	स्थिति	बजट
1.	'अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला और ईडब्ल्यूएस के लिए रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम के लिए परियोजना' सीएसआर का प्रभाव आकलन अध्ययन	विद्युत वित्त निगम लि.	डॉ रोमा देबनाथ मित्रा डॉ पवन के. तनेजा	अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की	रुपये 3 लाख (लगभग)
2.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रलय की पूर्व आईईसी योजना स्वस्थ नागरिक अभियान (एसएनए) का त्वरित मूल्यांकन	नीति आयोग	डॉ रोमा देबनाथ मित्रा डॉ पवन के. तनेजा	अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की	रुपये 23.7 लाख (लगभग)
3.	राष्ट्रीय एडस नियंत्रण कार्यक्रम आईवी का मूल्यांकन	नाको, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	डॉ रोमा देबनाथ मित्रा डॉ पवन के. तनेजा	अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की	रुपये 39.8 लाख जीएसटी
4.	आईएसटीएम योजना पर प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार का तीसरा पक्ष मूल्यांकन	आईएसटीएम, डीओपीटी	डॉ रोमा देबनाथ मित्रा डॉ पवन के. तनेजा	अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की	रुपये 4 लाख (लगभग)

जारी अनुसंधान परियोजनाएं (श्रेणी क)

क्रम संख्या	नाम	द्वारा प्रायोजित	अध्ययन दल	स्थिति	बजट
1.	पेंशनर्स पोर्टल का मूल्यांकन	पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग, भारत सरकार	डॉ रोमा देबनाथ मित्रा डॉ पवन के. तनेजा	डाटा संग्रहण का काम जारी है	रुपये 4 लाख
2.	डाक विभाग की योजनाओं का तीसरा पक्ष मूल्यांकन	डाक विभाग	डॉ रोमा देबनाथ मित्रा डॉ कुसुम लता	अंतिम राशि अभी प्राप्त की जानी है	रुपये 35 लाख

शोध पत्र और लेख

देबनाथ एम. रोमा (2020), “गूगल और अविश्वासः भारत से प्रमाण” का प्रकाशन ग्लोबल एनसाइक्लोपीडीया ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी, एंड गर्वनेंस, स्प्रिंगर इंटरनेशनल पब्लिशिंग में करने के लिए स्वीकृति मिली (Print + eBook ISBN 978-3-319- 20929-6, eReference ISBN 978-3-319-20928- 9, Print ISBN 978-3-319-20927-2)

पुस्तकें

1. 2020 के भावनात्मक आसूचना संग्रह की प्रस्तुती और भा.लो.प्र.सं. और एफईआईएल द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित सबसे प्रशंसित नेताओं, वक्ताओं और पैनल चर्चाओं के शिखर सम्मेलन और पुरस्कार का कवरेज। (https://www.amazon.com/Emotional-Intelligence-Compendium-Paper-Presentations/dp/B08M8GVXGK/ref=sr_1_4?dchild=1&keywords=ashis+s+en&qid=1605538894&sr=8-4; ISBN-13 : 979-8555451286; ASIN : B08M8GVXGK)

amazon.com पर पेपरबैक संस्करण (अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान)

https://www.amazon.com/Emotional-Intelligence-Compendium-Paper-Presentations/dp/B08M8GVXGK/ref=sr_1_4?dchild=1&keywords=ashis+s+en&qid=1605538894&sr=8-4

amazon.com पर किंडल संस्करण (अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान)

https://www.amazon.com/Emotional-Intelligence-Compendium-Paper-Presentations-ebook/dp/B08M5ZL95D/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=ashis+s+en&qid=1605539613&sr=8-1

amazon.in पर पेपरबैक संस्करण (भारत)

https://www.amazon.in/Emotional-Intelligence-Compendium-Paper-Presentations/dp/1637140568/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=ashis+s+en&qid=1605538868&sr=8-2

ISBN-10 : 1637140568

Notionpress.com पर पेपरबैक संस्करण (भारत) <https://notionpress.com/read/emotional-intelligence-1340925>

1. भा.लो.प्र.सं. के भीतर के अकादमिक कार्य के अन्य स्वरूपों के साथ सहयोग
(क) समिति/अन्य (विभाग और योजना और सलाहकार समिति, समन्वयकत्व, संपादकत्व, संयोजकता आदि की सदस्यता) – भागीदारी का व्योरा और प्रकृति
1. 16 से 20 फरवरी 2021 तक लर्निंग एंड डेवलपमेंट एलिसियन 2021 शिखर सम्मेलन और पुरस्कारों पर एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया
2. एपीपीपीए भागीदारों के लिए भा.लो.प्र.सं. में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला में अनुसंधान प्रस्ताव प्रस्तावीकरण
3. सदस्य, आर्थिक विकास और प्रबन्धन केन्द्र
4. सदस्य, चयन समिति (अनुसंधान)
5. समन्वयक, नई शिक्षा नीति: कार्यान्वयन चुनौतियां और आगे का मार्ग विषय पर टाउन हॉल चर्चा
6. समन्वयक, “सामरिक और परोपकारी सीएमआर: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए महामारी के बाद की चुनौतियां और अवसर” विषय पर वेबीनार

(ख) भा.लो.प्र.सं. के बाहर अकादमिक कार्य के साथ सहयोग

(समितियों/मंडलों आदि की सदस्यता)

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, यूएनएड्स, यूएनडीपी, डब्ल्यूएचओ, आदि द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के वित्तपोषण के लिए योजना पर राष्ट्रीय परामर्श बैठक V चरण

राष्ट्रीय एडस नियंत्रण संगठन, एसएसीएस के लिए एमओएचएफडब्ल्यू, डब्ल्यूएचओ, ग्लोबल फंड, यूनीसेफ, आदि द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एडस नियंत्रण कार्यक्रम IV और इसकी विस्तार अवधि (2013-2020) के मूल्यांकन की खोज पर प्रसार कार्यशाला

अनुसंधान निदेशन

क्रम संख्या	डिग्री	उम्मीदवार	विषय
1.	एम फिल	डॉ पी के मिश्रा	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का बहुभाषावाद पहलू: स्कूलों में कार्यान्वयन की चुनौतियां और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने का रास्ता
2.	एम फिल	श्री सुकुमार	आंतक के नियंत्रण में सुयक्त राज्य की भूमिका: 9/11 बाद का मूल्यांकन
3.	समर इंटरेशिप के लिए बिट्स पिलानी के विद्यार्थियों को निदेशित किया	श्री आदित्य सेठ श्री अनिकेत एमपी श्री विरल तिवारी	लोक प्रशासन के विभिन्न क्षेत्र

नुपूर तिवारी

क. शिक्षण/प्रशिक्षण

क (i) निदेशन

क्रम संख्या	पाठ्यक्रम का नाम अवधि	नया/पुनरावृत्ति	टिप्पणियां
-------------	-----------------------	-----------------	------------

- सीओई, जनजातीय मामले द्वारा आयोजित “जनजातीय अनुसंधान संस्थानों की क्षमता निर्माण और सुदृढ़ीकरण” विषय पर प्रशिक्षण। इसमें देश भर के टीआरआई के सभी प्रमुखों ने 28-29 जनवरी, 2020 को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में भाग लिया था।
- 25-26 फरवरी, 2020 को भा.लो.प्र.सं. में “पीएफएमएस ईट मॉड्यूल” पर एनजीओ के साथ प्रशिक्षण
- जनजातीय बुद्धिजीवियों और समावेशन पर प्रशिक्षण, जिसे कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज,

ज. शाखाओं के साथ सहयोग

- सौंपी गई शाखाएँ: पश्चिम बंगाल और मेघालय
- किए गए कोई अन्य आकदमिक अथवा संबंधित कार्य का व्योरा जिन्हें उपर्युक्त में शामिल नहीं किया गया

भुवनेश्वर में 28 और 29 फरवरी, 2020 के दौरान जनजातीय मामले के मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रायोजित किया है।

- 13-14 अगस्त 2020 को जनजातीय टैलेंट पूल पर प्रशिक्षण।
- 13 अक्टूबर 2020 को जनजातीय टैलेंट सम्मेलन पर प्रशिक्षण, उत्कृष्टता केन्द्र, भा.लो.प्र.सं।
- 30 नवम्बर 2020 को एनएफएसटी स्कॉलर्स के अनुसंधान की गुणवत्ता उन्नयन के लिए-क्षमता निर्माण प्रारूप पर प्रशिक्षण, एमओटीए और उत्कृष्टता केन्द्र।
- 4 दिसम्बर 2020 को जनजातीय टैलेंट पूल “जनजातीय विद्वान और विकास योजनाएं” पर प्रशिक्षण, उत्कृष्टता केन्द्र, भा.लो.प्र.सं।
- 28-30 जनवरी 2021 को जनजातीय सतत विकास पर बहु-विषयक दृष्टिकोण पर प्रशिक्षण।

9. 21-27 सितम्बर, 2020 को “आदिवासी अनुसंधान संस्थान का सुधार और सुदृढ़ीकरण पर प्रशिक्षण, उत्कृष्टता केन्द्र, भा.लो.प्र.स.।
10. भा.लो.प्र.स. में 3-4 सितम्बर, 2020 को राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन पर प्रशिक्षण: जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई), उत्कृष्टता केन्द्र, अनुसंधान संगठन।
11. जनजातीय अनुसंधान संस्थान के पुनरुद्धार और सुदृढ़ीकरण के लिए राष्ट्रीय परामर्श पर रोडमैप पर प्रशिक्षण और राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान, जनजातीय मामले के मंत्रालय और उत्कृष्टता केन्द्र, जनजातीय मामले का केन्द्र, भा.लो.प्र.स., 10 सितम्बर, 2020।
12. भारतीय लोक प्रशासन पर 29-30 जनवरी, 2020 के दौरान “जनजातीय अनुसंधान संस्थानों की क्षमता निर्माण और सुदृढ़ीकरण” पर दो-दिवसीय प्रशिक्षण।

कार्यशाला/सम्मेलन

1. 25 जून 2020 को जनजातीय समुदाय के लिए डिजिटल कौशल और मेंटरशिप पर गोल (गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स) वेबीनार।
2. 29 मई 2020 को “कोविड-19, द फलेक्सीबिलिटी स्टीग्मा एंड जेंडर इक्वलिटी” पर वेबीनार।
3. 25, 26 फरवरी 2020 को भा.लो.प्र.स. में “पीएफएमएस ईंट मॉड्यूल” पर गैर सरकारी संगठन के साथ परामर्श कार्यशाला।

क (ii) शिक्षण

46वां अप्पा :
निम्नलिखित के विज्ञय प्रभारी :

विकास में लिंग पर पाठ्यक्रम

केवल संख्या

12 व्याख्यान

जनजातीय क्षेत्रों में विकासात्मक
चुनौतियों पर पाठ्यक्रम

12 व्याख्यान

अप्पा

कुल

34 व्याख्यान

क (iii) अन्य कार्य (घंटों की संख्या केवल)

पैनल चर्चाएं

1. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के साथ आयोजित “एफआरए और पीईएसए के माध्यम से जनजातीय अधिकारों की रक्षा: मुद्रे, चुनौतियां और आगे की राह” विषय पर ओपन हाउस डिस्कशन (तिथि जनवरी 2020)

2. 20 मार्च, 2020 को आईआईपीए में “आदिवासी-केन्द्रीत सतत आजीविका सृजन और अभिनव अभ्यास” विषय पर पैनल चर्चा

क (iv) क्या आप शिक्षण के अपने योगदान की मात्रा और विषय से संतुष्ट हैं?

हां, मैं संतुष्ट हूं

1. पूरी हो चुकीं अनुसंधान परियोजनाएं (श्रेणी क) (वित्त पोषित और गैर वित्त पोषित अनुसंधान दोनों पर लागू)।

विषय: जनजातीय महोत्सव, अनुसंधान सूचना और जन शिक्षा योजना और निगरानी और मूल्यांकन का तीसरा पक्ष मूल्यांकन

II. पूरी हो चुकीं परियोजनाएं (श्रेणी क) (वित्त पोषित और गैर वित्त पोषित दोनों पर लागू)

1. विषय: न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लघु वानकीय उत्पाद (एमएफपी) और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला विकास के विपणन के लिए तंत्र

III. चल रहीं परियोजनाएं (श्रेणी क)

1. विषय: भारत में जनजातीय केंद्रित सतत आजीविका सृजन और नवाचारयुक्त कार्य

IV. चल रहीं परियोजनाएं (श्रेणी ख)

विषय: “टीआरआई अनुसंधान का भंडार”

छ. प्रकाशन

(क) पुस्तक और विशेष निबंध

1. स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के रूप में पंचायतें:

- समावेश और बहिष्करण के मुद्दे (कनिष्ठ प्रकाशन)
2. संस्कृति को हथियार बनाना: माओवादी विद्रोह और जनजातीय स्वशासन कृते डॉ नूपुर तिवारी
 3. जनजातीय अध्ययन की कला की स्थिति: एक व्याख्यात्मक ग्रंथ सूची
 4. पेसा और वामपंथी उग्रवादः झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के चरमपंथी प्रभावित क्षेत्रों का एक अध्ययन
 5. जनजातीय विकास और समावेशी नीति
 6. जनजातीय स्वशासन: पेसा और इसका कार्यान्वयन
 7. जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के लिए एक व्यवस्थित प्रशिक्षण मॉड्यूल “क्षमता निर्माण प्रारूपः बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षण प्रक्रिया”
 8. लघु वानकीय उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के मूल्यांकन पर रिपोर्ट
 9. जनजातीय केंद्रित सतत आजीविका सृजन और नवाचारयुक्त कार्य
 10. कार्यवाहियों की रिपोर्टः जनजातीय विकास के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच बातचीत के लिए एक मंच का निर्माण
 11. जनजातीय, बुद्धिजीवियों और समावेशन पर कार्यशाला पर रिपोर्टः एक आवश्यकता आधार मूल्यांकन
 12. जनजातीय योग्यता पूल के लिए मूल्यांकन और प्रशिक्षण सुदृढ़ीकरण पर रिपोर्ट, “गुणात्मक और मात्रात्मक पहल अनुसंधान पद्धति और सीएपीआई का इस्तेमाल करते हुए डाटा संग्रहण”
 13. ‘भारत की जनजातियों में असंतोष, अशांति और उग्रवाद के कारणों से निपटने के लिए विकास के मद्दे’ पर रिपोर्ट
 14. जनजातीय विकास, पैनल चर्चा और मंथन सत्र के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच संवाद के लिए
- एक मंच के निर्माण पर रिपोर्ट
15. ‘लाल गलियारा में अत्याचार और वामपंथी उग्रवाद’
 16. जनजातीय परंपराओं और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के संरक्षण पर रिपोर्ट
 17. “जनजातीय केंद्रित सतत आजीविका सृजन और नवाचारयुक्त कार्य” पर हुई पैनल चर्चा पर रिपोर्ट
 18. दो दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श “जनजातीय अनुसंधान संस्थान की क्षमता निर्माण और सुदृढ़ीकरण” पर रिपोर्ट
 19. जनजातीय टिकाऊपन विषय पर बहु-अनुशासनात्मक प्रयास पर जनजातीय योग्यता पूल आभासी सम्मेलन पर रिपोर्ट, 28-30 जनवरी, 2021
 20. जनजातीय योग्यता पूल, जनजातीय छात्रवृत्ति और सरकारी योजनाएं विषय पर विकास रिपोर्ट, 4 दिसम्बर, 2020
 21. जनजातीय योग्यता पूल जनजातीय सम्मलेन पर रिपोर्ट, 13 अक्टूबर, 2020
 22. ‘अनुसंधान पद्धतिः गुणात्मक और मात्रात्मक पहल और सीएपीआई का इस्तेमाल करते हुए डाटा संग्रहण’ पर जनजातीय योग्यता पूल पर रिपोर्ट
 23. राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलनः जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई), उत्कृष्टता केन्द्र, अनुसंधान संगठन पर रिपोर्ट, 3-4 सितम्बर, 2020
 24. ‘जनजातीय योग्यता पूल पर राष्ट्रीय परामर्श’ पर रिपोर्ट, 13-14 अगस्त, 2020
 25. कोविड-19, “लैंकिसबिलिटी स्टीग्मा और लैंगिक समानता’ पर वेबीनार
 26. ‘भारत में जनजातीय केंद्रित सतत आजीविका सृजन और नवाचारयुक्त कार्य’ पर पैनल चर्चा पर रिपोर्ट, आईआईपीए में 20 मार्च को
 27. ‘जनजातीय विकास और परंपराओं पर लाल गलियारे में हिंसा का प्रभाव’ विषय पर एक सारगर्भित पुस्तक

28. 'जनजातीय विकास के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच वार्ता के लिए एक मंच का निर्माण' पर पैनल चर्चा और मंथन सत्र पर रिपोर्ट, फरवरी, 2020
29. 'क्षमता निर्माण प्रारूपः प्रदर्शन सुधार के लिए प्रशिक्षण प्रक्रिया (टीआरआई के लिए एक पद्धतिबद्ध प्रशिक्षण मॉड्यूल)', 29-30 जनवरी, 2020
30. 'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय वित्तीय विकास निगम को सहायता' पर मूल्यांकन अध्ययन रिपोर्ट
31. 'भारत में जनजातीय केन्द्रित सतत आजीविका सृजन और नवाचार कार्य' पर पैनल चर्चा पर रिपोर्ट, आईआईपीए में 20 मार्च, 2020 को
32. 'जनजातीय विकास और परंपराओं पर लाल गलियारे में हिंसा का प्रभाव' पर सारगर्भित एक पुस्तिका

शोध पत्र/लेख

1. "कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में पंचायत सबसे आगे होने चाहिए" <http://www.governancenow.com/views/columns/in-covid19-panchayats-should-be-at-the-centre-stage>
2. सतत स्वास्थ्य के लिए सहकारी सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के रूप में परिपत्र लेख पत्र प्रबन्धन, बी.एन. वेन स्ट्रैटन और नूपुर तिवारी, जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, खंड 8, संख्या 3 मार्च 2020
3. ई-ग्राम स्वराज पोर्टल: पहला क्रांतिकारी कदम, शासन अब- अप्रैल 20, 2020 <http://www.governancenow.com/views/columns/egram-swaraj-portal-the-revolutionary-first-step>
4. सेमिनारों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों आदि में शोध पत्र की प्रस्तुति
1. जनजातीय विकास और परंपराओं पर लाल गलियारे में हिंसा का प्रभाव विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार में प्रस्तुत किया गया शोध पत्र-11-12 मार्च 2020

2. जनजातीय केंद्रित सतत आजीविका सृजन और नवाचारयुक्त कार्य पर राष्ट्रीय परामर्श में शोध पत्र की प्रस्तुती, भा.लो.प्र.सं. में 20 मार्च, 2020
3. "कोविड-19, "लेक्सिबिलिटी स्ट्रीग्मा और लैंगिक समानता" पर वेबीनार में पृष्ठभूमि आधारित शोध पत्र, 29 मई 2020
4. एचआरसी में शोध पत्र की प्रस्तुति
5. वेबीनार गोल में पृष्ठभूमि आधारित शोध पत्र की तैयारी
6. बीएच्यू में हुए एक वेबीनार में कोविड -19 के दौरान "घरेलू हिंसा" पर शोध पत्र की प्रस्तुति
7. बनारस में सनबीम इंस्टीट्यूट में आयोजित एक वेबीनार में "कोविड-19 में लैंगिंग समानता" पर शोध पत्र की प्रस्तुती

झ. भा.लो.प्र.सं. के भीतर अकादमिक कार्य के अन्य रूपों के साथ सहयोग

- (क) समितियाँ/अन्य (विभाग और योजना और सलाहकार समिति, समन्वयकत्व, संपादकत्व, संयोजकता आदि की सदस्यता) - भागीदारी का व्योरा और प्रकृति।
- (ख) भा.लो.प्र.सं. के बाहर अकादमिक कार्य के साथ सहयोग (समितियों/मंडलों आदि की सदस्यता)

ज. शाखाओं के साथ सहयोग

प्रदत्त शाखा

गतिविधियों में भागीदारी

6. सीओई जनजातीय मामले की समाचार पत्र पत्रिका
- i. सीओई जनजातीय मामले की समाचार पत्र पत्रिका 2020
7. सीओई पत्रिका: ई-पत्रिका
जनजातीय मामले और सामाजिक विकास की भारतीय पत्रिका (सीओई आईआईपीए एक ई-पत्रिका लाने वाला है)
- ट. भा.लो.प्र.सं. के बाहर किए गए अन्य अकादमिक कार्य का व्योरा

एनटीआरआई गतिविधियों की सूची

(16 अप्रैल, 2021 - अब तक)

क्र. संख्या	गतिविधियाँ	गतिविधियों की संख्या
1.	<p>रिक्तियों के लिए परिपत्र तैयार करना</p> <p>प्रशासनिक सह लेखा अधिकारी</p> <p>प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माणसलाहकार</p> <p>सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार</p> <p>अनुसंधान एवं मूल्यांकन सलाहकार</p> <p>अनुसंधान अधिकारी</p> <p>निजी सहायक सह कार्यालय सहायक</p> <p>मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)</p>	7
2.	<p>कार्यक्रम अनुसूची</p> <p>एसटीपीआरआई सदस्यों के लिए मास्टर प्रशिक्षकों का क्षमता निर्माण प्रशिक्षण</p> <p>मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए टीआरआईस के लिए</p> <p>एसटीपीआरआईस पर टॉट</p> <p>एसटीपीआरआईस पर प्रशिक्षण</p> <p>ग्राम पंचायत की तैयारी और कार्यान्वयन की आवश्यकता पर आधारित प्रशिक्षण</p> <p>कार्यक्रम (वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारियों के लिए)</p> <p>टीएसपी क्षेत्रों में संसृत मोड में विकास योजना-जीपीडीपी</p> <p>टीआरआईस के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम (मॉड्यूल -1)</p> <p>टीआरआईस के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम (मॉड्यूल -2)</p> <p>टीआरआईस के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम (मॉड्यूल -3)</p>	6
3.	<p>प्रशिक्षण मॉड्यूल</p> <p>जनजातीय अनुसंधान संस्थान के लिए एक व्यवस्थित प्रशिक्षण मॉड्यूल</p> <p>क्षमता निर्माणढांचा : बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षण प्रक्रिया (3 मॉड्यूल)</p> <p>टीआरआईस के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम</p> <p>जीपीडीपी की तैयारी और कार्यान्वयन पर टीआरआईस के लिए टॉट</p>	4
4.	एनटीआरआई रोड मैप - प्रारूप एवं प्रस्तुति	1
5.	एनटीआरआई - कैलेंडर एवं कार्यक्रम	-
6.	समीक्षा बैठकें	-

7.	<p>अब तक सम्पन्न कार्य</p> <p>श्रम सुधारों पर हाईलाइट और पीपीटी तैयार की गई</p> <p>एनटीआरआई प्रथम प्रस्तुति</p> <p>नेबरहुड कार्यक्रम (विदेश मंत्रालय)</p> <p>एनटीआरआई दिशानिर्देश</p> <p>ट्राई का पुनरुद्धार</p> <p>प्रो जॉर ग्रीस द्वारा जनजातीय प्रतिभा पूल प्रशिक्षण</p> <p>एसटीपीआरआई सदस्यों के लिए मास्टर प्रशिक्षकों का क्षमता निर्माण प्रशिक्षण पर प्रशिक्षण (16-18 जून, 2021)</p>	7
8.	<p>ओडिशा एवं यूएनडीपी के साथ एनटीआरआई बैठकें (जारी)</p> <p>13 मई, 2021 को ट्राई ओडिशा के साथ एनटीआरआई गतिविधियां और कार्यान्वयन योजना।</p> <p>17 मई, 2021 को एमओटीए, ट्राई ओडिशा तथा यूएनडीपी के साथ एनटीआरआई गतिविधियां एवं कार्यान्वयन योजना।</p> <p>28 मई, 2021 को ट्राई ओडिशा तथा यूएनडीपी के साथ एनटीआरआई गतिविधियां एवं कार्यान्वयन योजना।</p>	3
9.	<p>अन्य बैठकों का विवरण</p> <p>17 मई, 2021 को पिरामल फाउंडेशन के साथ सिक्ल सेल डिजीज पर चर्चा</p> <p>8 जून, 2021 को ट्राई, एमपी के साथ एसटीपीआरआईस के मास्टर प्रशिक्षक के लिए 75 पर भारत के अंतर्गत, जनजातीय मामले मंत्रालय संबंधित, सीबी कार्यक्रम पर चर्चा</p> <p>1 जुलाई, 2021 को 'ट्राई को सहयोग' योजना के अंतर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसीज़) तथा परियोजना प्रगति रिपोर्ट (पीपीआरस) जमा करना।</p>	3

सपना चड्डा

क्र. संख्या	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	नया/पुनरावृत्त	प्रायोजक
1.	जिला आयोगों के अध्यक्ष/सदस्यों के लिए “उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019” पर 110वां ऑनलाइन अनुकूलन प्रशिक्षण कार्यक्रम	23-25 नवंबर, 2020	नया	उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार
2.	जिला आयोगों के अध्यक्ष/सदस्यों के लिए “उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019” पर 111वां ऑनलाइन अनुकूलन प्रशिक्षण कार्यक्रम	22-24 फरवरी, 2021	नया	उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार
3.	जिला आयोगों के अध्यक्ष/सदस्यों के लिए “उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019” पर 112वां ऑनलाइन अनुकूलन प्रशिक्षण कार्यक्रम	22-24 मार्च, 2021	नया	उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार

4.	सीबीसीबी में सीपीआईओस के लिए “सूचना का अधिकार अधिनियम” पर एक दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	21 दिसंबर, 2020	नया	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारत सरकार
----	--	-----------------	-----	---

II संगोष्ठियाँ/कार्यशालाएं/सम्मेलन आयोजित

1.	“ई-कॉमर्स-नए सामान्य में लचीलापन रणनीतियाँ” पर वेबिनार	04 अगस्त, 2020	नया	उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार
2.	“लोक सेवा वितरण प्रणाली में आरटीआई अधिनियम की भूमिका” पर वेबिनार	01 अक्टूबर, 2020	नया	भा.लो.प्र.सं., नई दिल्ली
3.	छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय, पनवेल, नवी मुंबई और सेंट विलफ्रेड्स कॉलेज ऑफ लॉ, पनवेल, महाराष्ट्र के साथ संयुक्त रूप से आयोजित ‘उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 – एक गेम चेंजर’ पर वेबिनार	20 अक्टूबर, 2020	नया	उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार
4.	‘उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम- एक गेम चेंजर’ पर वाणिज्य विभाग, स्कूल ऑफ सोशल साइंस एंड लैगेजेस, वैल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, वैल्लोर, के साथ संयुक्त रूप से आयोजित वेबिनार	22 अक्टूबर, 2020	नया	उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार
5.	‘उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम - एक गेम चेंजर’ पर महाराष्ट्र नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, नागपुर के साथ संयुक्त रूप से आयोजित वेबिनार	17 नवंबर, 2020	नया	उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार
6.	‘उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019- एक गेम चेंजर’ पर आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ, (आईक्यूएसी), जेएसएस लॉ कॉलेज (स्वायत्त) मैसूर, कर्नाटका के साथ संयुक्त रूप से आयोजित वेबिनार	18 नवंबर, 2020	नया	उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार
7.	राज्य सरकार के अधिकारियों / ऑफिशियलस के लिए “उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 एवं नियम” पर दो-दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला	26-27 नवंबर, 2020	नया	उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार

8.	मध्य-प्रदेश सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों/ऑफिशियलस के लिए “उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019” पर दो-दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला	3-4 दिसंबर, 2020	नया	उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार
9.	मध्य-प्रदेश सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों/ऑफिशियलस के लिए “उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019” पर दो-दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला	7-8 दिसंबर, 2020	नया	उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार
10.	मध्य-प्रदेश सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों/ऑफिशियलस के लिए “उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019” पर दो-दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला	10-11 दिसंबर, 2020	नया	उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार
11.	राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2020, “उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की नई विशेषताएं” थीम पर	24 दिसंबर, 2020	नया	उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार
12.	उपभोक्ता अध्ययन केंद्र एवं जेवियर लॉ स्कूल, सेंट जेवियरस यूनिवर्सिटी, कोलकाता द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित “उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, उपभोक्ता एवं व्यापार की सहक्रियता” पर वेबिनार	15 जनवरी, 2021	नया	उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार
13.	एनसीडीआरसी के उत्तरी क्षेत्र के राज्यों तथा राज्य आयोगों के लिए “उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 : आगे का रास्ता” पर आभासी क्षेत्रीय सम्मेलन	27 जनवरी, 2021	नया	उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार
14.	एनसीडीआरसी के पूर्वी क्षेत्र के राज्यों तथा राज्य आयोगों के लिए “उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 : आगे का रास्ता” पर आभासी क्षेत्रीय सम्मेलन	29 जनवरी, 2021	नया	उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार

15.	“उपभोक्ता आयोगों का वित्तीय क्षेत्रधिकार” पर ऑनलाइन हितधारकों का परामर्श	01 फरवरी, 2021	नया	उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार
16.	एनसीडीआरसी के केंद्रीय क्षेत्र के राज्यों तथा राज्य आयोगों के लिए “उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 : आगे का रास्ता” पर आभासी क्षेत्रीय सम्मेलन	03 फरवरी, 2021	नया	उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार
17.	एनसीडीआरसी के दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों तथा राज्य आयोगों के लिए “उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 : आगे का रास्ता” पर आभासी क्षेत्रीय सम्मेलन	08 फरवरी, 2021	नया	उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार
18.	एनसीडीआरसी के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों तथा राज्य आयोगों के लिए “उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 : आगे का रास्ता” पर आभासी क्षेत्रीय सम्मेलन	09 फरवरी, 2021	नया	उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार
19.	“इलैक्ट्रॉनिक-उत्पादों पर ई-मूल्य निर्धारण की शुरुआत” पर ऑनलाइन हितधारकों का परामर्श	10 मार्च, 2021	नया	उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार
20.	आभासी रूप से मनाया गया विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021, “थीम - प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना”	15 मार्च, 2021	नया	उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार
21.	“उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 - एक आदर्श बदलाव” पर उपभोक्ता अध्ययन केंद्र द्वारा वेल टेक रंगराजन डॉक्टर सगुनथला आर एंड डी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टैक्नोलॉजी, चेन्नै के साथ संयुक्त रूप से आयोजित वेबिनार	26 मार्च, 2021	नया	उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार

अप्पा के सहयोग से

1.	प्रशासनिक कानून पर आधारित	अगस्त, 2020		
----	---------------------------	-------------	--	--

अ (iii) अन्य पाठ्यक्रमों में लगे सत्रों की संख्या

अ (iii) मात्र शिक्षण संख्या

व्याख्यानों की संख्या लगभग 40

इनमें पैनल चर्चा, समूह चर्चा, अभ्यास एवं केस चर्चा शामिल हैं।

अन्य कार्यक्रमों के सत्र

- एमईएस कार्यकारी अधिनियमों के लिए उच्च प्रबंधन पर छः-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (27

सम्पन्न शोध परियोजनाएं (श्रेणी अ) (वित्त पोषित तथा गैर-वित्त पोषित दोनों प्रकार के शोध पर लागू)

क्र. संख्या	नाम	द्वारा प्रायोजित	संपन्न/जारी	बजट (लाख में)
1.	स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना का मूल्यांकन (एसएसएसवाई)	गृह मंत्रालय	संपन्न	27,19,750
2.	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना के सक्रिय प्रकटीकरण का तृतीय पक्ष ऑडिट	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड	संपन्न	4.41
3.	अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना के सक्रिय प्रकटीकरण का तृतीय पक्ष ऑडिट	अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा	संपन्न	4.41
4.	राष्ट्रीय तापविद्युत निगम लिमिटेड द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना के सक्रिय प्रकटीकरण का तृतीय पक्ष ऑडिट	राष्ट्रीय तापविद्युत निगम लिमिटेड	संपन्न	4.41
5.	आईआईएसईआर कोलकाता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना के सक्रिय प्रकटीकरण का तृतीय पक्ष ऑडिट	आईआईएसईआर कोलकाता	संपन्न	4.41
6.	आईआईएसईआर टीवीएम द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना के सक्रिय प्रकटीकरण का तृतीय पक्ष ऑडिट	आईआईएसईआर टीवीएम	संपन्न	4.41
7.	आईआईएसईआर, मोहाली द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना के सक्रिय प्रकटीकरण का तृतीय पक्ष ऑडिट	आईआईएसईआर, मोहाली	संपन्न	4.41
8.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना के सक्रिय प्रकटीकरण का तृतीय पक्ष ऑडिट	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	संपन्न	4.41

अगस्त-2 सितंबर, 2020) में 1 सितंबर, 2020 को “प्रशासनिक कानून” पर सत्र।

- 11-22 जनवरी, 2021 तक तकनीकी कार्मिकों के लिए 15वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम में 21 जनवरी, 2021 को “भारतीय कानून प्रणाली” पर सत्र।
- ब, 2021 तक भारतीय रक्षा संपदा सेवा (आईडीइएस) के परीक्षाधारीनों के लिए आयोजित एक सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 11 फरवरी, 2021 को “प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत” पर सत्र।

9.	एनईईपीसीओ द्वारा सूचना का अधिकार अधि नियम के तहत सूचना के सक्रिय प्रकटीकरण का तृतीय पक्ष ऑडिट	एनईईपीसीओ	संपन्न	4.41
10.	ऊर्जा मंत्रलय द्वारा सूचना का अधिकार अधि नियम के तहत सूचना के सक्रिय प्रकटीकरण का तृतीय पक्ष ऑडिट	ऊर्जा मंत्रालय	संपन्न	4.41
11.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना के सक्रिय प्रकटीकरण का तृतीय पक्ष ऑडिट	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	संपन्न	4.41
12.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना के सक्रिय प्रकटीकरण का तृतीय पक्ष ऑडिट	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	संपन्न	4.41
13.	आईएसटीएम द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना के सक्रिय प्रकटीकरण का तृतीय पक्ष ऑडिट	आईएसटीएम	संपन्न	--.
14.	बीपी कार्यालय द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना के सक्रिय प्रकटीकरण का तृतीय पक्ष ऑडिट	बीपी कार्यालय	संपन्न	--
15.	एमएसएमई (विकास) अधिनियम, 2006 में परिवर्तन की आवश्यकता हेतु अध्ययन करना	एमएसएमई	जारी	20
16.	लघु, कुटीर एवं मध्यम उपक्रम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 में परिवर्तन की आवश्यकता का अध्ययन करने के लिए कार्य समूह लघु, कुटीर एवं मध्यम उपक्रम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 में परिवर्तन की आवश्यकता का अध्ययन करने के लिए कार्य समूह 14वें वित्त आयोग से 15वें वित्त आयोग चक्र तक जारी रखने के लिए सीबीआई योजनाओं का तृतीय पक्ष मूल्यांकन	केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो	जारी	9,97,500
17.	राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों की ईर्किग	उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार	संपन्न	8
18.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण एवं आवास शिकायतों के निवारण में रियल ऐस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 का प्रभाव	उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार	जारी	9

जारी शोध परियोजनाएं (श्रेणी ब)

क्र. संख्या	नाम	द्वारा प्रायोजित	संपन्न/जारी	संपन्न होने की तिथि	बजट (लाख में)
1.	उपभोक्ता अध्ययन केंद्र	उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार	जारी	जून 2020	करोड़
2.	एनसीएच के माध्यम से एकीकृत शिकायत समाधान प्रणाली	उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार	जारी	दिसंबर 2020	14.15 करोड़

अनुसंधान मार्गदर्शन

क्र. संख्या	संख्या नामांकित	प्रस्तुत की गई थिसिस	प्रदान की गई डिग्री
1.	श्री प्रेम चंद शर्मा अनुक्रमांक 4624	भारत में टेलिकॉम सेक्टर में वर्तमान “अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों” का मूल्यांकन और आगे	

पुस्तकें

- सुरेश मिश्रा एवं सपना चह्डा, कंस्यूमर हैंडबुक, सीसीएस, भा.लो.प्र.सं., नई दिल्ली, 2020
- सपना चह्डा, एविएशन एंड कंस्यूमर, 2020 (प्रेस में)
- सपना चह्डा, इंश्योरेंस एंड कंस्यूमर, 2020 (प्रक्रिया में है)
- सपना चह्डा, रिटेल सैक्टर एंड कंस्यूमर (प्रक्रिया में है)

पेपर/लेख

- सपना चह्डा, कंस्यूमर प्रोटैक्जन एक्ट, 2019 - एगेम चेंजर, आईआईपीए डाईजेस्ट, जुलाई-सितंबर 2020
- एस एन त्रिपाठी एवं सपना चह्डा, रूल ऑफ लॉ, योजना, सितंबर 2020, पृष्ठ 23-27
- सपना चह्डा एवं वरुनी बी आर, ड्रैकोनियन एसैन्शियल कोमोडिटीज़ एक्ट अंडरगोस एमेन्डमेंट, भा.लो.प्र.सं. डाईजेस्ट, अक्टूबर-दिसंबर 2020
- सपना चह्डा, एमरजिंग रेगुलेटरी फेमवर्क फॉर ई-कॉमर्स इन इंडिया : सम इनसाइट्स, इंटरनेशनल जनरल ऑफ एडवांस एंड इनोवेटिव रिसर्च, वाल्यूम 7, संस्करण 4 (II), अक्टूबर-दिसंबर, 2020, पृष्ठ 1-8

III. प्रस्तुत पेपर/सेमिनार में सत्र/कार्यशालाएं/सम्मेलन

- 18 जून, 2020 को उपभोक्ता अदालत समूह, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश, द्वारा आयोजित “आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन और उपभोक्ताओं पर इसके प्रभाव” पर ऑनलाइन चर्चा में पैनलिस्ट।
- 16 जुलाई, 2020 को उपभोक्ता अदालत समूह, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश, द्वारा आयोजित उपभोक्ता एवं विद्युत, पर ऑनलाइन चर्चा में पैनलिस्ट।
- 8 अगस्त, 2020 को कंस्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया (सीजीएसआई) के सहयोग से एच एस एन सी बोर्ड के जी जे आडवानी लॉ कॉलेज, मुंबई द्वारा “उपभोक्ता संरक्षण : कानून एवं नीतियाँ” पर ऑनलाइन कार्यशाला में “उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019” पर सत्र।
- 6 सितंबर, 2020 को स्वरनांधा ग्रुप ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 पर आयोजित ऑनलाइन वेबिनार में “उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत उत्पाद दायित्व” पर सत्र।
- 10 सितंबर, 2020 को प्रसन्ना कॉलेज ऑफ लॉ, कोथापेटा कुरनूल द्वारा “नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम” पर आयोजित ऑनलाइन वेबिनार में “ई-कॉमर्स एवं उपभोक्ता” पर सत्र।

- 17 अक्टूबर, 2020 को उपभोक्ता वकालत समूह, द्वारा सदस्यों के लिए आयोजित उपभोक्ता संरक्षण पर ऑनलाइन अनुकूलन कार्यक्रम में पैनलिस्ट।
- 20 नवंबर, 2020 को “कोविड-19 महामारी के दौरान उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण” विषय पर कंस्यूमर लॉ, एडवोकेसी एंड रिसर्च सेंटर, बीएमएस कॉलेज ऑफ लॉ एंड कंस्यूमर राइट्स, एजुकेशन एंड अवेयरनेस ट्रस्ट (सीआईएटी) द्वारा आयोजित एक दिवसीय राष्ट्र स्तरीय बहु-विषयक सम्मेलन में “उपभोक्ता संरक्षण एवं ई-कॉर्मस” पर सत्र।
- 20 फरवरी, 2021 को उपभोक्ता वकालत समूह, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश द्वारा आयोजित “बदलते पर्यावरण में उपभोक्ता संरक्षण” पर वेबिनार में “डिजिटल लेनदेन एवं उपभोक्ता संरक्षण” पर प्रस्तुति।
- 04.01.2021 को हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान, गुरुग्राम द्वारा आईटीएस अधिकारियों के लिए फाउंडेशन पाठ्यक्रम (23 नवंबर, 2020-06 मार्च 2021) में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 पर सत्र।

आपके द्वारा संस्थान को दिया गया कोई अन्य प्रमुख योगदान

- सदस्य, राजभाषा कार्यवाहन समिति, भा.लो.प्र.सं.
- सदस्य, केस स्टडी मूल्यांकन समिति, भा.लो.प्र.सं.
- संपादक, सीसीएस, भा.लो.प्र.सं. द्वारा प्रकाशित ट्रैमासिक ई-न्यूज़लैटर “कंस्यूमर डायलॉग” तथा एससीएचकेआरएमपी द्वारा प्रकाशित मासिक ई-न्यूज़लैटर “कंस्यूमर बुलेटिन”
- भालोप्रसं, कर्नाटक शाखा के लिए संकाय प्रभारी

भा.लो.प्र.सं. के बाहर अन्य शैक्षणिक/व्यावसायिक उपलब्धियां

1. सदस्य, स्क्रिप्ट समिति, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार
2. सदस्य, प्रतीक एवं नाम (अनुचित प्रयोग की

रोकथाम) अधिनियम, 1950 में संशोधन के लिए समिति

3. डोका, भारत सरकार के लिए राज्य उपभोक्ता आयोगों की रैकिंग के लिए दिशानिर्देश तैयार किए
4. कंस्टीट्यूशनल क्लब, जीजीएसआईपी युनिवर्सिटी द्वारा 2 नवंबर, 2020 को “मानव स्वयं डिजिटल अपराध के लिए उत्तरदायी है” विषय पर आयोजित बाद-विवाद प्रतियोगिता को जज किया

मनन द्विवेदी

शैक्षणिक उपलब्धियां :

1. अकेले लिखी पुस्तक, मनन द्विवेदी, “ट्रम्पस अमेरिका : इकॉनॉमिक पॉलिसीज़ एंड डिप्लोमैसी,” नई दिल्ली, एनी बुक्स, 2021।
2. मनन द्विवेदी, “इंडिया एंड अमेरिका इन दि कॉन्टैक्स्ट ऑफ दि इंडो पैसिफिक रिजन,” नई दिल्ली, सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज़, डिफेंस एंड डिप्लोमैसी, मई-जून, 2021।
3. अमेरिकी विदेज्ज नीति पर आधारित 2020 से 2021 में, पायोनियर में 10 लेख
4. मनन द्विवेदी, “साइबर वार्सेयर एंड अमेरिका,” यूआरएल : kiips.org.in
5. मनन द्विवेदी, “इंफरास्ट्रक्चरल अटैक इन युनाइटेड स्टेट्स,” यूआरएल : lokiniti.com
6. मनन द्विवेदी, संपादकीय “इंडिया यूएस स्ट्रैटिजिक टाइस इन दि इंडो पैसिफिक,” सुनील चौधरी, “इंडियास फॉरेन पॉलिसी : इश्यू एंड चैलेंजेस,” नई दिल्ली : पेंटागन बुक्स, 2020।
7. रिपोर्ट संपादकीय मनन द्विवेदी, राम भाड महालगी प्रबोदिनी, “गवरनेन्स इश्यू इन इंडिया,” 2020।
8. इग्नू मोनोग्राफ लेखन, “ब्रिक्स एंड दि “यूचर अहेड,” 2020।

जारी परियोजनाएं :

1. “इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी : कम्पैरिजन बिटवीन दि पास्ट एंड प्रेसेन्ट रिजाइम्स,” राशि : 12 लाख, अवधि : डेढ़ साल

श्यामली सिंह

पाठन/प्रशिक्षण

अ (i) संचालन

क्र. संख्या	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	नया/पुनरावृत्त	टिप्पणी
1.	तकनीकी कर्मियों के लिए 15वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम	2 सप्ताह (11-22 जनवरी, 2021)	पुनरावृत्त	
2.	जल संसाधान प्रबंधन एवं सतत् आदत (वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विद्) पर पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम (1 सप्ताह)	अ (ii) मात्र शिक्षण संख्या व्याख्यानों की संख्या	50 30 80	
3.	शासन में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं उभरते रुझान पर 10वां टी.पी. (वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीविद्) (1 सप्ताह) 1 सप्ताह (1-5 फरवरी, 2021) 1 सप्ताह पुनरावृत्त (8-12 फरवरी, 2021)	25 20 20		
			10	
			500	
व्याख्यानों की संख्या				
कुल योग				

अ (iii) अन्य कार्य (केवल घंटों की संख्या)

पैनल चर्चा

समूह चर्चा

अभ्यास

केस चर्चा

प्रशिक्षण प्रस्तावों की तैयारी

अ (iv) शिक्षण को दिए गए अपने योगदान की मात्र एवं सामग्री से क्या आप संतुष्ट हैं?

अपने योगदान में सुधार के लिए सुझाव दें।

जी हाँ, मैं अपने योगदान की सामग्री से संतुष्ट हूं, हालांकि सुधार की संभावना हमेशा बनी रहती है।

ब. संपन्न शोध परियोजनाएं (श्रेणी अ) (वित्त पोषित तथा गैर वित-पोषित दोनों प्रकार के अनुसंधान पर लागू)

I. शीर्षक : जलवायु परिवर्तन की स्थिति में जटिल आपदाओं के प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण

शोध प्रबंध

- दो शोध प्रबंध
- एक समुदाय मेले का आयोजन (माघ मेला)
- जलवायु विद्यालय पहल : विद्यालयों को जलवायु अनुकूल (क्लाइमेट स्मार्ट) बनाना, आकाशवाणी के साइंस वॉच कार्यक्रम में प्रसारित।
- पूर्वी हिमालय में जटिल आपदाओं एवं जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्यशाला का नई दिल्ली में आयोजन

रिपोर्टें :

- क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यशाला-उत्तरी एवं पश्चिमी सिक्किम

- जलवायु विद्यालय पहल
- आपदा तैयारी पर शिक्षक पुस्तिका
- आपदा सुरक्षा पुस्तिका

स : संपन्न शोध-परियोजनाएं (श्रेणी)

1.

- I. **शीर्षक :** जलवायु अनुकूल/क्लाइमेट स्मार्ट शासन
- II. **शीर्षक :** सिक्किम के चयनित जिलों में जैव विविधता संरक्षण के लिए क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण का आकलन
- III. **शीर्षक :** कठोर जलवायु के प्रति छोटे धारक चावल किसानों की स्वास्थ्य और पर्यावरण अतिसंबंदेनशीलता : कृषि परिस्थितिकी एवं पारंपरिक खेत पर एक तुलनात्मक अध्ययन

4

- I. **शीर्षक :** ओडीएम योजना का तृतीय पक्ष मूल्यांकन

5

- II. **शीर्षक :** कोविड-19 का दस्तावेजीकरण : भारत सरकार की प्रतिक्रिया
- द. **शीर्षक :** जारी अनुसंधान परियोजनाएं (श्रेणी अ)

1.

- शीर्षक :** गंगा नदी के हितधारियों के लिए मिश्रित क्षमता निर्माण कार्यक्रम

फ. तैयार केस स्टडी

1.

- शीर्षक :** गंगा उपाख्यान : केस स्टडी संग्रह

ग. प्रकाशन

(अ) पुस्तक का अध्याय

1.

- I. **' कौड़ी :** आईओटी-एनेबल्ड एयर मॉनीटरिंग सिस्टम

- II. **प्रकाशक :** स्प्रिंगर

- III. **स्थान :** सिंगापुर

वार्षिक रिपोर्ट

IV. प्रकाशन की तिथि : फरवरी 2019

(ब) पेपर एवं लेख

1.

- I. **शीर्षक :** चैलोन्जिस इन डिसास्टर मैनेजमेंट इन हिल एरियास : स्टडी ऑफ सिक्किम

- II. **जनरल :** दि जनरल ऑफ गवर्नेंस

- III. **स्थान :** भारत

- IV. **प्रकाशन की तिथि : जनवरी 2021**

2.

- I. **शीर्षक :** असोसिएजन ऑफ ब्लड कोलिनेस्टिरेस विद सैक्सुचुअल किरेन्सिस इन मैटाबॉलिक हैल्थ रिस्क्स अमंग विलेजर्स फ्रॉम पेस्टिसाइड-रिलेटेड फारमिंग विलेजिस

- II. **जनरल :** जनरल ऑफ इकोफिसिओलॉजी एंड ऑक्युपेशनल हैल्थ

- III. **i zlk ld :** इन्फोमैटिक्स पब्लिसिंग लिमिटेड

- IV. **स्थान :** भारत

- V. **प्रकाशन की तिथि : जून 2020**

3.

- I. **शीर्षक :** दि डिफरेन्ट इफैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट एक्सट्रीम्स ऑन फिजियोलॉजिकल हैल्थ अमंग एग्रोइकॉलॉजी एंड कन्वेशनल स्मालहोल्डर राइस फार्मर्स

- II. **प्रकाशक :** मेरी एन लाइबर्ट, इन्क

- III. **स्थान :** इंटरनेशनल

- IV. **प्रकाशन की तिथि : अप्रैल 2020**

4.

- I. **शीर्षक :** इफैक्ट्स ऑफ हीट ऑन फिजियोलॉजिकल हैल्थ बल्नरेबिलिटी अमंग एग्रोइकॉलॉजिकल एंड कन्वेशनल फार्मर्स इन ए क्लामेट चेन्ज

- II. **जनरल :** आरकाइव्स ऑफ एन्वायरोन्मेन्टल एंड ऑक्युपेशनल हैल्थ

- III. **स्थान :** इंटरनेशनल

5.

I. शीर्षक : फैटर्स एसोसिएटिड विद हैल्थ-रिस्क परसेप्शन टू हीट वेस अमंग एग्रोइकोलॉजिकल एंड कनवेन्शनल फार्मर्स इन दि ट्रॉपिक्स

II. प्रकाशक : इंटरनैशनल जरनल ऑफ क्लाइमेट
चेन्ज : इंपैक्टस एंड रिस्पॉन्स (समीक्षाधीन)

III. स्थान : प्रक्रियाधीन

IV. प्रकाशन की तिथि : प्रक्रियाधीन

6.

I. शीर्षक : चेन्जिस ऑफ सॉयल हैल्थ इन रिसोर्स टू स्लो-ऑनसेट क्लाइमेट चेन्जिस एट एग्रोइकोलॉजिकल एंड कनवेनशनल राइस फार्मलैन्ड इन दि टॉपिक्स

II. प्रकाशक : ट्रॉपिकल लाइफ साइंसिस रिसर्च (समीक्षाधीन)

III. स्थान : प्रक्रियाधीन

IV. प्रकाशन की तिथि : प्रक्रियाधीन

(स) कोई अन्य प्रकाशक

1.

I. पुस्तक का शीर्षक : स्ट्रैटिज़ी ऑफ मैनेजिंग कॉम्पलैक्स डिज़ाज़्टर इन दि फेस ऑफ क्लामेट चेन्ज

II. लेखक का नाम : डॉ. श्यामली सिंह एवं प्रो. वी. के. शर्मा

III. जरनल : इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन

IV. नाम : कॉफी टेबल हैंड बुक

V. प्रकाशन की तिथि : अगस्त 2020

(द) पस्तक समीक्षा लाग नहीं

I. पुस्तक का शीर्षक

II. लेखक का नाम

III. जरनल का नाम

IV. नाम

V. तिथि

ह. संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों आदि में
प्रस्तुत लेख।

स. भा.लो.प्र.सं. के भीतर शैक्षणिक कार्य के अन्य रूपों से संबंध

(अ) समिति/अन्य (प्रभाग, योजना एवं सलाकार समिति की सदस्यता, समन्वयक, संपादकत्व, संयोजक आदि)

- जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण एवं सूखा प्रशासन केंद्र के समन्वयक
 - अप्पा स्ट्रीम प्रभारी
 - डाक्युमेन्टेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (डीपीए) के संपादकीय सलाहकार बोर्ड के सदस्य

(ब) भा.लो.प्र.सं. के बाहर शैक्षणिक कार्य के अन्य रूपों से संबंध (समितियों/बोर्डों आदि की सदस्यता)

- भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् में विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नियुक्त
 - आईआरडीआर यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम यंग साइंटिस्ट, आईआरडीआर, हेदेन डिस्ट्रिक्ट, बीजिंग - 100094, पी. आर. चाइना
 - एयर वल्ड सर्विस फॉर ग्लोबल ऑडियन्स पर एक विशेष वार्ता कार्यक्रम “अंडरस्टैडिंग क्लाइमेट चेन्ज” में वार्ताकार को आमंत्रित किया
 - एमिटि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम अनुशोधन के बोर्ड पर
 - गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के पेपर सेटर के पैनल पर
 - भारत में बुने हुए बैगों के कचरे की स्थिति पर अंबुजा सीमेंट प्रायोजित अध्ययन के लिए सलाहकार
 - सोसायटी फॉर इन्डोर एनवायरन्मेंट के संपादक एवं सदस्य
 - भारतीय प्रदूषण नियंत्रण संघ, नई दिल्ली के संयुक्त सचिव

- जी.आई.डी.एम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
- एन.आई.डी.एम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

ज. शाखाओं के साथ संबंध

निर्दिष्ट शाखाएं : असम शाखा

गतिविधियों के साथ संबंध :

I. प्रशिक्षण : लागू नहीं

II. अनुसंधान/केस स्टडीज़ : लागू नहीं

III. गोष्ठी/सम्मेलन : आत्म निर्भर भारत : सामाजिक वानिकी पर वेबिनार

झ. भा.लो.प्र.सं. के बाहर किए गए शैक्षणिक कार्यों का विवरण

- जीआईडीएम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
- एनआईडीएम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
- ओएसडीएमए के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर प्रक्रियाधीन हैं

ज. किसी अन्य शैक्षणिक या संबंधित गतिविधि का विवरण जो कि ऊपर नहीं दिया गया है

- पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित जलवायु जनित हानि एवं क्षति केंद्र प्रक्रियाधीन है
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रायोजित “जलवायु स्मार्ट शासन” पर उत्कृष्टता केंद्र प्रक्रियाधीन है
- क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क दक्षिण एशिया के साथ परामर्श प्रक्रियाधीन है

ममता पठानिया

अ. शिक्षण/प्रशिक्षण

क्र. संख्या	कार्यक्रम	अवधि
1.	कोविड 19 मीडिया तथा उपभोक्ता सशक्तिकरण, उपभोक्ता अध्ययन केंद्र, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (भा.लो.प्र.सं.) पर वेबिनार	7 जुलाई, 2020

2.	भारतीय डाक और दूरसंचार लेखा परीक्षा और वित्त सेवा के परिवीक्षाधीनों के लिए लोक प्रशासन विषय पर मॉड्यूल (बैच 2019)	10-21 अगस्त, 2020
3.	उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कुशल शासन और प्रशासन (एसईजीए), जयपुर, राजस्थान के लिए बनी सोसाइटी के सहयोग के साथ “उपभोक्ता संरक्षण और सशक्तिकरण” विषय पर वेबीनार	28 अक्टूबर, 2020
4.	“उपभोक्ता संरक्षण और कल्याण” विषय पर क्षेत्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइनों के समन्वयकों एवं परामर्शदाताओं के लिए 5वां जेडसीएच ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	02-06 नवंबर, 2020
5.	आयोजित हुए एनजीओ/वीसीओ प्रमुखों के लिए “उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019” विषय पर प्रशिक्षकों का 18वां ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	04-06 नवंबर, 2020
6.	संकाय सदस्यों/प्रशिक्षकों के लिए “उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019” विषय पर प्रशिक्षकों का 26वां ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	09-11 नवंबर, 2020
7.	“उपभोक्ता जागरूकता” विषय पर ऑनलाइन राष्ट्रीय पोस्टर प्रतियोगिता	22 नवंबर, 2020
8.	उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित केआईईटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के सहयोग से “उपभोक्ता संरक्षण और सशक्तिकरण” विषय पर वेबीनार	02 दिसंबर, 2020
9.	राष्ट्रीय स्तरीय निबन्ध प्रतियोगिता-2020	15 दिसंबर, 2020
10.	राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2020 थीम: “उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की नई विशेषताएं”	24 दिसंबर, 2020
11.	“राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: विद्यार्थी सशक्तिकरण” विषय पर राष्ट्रीय वेबीनार	28 जनवरी, 2021

12.	भारतीय रक्षा संपदा सेवा के परिवीक्षाधीनों के लिए लोक प्रशासन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	8-12 फरवरी, 2021
13.	एनजीओ/वीसीओ प्रमुखों के लिए “उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019” विषय पर प्रशिक्षकों का 19वां ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	10-12 फरवरी, 2021
14.	“उपभोक्ता संरक्षण और कल्याण” विषय पर क्षेत्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइनों के समन्वयकों एवं परामर्शदाताओं के लिए 6वां जेडसीएच ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	01-05 मार्च, 2020
15.	रफी अहमद किदवर्ई राष्ट्रीय डाक अकादमी (आरएकेएनपीए), गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश डाक विभाग, संचार मंत्रालय, डाक विभाग के सहयोग से केन्द्र द्वारा उपभोक्ता अध्ययन, आईआईपीए, नई दिल्ली के लिए परिवीक्षकों के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विषय पर तीन दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम	3-5 मार्च, 2021
16.	कोंगू इंजीनियरिंग कॉलेज पेरून्दुर्ई, इरोड-638060, तमिलनाडु के सहयोग से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 विज्ञय पर वेबीनार	09 अप्रैल, 2021

- 46वें अप्पा, 2020-2021 में उपभोक्ता संरक्षण: कानून और नीति विषय पर अप्पा, पाठ्यक्रम प्रभारी
- 46वें अप्पा, 2020-2021 में लोक प्रशासन के आयाम विषय के अप्पा, पाठ्यक्रम प्रभारी

पूरी हो चुकीं अनुसंधान परियोजनाएं (श्रेणी क)

क्रम संख्या	नाम	द्वारा प्रायोजित	पूरी हो चुकीं/चल रहीं	बजट
1.	चुनिन्दा राज्यों में खाने का सामान बेचने वाले फेरीवालों के बीच खाद्य सुरक्षा मानकों और पार्टिंगों और विवाहों के दौरान खाने की बर्बादी रोकने के सुझावित उपायों का भी मूल्यांकन	उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार	पूरी हो चुकी	(9 लाख)

3. 46वें अप्पा, 2020-2021 में सुशासन और जन सेवा वितरण विज्ञय पर अप्पा, पाठ्यक्रम प्रभारी

क (ii) शिक्षण

केवल संख्या

व्याख्यानों की संख्या (दोहराए गए विषय) लगभग / 60 व्याख्यानों की संख्या (नए विषय) लगभग / 410

आधा-कार्यकाल समाप्त कर चुके आईडीईएस अधिकारियों के लिए अग्रलिखित विषयों पर सत्र: स्थानीय स्वशासन, प्रशासन में नैतिकता, लोक प्रशासन, उपभोक्ता संरक्षण: शिक्षा और सशक्तिकरण, खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता, भारत में उपभोक्ता संरक्षण पर एक अंतरदृष्टि, डीएसटी के विभिन्न कार्यक्रमों में उपभोक्ता शिकायत निवारण: राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन का कार्य, बुनियादी पाठ्यक्रम, अप्पा, उपभोक्ता अध्ययन केन्द्र, ‘नागरिक-केन्द्रित शासन’ पर भारतीय डाक संचार लेखा और वित्त सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम के परिवीक्षकों के लिए लोक प्रशासन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।

क (iii) अन्य कार्य (घंटों की संख्या केवल)

पैनल चर्चाएं : 10 घंटे (लगभग)

समूह चर्चाएं : 10 घंटे (लगभग)

अभ्यास : लागू नहीं

मुद्रे संबंधी चर्चाएं : 7 घंटे (लगभग)

प्रशिक्षण प्रस्तावों की तैयारी : 5 घंटे (लगभग)

क (iv) क्या आप शिक्षण में अपने योगदान की अपनी मात्रा और विषय से संतुष्ट हैं?

हां, बहुत अधिक और इस क्षेत्र में अधिक योगदान के लिए उत्साहित हूं।

चल रहीं अनुसंधान परियोजनाएं (श्रेणी क)

क्रम संख्या	नाम	द्वारा प्रायोजित	पूरी हो चुकीं/चल रहीं	बजट
1.	कोविड-19: कन्यूमर पर्सपेरिट्व द न्यू नॉर्मल	उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार	चल रही	(9 लाख)

चल रहीं अनुसंधान परियोजनाएं (श्रेणी ख)

क्रम संख्या	विषय	अवधि	धन मुहैया करने वाली एजेंसी	पूरा होने की अवधि	बजट
1.	एनसीए के माध्यम से एकीकृत शिकायत समाधान प्रणाली	चल रही है	उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार	जून, 2021	14.15 करोड़
2.	उपभोक्ता अध्ययन केन्द्र	चल रही है	उपभोक्ता विभाग, भारत सरकार	जून, 2021	15 करोड़

(ग) अनुसंधान निर्देशन

क्रम संख्या	नामांकित संख्या	जमा कराए गए शोध	प्रदान की गई डिग्री
1.	4627- एयर कमांड एस. श्रीकांत, वीएसएम	भारतीय पुलिस सेवाओं (एनसीटी) में कार्यबल की तैनाती को युक्तिसंगत बनाना: एन आईडियल टीथ टू टेल रेश्यो (टी3आर)	पूरी हो चुकी है

प्रकाशन

पुस्तक/पुस्तिका (विशेष निबन्ध)

- क्लामेंट चंज, सर्टेनेबिलिटी एंड कन्यूमर्स: दुवर्ड्स ए बैटर “यूचर, सुरेश मिश्रा, ममता पठानिया, कॉन्सेप्ट पब्लिकेशन, नई दिल्ली,-2021
- सर्टेनेबल कन्यूमर, सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, ममता पठानिया, भा.लो.प्र.सं., नई दिल्ली, 2020
- उपभोक्ताओं पर कीटनाशकों का प्रभाव, भा.लो.प्र.सं., नई दिल्ली, 2020

समाचार पत्र और लेख

- “उपभोक्ता संरक्षण और जागरूकता का महत्व” 4था संस्करण, डायरेक्ट सेलिंग टूडे, नई दिल्ली, अप्रैल 2020

- “उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019” उपभोक्ता आवाज, खंड-5, अक्टूबर-दिसम्बर, 2020

(घ) पुस्तक समीक्षाएं-कोई नहीं

ज. सेमिनारों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों आदि में प्रस्तुत किए गए शोध पत्र

- सेमिनारों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों आदि का विषय
 - प्रिंस श्री वेंकटेश्वर आर्ट एंड साइंस कॉलेज, चैन्सी द्वारा 23 मई 2020 को आयोजित “कोविड-19 महामारी के दौरान उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ता पक्षपोषण” विषय पर एक राष्ट्रीय वेबीनार में पैनलिस्ट
 - एमके-एलएम के अमलानी कॉलेज ऑफ कॉर्मर्स एंड इकोनोमिक्स, मुम्बई और महिला एमओपी वैश्वन कॉलेज, चैन्सी द्वारा 31 मई, 2020

- को आयोजित “सतत विकास की भूमिका” विषय पर एक वेबीनार में पैनेलिस्ट
- एसपीएम, पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनीवर्सिटी (पीडीपीयू), गुजरात द्वारा 20 जून, 2020 को आयोजित “महामारी के दौरान उपभोक्ता संरक्षण” विषय पर एक वेबीनार में पैनेलिस्ट
- 1. भा.लो.प्र.सं. के भीतर अकादमी कार्य के अन्य स्वरूपों के साथ सहयोग**
- (क) समिति/अन्य (प्रभाग और योजना एवं सलाहकार समिति की सदस्यता, समन्वयक, संपादकत्व, संयोजकत्व आदि)- भागीदारी का ब्योरा और प्रकृति
- राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन, सीसीएस, भा.लो. प्र.सं., नई दिल्ली के सह-परियोजना निदेशक
 - सदस्य एनसीएच कर्मचारी चयन समिति
 - सदस्य: ई-न्यूजलेटर का संपादकीय मंडल, “उपभोक्ता संवाद” (यह तिमाहिक है और इसका प्रकाशन उपभोक्ता अध्ययन केन्द्र द्वारा किया जाता है)
 - सदस्य: पत्रिका का संपादकीय मंडल, “उपभोक्ता न्याय” उपभोक्ता कानून और नीति पर उपभोक्ता अध्ययन केन्द्र का मासिक नवीनीकरण
 - संस्थान द्वारा समय-समय पर गठित आंतरिक समितियों का सदस्य
 - (ख) भा.लो.प्र.सं. के बाहर किए गए अकादमिक कार्य के साथ सहयोग (समितियों/मंडलों आदि की सदस्यता)
 - सदस्य नेष्टानल मिर कमेटी छ्डएनएमसीऋ, भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली, की उपभोक्ता नीति पर समिति (सीओपीओएलसीओ)
 - नियुक्त सदस्य, एरिया एडवाइजरी बोर्ड (एएबी) और बोर्ड ऑफ स्टडीज (बीओएस), अमेठी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी (एआईपीपी), अमेठी यूनीवर्सिटी, उत्तर प्रदेश
- सदस्य, उपभोक्ता जागरूकता पर ऑडियो-विजुअल और प्रिंट क्रिएटिव के लिए लिपियों पर विचार स्क्रिप्ट समिति (जागो ग्राहक जागो के बैनर के अंतर्गत), उपभोक्ता मामले विभाग (डीसीए), भारत सरकार**
- विभिन्न राज्यों के यूपीएससी और अनेक लोक सेवा आयोगों की समीक्षा और मूल्यांक सीमित पर**
- ज. शाखाओं के साथ सहयोग**
- सौंपी गई शाखाः तमिलनाडु, तेलंगाना और आन्ध्र प्रदेश
- ट. भा.लो.प्र.सं. द्वारा बाहर किए गए अन्य अकादमिक कार्य का ब्यौरा**
- पैनेलिस्ट/विशेषज्ञ के रूप में निम्नलिखित कार्यक्रमों में आमत्रित किया गया
 - प्रिंस श्री वेंकेटेशवर आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज, चैन्नई, द्वारा 23 मई, 2020 को आयोजित “कोविड-19 महामारी के दौरान उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ता पैरवी” विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार
 - एमकेएलएम के अमलानी कॉलेज ऑफ कॉर्मस एंड इकोनोमिक्स, मुम्बई और महिला एमओपी वैश्वनव कॉलेज, चैन्नई द्वारा 31 मई, 2020 को आयोजित “सतत विकास की भूमिका” विषय पर एक वेबिनार
 - एसपीएम, पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनीवर्सिटी (पीडीपीयू), गुजरात द्वारा 20 जून, 2020 को आयोजित “महामारी के दौरान उपभोक्ता संरक्षण” विषय पर एक वेबिनार
- ठ. शुरू की गयी किसी अन्य शैक्षणिक या संबंधित गतिविधियों का विवरण जिसे ऊपर शामिल नहीं किया गया है।**
- प्राइड (PRIDE), लोक सभा सचिवालय, भारतीय संसद, नई दिल्ली द्वारा 7 अक्टूबर, 2020 को ‘कंसेप्चुअल फाउंडेशन ऑफ

पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन’ के आयोजन पर लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधानमंडल सचिवालयों के अधिकारियों के लिए ‘ऑनलाइन प्रबंधन विकास कार्यक्रम’ के लिए अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित किया गया।

गदाधर महापात्र

क. शिक्षण/प्रशिक्षण
क (i) निर्देशन

क्रमांक पाठ्यक्रम का नाम अवधि
नई/रिपोर्ट टिप्पणी

1. ऑनलाइन पब्लिक पॉलिसी मॉड्यूल ‘भूमि, श्रम और प्रवासन’ शीर्षक विकसित किया और 2 जुलाई, 2020 से लेकर 30 अप्रैल तक, वर्ष 2021-11 सत्र में आयोजित 46 वें डिजिटल एडवांस्ड प्रोफेशनल प्रोग्राम इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (अप्पा) में व्याख्यान दिये गये।
2. ऑनलाइन कंटेम्परेरी गवर्नेंस इश्यू इलेक्ट्रिव ‘डायनेमिक्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा: माइग्रेशन, एडेप्टेशन एंड ओवरसीज इंडियन कम्युनिटीज’ शीर्षक विकसित किया और 2 जुलाई, 2020 से लेकर 30 अप्रैल तक, वर्ष 2021-11 सत्र में आयोजित 46वें डिजिटल एडवांस्ड प्रोफेशनल प्रोग्राम इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (अप्पा) में व्याख्यान दिये गये।
3. दो दिवसीय प्रायोजित नेशनल वर्चुअल कान्फ्रेंस ऑन एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल वूमन थ्रो आन्टप्रनरिशप एंड स्किल डेवेलपमेंट : परस्पर्क्ट्स एंड चैलेंज्ज़ वर्ष 2020 नवंबर, 2020) प्रायोजित कार्यक्रम आयोजित किया गया। 86 पेपर लेखकों ने आठ (08) पूर्ण सत्रों में अपना पेपर प्रस्तुत किया।
4. 46वें डिजिटल अप्पा प्रतिभागियों के लिए पब्लिक पॉलिसी मॉड्यूल-लैंड, लेबर एंड माइग्रेशन ऑन ‘रियल लेबर लॉ रिफार्म्स: न्यू कोड्स फार एन्हांस्ड सोशल स्क्यॉरिटी’ में अप्पा टाउन हॉल व्याख्यान का आयोजन किया गया (18 दिसंबर, 2020-शुक्रवार 3.00 बजे से लेकर शाम से 5.30 बजे तक)।

श्री हीरालाल सामरिया, आईएएस, सूचना आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयोग और डॉ. एच. श्रीनिवास, आईआरपीएस, डीजी, वी.वी.जी.एल.एन.आई. पैनल चर्चा में मुख्य चर्चाकर्ता थे।

5. 46 वें डिजिटल एपीपीपीए कन्टेम्परेरी गवर्नेंस इश्यू: इलेक्ट्रिव ऑन ‘डायमेनिक्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा: माइग्रेशन, एडेप्टेशन एंड ओवरसीज इंडियन कम्युनिटीज’ में अप्पा टाउन हॉल व्याख्यान का आयोजन किया गया (29 जनवरी, 2021 सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 12.30 बजे तक। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त महामहिम बैरी ओफरैल एओ ने ‘द इंडियन डायस्पोरा एंड द ऑस्ट्रेलिया-इंडिया पार्टनरशिप’ पर 46वें अप्पा प्रतिभागियों को संबोधित किया।
6. माइग्रेशन एंड जॉब क्रिएशन इन कन्टेम्परेरी इंडिया: ‘परस्पर्क्ट्स एंड चैलेंज्ज़’ विषय पर भा.लो.प्र.सं. वेबिनार का आयोजन किया गया (22 जुलाई, 2020 दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 4.30 बजे तक)। जेएनयू, नई दिल्ली में अर्थशास्त्र के पूर्व प्रोफेसर, प्रो. संतोष मेहरोत्रा, और अर्थशास्त्र, शिक्षा और प्रवासन के पूर्व प्रोफेसर, प्रो. बिनोद खदरिया, वेबिनार में मुख्य चर्चाकर्ता थे।

क (ii) शिक्षण

	केवल संख्या
व्याख्यानों की संख्या (रिपोर्ट टॉपिक्स):	25
व्याख्यानों की संख्या (नए टॉपिक्स) :	25
कुल :	50
क (iii) अन्य कार्य (घंटों की संख्या मात्र)	
पैनल चर्चा :	10
समूह चर्चा :	10
अभ्यास :	2
मामलों की चर्चा :	0
प्रशिक्षण प्रस्तावों की तैयारी :	300
क (iv) क्या आप शिक्षण में अपने योगदान की मात्रा और सामग्री से संतुष्ट महसूस करते हैं? हाँ, मैं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को विकसित करने एवं लागू करने और भा.लो.प्र.सं. में अनुसंधान परियोजनाओं और संगोष्ठी/राष्ट्रीय सम्मेलन के सम्बन्ध में संतुष्ट महसूस करता हूँ।	

अपने योगदान में सुधार करने के लिए सुझाव दें

भा.लो.प्र.सं.में अत्याधुनिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विकसित और कार्यान्वित करने के लिए, टीएनए, ईओटी, एमओटी, ईएलटी, मेंटॉरिंग स्कल्स, फैसीलेशन स्किल्स, इंट्रोडक्शन टू एसएटी कोर्स और एनटीपी जैसे वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल ट्रेनिंग (डीओपीटी) के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से भाग लेने के लिए मैं उत्सुक हूँ। मैंने इससे पहले डीओपीटी के डीटीएस और डीओटी पाठ्यक्रम पूरे कर लिए हैं।

पूर्ण की गयी अनुसंधान परियोजनाएं (श्रेणी क)
(वित्त पोषित और गैर-वित्त पोषित अनुसंधान दोनों पर लागू होता है) परियोजना संख्या 1।

1. शीर्षक: इम्पेक्ट इवेल्यूएशन ऑफ द स्कीम नेशनल फैलोशिप एंड स्कॉलरशिप फार हायर एजूकेशन ऑफ एसटी स्टूडेंट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेर्स।

पूर्ण की गयी अनुसंधान परियोजनाएं (श्रेणी क)
(वित्त पोषित और गैर-वित्त पोषित अनुसंधान दोनों पर लागू होता है) परियोजना संख्या 2।

2. शीर्षक: इवेल्यूएशन ऑफ द स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फार एसटी स्टूडेंट्स फार स्टडीज अब्रॉड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेर्स।

चालू अनुसंधान परियोजनाएं (श्रेणी क)

3. शीर्षक: इवेल्यूएशन ऑफ द इम्पेक्ट ऑफ मिशन शक्ति इन वूमन एम्पावरमेंट इन केबीके डिस्ट्रिक्स इन ओडिशा।

चल रही अनुसंधान परियोजनाएं (श्रेणी ख)

4. शीर्षक: फारेस्ट राइट्स एक्ट, 2006- असेसमेंट ऑफ ग्राउंड रियलटी।

पत्र और लेख

1. शीर्षक: इंटीग्रेटड रबर डेवेलपमेंट प्रॉजेक्ट्स एंड इट्स इम्पेक्ट्स ऑन ट्राइबल लिवलीहुड्स : द केस ऑफ नार्थ-इस्ट रीजन विद द स्पेशल रिफरेन्स टू त्रिपुरा (आगामी)।

2. जर्नल: इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (आईजेपीए), सेज पब्लिशिंग

3. वॉल्यूम: 67

4. संख्या: अंक 4

5. दिनांक: अक्टूबर-दिसंबर अंक

(स) पुस्तक समीक्षा

क. पुस्तक का शीर्षक: जोसेफ ए. शुम्पीटर का ग्रंथ, आन्ट्रप्रनशिप-क्लासिक। कैलिफोर्निया: स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2011, 4+ 368 पीपी., डॉलर 35.00।

ख. लेखक का नाम: मार्कस सी. बेकर, थोरबर्जन नुडसन और रिचर्ड स्वेडर्ग

ग. जर्नल का नाम: इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सेज जर्नल्स

घ. संख्या: वॉल्यूम। 66 अंक 2

ड. दिनांक: अप्रैल-जून, 2020

एच. संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों, आदि में प्रस्तुत किया गया प्रपत्र।

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू), महिला बाल विकास मंत्रालय ने 'एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल वूमन थ्रो आन्ट्रप्रनशिप एंड स्किल डेवेलपमेंट : परस्पर्क्ट्स एंड चैलेंज' पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए रु. 2,79,000/- (रुपये दो लाख उनहत्तर हजार मात्र)की मंजूरी दी है। फाइल संख्या: 16(148)/2019-2020/एनसीडब्ल्यू (एनसीडब्ल्यू), दिनांक 01/11/2019।

दो दिवसीय प्रायोजित नेशनल वर्चुअल कान्फ्रेंस ऑन 'एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल वूमन थ्रो आन्ट्रप्रनशिप एंड स्किल डेवेलपमेंट : परस्पर्क्ट्स एंड चैलेंज' पर नेशनल कमीशन फार वूमन (एनसीडब्ल्यू) का आयोजन किया, (5-6 नवंबर, 2020) प्रायोजित कार्यक्रम आयोजित किया गया। 86 पेपर लेखकों ने आठ (08) पूर्ण सत्रों में अपना पेपर प्रस्तुत किया।

1. संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों आदि का शीर्षक:

2. आयोजन एजेंसी

3. जगह तारीखः
4. वित्त पोशक एजेंसीः
5. अनुदानः
6. प्रस्तुत पेपर का शीर्षकः

I. भा.लो.प्र.सं. के भीतर अन्य अकादमिक कार्यों के साथ संबद्धता

K. समिति/अन्य (डिवीजन और योजना और सलाहकार समिति की सदस्यता, समन्वयक, संपादकीय, संयोजक, आदि) - विवरण और भागीदारी की प्रकृति।

- नोडल व्यक्ति- नेशनल जल जीवन मिशन, जल राशि मंत्रालय के तहत प्रमुख संसाधन केंद्र- भा.लो.प्र.सं।
- टीम सदस्य, जनजातीय अध्ययन और अन्वेषण केंद्र, भा.लो.प्र.सं।

(ख) भा.लो.प्र.सं. के बाहर अकादमिक कार्यों के साथ संबंध (समितियों/बोर्डों की सदस्यता, आदि)

- पीएच.डी. उम्मीदवार श्री अनुराग दत्ता के लिए बाहरी सह-गाइड। (नामांकन संख्या ए6261419002), एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (एआईएसएस), एमिटी

पवन कुमार तनेजा

K. शिक्षण/प्रशिक्षण

K (i) निर्देशन

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	नई/रिपीट	राजस्व जनित	टिप्पणी
1.	46 वां एडवांस्ड प्रोफेशनल प्रोग्राम इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन	10 महीने (जुलाई 1, 2020 से 30 अप्रैल 2021)	नई	338 लाख रुपये	आईए, आईएएफ, आईएनएस, आईसीजी, आईईएस, आईआरएस, एमईएस और आईटीएस केडर से के 29 अधिकारी

यूनिवर्सिटी, नोएडा।

- पीएच.डी. उम्मीदवार सुश्री अर्निमा भार्गव के लिए बाहरी पर्यवेक्षण। एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (एआईएसएस), एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा।

J. शाखाओं के साथ संबद्धता

शाखा : भा.लो.प्र.सं., भुवनेश्वर की क्षेत्रीय शाखा के सदस्य।

3. सेमिनार/सम्मेलन: भा.लो.प्र.सं. क्षेत्रीय शाखा-भुवनेश्वर के लिए भा.लो.प्र.सं. वेबिनार शृंखला के एक भाग के रूप में अगस्त, 2021 में 'स्मार्ट सिटी' पर वेबिनार आयोजित किया जाएगा।

K. भा.लो.प्र.सं. के बाहर किए गए अन्य शैक्षणिक कार्यों का विवरण

15-17 जून, 2020 के दौरान, डॉ. गदाधर महापात्र ने वी.वी. गिरि नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित 'भारत में श्रम कानूनों के संहिताकरण की दिशा में हालिया पहल' पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में सफलतापूर्वक भाग लिया।

E. शुरू की गयी किसी अन्य शैक्षणिक या संबंधित गतिविधियों का विवरण जिसे ऊपर शामिल नहीं किया गया है।

2.	इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन फाइनेंस फार नॉन फाइनेंस बैंक ग्राउंड लीडर्स (ऑनलाइन)	1 सप्ताह 08 से 12 मार्च, 2021	नई	2.55 लाख रुपये	16 देशों से 40 पेशेवरों के लिए ई-आईटीईसी कार्यक्रम
3.	इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन डाटा एनॉलॉजिटिक्स फार बिगिनर्स (ऑनलाइन)	1 सप्ताह (मार्च 22 से 26, 2021)	नई	2.55 लाख रुपये	23 देशों से 40 पेशेवरों के लिए ई-आईटीईसी कार्यक्रम
4.	नौवां फाइनेंसियल मैनेजमेंट प्रोग्राम फार साइंटिस्ट्स एंड टेक्नोलोजिस्ट (ऑनलाइन)	1 सप्ताह (नवंबर 23 से 27, 2020)	रिपोर्ट	8 लाख रुपये	एम्स, दिल्ली, आईसीएआर, इसरो, डीएसटी, आईसीएमआर, आईएमडी आदि से 26 वरिष्ठ वैज्ञानिक, संकाय सदस्य।
5.	मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइसेस	1 सप्ताह (जनवरी 20-24, 2020)	नई	अप्पा का हिस्सा	आईए, आईएएफ, आईएनएस, आईसीजी, आईईएस, आईआरएस, एमईएस और आईटीएस केंद्र से के 29 अधिकारी
6.	ऑपरेशंस मैनेजमेंट	2 सप्ताह (10 सत्र)	रिपोर्ट	अप्पा का हिस्सा	आईए, आईएएफ, आईएनएस, आईसीजी, आईईएस, आईआरएस, एमईएस और आईटीएस केंद्र से के 29 अधिकारी
7.	फाइनेंसियल मैनेजमेंट	2 सप्ताह (10 सत्र)	नई	अप्पा का हिस्सा	आईए, आईएएफ, आईएनएस, आईसीजी, आईईएस, आईआरएस, एमईएस और आईटीएस केंद्र से के 29 अधिकारी

क (ii) शिक्षण	केवल संख्या	पैनल चर्चा	:	45
व्याख्यानों की संख्या (रिपोर्ट टॉपिक्स) :	27	समूह चर्चा	:	30
व्याख्यानों की संख्या (नए टॉपिक्सऋ) :	17	अभ्यास	:	40
कुल :	54	मामलों की चर्चा	:	30
क (iii) अन्य कार्य (घंटों की संख्या मात्र)		प्रशिक्षण प्रस्तावों की तैयारी	:	120

क (iv) क्या आप शिक्षण में दिये गये आपके योगदान
और कंटेंट्स से संतुष्ट हैं ?
हाँ

अपने योगदान को बेहतर बनाने के लिए उपाय सुझाएं।
अधिक ऑनलाइन पाठ्यक्रम सामग्री और इन-हाउस
केस स्टडी विकसित करने की आवश्यकता।

पूरी की गयीं अनुसंधान परियोजनाएं (श्रेणी क) (वित्त पोषित और गैर-वित्त पोषित अनुसंधान दोनों पर लागू होती है)

क्रमांक	नाम	प्रायोजित	स्टडी दल	अवस्थिति	बजट
1.	इवेल्यूएशन ऑफ प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	डॉ पवन के तनेजा डॉ गिरीश कुमार	अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत	59 लाख रुपये
2.	इम्पेक्ट असेसमेंट स्टडी ऑफ सीएसआर प्रोजेक्ट फार एम्लायमेंट ओरिएन्ट ट्रेनिंग एंड स्किल डेवेलपमेंट प्रोग्राम फार एससी/एसटी/ओबीसी/वूमन एंड इडब्ल्यूएस	पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	डॉ पवन के तनेजा डॉ रोमा मित्रा देबनाथ	अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत	3 लाख रुपये (लगभग)
3.	रेपिड असेसमेंट ऑफ स्वास्थ्य नागरिक अभियान (एसएनए) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की पूर्ववर्त आईईसी योजना।	नीति आयोग	डॉ पवन के तनेजा डॉ रोमा मित्रा देबनाथ	अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत	23.7 लाख रुपये
4.	इंटेंट एंड अन इंटेंट इंप्लीकेशंस ऑफ सीएसआर रेयूलेशन इन इंडिया: रेयूलेटर एंड रेयूलेटड पर्सेपेक्टिव्स	डेकिन यूनीवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया	डॉ पवन के तनेजा	एक शोध पत्र प्रकाशित दूसरा पेपर समीक्षा करने के लिए	-
5.	इवेल्यूएशन ऑफ नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 4	नाको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	डॉ पवन के तनेजा डॉ रोमा मित्रा देबनाथ	अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत	39.8 लाख रुपये +जीएसटी
6.	थर्ड पार्टी इवेल्यूएशन ऑफ ऑगमेंटेशन ऑफ ट्रेनिंग फेसिलिटीज एट आईएसटीएम स्कीम	आईएसटीएम, डीओपीटी	डॉ पवन के तनेजा डॉ रोमा मित्रा देबनाथ	अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत	4 लाख रुपये (लगभग)

चालू अनुसंधान परियोजनाएं (श्रेणी क)

क्रमांक	नाम	प्रायोजित	स्टडी दल	अवस्थिति	बजट
1.	एनईजीपी अवेयरनेस एंड स्किल डेवेलपमेंट प्रोग्राम फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल एसी/एसटी ऑफीसियल्स श्रो स्टेट एडमिनिस्ट्रॉटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (एटीआई)	भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	डॉ. चारू मल्होत्रा डॉ. पवन के तनेजा	पीआरसी की बैठक होनी है	7 करोड़ रुपये

2.	इवेल्यूएशन ऑफ पेंसनर्स पोर्टल	पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, सरकार	डॉ पवन के तनेजा डॉ रोमा मित्रा देबनाथ	प्रक्रिया में डेटा संग्रह	4 लाख रुपये
3.	इम्पेक्ट एस्टीमेशन ऑफ एसएपी इंडिया कंट्रीब्यूशन इन इंडियन इकॉनोमी	एसएपी इंडिया	डॉ. चारू मल्होत्रा डॉ पवन के तनेजा	इंसेप्शन रिपोर्ट तैयारी की प्रक्रिया में	38.94 लाख रुपये

केस स्टडी तैयार

- “यूजिंग डिजिटल स्पेस फॉर इन्नोवेटिंग ट्रेडीशनल प्रॉडक्ट: अ केस स्टडी ऑफ एमएमटीसी पीएमपी डिजिटल गोल्ड”
- “सीएसआर एंड स्टेनेबल डेवेलपमेंट प्रैक्टिस इन सीपीएसई: अ केस स्टडी ऑफएनएचपीसी लिमिटेड”।

प्रकाशन

प्रपत्र और लेख

- तनेजा, पी.के., और तनेजा, एस. (2020) मैनेजिंग नेचरन डिसेस्टर रिस्क विद अर्थक्वेक डेमेज सिनेरियोज एंड शेकआउट एक्सरसाइज़ज़: लेसंस फॉम अध्यासों के साथ प्राकृतिक आपदा जोखिम का प्रबंधन: भारत में मेगावाट = 8 मंडी मल्टी-हॉल्डर्स सिनेरियो इन इंडिया। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज, 6(1), 30-4
- जैन, ए., कंसल, एम., जोशी, एम., और तनेजा, पी। (2021)। इज द इंडियन कॉर्पोरेट सोशल रेसपॉस्बिलिटी लॉ वर्किंग फार पब्लिक सैक्टर? पब्लिक मनी एंड मैनेजमेंट, 1-10।

एच. संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों, आदि में प्रस्तुत किये गये प्रपत्र।

- डोगरा, एन., डे, एस., तनेजा, पी., कुमार, वी. और दीपिका, जी. (2020)। एन इकॉलोजिकल स्टडी फार द एसोसिएशन फार लांग टर्म पीएम 2.5 विद कोविड-19 मॉर्टलिटी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ इंडिया। क्लाइमेटोलोजिकल, मेटेओरोजिकल एंड

एन्वायरनमेंटल फैक्टर इन द कोविड-19 पेंडेमिक : विश्व मेट्रोलॉजिकल संगठन द्वारा आयोजित ड्राइवरों, पूर्वानुमेयता और कार्रवाई योग्य जानकारी पर एक अंतरराष्ट्रीय वर्चुअल संगोष्ठी, 4-6 अगस्त 2020।

- तनेजा, पी.के. और डोगरा, एन. (2020) एंसोसिएशन ऑफ एयर पॉल्युशन विद कोविड-19 मॉर्विडिटी एंड मॉर्टलिटी एट स्मार्ट सिटीज इन इंडिया : एक पारिस्थितिक अध्ययन, संक्रामक रोगों के पर्यावरणीय निर्धारकों पर अंतर्राष्ट्रीय ई-सम्मेलन (फोकस कोविड-19), 7 से लेकर 10 दिसंबर 2020, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हैल्थ मैनेजमेंट रिसर्च, नई दिल्ली और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हैल्थ (एनआईएचई, संयुक्त राज्य अमेरिका)।

I. भा.लो.प्र.सं. के भीतर शैक्षणिक कार्य के अन्य रूपों के साथ संबद्धता

- (क) समिति / अन्य (डिवीजन और योजना और सलाहकार समिति की सदस्यता, समन्वयक, संपादकीय, संयोजक, आदि) - विवरण और भागीदारी की प्रकृति।
- सह-निदेशक, 46वां डिजिटल अप्पा
 - सदस्य, आर्थिक विकास और प्रबंधन केंद्र
 - समन्वयक, टाउन हॉल डिस्कशन ऑन स्ट्रेंथेनिंग हैल्थ सिस्टम इन इंडिया (भारत) - पोस्ट कोविड सिनेरियो।
 - “कोविड 19 के विभिन्न चरणों के दौरान भारत सरकार की स्वास्थ्य संचार रणनीति” पर समन्वयक, वेबिनार।

(ख) आईआईपीए के बाहर अकादमिक कार्य के साथ संबंध (समितियों/बोर्डों आदि की सदस्यता)

- नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स, फरीदाबाद द्वारा “लीवरेज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट” पर एक ऑनलाइन वार्ता देने के लिए आमंत्रित किया गया, आईआरएस (सी एंड ई) के 69वें बैच के अधिकारी 17/06/2020, जून 15- 18, 2020।
- राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान द्वारा 11 से 15 जनवरी 2021 के बीच “प्रोजेक्ट एंड रिस्क मैनेजमेंट” पर एक ऑनलाइन एमडीपी में “वर्क ब्रैकडाउन स्ट्रक्चर इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट” पर एक ऑनलाइन वार्ता देने के लिए आमंत्रित किया गया।
- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, यूएनएड्स, यूएनडीपी, डब्ल्यूएचओ आदि द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 5 चरण के वित्तपोषण के लिए योजना पर राष्ट्रीय परामर्श बैठक आयोजित की गयी।
- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, राज्य एड्स रोकथाम और नियंत्रण सोसायटी (एसएसीएस) के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, ग्लोबल फंड, यूनिसेफ, आदि द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 4 और इसकी विस्तार अवधि (2013- 2020) के मूल्यांकन की खोज पर प्रसार कार्यशाला।

जे. शाखाओं के साथ संबद्धता

शाखा : उत्तर प्रदेश

एल. शुरू की गयी किसी अन्य शैक्षणिक या संबंधित गतिविधियों का विवरण जिसे ऊपर शामिल नहीं किया गया है।

क्रमांक	डिग्री	उम्मीदवार	विषय
1.	एम.फिल	विक्रम बोरा	रक्षा विनिर्माण और खरीद में आत्मनिर्भरता के लिए रणनीतिक साझेदारी मॉडल का महत्वपूर्ण आकलन

2.	एम. फिल	डॉ मनीष होनवाड़	कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की सुरक्षा के लिए एनेस्थिसियोलॉजिस्ट की भूमिका और संक्रमण नियंत्रण उपाय - मिश्रित कोविड अस्पताल में एक पूर्वव्यापी अध्ययन
3.	एम. फिल	काढा श्रीनिवास राव	रक्षा उपकरण डिजाइनरों, उत्पादकों और उपयोगकर्ताओं के बीच इंटरफेस तंत्र का मूल्यांकन

सुरभि पांडेय

क. शिक्षण/प्रशिक्षण

क (i) निर्देशन

क्रमांक पाठ्यक्रम का नाम
अवधि नई/रिपीट टिप्पणी

- सीबीआईसी अधिकारियों और भूटान सरकार के लिए डेटा एनालिटिक्स और ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चार दिवसीय कार्यशाला का समन्वय और व्यवस्था की।
- केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के लिए “लीडरज़िप एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन” पर तीन दिवसीय कार्यक्रम का समन्वय और व्यवस्था।
- आईआरएस (सी एंड आईटी) के 72वें बैच न्यू फार एनएसीआईएन, फरीदाबाद के लिए चार दिवसीय ऑनलाइन “पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन” का समन्वय और व्यवस्था।
- कॉरपोरेट कार्यकारियों के लिए चैंजड मैनेजमेंट इन एडवांस्ड लीडरशिप प्रोग्राम पर सत्र का आयोजन: एक्सीलेंस फार आत्म निर्भर (लीन) भारत।

5. नासेन के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट और वर्क लाइफ बैलेंस पर एक दिवसीय सत्र का आयोजन किया।
6. भारतीय बीमा निगम के एओ और एएओ के लिए “ऑनलाइन एडवांस्ड टाइम मैनेजमेंट इन नॉर्मल” पर सत्र आयोजित किया।
7. नासेन, जेडटीआई दिल्ली के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट और वर्क लाइफ बैलेंस पर सत्र आयोजित किया।
8. सीबीआईसी अफिसर्स, नासेन, फरीदाबाद के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी पर सत्र आयोजित किया।
9. इंस्पेक्टर्स और सीबीआईसी अफिसर्स, नासेन, फरीदाबाद के लिए साइबर फोरेंसिक पर सत्र आयोजित किया।
10. साइबर सुरक्षा रणनीति, साइबर निरस्त्रीकरण और रक्षा खरीद (डीपीपी) में 46वें अप्पा में तीन वर्ग (स्ट्रीम्स) लिए।
11. केंद्रीय मंत्री जनरल वी के सिंह, सीओएएस की राष्ट्रीय सुरक्षा वार्ता का समन्वय और व्यवस्था की।
12. इनर इंजीनियरिंग और वेल बीइंग पर सदगुरु सत्र का समन्वय और व्यवस्था की।
13. तीनों सेनाओं द्वारा रक्षा खरीद पर पैनल चर्चा की।
14. दिनांक 15 मार्च को भा.लो.प्र.सं. में एनडीयू नेपाल प्रतिनिधिमंडलके लिए भा.लो.प्र.सं. प्रजेंटेशन बनाया और समन्वित किया।

क (ii) शिक्षण

	केवल संख्या
व्याख्यानों की संख्या (रिपीट टॉपिक्स) :	58
व्याख्यानों की संख्या (नए टॉपिक्स) :	58
कुल :	116

क (iii) अन्य कार्य (घंटों की संख्या मात्र)

पैनल चर्चा	: रक्षा खरीद पर 46वें अप्पा अधिकारियों के साथ
त्रि सेवा पैनल चर्चा	: (3 घंटे)
समूह चर्चा	: (3 घंटे)
अभ्यास	: प्रयोगशाला अभ्यास (10 घंटे)
मामलों की चर्चा	: प्रशिक्षण की तैयारी
प्रस्ताव	: तैयार 10 प्रशिक्षण प्रस्ताव (40 घंटे)

क (iv) क्या आप शिक्षण में दिये गये अपने योगदान और सामग्री से संतुष्ट हैं? हाँ और लगातार सुधार हो रहा है।

अपने योगदान को बेहतर बनाने के लिए उपाय सुझाएं। शिक्षण क्षेत्र में कुछ प्रमाणित प्रशिक्षण की आवश्यकता है। व्यक्तिगत रूप से मैंने डेटा साइंस में एक पूरा किया है।

पूर्ण अनुसंधान परियोजनाएं (श्रेणी क)

पूर्ण अनुसंधान परियोजनाएं (श्रेणी ख)

चालू अनुसंधान परियोजनाएं (श्रेणी क)

चालू अनुसंधान परियोजनाएं (श्रेणी ख)

सभी श्रेणियों को सारणीबद्ध रूप में संक्षेपित किया गया है:

क्रमांक	स्टडी टाइटल	संकाय का नाम	मंत्रलय/विभाग	कुल लागत	रिसर्च टीम	अवस्थिति
1.	इंपूविंग गवर्नेन्स: रिकंस्ट्रक्चरिंग डेस्क ऑफिसर- अ स्टडी	प्रो. सी. शीला रेड्डी डॉ सुरभि पांडेय	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग	कुछ नहीं	प्रो. शीला रेड्डी डॉ सुरभि पांडेय	सम्मिलित
2.	कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन रिपोर्ट	डॉ सुरभि पांडेय	सीबीसी	कुछ नहीं	अमिताभ रंजन और प्रो. अशोक विशनदास	सम्मिलित

3.	थर्ड पार्टी इवेल्यूएशन ऑफ बॉर्डर एरिया डेवेलपमेंट प्रोग्राम (बीएडीपी) स्कीम फार बॉर्डर मैनेजमेंट, गृह मंत्रालय	डॉ सुरभि पांडेय	गृह मंत्रालय	लाख में	मनीषा चौहान यूमना जमाल सुदेती कंबोज	सम्मिलित
4.	थर्ड पार्टी इवेल्यूएशन ऑफ कोस्टल सिक्योरिटी सर्विस (सीएसएस) फेज-2 फार बॉर्डर मैनेजमेंट, गृह मंत्रालय	डॉ सुरभि पांडेय	गृह मंत्रालय	8.50 लाख	शौर्या सिंगुरु सुरभि खुल्लर	सम्मिलित
5.	थर्ड पार्टी इवेल्यूएशन ऑफ बॉर्डर इंफस्ट्रक्चर मैनेजमेंट (बीआईएम), स्कीम फार बॉर्डर मैनेजमेंट, गृह मंत्रालय	डॉ सुरभि पांडेय	गृह मंत्रालय	9 लाख	मनीषा चौहान यूमना जमाल	सम्मिलित
6.	थर्ड पार्टी इवेल्यूएशन ऑफ इंडियन साइबर क्राइम कार्डिनेशन सेंटर (आई4सी) स्कीम, गृह मंत्रालय	डॉ सुरभि पांडेय	गृह मंत्रालय	8 लाख	मनीषा चौहान सुरभि खुल्लर शौर्या सिंगुरु	सम्मिलित
7.	थर्ड पार्टी इवेल्यूएशन ऑफ द स्कीम फार “एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स” ऑफ डीएआर एंड पीजी	डॉ सुरभि पांडेय	प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	28 लाख	मनीषा चौहान यूमना जमाल तनुष्का शर्मा	सम्मिलित
8.	थर्ड पार्टी इवेल्यूएशन ऑफ “डेवेलपिंग स्पेलिस्ट इंवेस्टीगेटर्स” (डीएसआई) स्कीम	डॉ सुरभि पांडेय	बीपीआरएंडडी, गृह मंत्रालय	11 लाख	शौर्या सिंगुरु यूमना जमाल	सम्मिलित
9.	थर्ड पार्टी इवेल्यूएशन ऑफ “असिस्टेंस टू स्टेट्स एंड यूटीआई फार नारकोटिक्स कंट्रोल” स्कीम ऑफ एनसीबी	डॉ सुरभि पांडेय	एनसीबीए गृह मंत्रालय	11 लाख	यूमना जमाल मनीषा चौहान शिप्रा बाली राहुल शर्मा	चल रहा है

10.	थर्ड पार्टी इवेल्यूएशन ऑफ साइबर क्राइम प्रीवेंशन अगेंस्ट वूमन एंड चिल्ड्रेन (सीसीपीडब्ल्यूसी) स्कीम	डॉ सुरभि पांडेय	गृह मंत्रालय	8 लाख	मनीषा चौहान	सम्मिलित
11.	थर्ड पार्टी इवेल्यूएशन ऑफ कैपीटल एंड रेवेन्यू स्कीम इन एलबीएसएनए	डॉ सुरभि पांडेय	एलबीएसएनए, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग	11 लाख	शौर्या सिंगुरु	चल रहा है
12.	थर्ड पार्टी इवेल्यूएशन ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम (ईआरएसएस) फार सेफ्टी ऑफ वूमन अंडर द निर्भया फंड, गृह मंत्रालय	डॉ सुरभि पांडेय	महिला सुरक्षा प्रभाग, गृह मंत्रालय	8 लाख	मनीषा चौहान यूमना जमाल आयुष नेगी डॉ. चंद्रा सेन शिप्रा बाली	चल रहा है
13.	थर्ड पार्टी इवेल्यूएजन ऑफ कैपीसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ इंवेस्टीगेटर्स एंड प्रोजिक्ट्यूर्ट्स फार सेफ्टी ऑफ वूमन अंडर द निर्भया फंड, गृह मंत्रालय	डॉ सुरभि पांडेय	महिला सुरक्षा प्रभाग, गृह मंत्रालय	8 लाख	मनीषा चौहान यूमना जमाल आयुष नेगी डॉ. चंद्रा सेन शिप्रा बाली	चल रहा है
14.	थर्ड पार्टी इवेल्यूएशन ऑफ स्ट्रेंथनिंग डीएनए एनॉलाइसेस, साइबर फारेंसिक एंड रिलेटेड फेसिलिटीज इन एसएफएसएल फार सेफ्टी ऑफ वूमन अंडर द निर्भया फंड, गृह मंत्रालय	डॉ सुरभि पांडेय	महिला सुरक्षा प्रभाग, गृह मंत्रालय	8 लाख	मनीषा चौहान यूमना जमाल आयुष नेगी डॉ. चंद्रा सेन शिप्रा बाली	चल रहा है
15.	थर्ड पार्टी इवेल्यूएशन ऑफ स्ट्रेंथनिंग एंटी हयूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स इन आल डिस्ट्रिक्ट्स फार सेफ्टी ऑफ वूमन अंडर द निर्भया फंड, गृह मंत्रालय	डॉ सुरभि पांडेय	महिला सुरक्षा प्रभाग, गृह मंत्रालय	8 लाख	मनीषा चौहान यूमना जमाल आयुष नेगी डॉ. चंद्रा सेन शिप्रा बाली	चल रहा है
16.	थर्ड पार्टी इवेल्यूएशन ऑफ स्ट्रेंथनिंग वूमन हैल्प डेस्क इन पुलिस स्टेशंस फार सेफ्टी ऑफ वूमन अंडर द निर्भया फंड, गृह मंत्रालय	डॉ सुरभि पांडेय	महिला सुरक्षा प्रभाग, गृह मंत्रालय	8 लाख	मनीषा चौहान यूमना जमाल आयुष नेगी डॉ. चंद्रा सेन शिप्रा बाली	चल रहा है

17.	थर्ड पार्टी इवेल्यूएशन ऑफ सेफ्टी प्रोजेक्ट्स फार सेफ्टी ऑफ वूमन अंडर द निर्भया फंड, गृह मंत्रालय	डॉ सुरभि पांडेय	महिला सुरक्षा प्रभाग, गृह मंत्रालय	8 लाख	मनीषा चौहान यूमना जमाल आयुष नेगी डॉ. चंद्रा सेन शिप्रा बाली	चल रहा है
-----	--	-----------------	------------------------------------	-------	---	-----------

केस स्टडी तैयार

- शीर्षक: इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम इन इंडिया; अ क्रिटिकल एनॉलाइसेस)

प्रकाशन

पुस्तकें:

- शीर्षक: एमडीपी कॉफी टेबल बुक
- प्रकाशक: भा.लो.प्र.सं.
- जगह: भा.लो.प्र.सं.
- प्रकाशन की तिथि: 9 जनवरी

प्रपत्र और लेख

- शीर्षक: इंपेक्ट ऑफ ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी इन रीयल टाइम गवर्नेंस
- जर्नल: एससीएम जर्नल ऑफ इंडियन मैनेजमेंट
- बॉल्यूम (समीक्षा और प्रकाशन के तहत)
- संख्या:
- तिथि:

(ग) कोई अन्य प्रकाशन

- शीर्षक: आर्टिकल ऑन साइबर पेडेमिक
- पुस्तकों में अध्याय/जर्नल में लेख :
- जगह: दिल्ली
- दिनांक: 21 जुलाई
- प्रस्तुत पेपर का शीर्षक:

I. भा.लो.प्र.सं. के भीतर शैक्षणिक कार्य के अन्य रूपों के साथ संबद्धता

(क) समिति/अन्य (डिवीजन एवं योजना और सलाहकार समिति की सदस्यता, समन्वयक,

संपादकीय, संयोजक, आदि) - विवरण और भागीदारी की प्रकृति।

1. तकनीकी समिति

2. दो राष्ट्रीय स्तर के वेबिनार के संयोजक

(ख) Hkykisizl a ds ckgj 'Klf. kd dk; Zds l kfk l tdk ¼ fefr; k@ckMs vfn dh l nL; rk½

1. भारतीय मानक ब्यूरो

2. सीमा क्षेत्र विकास पर गृह मंत्रालय

3. आई4सी. एमएचए (साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र)

जे. शाखाओं के साथ संबद्धता

शाखा : उत्तर प्रदेश

3. संगोष्ठी/सम्मेलन: स्वच्छ गंगा पर वेबिनार 21 नवंबर को प्रस्तावित

के. भा.लो.प्र.सं. के बाहर किए गए अन्य शैक्षणिक कार्यों का विवरण

1. आई4सी डिवीजन, गृहमंत्रालय में साइबर सुरक्षा के मुद्दों पर भा.लो.प्र.सं. प्रस्तुत किया

2. बीआईएस के लिए एक सदस्य के रूप में कार्य

- उच्च शिक्षा, कौशल विकास और संबंधित सेवाएं अनुभागीय समिति, एसएसडी 04
- स्कूल शिक्षा और संबंधित सेवाएं अनुभागीय समिति, एसएसडी 15
- ई-बीआईएस पोर्टल- भारतीय मानक की समीक्षा: आईएस 16533: 2016 टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया है।
- उच्च शिक्षा, कौशल विकास और संबंधित सेवाओं में मानकीकरण के लिए रणनीति और रोडमैप

दस्तावेज़ के लिए पैनल की पहली बैठक, एसएसडी
04/पी-1

3. बीएम डिवीजन के लिए कार्य, गृह मंत्रालय
- सीमावर्ती क्षेत्र के गांवों और जिलों की रैकिंग की रूपरेखा
4. एमईआईटीवार्ड को परामर्श - ईएमसी 2.0 योजना के लिए उद्योग और हितधारक परामर्श।

एल. शुरू की गयी किसी अन्य शैक्षणिक या संबंधित गतिविधियों का विवरण जिसे ऊपर शामिल नहीं किया गया है।

1. केंद्रीय मंत्री जनरल वी. के सिंह, सीओएस की राष्ट्रीय सुरक्षा वार्ता का समन्वय और व्यवस्था।
2. आंतरिक इंजीनियरिंग और भलाई पर सदगुरु, ईशा फाउंडेशन सत्र का समन्वय और व्यवस्था।
3. त्रि सर्विस एयर इंडिया, सेना और नौसेना द्वारा रक्षा खरीद पर पैनल चर्चा: तीन सितारा अधिकारियों द्वारा रक्षा खरीद और प्रक्रिया के बारे में चर्चा।
4. जनरल राजेश पंत (पीएमओ कार्यालय, एनसीएससी) और श्री भल्ला, निदेशक, आई4सी, गृह मंत्रालय द्वारा साइबर सुरक्षा और सोशल इंजीनियरिंग पर

अमित कुमार सिंह

क. शिक्षण/प्रशिक्षण (i)

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	प्रायोजक एजेंसी	नई/रिपीट
1.	नगर निगम और ग्रेड 'ए' नगर पालिकाओं के नगर आयुक्तों के लिए नगरीय प्रशासन पर तीन दिवसीय डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम	14-16 दिसंबर, 2020	तमिलनाडु सरकार	नई
2.	एसएलटीसी (स्टेट लेवल टैक्नीकल सेल) और सीएलटीसी (सिटी लेवल टैक्निकल सेल) के विशेषज्ञों/विशेषज्ञों के लिए पीएमएवार्ड-एचएफए।	19 जनवरी, 2021	हिमाचल प्रदेश सरकार	नई
3.	एसएलटीसी (स्टेट लेवल टैक्नीकल सेल) और सीएलटीसी (सिटी लेवल टैक्निकल सेल) के विशेषज्ञों/विशेषज्ञों के लिए पीएमएवार्ड-एचएफए।	21 जनवरी, 2021	हिमाचल प्रदेश सरकार	नई

ऑनलाइन वेबिनार का समन्वय और व्यवस्था।

5. श्री तुहिन कांता पांडे, आईएएस द्वारा निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम) पर ऑनलाइन वेबिनार का समन्वय और व्यवस्था।
6. मैट्रिक्स फार ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड डिज़ाइन (एमओओडी) के लिए नए प्लेटफॉर्म का अनुकूलन यानी भा.लो.प्र.सं. शिक्षा।
7. भा.लो.प्र.सं. एलएमएस और डब्ल्यूआईजेडआईक्यू पर कार्य।
8. वीबेक्स इंस्टालेशन और टीम रिन्यूअल।
9. एमडीपी यूपी न्यायपालिका के कॉफी टेबल बुक की तैयारी और संपादन
10. अप्पा अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय फोरेंसिक प्रयोगशाला के दौरे का आयोजन
11. दिनांक 15 मार्च को भा.लो.प्र.सं. में एनडीयू नेपाल प्रतिनिधिमंडल के लिए भा.लो.प्र.सं. की प्रस्तुति और समन्वय।
12. भा.लो.प्र.सं. द्वारा सीबीसी को प्रस्तुत क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) रिपोर्ट की तैयारी और संपादन।

क (ii) शिक्षण	केवल संख्या	करता हूँ; हालांकि सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है।
व्याख्यानों की संख्या (रिपीट टॉपिक्स) :	7	ख. प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव
व्याख्यानों की संख्या (नए टॉपिक्स) :	18	
कुल :	25	
क (iii) अन्य कार्य (घटों की संख्या मात्रा)		
पैनल चर्चा :	5	• डॉ. कुसुम लता के साथ एससीटीपी और टीडीपी के तहत तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया: “डिसेन्ट्रलाइज्ड प्लानिंग इन न्यू नॉर्मल”।
समूह चर्चा :	6	• डॉ. ममता पठानिया के साथ भारतीय रक्षा संपदा सेवा के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जुड़ेंगे।
अभ्यास :	8	• भा.लो.प्र.सं., नई दिल्ली में बिहार प्रशासनिक सेवा परिवीक्षाधीनों के लिए बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवेलपमेंट (बीआईपीएआर डी) पटना, बिहार के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने समन्वय।
मामलों की चर्चा :	5	
तैयार प्रशिक्षण प्रस्ताव :	400	
क) (i) क्या आप शिक्षण में दिये गये अपने योगदान और सामग्री से संतुष्ट हैं? अपने योगदान में सुधार करने के लिए सुझाव दें		
हाँ, मैं शिक्षण में अपने योगदान से संतुष्ट महसूस		

ग. शोध अध्ययन पूर्ण/जारी

क्रमांक	नाम	प्रायोजक	पूर्ण/चालू
1.	“सभी के लिए प्रशिक्षण” योजना पर मूल्यांकन अध्ययन	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग	पूर्ण
2.	“विदेशी प्रशिक्षण के घरेलू वित्तपोषण” का मूल्यांकन अध्ययन	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग	पूर्ण
3.	मध्य क्षेत्र योजना का तृतीय-पक्ष मूल्यांकन अर्थात् “स्वतंत्रता सेनानी पेंशन और अन्य लाभ”	गृह मंत्रालय	पूर्ण
4.	14 से 15 वर्ष पंचवर्षीय योजना के लिए सीबीआई की चालू र. योजनाओं का मूल्यांकन	सीबीआई मुख्यालय	चालू
5.	राहत गंज/अरम गंज, रोशनआरा रोड, पुल बंगश नई दिल्ली में संपत्ति संख्या 8736-सी के भूमि अधिग्रहण के सामाजिक प्रभाव का आकलन	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी)	जल्द शुरू किया जाएगा
6.	नई दिल्ली के गांव खानपुर में भूमि अधिग्रहण का सोशल इंपैक्ट असेसमेंट (एसआईए)	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी)	जल्द शुरू किया जाएगा
7.	“रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के तहत विवाद समाधान तंत्र के प्रभाव आकलन” पर अनुसंधान अध्ययन	कानून और न्याय मंत्रालय	पुष्टि का इंतजार

घ. अनुसंधान मार्गदर्शन

क्रमांक	नंबर नामांकन	शोध निबंधा शीर्षक	डिग्री पुरस्कार
1.	श्री देवेंद्र सिंह कच्छवाहा (45वां अप्पा)	वर्तमान परिदृष्टि में दूरसंचार विभाग के दूरसंचार अधिकारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताएं	पुरस्कृत
2.	ब्रिगेडियर डी. मिश्रा (46वां अप्पा)	पाकिस्तानी प्रशासन में पाकिस्तानी सेना का बढ़ता प्रभुत्व और भारत-पाक संबंधों पर परिणामी प्रभाव	पुरस्कृत

ड. प्रशिक्षण/सेमिनार/कार्यशाला सम्मेलनों में भाग लिया और कागजात प्रस्तुत किए।

- दिनांक 27 जुलाई, 2020 को “कोविड-19 महामारी के दौरान अपशिष्ट प्रबंधन” पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया।
- राज्यसभा टीवी पर “भारतीय शहरों के रहने योग्यता सूचकांक” पर पैनल चर्चा में भाग लिया।
- सीयूएस/आरसीयूईएस और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की वर्चुअल बैठक में भाग लिया।
- आईआईपीए और विभिन्न अन्य संगठनों द्वारा आयोजित 20 से अधिक वेबिनार में भाग लिया।
- दिनांक 31 जुलाई, 2020 को एनआईयूए, में बुनियादी कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर ई-परामर्श में भाग लिया।

च. प्रकाशन

- सिंह ए.के. (2020): मिशन कर्मयोगी - इन्कारनेशन ऑफ इप्रूविंग द गवर्मेंट ह्यूमन रिसोर्स स प्रैक्टिस इन इंडिया, भा.लो.प्र.सं. डाइजेस्ट में प्रकाशन के लिए प्रस्तुत।
- सिंह ए.के. (2020): “फ्रेस वाटर रिसोर्स स इन इंडिया - इस्पूज एंड कंसर्न” जिसे एस मिश्रा और एम. पठानिया (संपा.) की पुस्तक, ‘क्लाइमेट चेंज, स्टेनेबिलिटी एंड कंज्यूमर: टूवर्ड्स ए बेटर फ्यूचर’, कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी (पी) लिमिटेड, ए/15-16, कर्मशियल ब्लॉक, मोहन गार्डन नई दिल्ली - 110 059 (भारत) में प्रकाशित किया जाएगा।

- सिंह ए.के. (2020): मानविकी में प्रकाशित “इंपैक्ट ऑफ रियल एस्टेट रेयूलेटरी एक्ट, 2016”, “जुलाई-दिसंबर 2019), आईएसएसएन: 0975-7880 271।

छ. शाखाओं के साथ संबद्धता

शाखा : असम शाखा

- संगोष्ठी/सम्मेलन: स्वच्छ भारत मिशन का वेबिनार अगस्त, 2021 में आयोजित किया जाएगा।

ज. अन्य कार्यों में भागीदारी

- मिशन कर्मयोगी के तहत भा.लो.प्र.सं. इंटर्नल फ्रेशिंग टीम के सदस्य रहे।
- दिनांक 5 मार्च, 2021 को “इंडियन सिटीज एंड ईंजी लाइफ” विषय पर राज्यसभा टीवी पर वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया।
- 46वें अप्पा प्रतिभागियों के लिए दो एक्सपोजर यात्राओं का आयोजन किया।
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के लिए पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के यूएलबी में सामुदायिक भागीदारी कानून के कार्यान्वयन पर डेटा संग्रह (चालू)।
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के लिए पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के निर्वाचित/अस्तित्व में मौजूद यूएलबी में पुरुष और महिला पार्षदों की संख्या की वर्तमान स्थिति पर डेटा संग्रह।
- कई शोध परियोजनाओं/मूल्यांकन अध्ययनों को भा.लो.प्र.सं. में लाने में सफल।

अनुसूची च.6

वर्ष 2020-2021 के दौरान शाखाओं को दी गई वित्तीय सहायता का विवरण

क्रमांक	क्षेत्रीय शाखाएं	वित्तीय सहायता	50 प्रतिशत ब्याज/ वार्षिक सदस्यता	कुल राशि
1.	असम	30000	1136	31136
2.	बिहार	30000	4219	34219
3.	दिल्ली	30000	10425	40425
4.	गोवा (वेस्ट कोस्ट)	0	0	0
5.	गुजरात	0	0	0
6.	हरियाणा	30000	1974	31974
7.	हिमांचल प्रदेश	0	0	0
8.	जम्मू-कश्मीर	30000	4190	34190
9.	झारखण्ड	0	0	0
10.	कर्नाटक	30000	2352	32352
11.	केरल	30000	2082	32082
12.	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	30000	2892	32892
13.	महाराष्ट्र	30000	4407	34407
14.	मणिपुर	0	0	0
15.	मेघालय	0	0	0
16.	मिजोरम	0	405	405
17.	ओडिशा	30000	1974	31974
18.	पंजाब और चंडीगढ़	0	2000	2000
19.	राजस्थान	30000	2865	32865
20.	तमिलनाडु	30000	5895	35895
21.	तेलंगाना और आंध्र प्रदेश	30000	4807	34807
22.	उत्तर प्रदेश	30000	6726	36726
23.	उत्तराखण्ड	0	0	0
24.	पश्चिम बंगाल	0	0	00
	योग (क)	420000	58349	478349

क्रमांक	क्षेत्रीय शाखाएं	वित्तीय सहायता	50 प्रतिशत ब्याज/वार्षिक सदस्यता	कुल राशि
1.	आगरा	15000	297	15297
2.	ओरंगाबाद	0	758	758
3.	बरेली	15000	432	15432
4.	बुदौन	0	1271	1271
5.	बर्द्वान	15000	351	15351
6.	कोयम्बटूर	0	0	0
7.	कुड्डालोर	15000	946	15946
8.	कटक	0	0	0
9.	धारवाड़	15000	324	15324
10.	डिंडीगुल	0	0	0
11.	गुलबर्गा	0	514	514
12.	हावड़ा	15000	297	15297
13.	इंदौर	0	432	432
14.	जबलपुर	0	378	378
15.	जमशेदपुर	0	0	0
16.	कानपुर	15000	1406	16406
17.	करीमनगर	15000	244	15244
18.	मदुरै	0	1297	1297
19.	मेरठ	0	0	0
20.	मुजफ्फरपुर	0	676	676
21.	मैसूर	0	0	0
22.	नागपुर	0	1000	1000
23.	नासिक	0	0	0
24.	पटियाला	0	0	0
25.	पाटलिपुत्र	0	244	244
26.	पुडुचेरी	15000	541	15541
27.	पुणे	0	1385	1385
28.	सैदापेट	0	0	0
29.	सलेम	0	0	0
30.	सांगली	0	0	0
31.	सिरोही	0	0	0
32.	तंजावुर	0	163	163

33.	तिरुचिरापल्ली	0	0	0
34.	तिरुनेलवेली	0	0	0
35.	तिरुपति	15000	899	15899
36.	तिरुपत्तूर	15000	378	15378
37.	वडोदरा	15000	297	15297
38.	वल्लभ विद्यानगर	0	108	108
39.	वेल्लोर	0	0	0
40.	विल्लुपुरम	15000	460	15460
41.	विरुद्धनगर	0	0	0
42.	विशाखापट्टनम	15000	811	15811
43.	वारंगल	0	1055	1055
	योग (ख)	210000	17036	226964
	योग (क)	420000	58349	478349
	कुल योग (क) + (ख)	630000	75385	705313

अनुसूची च-7

वर्ष 31.03.2021 के लिए भा.लो.प्र.सं. क्षेत्रीय/स्थानीय शाखाओं से जुड़े संकाय सदस्य

क्रमांक	स्थानीय/क्षेत्रीय शाखा नाम का नाम	संकाय सदस्यों के नाम
1.	असम	डॉ. श्यामली सिंह
2.	बिहार	डॉ. नुपूर तिवारी
3.	दिल्ली	प्रो. सुरेश मिश्र
4.	गुजरात	प्रो. अशोक विशनदास
5.	हरियाणा	डॉ. नीतू जैन
6.	हिमाचल प्रदेश	डॉ. साकेत बिहारी
7.	जम्मू-कश्मीर	प्रो. अशोक विशनदास
8.	झारखण्ड	डॉ. मनन द्विवेदी
9.	कर्नाटक	डॉ. सपना चड्डा
10.	कर्नाटक	डॉ. पवन तनेजा
11.	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	डॉ. कुसुम लता
12.	महाराष्ट्र	प्रो. विनोद के शर्मा
13.	मणिपुर	डॉ. सचिन चौधरी
14.	मेघालय	डॉ. रोमा देबनाथ
15.	मिजोरम	डॉ. अमित सिंह
16.	ओडिशा	डॉ. गदाधर महापात्रा
17.	पुडुचेरी	डॉ. चारू मल्होत्रा
18.	पंजाब और चंडीगढ़ (यूटी)	प्रो. के के पांडेय
19.	राजस्थान	प्रो. सुरेश मिश्र
20.	तमिलनाडु	डॉ. ममता पठानिया
21.	तेलंगाना और आंध्र प्रदेश	डॉ. ममता पठानिया
22.	उत्तर प्रदेश	डॉ. सुरभि पांडेय
23.	उत्तराखण्ड	डॉ. वी एन आलोक
24.	पश्चिम बंगाल	डॉ. रोमा देबनाथ

अनुसूची च.8

संकाय और वरिष्ठ अधिकारी (31.03.2021)

श्री सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी, आईएएस (सेवानिवृत्त) महानिदेशक

श्री अमिताभ रंजन, कुल सचिव

प्रोफेसर

1.	प्रो. वीके शर्मा	आपदा प्रबंधन के प्रोफेसर
2.	प्रो. के.के पांडेय	शहरी प्रबंधन के प्रोफेसर
3.	प्रो. सुरेश मिश्रा	लोक प्रशासन के प्रोफेसर (उपभोक्ता मामलों में विशेषज्ञता के साथ)
4.	प्रो. अशोक कुमार विश्वनदास	एप्लाइड इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर

एसोसिएट प्रोफेसर

1.	डॉ. वीएन आलोक	शहरी वित्त में एसोसिएट प्रोफेसर
2.	डॉ. कुसुम लता	शहरी और क्षेत्रीय योजना में एसोसिएट प्रोफेसर
3.	डॉ. चारू मल्होत्रा	ई-गवर्नेंस और आईसीटी में एसोसिएट प्रोफेसर
4.	डॉ. सचिन चौधरी	लोक प्रशासन में एसोसिएट प्रोफेसर
5.	डॉ. नीतू जैन	व्यवहार विज्ञान में एसोसिएट प्रोफेसर
6.	डॉ. साकेत बिहारी	एसोसिएट प्रोफेसर (विकास अध्ययन)
7.	डॉ. रोमा देबनाथ	एप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर
8.	डॉ. नूपुर तिवारी	राजनीति विज्ञान और ग्रामीण विकास में एसोसिएट प्रोफेसर (पंचायती राज सहित)

सहायक प्रोफेसर

1.	डॉ. सपना चड्डा	संवैधानिक और प्रशासनिक कानून में सहायक प्रोफेसर
2.	डॉ. मनन द्विवेदी	अंतरराष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन में सहायक प्रोफेसर
3.	डॉ. श्यामली सिंह	पर्यावरण प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन में सहायक प्रोफेसर
4.	डॉ. ममता पठानिया	लोक प्रशासन में सहायक प्रोफेसर
5.	डॉ. गदाधर महापात्रा	समाजशास्त्र में सहायक प्रोफेसर
6.	डॉ. पवन कुमार तनेजा	असिस्टेंट प्रोफेसर ऑपरेशन रिसर्च
7.	डॉ. सुरभि पांडेय	आईटी और ई-गवर्नेंस के असिस्टेंट प्रोफेसर
8.	डॉ. अमित कुमार सिंह	शहरी विकास के सहायक प्रोफेसर

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

1.	श्री मिथुन बरुआ	उप कुल सचिव (एएस)
2.	श्री ओ. पी. चावला	उप पंजीयक (वित्त एवं प्रशासन)
3.	श्रीमती मैथिली	सहायक रजिस्ट्रार (प्रशासन)
4.	श्रीमती अलका जिंदल	अधीक्षक (प्रशिक्षण)
5.	श्री एमएस बिष्ट	अधीक्षक (सदस्यता)
6.	श्री अनिल कुमार शर्मा	अधीक्षक (अप्पा)
7.	श्री आर.डी. कर्दम	प्रभारी अधिकारी (लेखा)

पब्लिकेशन स्टॉफ

1.	सुश्री मेघना चुक्कथ	सहायक प्रकाशन अधिकारी
----	---------------------	-----------------------

वरिष्ठ पुस्तकालय स्टॉफ सदस्य

1.	श्री हुकम चंद यादव	कार्यवाहक पुस्तकाल्याध्यक्ष
2.	श्रीमती मीना	पेशेवर सहायक (सीनियर स्केल)
3.	श्री हेमंत खरे	पेशेवर सहायक (सीनियर स्केल)
4.	श्रीमती शक्ति चौहान	पेशेवर सहायक (सीनियर स्केल)
5.	श्री नरेंद्र कुमार	पेशेवर सहायक (सीनियर स्केल)
6.	श्रीमती सुनीता गौतम	पेशेवर सहायक (सीनियर स्केल)

रिसर्च कोर्डिनेट यूनिट

1.	श्री राकेश जोशी	अधीक्षक (आरएंडसी और सीयूएस)
----	-----------------	-----------------------------

रख-रखाव अनुभाग

1.	श्री हरि ओम गोयल	कार्यपालक अधियंता
2.	श्री अशोक शर्मा	इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर

अनुसूची च.9

शहरी अध्ययन केंद्र की गतिविधियाँ (अप्रैल 2020-मार्च 2021)

कोविड-19 के कारण वर्ष 2020-21 की शुरुआत देशव्यापी तालाबंदी और अनुसंधान और प्रशिक्षण से संबंधित शैक्षणिक गतिविधियों के लिए एक बाधा के साथ हई थी। सीयूएस ने अपनी गतिविधियों को उपयुक्त रूप से संशोधित किया और अनुसंधान और प्रशिक्षण, अंतर-संस्थागत समन्वय, वेबिनार और संरचित चर्चाओं को कवर करते हुए डिजिटल कनेक्टिविटी और वर्चुअल मोड को जल्दी से अपनाया। साथ ही, पूर्व-डिज़ाइन किए गए प्रश्नावली/डेटाशीट और सूचना के संग्रह पर ऑनलाइन शोधकार्य शुरू किया गया था।

सीयूएस ने क्षमता निर्माण पर ऑनलाइन संबंद्धता के लिए राज्य सरकारों से उनके सहयोग के लिए भी संपर्क किया। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश आदि जैसे कग्र राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन और शैक्षणिक कार्यों पर हस्ताक्षर करने के लिए आगे आने के साथ इसके सकारात्मक परिणाम मिले हैं।

डिजिटल प्रक्रिया को संचालित करने के लिए मूडल और गूगल मीट, सिस्को (वेबेक्स), माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आदि के माध्यम से वर्चुअल प्लेटफॉर्म बनाया गया था।

नए सामान्य के अनुरूप, सीयूएस ने ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए अनूठी सामग्री भी विकसित की जिसमें बीडियो, पीपीटी, प्रश्नोत्तरी और आईआईपीए डिजिटल प्लेटफार्म (मूडल) के तहत रखी गई पठन सामग्री शामिल है। विभिन्न शहरी विषयों पर 35 मॉड्यूल विकसित किए गए हैं और उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रखा गया है।

दीर्घकालिक समन्वय और तालमेल के लिए एनआईयूए के साथ एक अलग समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। एसबीएम (स्वच्छ भारत मिशन) और स्मार्ट सिटीज मिशन पर एनआईयूए नेटवर्क की सूचना साझा करने और साझेदारी पर गतिविधियाँ शुरू की गई हैं।

मिशन कर्मयोगी के फोकस के अनुरूप, योग्यता का आकलन करने, अंतर की पहचान करने और तदनुसार मॉड्यूल के लिए सामग्री विकसित करने के लिए टीएनए अध्ययन किए गए।

वर्ष के दौरान शुरू की गई गतिविधियों में शामिल हैं:

- क. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण गतिविधियाँ (जिनमें 25 कार्यक्रम, ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए 35 मॉड्यूल और 1254 प्रतिभागी शामिल हैं)
- ख. अनुसंधान और सलाहकार सेवाएं (जिनमें 11 अनुसंधान और संबंधित गतिविधियाँ, सलाहकार सेवाओं के 11 क्षेत्र शामिल हैं)
- ग. प्रकाशन और अन्य व्यावसायिक गतिविधियाँ (जिनमें ट्रैमासिक जर्नल, भा.लो.प्र.सं. डाइजेस्ट का विशेष अंक, पत्र, टीवी वार्ता, सेमिनार में भागीदारी शामिल हैं)

क. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण गतिविधियाँ

इन आयोजनों में शामिल हैं (1) नौ वर्चुअल कार्यशालाएं, वेबिनार और समन्वय बैठकें, (2) शहरी विकास और संबंधित मुद्दों पर नौ अनुकूलित और मिश्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम, और (3) अखिल भारतीय/केंद्रीय, रक्षा सेवाओं, सरकारी विभागों और एजेंसियों के सरकारी अधिकारियों के लिए सात ऑनलाइन मिड कैरियर/कैरियर वृद्धि कार्यक्रमों के लिए शहरी मॉड्यूल का डिजाइन, विकास और वितरण। ।

वर्चुअल कार्यशाला, वेबिनार और समन्वय बैठकें

इन नौ आयोजनों ने प्रतिभागियों को विशिष्ट विषयों पर विचार-विमर्श करने के लिए गणमान्य व्यक्तियों और उच्च प्रतिष्ठित पेशेवरों के साथ बातचीत करने की सुविधा प्रदान की। (तालिका 1) संसाधन व्यक्तियों में श्री

दुर्गा शंकर मिश्रा (आईएएस), सचिव, श्री संजय कुमार (आईएएस), जेएस (एनयूएलएम और एलएसजी), सुश्री डी थारा (आईएएस), जेएस (एएमआरयूटी), श्री योगेंद्र सिंह, निदेशक (एलएसजी), आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और श्री हितेश वैद्य, निदेशक, एनआईयूए, श्री शैलेष पाठक, सीईओ और निदेशक, एलएंडटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और आरसीयूईएस (हैदराबाद, मुंबई और लखनऊ) के निदेशक। भावी गतिविधियों के पूर्वांकलन हेतु श्री कुणाल कुमार (आईएएस), जेएस (एससीएम) और एनआईयूए के साथ एक दूसरी वर्चुअल अंतर-संस्थागत सहयोग वेबिनार का आयोजन किया गया।

शहरी विकास और संबंधित मुद्दों पर आँनलाइन अनुकूलित/मिश्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम

नौ अनुकूलित और बेलेंडेड प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नगर आयुक्तों, पीएमएवाई के पदाधिकारियों, अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन के अधिकारियों, कैट बोर्ड/एमईएस आदि के अधिकारियों के लिए विशेष कार्यक्रम शामिल थे। (तालिका 2) रिसोर्स पर्सन श्री संजय कुमार (आईएएस), जेएस (एनयूएलएम), श्री एमिर्ट अभिजात, जेएस (पीजीआई), एमएस डी थारा, जेएस (अमृत), श्री योगेन्द्र सिंह, निदेशक (एलएसजी), श्री आरएस सिंह, निदेशक (एचएफए), डॉ उषा महावीर, पूर्व ईडी (प्रोजेक्ट्स) हुडको आदि शामिल थे।

इसके अलावा, अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं और रक्षा सेवाओं के सरकारी अधिकारियों के लिए शहरी शासन पर एक सप्ताह का मॉड्यूल भी दिया गया।

सरकारी अधिकारियों के लिए आँनलाइन मिड-कैरियर कार्यक्रमों में शहरी मॉड्यूल का डिजाइन, विकास और वितरण

सरकारी अधिकारियों (अखिल भारतीय/केंद्रीय और रक्षा सेवाओं और सरकारी विभागों और एजेंसियों) के लिए भा.लो.प्र.सं. के सात मध्य कैरियर/कैरियर वृद्धि कार्यक्रमों के लिए शहरी मॉड्यूल का डिजाइन विकास और आँनलाइन वितरण किया गया था।

ख. अनुसंधान और सलाहकार सेवाएं (11)

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को सुझाए गए समकालीन शहरी मुद्दों पर अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं को इस प्रकार शुरू किया गया: -

अनुसंधान

1. तमिलनाडु में क्लाइमेट स्मार्ट म्यूनिसिपल सर्विसेज – केस स्टडीज
2. अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों द्वारा शहरी मुद्दों पर निबंधन
3. शहर और शहरीकरण जनगणना पर आंतरिक अनुसंधान।
4. नगर सेवाओं की जलवायु स्मार्ट डिलीवरी पर आंतरिक अध्ययन।
5. तमिलनाडु में नगर निगम के अभियंताओं के लिए शहरी शासन पर वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु ट्रेनिंग नीड असेसमेंट (टीएनए) (चालू)
6. मंत्रालयों/गज्जों और अन्य शहरी संस्थानों को प्रस्तुत तकनीकी प्रस्ताव, जिन पर बातचीत चल रही है, जिसमें निम्न शामिल हैं:-
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लिए भूमि अधिग्रहण का सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए)।
- तमिलनाडु नगर निगम के अधिकारियों/इंजीनियरों के लिए टीएनए।
- मध्य प्रदेश के शहरी पदाधिकारियों के लिए टीएनए।
- सीरिया के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों द्वारा शहरी एक्सपोजर दौरा (विदेश मंत्रालय को प्रस्तुत)
- हिमाचल प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों में कार्यकारी अधिकारियों और सचिवों के लिए प्रेरण कार्यक्रम।

सलाहकार सेवाएं

- म.प्र. शहरी आवास रेंटल पॉलिसी 2020-21 के लिए विशेष जानकारी।

- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के लिए समय-समय पर? संसदीय प्रश्नों पर शहरों/राज्यों से सूचना संग्रह।
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को कार्यों के हस्तांतरण पर उपलब्ध कराया गया संक्षिप्त नोट।
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को यूएलबी के सशक्तिकरण पर बैकग्राउंड नोट।
- सामाजिक-आर्थिक जनगणना-2021 पर प्रश्नावली के लिए शैक्षिक जानकारी।
- सीटों के आरक्षण के बारे में राज्यों से जानकारी और नगर निगम चुनाव लड़ने की पात्रता।
- सामुदायिक संपर्क (नियम और संस्थान) पर प्रदान की गई सूचना/मामले अध्ययन।
- स्थानीय निकाय चुनावों पर राज्यों की अवस्थिति। (आखिरी बार आयोजित और अगले आयोजन के लिए)
- मध्य प्रदेश में संपत्ति कर जुटाने के लिए रोडमैप पर संक्षिप्त नोट।
- अरुणाचल प्रदेश में एनयूएलएम के तहत सामुदायिक आयोजकों के लिए कार्य योजना।
- हिमाचल प्रदेश में पीएमएवाई में विशेषज्ञों के लिए अनुवर्त एजेंडा।

ग. प्रकाशन और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां (त्रैमासिक जर्नल, डाइजेस्ट का विशेष अंक, पेपर, टीवी वार्ता, सेमिनार में भागीदारी) विभिन्न प्रकाशनों और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का श्रेय सीयूएस को जाता है।

पब्लिकेशंस

1. नगरलोक (त्रैमासिक) नियमित रूप से प्रकाशित होता है।
2. आईआईपीए डाइजेस्ट का विशेष अंक (शहरी क्षेत्र को समर्पित), खंड संख्या 02 अंक 03 जुलाई -

सितंबर, 2020। (शहरी विकास और अर्थव्यवस्था पर श्री दुर्गा शंकर मिश्रा और श्री संजय कुमार (आईएएस) और जेएस (एनयूएलएम) के साथ प्रधानमंत्री स्ट्रीट बैंडर आत्मनिर्भर निधि पर विशेष बातचीत शामिल) - एक गुणक प्रभाव के लिए एक जमीनी संपर्क)

3. महामारी के प्रबंधन पर थीम पेपर।
4. भारत में जलवायु परिवर्तन पर शहरी एजेंडे पर प्रपत्र।
5. बोल्स्टर यूएलबी केपेसिटी टू राइज रेवेन्यू, फाइनेंसियल एक्सप्रेस, 25 दिसंबर, 2020।
6. प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए स्थानीय कार्रवाई, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, 18 नवंबर, 2020।
7. शहरी गरीबों के आवास के लिए नीति एजेंडा; निर्माण सारिका, जुलाई-सितंबर 9(3), 2020।
8. यूएलबी, फाइनेंशियल एक्सप्रेस के लिए सांस लेने की जगह, अगस्त, 6, 2020।
9. द अर्बन पिक्चर, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, 3 फरवरी, 2021 (बजट 2021 पर लेख)
10. भारत में पात्र बस्तियों के नगरीकरण पर प्रपत्र।

vU; Q kol kf; d xfrfofek; k

- क. एनसीटीडी, आईटीपीआई (इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन एंड प्लानिंग ऑफ इंडिया), एएमडीए (एसोसिएशन ऑफ म्युनिसिपल एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज) और नगरलोक, एशियन रिव्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आदि जैसे प्रतिष्ठित पत्रिकाओं के संपादकीय बोर्ड, एनसीआर योजना बोर्ड, सरकार द्वारा स्थापित उच्च प्रतिष्ठित एजेंसियों और संस्थानों/आयोगों द्वारा संकाय सदस्यों को मान्यता दी गई है।
- ख. इसके अलावा, सीयूएस फैकल्टी ने हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन सेटलमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (एचएसएमआई), स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के लिए फैकल्टी इनपुट

भी प्रदान किए। इन कार्यक्रमों ने ज्ञान के आगे प्रसार के लिए सिखाने और सीखने का अवसर प्रदान किया।

ग. संकाय ने समकालीन शहरी मुद्दों पर कई संगोष्ठियों/कार्यशालाओं और टीवी चर्चाओं में भाग लिया।

तालिका 1

वर्चुअल कार्यशालाएं, वेबिनार और समन्वय बैठकें

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	अवधि	प्रतिभागियों की संख्या
1.	अटल मिशन फार रीज्यूबेनेशन एंड अर्वन ट्रांसफारमेशन (अमृत) पर वेबिनार	10 फरवरी, 2021	134
2.	एनआईयूसीए और स्मार्ट सिटीज मिशन के साथ समन्वय बैठक	21 सितंबर, 2020	12
3.	शहरी अध्ययन केंद्रों की वेबिनार/वर्चुअल मीटिंग	17 अगस्त, 2020	30
4.	कोविड-19 महामारी के दौरान अपशिष्ट प्रबंधन	27 जुलाई, 2020	180
5.	समकालीन भारत में प्रवासन और रोजगार सृजन: संभावनाएं और चुनौतियां	22 जुलाई, 2020	135
6.	वेबिनार ऑन पेंडेमिक रेजीलिएंट मेट्रो सिटीज	16 जुलाई, 2020	120
7.	शहरी शासन और बुनियादी ढांचे के लिए नए सामान्य पर वेबिनार	15 जून 2020	80
8.	कोविड-19 के बाद में सार्वजनिक सेवा वितरण	10 जून, 2020	40
9.	कोरोना संकट में भारत में स्थानीय सरकारों की उभरती भूमिका	27 मई, 2020	95

तालिका 2

शहरी विकास और संबंधित मुद्दों पर ऑनलाइन अनुकूलित/मिश्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	अवधि	प्रतिभागियों की संख्या
10.	हिमाचल प्रदेश (बैच-2) में एसएलटीसी (राज्य स्तरीय तकनीकी प्रकोष्ठ) और सीएलटीसी (शहर स्तरीय तकनीकी प्रकोष्ठ) पर विशेषज्ञों/निपुणों के लिए पीएमएवाई-एचएफए पर एक दिवसीय विशेष ऑनलाइन कार्यक्रम।	21 जनवरी, 2021	26
11.	हिमाचल प्रदेश (बैच-1) में एसएलटीसी (राज्य स्तरीय तकनीकी प्रकोष्ठ) और सीएलटीसी (शहर स्तरीय तकनीकी प्रकोष्ठ) पर विशेषज्ञों/निपुणों के लिए पीएमएवाई-एचएफए पर एक दिवसीय विशेष ऑनलाइन कार्यक्रम।	19 जनवरी, 2021	27
12.	शहरी प्रबंधन एवं विकास में अनौपचारिक निकायों की भूमिका पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	दिसंबर, 2020	29

13.	तमिलनाडु के नगर आयुक्तों के लिए शहरी शासन पर तीन दिवसीय विशेष वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम	दिसंबर 14-16, 2020	20
14.	शहरी आधारभूत संरचना परियोजनाओं के विकास और प्रबंधन पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	अक्टूबर, 2020	29
15.	सभी भारतीयों/केंद्रीय सेवा अधिकारी के लिए शहरी शासन पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम/	सितंबर, 2020	29
16.	सैन्य अभियंता सेवाओं / छावनी बोर्ड के कार्यकारी अभियंताओं के लिए 'वरिष्ठ प्रबंधन पाठ्यक्रम'	30 अगस्त से 5 सितंबर, 2020।	57
17.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लोक प्रशासकों से उन्नत डेटा विश्लेषण पर एक सप्ताह का क्षमता विकास कार्यक्रम।	21 से 25 सितंबर, 2020।	25
18.	सैन्य अभियंता सेवाओं/छावनी बोर्ड के इंजीनियरों के लिए मानव संसाधन प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	15-16 अक्टूबर, 2020	30

तालिका 3

सरकारी अधिकारियों के लिए ऑनलाइन मिड-कैरियर कार्यक्रम में शहरी मॉड्यूल का डिजाइन, विकास और वितरण

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	अवधि	प्रतिभागियों की संख्या
19.	“नेतृत्व और लोक प्रशासन” पर तीन दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	04 जनवरी - 06, 2021	20
20.	9वां एडवांस्ड लीडरशिप प्रोग्राम “लीडरशिप एक्सीलेंस फॉर आत्म निर्भर (लीन) भारत”	23 नवंबर - 11 दिसंबर, 2020	14
21.	वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के लिए वैज्ञानिक संगठनों में वित्तीय प्रबंधन पर 9वां टी.पी. (सभी स्तरों के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद्)	नवंबर 23-27, 2020	35
22.	राज्य एटीआई के माध्यम से जिला अधिकारियों के लिए परियोजना जागरूकता और कौशल विकास कार्यक्रम के तहत “शासन में डिजिटल परिवर्तन” पर तीन दिवसीय आभासी शिखर सम्मेलन	अक्टूबर 13-15, 2020	25
23.	बैच-2019 के आईपी एंड ताएफएस ओटीएस का ऑनलाइन अटेंचमेंट (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन फाइनेंस द्वारा प्रायोजित)	10-21 अगस्त, 2020	4
24.	एनएडीपी अधिकारियों के लिए लोक प्रशासन और फाउंडेशन मॉड्यूल, (एनएडीपी, रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित)	जुलाई 13-15, 2020	34
25.	सिक्किम के अधिकारियों के लिए “जलवायु स्मार्ट गवर्नेंस” (डीएसटी, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	जून 1-5, 2020	24

अनुसूची च. 10

उपभोक्ता अध्ययन केंद्र की गतिविधियाँ (अप्रैल 2020- मार्च 2021)

1. प्रस्तावना

उपभोक्ता अध्ययन केंद्र भा.लो.प्र.सं. के बारह केंद्रों में से एक है और सचिव, सीए, भारत सरकार की अध्यक्षता वाली निगरानी समिति के नीति निर्देशों के तहत भा.लो.प्र.सं. के कानूनी ढांचे के भीतर संचालित होता है। केंद्र की भूमिका परिचालन के साथ-साथ प्रचारात्मक दोनों ही प्रकार की है। जुलाई 2007 में भा.लो.प्र.सं. में उपभोक्ता अध्ययन केंद्र स्थापित किया गया था और इसे उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। केंद्र अपनी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उत्कृष्टता केंद्र के रूप में उभरा चुका है। यह देश में अपनी तरह का एकमात्र केंद्र है जो विशेष रूप से उपभोक्ताओं के शिक्षा के अधिकार के संरक्षण और प्रचार के लिए समर्पित है। केंद्र भा.लो.प्र.सं. के कानूनी ढांचे और सचिव, सीए, भारत सरकार की अध्यक्षता वाली निगरानी समिति के नीति निर्देशों के भीतर काम करता है। केंद्र की भूमिका परिचालन के साथ-साथ प्रचारात्मक दोनों प्रकार की है। केंद्र की गतिविधियों में विभिन्न हितधारकों की क्षमता निर्माण, सेमिनार, कार्यशालाएं, अनुसंधान, प्रलेखन और सूचना का प्रसार शामिल है। केंद्र का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों और कल्याण को सुविधाजनक बनाना है।

उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ता कल्याण पर अनुसंधान और नीति संबंधी मुद्दों के लिए केंद्र को उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारत सरकार के “थिंक टैक” और “नॉलेज पार्टनर” के रूप में मान्यता दी गई है। केंद्र राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन और राज्य

एपीपीपीए अनुसंधान मार्गदर्शन

सीसीएस संकाय सदस्यों ने निम्नलिखित शोध प्रबंधों का मार्गदर्शन किया:

क्र.सं.	विषय और उम्मीदवार का नाम	गाइड का नाम
1.	ब्रिगेडियर अतुल भदौरिया, सेना बेस कार्यशालाओं के लिए एक्सप्लोरेशन ऑफ गवर्नेंट ओन्ड कांट्रेक्टर ऑपरेटर ग्रोसस	प्रो सुरेश मिश्रा

2.	श्री खगेश गर्ग, अ स्टडी ऑफ पॉलिसी एंड प्रोग्राम ऑन एल्कोहल (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का केस स्टडी)	प्रो सुरेश मिश्रा
3.	श्री प्रेम चंद शर्मा, असेसमेंट ऑफ इंजिस्ट्रिंग नो योर कस्टमर (केवाईसी) नार्म्स इन टेलीकॉम सैक्टर इन इंडिया एंड वे फारवर्ड	डॉ सपना चड्डा
4.	एयर कमोडोर एस. श्रीकांत, भारतीय पुलिस सेवाओं (एनसीटी) में कार्य बल की तैनाती का युक्तिकरण: एन आइडियल टीथ टू टायल रेश्यो (टी3आर)	डॉ ममता पठानिया

3. अनुसंधान अध्ययन

इस अवधि के दौरान, केंद्र ने विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रभाव का आकलन करने और क्षेत्र में एक डेटाबेस बनाने के लिए 7 मूल्यांकन और शोध अध्ययन किए।

1. रैंकिंग ऑफ स्टेट कंज्यूमर डिस्प्लॉट रिडेसल कंमीशन (पूर्ण)
2. चुलनदा राज्यों में स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के बीच खाद्य सुरक्षा मानकों का मूल्यांकन और पार्टियों और विवाहों के दौरान भोजन की बर्बादी और रोकने के उपाय (पूर्ण)
3. उपभोक्ता मामलों के निपटान और उपभोक्ता मंचों के कामकाज में प्रक्रियात्मक देरी का विश्लेषण (पूर्ण)
4. कोविड-19 लॉकडाउन चरण के दौरान “पेरेंट्स पर्सेष्यन रिगार्डिंग ई-लर्निंग” पर अध्ययन (पूर्ण)
5. चुनिंदा राज्यों में उपभोक्ता अधिकारों पर कोविड-19 के प्रभाव पर अध्ययन (चालू)
6. जिला उपभोक्ता के कामकाज का मूल्यांकन - कर्नाटक में सूचना केंद्र और उपभोक्ताओं के बीच संतुष्टि का स्तर (चालू)
7. एनसीआर में उपभोक्ता संरक्षण और आवास शिकायतों के निवारण में रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 का प्रभाव। (चालू)

4. प्रकाशन

उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ता कल्याण के विभिन्न पहलुओं पर सूचना का प्रसार करने के लिए,

केंद्र ने इस अवधि के दौरान तीन पुस्तकें और तीन मोनोग्राफ निकाले। 4 मोनोग्राफ प्रक्रिया में हैं। केंद्र के शिक्षकों और कर्मचारियों ने भी उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर शोधपत्र प्रस्तुत और प्रकाशित किए। इसके अलावा ई-न्यूजलेटर्स, एडवाइजरी और कैलेंडर के रूप में जागरूकता सामग्री भी प्रकाशित की गई और सामान्य जागरूकता और शिक्षा के लिए व्यापक रूप से प्रसारित की गई।

क. किताबें

1. सुरेश मिश्रा और सपना चड्डा, कंज्यूमर हैंडबुक, सीसीएस, भा.लो.प्र.सं., नई दिल्ली, 2020
2. सुरेश मिश्रा और ममता पठानिया, (संपा.), क्लाइमेट चेंज स्टेनेबिलिटी एंड कंज्यूमर: ट्रुवर्डस ए बेटर “यूचर, कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी (पी) लिमिटेड, नई दिल्ली, 2020
3. पी.वी.वी.एस मूर्ति, मैनुअल ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन (प्रिंट में)

ख. मोनोग्राफ

1. सुरेश मिश्रा, रेरा एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन कंज्यूमर्स, सीसीएस, भा.लो.प्र.सं., नई दिल्ली, 2019 (प्रिंट में)
2. ममता पठानिया, इम्पैक्ट्स ऑफ पेस्टीसाइट्स ऑन कंज्यूमर्स (प्रिंट में)
3. सुरेश मिश्रा और वीरेंद्र नाथ मिश्रा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019-एक परिचय (हिंदी) (प्रिंट में)
4. सुरेश मिश्रा, इम्पैक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजेशन ऑन चिल्ड्रेंस (ड्राफ्ट तैयार)

5. सपना चड्डा, इंस्पोरेंस एंड कंज्यूमर्स (ड्राफ्ट तैयार)
6. ममता पठानिया, कोविड-19: कंज्यूमर परसेप्टिव द न्यू नॉर्मल (प्रक्रिया के तहत)
7. सपना चड्डा, रिटेल सैक्टर एंड कंज्यूमर्स (प्रक्रिया के तहत)

ग. प्रपत्र/ लेख

1. सपना चड्डा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 - एक गेम चेंजर, भा.लो.प्र.सं. डाइजेस्ट, जुलाई - सितंबर 2020
2. एस.एन. त्रिपाठी और सपना चड्डा, रूल ऑफ लॉ, योजना, सितंबर 2020, पीपी. 23-27
3. सपना चड्डा और वरुणी बी.आर., ड्रैकोनियन एसेंसिशल कोमोडिटी एक्ट अंडरगोज अमेंडमेंट, भा.लो.प्र.सं. डाइजेस्ट, अक्टूबर-दिसंबर 2020
4. सपना चड्डा, इमर्जिंग रेगुलेटरी फेमवर्क फॉर ई-कॉर्मर्स इन इंडिया: सम इनसाइट्स, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस एंड इनोवेटिव रिसर्च, वॉल्यूम 7, अंक 4 (2), अक्टूबर- दिसंबर, 2020, पृ.सं. 1-8
5. ममता पठानिया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019, कस्मर्स आवाज, वॉल्यूम. 5 अंक 2, अक्टूबर-दिसंबर 2020

5. प्रचार और उपभोक्ता जागरूकता सामग्री

केंद्र ने उपभोक्ता जागरूकता ई-कैलेंडर निकाला जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2020 के अवसर पर जारी किया गया था। इसके अलावा केंद्र ने नए सीपी अधिनियम, 2019 पर जागरूकता ब्रोशर और पैम्पलेट तैयार किए हैं। केंद्र ने प्रचार सामग्री, कुंजी भी तैयार की है। एनसीएच के प्रचार के लिए जंजीरें और मग। इन्हें उपभोक्ताओं और अन्य हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, यात्राओं और अन्य अवसरों के दौरान वितरित किया जाता है।

6. ई-समाचार पत्र

केंद्र विभिन्न हितधारकों के लाभ के लिए

ई-न्यूज़लेटर “उपभोक्ता संवाद” लाया है। चार तिमाहियों के लिए ई-न्यूज़लेटर तैयार कर वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। इसे संसद सदस्यों सहित कई लोगों को ईमेल भी किया गया था।

7. ई-पत्रिका

केंद्र जुलाई 2016 से हिंदी में ई-पत्रिका “उपभोक्ता वार्ता” निकाल रहा है। ई-पत्रिका त्रैमासिक है और इसे चार तिमाहियों के लिए प्रकाशित किया गया है।

8. सोशल मीडिया पर सीसीएस

केंद्र अब उपभोक्ताओं तक पहुंचने और उन्हें शिक्षित करने के लिए सोशल मीडिया का भी उपयोग कर रहा है। केंद्र की गतिविधियों से संबंधित जानकारी, महत्वपूर्ण घटनाओं और उपभोक्ताओं के लिए अन्य उपयोगी जानकारी फेसबुक और ट्विटर पर साझा की जाती है। फेसबुक पेज “Centrefor Consumer Studies” andTwitter @CCS_IIPA (Consumer Dialogue). है। सोशल मीडिया के माध्यम से कई उपभोक्ता मुद्दों को भी उजागर किया जाता है।

9. विभिन्न समितियों की सदस्यता

केंद्र के संकाय सदस्य विभिन्न समितियों के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। वे इन समितियों में विचार-विमर्श के माध्यम से नीतिगत मुद्दों पर योगदान देते रहे हैं।

1. सदस्य, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल।
2. सदस्य, नेशनल मिर कमेटी ऑफ कोपोल्को, बीआईएस, नई दिल्ली।
3. सदस्य, कमेटी ऑन मिसलीडिंग एडवर्टाइमेंट एंड चीटिंग ऑफ कंज्यूमर्स थ्रो मनी सर्कुलेशन स्कीम, डीसीए।
4. सदस्य, उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने के लिए मल्टी मीडिया एडवाइजरी कमेटी, डीसीए।
5. सदस्य, उपभोक्ता जागरूकता पर आँडियो-विजुअल और प्रिंट क्रिएटिव के लिए लिपियों पर विचार के लिए स्क्रिप्ट कमेटी, डीसीए।
6. सदस्य, जागरूकता पैदा करने के लिए एम्पावर्ड कमेटी, डीसीए, भारत सरकार।

7. सदस्य, भ्रामक विज्ञापनों पर इंटर मिनिस्ट्रीयल मॉनिटरिंग कमेटी।
8. सदस्य, सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी भ्रामक विज्ञापनों पर डीसीए और एएससीआई के बीच समझौता ज्ञापन के तहत।
9. सदस्य, स्टेंडिंग कमेटी विभिन्न कानूनों, डीसीए के तहत पैकेज़ कमोडिटी पर लेबललग आवश्यकताओं को सुसंगत बनाने के लिए।
10. सदस्य, कमेटी फॉर अमेंडमेंट इन एम्बलेम एंड नेम्स (पीवेंशन ऑफ इम्प्रापर यूज) एक्ट, 1950।
11. सदस्य, कमेटी टू फार्मूलेटिंग द रूल्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नियम बनाने के लिए।
12. सदस्य, एक्जीक्यूटिव कमेटी, जेडसीएच, डीओसीए, भारत सरकार के प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए।
13. सदस्य, कन्सल्टेटिव कमेटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सबजेक्ट रिफार्म्स इन टीपीडीएस- वन नेशन वन राशन कार्ड।
14. सदस्य, डिपार्टमेंट और कंज्यूमर अफेयर डीओसीए द्वारा चलाये जा रही उपभोक्ता जागरूकता गतिविधियों के प्रदर्शन की समीक्षा करने वाली कमेटी।

10. अन्य प्रचारक गतिविधियां

जागरूकता पैदा करने और उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए, सीसीएस:

- प्रो. सुरेश मिश्रा, दिनांक 4 जुलाई, 2020 को श्री दुर्गा मल्लेश्वर सिद्धार्थ महिला कलाशाला द्वारा “उपभोक्ता संरक्षण में कोविड-19 नई चुनौतियां और रणनीतियाँ” पर वेबिनार में मुख्य वक्ता रहे।
- प्रो. सुरेश मिश्रा द्वारा दिनांक 5 जुलाह, 2020 को गांधीवादी शांति अध्ययन विभाग, पीयू द्वारा “कोविड-19 ट्रूवडर्स ए स्स्टेनेबल लाइफस्टाइल” पर वेबिनार में सत्र आयोजित किया गया।
- डॉ. सपना चड्डा, सीसीएस, भा.लो.प्र.सं. दिनांक

16 जुलाई, 2020 को कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप द्वारा आयोजित उपभोक्ता और बिजली पर ऑनलाइन चर्चा में पैनलिस्टों में से एक थीं।

- दिनांक 8 अगस्त 2020 को प्रो. सुरेश मिश्रा द्वारा कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया (सीजीएसआई) के सहयोग से “एचएसएनसी बोर्ड के जीजे आडवाणी लॉ कॉलेज, मुंबई द्वारा आयोजित” “उपभोक्ता संरक्षण: कानून और नीतियां” पर ऑनलाइन कार्यशाला में “कोविड-19 और उपभोक्ता संरक्षण पर सत्र आयोजित किया गया।
- दिनांक 8 अगस्त 2020 को एचएसएनसी बोर्ड के जीजे आडवाणी लॉ कॉलेज, मुंबई द्वारा कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया (सीजीएसआई) के सहयोग से आयोजित “उपभोक्ता संरक्षण: कानून और नीतियां” पर ऑनलाइन कार्यशाला में “उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019” पर डॉ सपना चड्डा द्वारा सत्र आयोजित किया गया।
- दिनांक 8 अगस्त 2020 को एचएसएनसी बोर्ड के जीजे आडवाणी लॉ कॉलेज, मुंबई द्वारा 8 अगस्त को कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया (सीजीएसआई) के सहयोग से आयोजित “उपभोक्ता संरक्षण: कानून और नीतियां” पर ऑनलाइन कार्यशाला में “उपभोक्ता शिक्षा और जागरूकता” पर डॉ ममता पठानिया द्वारा सत्र आयोजित किया गया।
- दिनांक 8 अगस्त 2020 को एचएसएनसी बोर्ड के जीजे आडवाणी लॉ कॉलेज, मुंबई द्वारा कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया के सहयोग से आयोजित “उपभोक्ता संरक्षण: कानून और नीतियां” पर ऑनलाइन कार्यशाला में “उपभोक्ता शिकायत निवारण: राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन की भूमिका” पर सुश्री दीपिका सुर द्वारा सत्र (सीजीएसआई) आयोजित किया गया।
- दिनांक 6 सितंबर, 2020 को प्रोफेसर सुरेश मिश्रा द्वारा स्वर्णध्रि ग्रुप ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज, एपी द्वारा आयोजित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,

- 2019 पर ऑनलाइन वेबिनार में “उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण” पर सत्र आयोजित किया गया।
 - दिनांक 6 सितंबर, 2020 को डॉ सपना चड्डा द्वारा स्वर्णध्रि ग्रुप ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज, एपी द्वारा 6 सितंबर, 2020 को आयोजित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 पर ऑनलाइन वेबिनार में “सीपी अधिनियम, 2019 के तहत उत्पाद दायित्व” पर सत्र आयोजित किया गया।
 - दिनांक 30 सितंबर, 2020 को प्रो. सुरेश मिश्रा ने राज्यसभा टीवी पर देश देशांतरः एफएसएसएआई के नए नियम और उपभोक्ता पर पैनल चर्चा में भाग लिया।
 - दिनांक 17 अक्टूबर, 2020 को आयोजित उपभोक्ता वकालत समूह द्वारा सदस्यों के लिए ऑनलाइन अधिविन्यास कार्यक्रम के लिए प्रो. सुरेश मिश्रा और सपना चड्डा वक्ता ने अध्यक्षता की।
 - दिनांक 2 नवंबर, 2020 को डॉ. सपना चड्डा ने कॉन्स्टीट्यूशनल क्लब, जीजीएसआईपी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित वाद-विवाद प्रतियोगिता “ह्यूमन इंज रिस्पॉन्सिबिल फॉर डिजिटल क्राइम इटसैल्फ” में जज की भूमिका निभायी।
 - दिनांक 20 नवंबर, 2020 को प्रो. सुरेश मिश्रा उपभोक्ता कानून, वकालत और अनुसंधान केंद्र, बीएमएस कॉलेज ऑफ लॉ एंड कंज्यूमर राइट्स, एजुकेशन और जागरूकता ट्रस्ट (सीआरईएटी) में आयोजित “कोविड-19 महामारी के दौरान उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण” पर एक दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के बहु-विषयक सम्मेलन में सत्र का आयोजन किया गया।
 - दिनांक 21 नवंबर, 2020 को प्रोफेसर सुरेश मिश्रा कानूनी इंटर्न और उपभोक्ता समन्वय परिषद द्वारा आयोजित “नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम” पर वेबिनार में अतिथि वक्ता रहे।
- 11. एनसीएच के माध्यम से एकीकृत उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली**
- केंद्र भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा स्थापित शिकायत निवारण तंत्र राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) का प्रबंधन भी करता है ताकि उपभोक्ताओं को उनके उपभोक्ता संबंधी मुद्दों के निवारण के लिए शिक्षित किया जा सके और उनकी शिकायतों को हल करने के प्रयास किए जा सकें। एनसीएच में उपभोक्ता शिकायतों के समाधान के लिए इस वैकल्पिक निवारण तंत्र को ‘अभिसरण’ के रूप में ब्रॉडेड किया गया है और यह पूर्व-मुकदमेबाजी स्तर पर उपभोक्ता शिकायतों को हल करने के लिए एक सफल मॉडल साबित हुआ है। जनवरी 2019 में, सीसीएस, भा. लो.प्र.सं. द्वारा प्रबंधित स्टेट कंज्यूमर हेल्पलाइन नॉलेज रिसोर्स मैनेजमेंट पोर्टल (एससीएचकेआरएमपी) को एनसीएच के साथ एकीकृत किया गया था और अब इस परियोजना का शीर्षक एनसीएच के माध्यम से एकीकृत उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली’ है।

सेंटर फॉर कंज्यूमर स्टडी

आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची (अप्रैल 2020 से मार्च 2021)

क्रमांक	कार्यक्रम	अवधि	पाठ्यक्रम समन्वयक	स्थल	प्रतिभागियों की सूची
1.	कोविड-19 मीडिया और उपभोक्ता सशक्तिकरण, उपभोक्ता अध्ययन केंद्र, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), नई दिल्ली पर वेबिनार	07 जुलाई, 2020	ममता पठानिया	आईआईपीए, नई दिल्ली	130
2.	“ई-कॉमर्स: लचीलापन रणनीतियों में नए सामान्य” भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, “आईआईपीए”, नई दिल्ली पर वेबिनार	04 अगस्त, वर्ष 2020	सपना चड्ढा		308
3.	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, (आईआईपीए) नई दिल्ली में आयोजित “लोक सेवा वितरण प्रणाली में आरटीआई अधिनियम की भूमिका, पर वेबिनार।	01 अक्टूबर, 2020	सपना चड्ढा	आईआईपीए, नई दिल्ली	153
4.	महाराष्ट्र के सेंटर विलफ्रेड कॉलेज ऑफ लॉ, पनवेल, महाराष्ट्र के सहयोग से छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय, पनवेल, नवी मुंबई और सेंटर फॉर कंज्यूमर स्टडीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, (आईआईपीए), नई दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित “उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019- ए गेम चेंजर” पर वेबिनार।	20 अक्टूबर, 2020	सपना चड्ढा	आईआईपीए, नई दिल्ली	173
5.	भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा प्रायोजित वाणिज्य विभाग, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज एंड लैंग्वेजेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वेल्लोर और सेंटर फॉर कंज्यूमर स्टडीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ‘कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट’ -ए गेम चेंजर पर वेबिनार।	22 अक्टूबर, 2020	सपना चड्ढा	आईआईपीए, नई दिल्ली	570

6.	कुशल शासन और प्रशासन (एसईईए), जयपुर, राजस्थान उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित, सेंटर फॉर कंज्यूमर स्टडीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, (आईआईपीए), नई दिल्ली और सोसाइटी फॉर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित “कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट” पर बेबिनार।	28 अक्टूबर, 2020	ममता पठानिया	आईआईपीए, नई दिल्ली	531
7.	भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा प्रायोजित उपभोक्ता अध्ययन केंद्र, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा आयोजित “उपभोक्ता संरक्षण और कल्याण” पर पर जोनल उपभोक्ता हेल्पलाइन के समन्वयकों और परामर्शदाताओं के लिए 5वां जेडसीएच ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम।	नवंबर 02-06, 2020	ममता पठानिया	आईआईपीए, नई दिल्ली	31
8.	भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा प्रायोजित सेंटर फॉर कंज्यूमर स्टडीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली द्वारा आयोजित एनजीओ/ वीसीओ के प्रमुखों के लिए “उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019” पर 18वां ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम।	नवंबर 4-6, 2020	सुरेश मिश्रा ममता पठानिया	आईआईपीए, नई दिल्ली	39
9.	संकाय सदस्यों/प्रशिक्षकों के लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित सेंटर फॉर कंज्यूमर स्टडीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली द्वारा आयोजित “उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019” पर प्रशिक्षकों का 26वां ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम।	नवंबर 9-11, 2020	सुरेश मिश्रा ममता पठानिया	आईआईपीए, नई दिल्ली	34

10.	डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित सेंटर फॉर कंज्यूमर स्टडीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली और महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित “कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019- ए गेम चेंजर” पर बेबिनार।	नवंबर 17, 2020	सपना चड्डा	आईआईपीए, नई दिल्ली	249
11.	डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित सेंटर फॉर कंज्यूमर स्टडीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (आईआईपीए), नई दिल्ली और इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल (आईक्यूएसी) और जेएस लॉ कॉलेज (स्वायत्त), मैसूर, कर्नाटक द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित “उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 - ए गेम चेंजर” पर बेबिनार।	नवंबर 18, 2020	सपना चड्डा	आईआईपीए, नई दिल्ली	682
12.	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा “ऐथिक्स एंड गवर्नेंस” पर प्रथम स्वर्गीय डॉ यू. सी. अग्रवाल मेमोरियल व्याख्यान	नवंबर 19, 2020	सुरो मिश्रा	आईआईपीए, नई दिल्ली	55
13.	डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित सेंटर फॉर कंज्यूमर स्टडीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (आईआईपीए), नई दिल्ली द्वारा आयोजित “कंज्यूमर अवेयरनेस” पर ऑनलाइन राष्ट्रीय पोस्टर प्रतियोगिता।	नवंबर 22, 2020	ममता पठानिया	आईआईपीए, नई दिल्ली	241

14.	डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित उपभोक्ता अध्ययन केंद्र, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), नई दिल्ली द्वारा आयोजित जिला आयोगों के अध्यक्षों/सदस्यों के लिए “कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019” पर 110 वां ऑनलाइन उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम।	नवंबर 23-25, 2020	सुरेश मिश्रा ममता पठानिया	आईआईपीए, नई दिल्ली	130
15.	डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित सेंटर फॉर कंज्यूमर स्टडीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (आईआईपीए), नई दिल्ली द्वारा आयोजित राज्य सरकारों के अधिकारियों/अधिकारिक कर्मचारियों के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 और नियमों पर दो दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला।	नवंबर 26-27, 2020	सुरेश मिश्रा ममता पठानिया	आईआईपीए, नई दिल्ली	66
16.	डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित सेंटर फॉर कंज्यूमर स्टडीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली (आईआईपीए), और केआईईटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित “उपभोक्ता संरक्षण और सशक्तिकरण” पर वेबिनार।	दिसम्बर, 2 2020	ममता पठानिया	आईआईपीए, नई दिल्ली	358
17.	डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित उपभोक्ता अध्ययन केंद्र, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित जिला स्तरीय अधिकारियों/खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधिकारियों के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 पर दो दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया।	दिसम्बर, 3-4 2020	सपना चड्डा	आईआईपीए, नई दिल्ली	65

18.	डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित उपभोक्ता अध्ययन केंद्र, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित जिला स्तरीय अधिकारियों/खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधिकारियों के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 पर दो दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया।	दिसम्बर, 7-8 2020	सपना चड्डा	आईआईपीए, नई दिल्ली	68
19.	डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सेंटर फॉर कंज्यूमर स्टडीज, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा आयोजित खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों/अधिकारियों के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 पर दो दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला।	दिसम्बर, 10-11 2020	सपना चड्डा	आईआईपीए, नई दिल्ली	68
20.	डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित सेंटर फॉर कंज्यूमर स्टडीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (आईआईपीए), नई दिल्ली द्वारा आयोजित निबंध प्रतियोगिता – 2020 का आयोजन।	दिसम्बर, 20 2020	ममता पठानिया	आईआईपीए, नई दिल्ली	23
21.	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (आईआईपीए) द्वारा आयोजित सीपीसीबी में सीपीआईओ के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम पर एक दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम।	दिसम्बर, 21 , 2020	सपना चड्डा	आईआईपीए, नई दिल्ली	38

22.	भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा प्रायोजित सेंटर फॉर कंज्यूमर स्टडीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2020 आयोजित किया गया, विषय: “उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की नई विशेषताएं”।	दिसम्बर, 24 2020	सपना चड्डा ममता पठानिया	आईआईपीए, नई दिल्ली	986
23.	डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित सेंटर फॉर कंज्यूमर स्टडीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (आईआईपीए), न्यू दिल्ली एंड जेवियर लॉ स्कूल, सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी, कोलकाता द्वारा संयुक्त रूप से “उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 उपभोक्ता और व्यवसाय का तालमेल” पर वेबिनार का आयोजन किया गया।	23 जनवरी, 2021	सपना चड्डा	आईआईपीए, नई दिल्ली	407
24.	डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित सेंटर फॉर कंज्यूमर स्टडीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली द्वारा नॉर्थ जोन स्टेट्स ऑफ एनसीडीआरसी और स्टेट कमीशन आॅन “कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 वर्चुअल क्षेत्रीय सम्मेलन : वे फॉरवर्ड का आयोजन किया गया।	27 जनवरी, 2021	सपना चड्डा	आईआईपीए, नई दिल्ली	20
25.	सेंटर फॉर कंज्यूमर स्टडीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली द्वारा “राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: सशक्तिकरण छात्र” पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया।	28 जनवरी, 2021	ममता पठानिया	आईआईपीए, नई दिल्ली	192

26.	डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित सेंटर फॉर कंज्यूमर स्टडीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली द्वारा ईस्ट जोन स्टेट्स ऑफ एनसीडीआरसी और स्टेट कमीशन ऑन “कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 वर्चुअल क्षेत्रीय सम्मेलन : वे फॉरवर्ड का आयोजन किया गया।	29 जनवरी, 2021	सपना चड्डा	आईआईपीए, नई दिल्ली	14
27.	डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता अध्ययन केंद्र, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के सहयोग से “पेक्यूनियरी ज्यूरिस्टिक्शन ऑफ कंज्यूमर कमीशन” पर ऑनलाइन स्टेकहाल्डर्स कंसल्टेशन का आयोजन किया गया।	01 फरवरी, 2021	सपना चड्डा	आईआईपीए, नई दिल्ली	112
28.	डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित सेंटर फॉर कंज्यूमर स्टडीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली द्वारा सेंट्रल जोन स्टेट्स ऑफ एनसीडीआरसी और स्टेट कमीशन ऑन “कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 वर्चुअल क्षेत्रीय सम्मेलन : वे फॉरवर्ड का आयोजन किया गया।	03 फरवरी, 2021	सपना चड्डा	आईआईपीए, नई दिल्ली	26
29.	डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित सेंटर फॉर कंज्यूमर स्टडीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली द्वारा साउथ जोन स्टेट्स ऑफ एनसीडीआरसी और स्टेट कमीशन ऑन “कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 वर्चुअल क्षेत्रीय सम्मेलन : वे फॉरवर्ड का आयोजन किया गया।	8 फरवरी, 2021	सपना चड्डा	आईआईपीए, नई दिल्ली	17

30.	डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित सेंटर फॉर कंज्यूमर स्टडीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली द्वारा नाथ-इस्ट जोन स्टेट्स ऑफ एनसीडीआरसी और स्टेट कमीशन ऑन “कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 वर्चुअल क्षेत्रीय सम्मेलन : वे फॉरवर्ड का आयोजन किया गया।	9 फरवरी, 2021	सपना चड्डा	आईआईपीए, नई दिल्ली	13
31.	डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित सेंटर फॉर कंज्यूमर स्टडीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (आईआईपीए), नई दिल्ली द्वारा एनजीओ के प्रमुखों/ वीसीओ के प्रमुखों के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 पर प्रशिक्षकों का 19वां ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।	10-12 फरवरी, 2021	सपना चड्डा ममता पठानिया	आईआईपीए, नई दिल्ली	38
32.	डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित सेंटर फॉर कंज्यूमर स्टडीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (आईआईपीए), नई दिल्ली द्वारा जिला आयोगों के अध्यक्षों/सदस्यों के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 पर 111 वां ऑनलाइन उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।	22-24 फरवरी, 2021	सुरेश मिश्रा सपना चड्डा	आईआईपीए, नई दिल्ली	65
33.	डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित सेंटर फॉर कंज्यूमर स्टडीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (आईआईपीए), नई दिल्ली द्वारा “उपभोक्ता संरक्षण और कल्याण” पर जोनल उपभोक्ता हेल्पलाइन के समन्वयकों और काउंसलसर्स के लिए छठा जेडसीएच ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।	1-5 मार्च, 2021	ममता पठानिया दीपिका सुर	आईआईपीए, नई दिल्ली	39

34.	भारतीय डाक सेवा केंद्र, आईआईपीए, नई दिल्ली द्वारा रफी अहमद किंवद्वय राष्ट्रीय डाक अकादमी (आरएकेएनपीए), गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश डाक विभाग, सचार मंत्रालय, डाक विभाग के सहयोग से भारतीय डाक सेवा (आईपीओ) के परिवीक्षार्थियों के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पर तीन दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया (फेस टू फेस)।	3-5 मार्च, 2021	सुरेश मिश्रा ममता पठानिया	आईआईपीए, नई दिल्ली	14
35.	डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित सेंटर फॉर कंज्यूमर स्टडीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (आईआईपीए), नई दिल्ली द्वारा ऑनलाइन वेबिनार ऑन स्टेकहाल्डर्स कंसल्टेशन “इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर ई-मूल्य निर्धारण की शुरूआत” आयोजित किया गया।	10 मार्च, 2021	सुरेश मिश्रा सपना चड्डा	आईआईपीए, नई दिल्ली	63
36.	सेंटर फॉर कंज्यूमर स्टडीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (आईआईपीए), नई दिल्ली के सहयोग से डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, भारत सरकार द्वारा वर्चुअल विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 “विषय: ट्रेकिलंग प्लास्टिक पॉल्यूशन” आयोजित किया गया।	15 मार्च, 2021	सुरेश मिश्रा सपना चड्डा	आईआईपीए, नई दिल्ली	360
37.	डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित सेंटर फॉर कंज्यूमर स्टडीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (आईआईपीए), नई दिल्ली द्वारा जिला आयोगों के सदस्य अध्यक्षों के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 पर 112 वां ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।	22-24 मार्च, 2021	सुरेश मिश्रा सपना चड्डा	आईआईपीए, नई दिल्ली	70

38.	डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित सेंटर फॉर कंज्यूमर स्टडीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (आईआईपीए), नई दिल्ली और वेल टेक रंगराजन डॉ संगुथला आरएंडडी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चेन्नई द्वारा संयुक्त रूप से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 ए प्रतिमान “बदलाव” पर वेबिनार का आयोजन किया गया।	26 मार्च, 2021	सपना चड्ढा	आईआईपीए, नई दिल्ली	820
-----	--	----------------	------------	--------------------	-----

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए संसाधन व्यक्ति

क्रमांक	कार्यक्रम	अवधि
1.	वाणिज्य विभाग, श्री दुर्गा मल्लेश्वर सिद्धार्थ महिला कलाशाला, कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित “कोविड- 19 न्यू चैलेंज एंड स्ट्रेटिजी इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन” पर एक दिवसीय राष्ट्रीय एफडीपी वेबिनार	04 जुलाई, 2020
2.	गांधीवादी शांति अध्ययन विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा “कोविड-19 टूर्वर्ड अ ससटेनेबल लाइफस्टाइल” पर वेबिनार।	5 जुलाई, 2020
3.	उपभोक्ता वकालत समूह, ए पी द्वारा आयोजित उपभोक्ता और बिजली पर ऑनलाइन चर्चा।	16 जुलाई, 2020
4.	जीजे आडवाणी कॉलेज, मुंबई, महाराष्ट्र द्वारा आयोजित “कोविड - 19 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019” पर वेबिनार।	08 अगस्त, 2020
5.	स्वर्णधा ग्रुप ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेज, ए पी द्वारा आयोजित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 पर ऑनलाइन वेबिनार	6 सितंबर, 2020
6.	श्री प्रसन्ना कॉलेज ऑफ लॉ, कोथापेटा कुरनूल, आंध्र प्रदेश द्वारा आयोजित “द न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ” पर वेबिनार।	10 सितंबर, 2020
7.	उपभोक्ता वकालत समूह, ए पी द्वारा सदस्यों के लिए ऑनलाइन ओरिएंटेशन कार्यक्रम	17 अक्टूबर, 2020
8.	बी.एम.एस. कॉलेज ऑफ लॉ, कंज्यूमर लॉ, एडवोकेसी एंड रिसर्च सेंटर (सीएलएआरसी, बीएमएससीएल) और उपभोक्ता अधिकार, शिक्षा और जागरूकता ट्रस्ट (सृजन) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित सीओवीडी-19 महामारी के दौरान उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण “पर एक दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का बहुविषयक सम्मेलन (निर्माण)	20 नवंबर, 2020
9.	कानूनी इंटर्न और उपभोक्ता समन्वय परिषद द्वारा आयोजित “नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम” पर वेबिनार।	21 नवंबर, 2020

अनुसूची च.11

2020-21 के दौरान संकाय सदस्यों को दिए जाने वाले मानदेय और वेतन का विवरण

क्र.सं.	नाम	वेतन	मानदेय	योग
1.	प्रो. सुरेश मिश्रा	3078590	0	3078590
2.	प्रो. के.के. पाण्डेय	2756156	88928	2845084
3.	प्रो. वी.के. शर्मा	2088512	154167	2242679
4.	डॉ. वी.एन. आलोक	2484144	0	2484144
5.	डॉ. चारू मल्होत्रा	2245788	0	2245788
6.	डॉ. सचिन चौधरी	2707188	104400	2811588
7.	डॉ. कुमुम लता	2414880	15472	2430352
8.	डॉ. सी. शीला रेड्डी	2073533	0	2073533
9.	डॉ. नीतू जैन	2680188	0	2680188
10.	डॉ. रोमा देबनाथ	2624304	0	2624304
11.	डॉ. सपना चड्ढा	1795344	262773	2058117
12.	डॉ. ममता पठानिया	1548804	0	1548804
13.	डॉ. गदाधर मोहपात्रा	1564104	0	1564104
14.	डॉ. पवन कुमार तनेजा	1220628	88928	1309556
15.	डॉ. मनन द्विवेदी	1605840	0	1605840
16.	डॉ. साकेत बिहारी	2211480	0	2211480
17.	डॉ. नुपुर तिवारी	2606304	0	2606304
18.	डॉ. श्यामली सिंह	1500654	0	1500654
19.	डॉ. सुरभि पाण्डेय	1148142	0	1148142
20.	डॉ. अमित कुमार सिंह	960000	127189	1087189
21.	डॉ. गीतांजलि नटराज	548333	0	548333
22.	डॉ. अशोक कुमार विशनदास	2100000	0	2100000
23.	डॉ. गोविंद भट्टाचार्जी	630000	0	630000
	योग	44592916	841857	45434773

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के सदस्यों के लिए योग्य सुझाव

हमने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) के वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च 2021 को बैलेंस शीट, और समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते का विवरण, प्राप्तियां और भुगतान शामिल हैं, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश भी शामिल है।

हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के योग्य सुझाव के लिए आधार खंड में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त वित्तीय विवरण यह जानकारी देते हैं कि साथ में वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2021 को संस्थान की वित्तीय स्थिति का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, और वर्ष के लिए आय एवं व्यय और प्राप्ति एवं भुगतान का विवरण संस्थान के भारतीय चार्टर्ड एकाउटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार समाप्त होता है।

योग्य सुझाव के आधार

हमने अपना ऑडिट आईसीएआई द्वारा जारी किए गए ऑडिटिंग पर मानकों (एसए) के अनुसार किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार इकाई से स्वतंत्र हैं और हमने आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

हम रिपोर्ट करते हैं कि,

क. सेवा कर

आईआईपीए एक शिक्षा संस्थान होने के नाते सरकार से सेवा कर में छूट का अनुरोध करता रहा है। हालांकि, दिनांक 1 अप्रैल 2016, किसी भी प्रतिक्रिया के अभाव में आईआईपीए ने सेवा कर लागू कर दिया है। जैसा कि हमें बताया गया है, दिनांक 1 अप्रैल 2016 से पहले सेवा कर के अनुपालन पर प्रतिक्रिया मिलने के बाद ध्यान दिया जाएगा। 01-04-2016 से पहले सेवा कर की प्रयोज्यता के संबंध में विशेषज्ञ की राय ली जानी चाहिए।

ख. माल और सेवा कर

विशेष रूप से सेवा के प्रावधान के खिलाफ समायोज्य इनपुट क्रेडिट पर जीएसटी मामलों की समीक्षा करने की आवश्यकता है। यदि कोई हो, हम इसके प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

ग. स्रोत पर कर कटौती

आईआईपीए ने उपार्जन के आधार पर स्रोत पर कर (टीडीएस) का हिसाब नहीं दिया है। यह देखा गया कि 32,537 रुपये के देय खर्चों पर स्रोत पर कर (टीडीएस) की देनदारी नहीं बढ़ाई गई है। जैसा कि हमें बताया गया है, स्रोत पर कर (टीडीएस) की देनदारी खर्चों के भुगतान के समय तय की जाएगी।

घ. वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे उपयोगिता प्रमाण पत्र परियोजना प्रमुखों द्वारा अनुमोदित बयानों पर आधारित हैं।

आगे ध्यान आकर्षित किया जाता है

- “अनुपयोगी अनुदान शेष” जिसमें 2019-20 तक 238.05 लाख की प्राप्त अनुदान राशि शामिल है। इनमें से कुछ बकाया लंबी अवधि से बकाया है। इसे जल्द से जल्द ठीक करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

वर्ष	राशि (लाख में)
2014-15 तक	37.76
वर्ष 2017-18 के लिए	85.06
वर्ष 2018-19 के लिए	70.16
वर्ष 2019-20 के लिए	45.07
कुल	238.05

- वर्तमान दायित्व में 264.68 लाख की राशि शामिल है, जो प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अग्रिम के रूप में प्राप्त हुई थी, लेकिन अब तक इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित नहीं किए जाने के कारण इसे आय के रूप में शामिल नहीं किया गया था।
- वर्तमान देनदारी में 85.70 लाख रुपये की राशि शामिल है जो प्रशिक्षण कार्यक्रमों और परियोजनाओं से प्राप्त होती है लेकिन जानकारी के अभाव के कारण अब तक आय के रूप में दर्ज नहीं की गई है। हमारी राय में, इसे जल्द से जल्द समाधान करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- वर्तमान संपत्ति में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बदले ₹234.22 लाख की प्राप्य राशि शामिल है। इसे जल्द से जल्द ठीक करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

वर्ष	राशि (लाख में)
2012-13 तक	32.65
वर्ष 2017-18 के लिए	121.16
वर्ष 2018-19 के लिए	73.54
वर्ष 2020-21 के लिए	6.87
कुल	234.22

- मौजूदा संपत्ति में “मैसर्स ट्रैवियनस्पायर ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड” से 65.98 लाख रुपये की प्राप्य राशि शामिल है। इस राशि का भुगतान 45वां अप्पा विदेश यात्रा के लिए किया गया था, जो कोविड-19 महामारी के कारण रद्द हो गई थी, इसे जांचने और समायोजित करने की आवश्यकता है।
- ऋण और अग्रिम में नौ सदस्यों से प्राप्त 11.39 लाख रुपये शामिल हैं। इनमें से तीन सदस्य पहले ही संगठन छोड़ चुके हैं।

एनआईडीएम से प्राप्य किराया (20 प्रतिशत)

- पिछले चार साल से 2.17 करोड़ का बकाया है। इसे जल्द से जल्द ठीक करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अचल संपत्ति रजिस्टर जीएफआर प्रावधानों के अनुसार हैं। इन्हें नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए।

अनुदान से अर्जित अचल संपत्तियों का लेखांकन उपचार

वर्तमान में, अनुदान से प्राप्त अचल संपत्तियों को परिसंपत्ति निधि में संबंधित क्रेडिट के साथ पूंजीकृत किया जाता है। हमारी राय में, अनुदान से अर्जित संपत्ति का मूल्य संपत्ति की सकल लागत से घटाया जाना चाहिए। तथापि, परिसम्पत्तियों के निष्कर्षों की अंतिम समीक्षा लंबित होने तक प्रबंधन द्वारा उसके किसी प्रभाव पर विचार नहीं किया गया है।

- 121.99 करोड़ रुपये तक की भारी दीर्घकालिक देयता (जिसमें सेवानिवृत्ति लाभ जैसे पेंशन, ग्रेचुटी आदि शामिल हैं) है। यह भारी दायित्व और बड़ी देनदारी चिंता करने का कारण है और आईआईपीए को इस मुद्दे के समाधान के तरीकों और साधनों पर गौर करना चाहिए।

प्रबंधन की जिम्मेदारियां और वित्तीय विवरणों के लिए शासन के साथ आरोप लगाने वाले, इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं जो आम तौर पर भारत में स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार इकाई की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और उचित दृष्टिकोण देते हैं। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो एक सच्चे और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और सामग्री के गलत बयान से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन संस्था की एक चालू संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो इकाई को समाप्त करने या समाप्त करने का इरादा नहीं रखता है, तब तक चल रहे चिंता से संबंधित मामलों का खुलासा करना और लेखांकन के आधार पर चलने वाली चिंता के आधार का उपयोग करना है। संचालन, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

जिन लोगों पर शासन का आरोप लगाया जाता है, वे इकाई की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार होते हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार आयोजित एक ऑफिट हमेशा एक महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकता पर रिपोर्ट

हम रिपोर्ट करते हैं कि:

1. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।
2. हमारी राय में, संस्थान द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकों को रखा गया है, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा से प्रतीत होता है।

जीएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी

चर्टरित लेखापाल

एफआरएन नंबर 00257एन/एन500339

सुनील अग्रवाल

भागीदार

एम. नंबर 083899

16, डीडीए फ्लैट्स, पंचशील पार्क,

मालवीय नगर के पास, नई दिल्ली-110017

स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 27/09/2021

यूटीआईएन संख्या: 21083899एएएडीएम7638

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

31 मार्च 2021 का तुलन-पत्र

	अनसूची	31.03.2021	31.03.2020
		को	को
		(₹)	(₹)
वेयताएँ			
परिसंपत्ति निधि	1	16,57,11,358	13,73,39,594
परिसंपत्ति निधि एफसीआरए	1	8,42,449	8,42,449
संचित अधिशेष/(घाटा)		(1,22,83,55,901)	(1,09,86,80,751)
सदस्यता निधि सहित पूँजीगत निधि	2	8,81,44,882	7,58,23,389
अप्रयुक्त अनुदान:	3	22,58,83,044	12,94,28,504
- सामान्य निधि	<u>22,41,61,280</u>	-	-
- विदेशी निधि	<u>17,21,764</u>	-	-
प्रावधान:			
- देय ग्रेच्युटी		6,84,00,000	6,34,00,000
- छुटी नकदीकरण देय		6,16,00,000	6,35,00,000
- पेशन देय		1,21,99,00,000	1,09,24,36,418
वर्तमान देनदारियां	4	6,10,47,927	6,04,11,931
	योग	66,31,73,759	52,45,01,534
संपत्तियां			
स्थायी परिसंपत्ति निधि- अनुदान से बाहर (सकल)	5	16,57,11,358	13,73,39,594
फिक्स्ड एसेट फंड-स्वयं के फंड	5	45,71,619	48,41,693
एसेट फंड एफसीआरए	5	8,42,449	8,42,449
निवेश	6	24,27,76,054	7,13,13,293
प्राप्य अनुदान	3	4,28,20,623	2,77,97,040
वर्तमान संपत्ति	7	20,64,51,656	28,23,67,465
	योग	66,31,73,759	52,45,01,534
खातों में महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ और टिप्पिण्याँ	13		
हमारी रिपोर्ट के अनुसार भी तिथि, अनुसूचियां 1			
से 13 तक खातों का एक अभिन्न अंग है।			
कृते जी.एस.ए. तथा सहयोगी एल.एल.पी.			
चर्चित लेखापाल			
एफ.आर.एन. 000257एन/एन500339			

कार्यकारी परिषद्

सुनील अग्रवाल	एस.एन. त्रिपाठी महानिदेशक	के.के. पांडे	अमिताभ रंजन कुल सचिव
भागीदार	(सदस्य सचिव)	सदस्य-ईसी	(मुख्य लेखा अधिकारी)

मो.नं. 083899

नई दिल्ली

दिनांक : 27.09. 2021

यू.डी.आई.एन.सं. : 21083899एएएडीएम7638

वार्षिक रिपोर्ट

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा

	अनसूची	वर्ष 2020-21		वर्ष 2019-20	
		हेतु (₹)	हेतु (₹)	हेतु (₹)	हेतु (₹)
आय					
डीओपीटी से सहायता अनुदान- वेतन		9,50,00,000		8,50,00,000	
डीओपीटी से सहायता अनुदान- सामान्य		8,00,00,000		6,00,00,000	
सदस्य सदस्यता	8	8,78,681		10,24,410	
प्रकाशनों की बिक्री		25,305		3,48,570	
ओवरहेड शुल्क सहित अनुसंधान कार्यक्रमों से शुद्ध आय		2,11,60,972		1,92,69,117	
प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए शुल्क		1,83,06,694		20,79,10,199	
अन्य आय:					
-उपयोगकर्ता शुल्क		46,91,725		1,32,40,498	
-विविध रसोई	9	52,96,806		67,26,607	
प्रशिक्षण कार्यक्रम शुल्क प्राप्त		6,87,000		69,94,747	
प्रयोक्ता प्रभार प्राप्त		-		96,182	
	कुल			22,60,47,183	40,06,10,330
व्यय					
वेतन और भत्ते	10	9,87,66,592		9,97,11,655	
परिसर रखरखाव	11	2,36,92,282		2,90,65,653	
प्रशासनिक और अन्य व्यय	12	57,39,367		56,72,573	
पुस्तकालय आवधि और बाध्यकारी शुल्क		4,49,308		5,18,609	
प्रशिक्षण कार्यक्रम		1,04,89,806		19,47,55,196	
प्रकाशनों		6,40,809		5,42,862	
शाखा संवर्धन गतिविधियाँ		1,18,565		4,75,904	
एएमटी सीजीएचएस को भुगतान किया गया		15,98,272		10,94,647	
मूल्यद्वास	5	8,34,775		6,56,606	
पेंशन		7,00,80,311		6,00,00,000	
जीएसटी/प्रीमियम व्यय		1,59,822		82,34,467	
आईआईपीए रिजर्व फंड में ट्रांसफर की गई राशि		21,11,574		-	
रिसर्च एंडोमेंट फंड में ट्रांसफर की गई राशि		2,34,252		-	
दीर्घकालिक सेवानिवृत्ति देयता					
उपहार	10	99,64,714		65,04,960	
नकदीकरण छोड़ें	10	33,78,301		61,63,714	
पेंशन व्यय	10	12,74,63,582		10,82,97,659	
		35,57,22,332		52,16,94,505	
वर्ष के लिए आय से अधिक व्यय		(12,96,75,150)		(12,10,84,174)	
पिछले वर्ष की आय से अधिक व्यय		(1,09,86,80,751)		(97,75,96,577)	
		(1,22,83,55,901)		(1,09,86,80,751)	
अधिशेष तुलन पत्र में अग्रेनीत #	13				
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ तथा टिप्पणियाँ					

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष की प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा

अनसूची	वर्ष 2020-21 (₹)	वर्ष 2019-20 (₹)
7	19,70,20,157	15,62,21,265
ए	33,03,60,182	42,85,76,902
बी	22,01,62,295	17,13,44,953
3	18,24,35,417	25,70,38,301
	92,99,78,051	1,01,31,81,421
बी	39,61,95,149	20,12,26,117
3	15,05,65,875	18,27,20,495
7	5,30,41,651	19,70,20,157
	92,99,78,050	1,01,31,81,421

अनुसूचियां ए से बी जाँच की गयी और सही पाया गया

प्राप्तियाँ और भुगतान का एक अभिन्न हिस्सा हैं।

कृते जीएसए और एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टरित लेखापाल

एफआरएन - 000257एन/एन500339

सनील अग्रवाल

भागीदार

मो.नं. 083899

स्थानः नई दिल्ली

16ए डीडीए फ्लेट्स, पंचशील पार्क, नियर

मालवीय नगर

नई दिल्ली - 1100017

दिनांक 27-09-2021

यू.डी.आई.एन.सं. : 21083899एएएडीएम7638

कार्यकारी परिषद

के.के. पांडे

अमिताभ रंजन कल सचिव

सदस्य-कार्यकारी परिषद (मख्य लेखा अधिकारी)

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची-1
परिसंपत्ति राशि

	01.04.2020 को अधिशेष	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान समायोजन/ प्रयुक्त	31.03.2021 को अधिशेष
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
आई.आई.पी.ए. (कोर)	11,23,72,521	3,63,88,353	95,40,758	13,92,20,116
सी.यू.एस.	46,30,790	-	-	46,30,790
ए.पी.पी.ए. (अप्पा)	96,96,784	8,98,703	-	1,05,95,487
सी.सी.एस.	31,54,902	-	-	31,54,902
एन.सी.एच.	74,84,597	2,77,500	-	77,62,097
नमामि गंगे	-	3,47,966	-	3,47,966
उप योग	13,73,39,594	3,79,12,522	95,40,758	16,57,11,358
एफसीआरए	8,42,449	-	-	8,42,449
उप योग	8,42,449	-	-	8,42,449
कुल योग	13,81,82,043	3,79,12,522	95,40,758	16,65,53,807

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची-2 पूँजीगत राशि

	01.04.2020 को शेष	ब्याज	अंशदान	प्रयुक्त राशि	31.03.2021 को शेष
क	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
वार्षिक स्कूल पुरस्कार निधि	1,00,802	7,424	-	-	1,08,226
भूपेन्द्र हूजा स्मारक निधि	48,371	3,017	-	2,420	48,968
कंसल्टेंसी सपोर्ट फंड	14,11,662	1,78,861	-	-	15,90,523
आईआईपीए रिजर्व फंड	-	-	23,29,887	-	23,29,887
इंफास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड	4,75,14,756	41,33,364	-	92,690	5,15,55,430
नायदुमा मेमोरियल साइंस फाउंडेशन	11,18,650	42,400	-	7,765	11,53,285
प्रो एस सरोजा मेमोरियल फंड	5,46,739	32,500	-	5,499	5,73,740
रिसर्च एंडोमेंट फंड	45,10,000	3,84,016	2,34,252	14,802	51,13,466
श्रीमती कुसुम ताईशंकर राव चव्हाण मेमो. निधि	1,53,669	8,816	-	3,084	1,59,401
स्टाफ हितकारी कोष	4,99,977	63,617	-	6,000	5,57,594
टी.एन. चतुर्वेदी पुरस्कार	1,07,164	7,002	-	10,081	1,04,085
पीके उमाशंकर मेमोरियल फंड	-	1,23,600	12,50,000	1,41,020	12,32,580
यू.सी. अग्रवाल मेमोरियल फंड	-	59,761	25,00,000	2,40,623	23,19,138
उप योग	5,60,11,790	50,44,378	63,14,139	5,23,984	6,68,46,323
ख					
(सदस्यता पूँजी कोष)					
कॉर्पोरेट सदस्यता पूँजी कोष	38,09,105	2,58,751	-	1,40,063	39,27,793
आजीवन सदस्यता पूँजी कोष	1,60,02,494	10,89,003	14,20,000	11,40,731	1,73,70,766
उप योग	1,98,11,599	13,47,754	14,20,000	12,80,794	2,12,98,559
कुल योग	7,58,23,389	63,92,132	77,34,139	18,04,778	8,81,44,882

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची-3

अप्रयुक्त अनुदान शेष

अप्रयुक्त शेष 01.04.2020	वर्ष के दौरान प्राप्त	कुल (₹)	भुगतान समायोजित (₹)	देय/वर्ष के लिए दिया गया अग्रिम (₹)	अप्रयुक्त शेष 31.03.2021 (₹)	
					अप्रयुक्त शेष	देय/वर्ष के अप्रयुक्त शेष
					ग्राहक	देय/वर्ष के अप्रयुक्त शेष
(क) सामान्य निधि						
हाऊसिंग और शहरी मामलों (1,09,96,325)	3,34,39,342	2,24,43,017	2,42,25,783	15,82,853	(33,65,619)	
के मंत्रालय से अनुदान, शहरी अध्ययन के लिए केंद्र के लिए (रुपये की आंतरिक प्राप्त सहित-) (अनुनाद अनुबंध-2)						
अनुदान-सहायता पूँजी	-	10,50,00,000	10,50,00,000	4,83,00,000	5,67,00,000	-
एपोपीए	3,97,01,493	2,18,25,360	6,15,26,853	55,89,841	-	5,59,37,012
उपभोक्ता मामलों के लिए केंद्र	21,22,124	-	21,22,124	-		21,22,124
सीसीएस चरण द्वितीय (सहित प्रकाशन)	1,17,38,347	-	1,17,38,347	2,36,69,829	6,83,909	(1,26,15,391)
उपभोक्ता केंद्र मामले (योजना)	11,67,393	-	11,67,393	-	-	11,67,393
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन	66,593	-	66,593	-	-	66,593
आईसीजीआर-एनसीएच परियोजना	59,52,762	4,00,00,000	4,59,52,762	3,88,83,022	37,46,166	33,23,574
जनजातीय मामलों का केंद्र (कॉर्टेक्स)	7,34,749	-	7,34,749	35,18,532	2,53,995	(30,37,778)
अप्पा के लिए अन्य अनुदान विदेश/क्षेत्र का दौरा	2,26,27,809	1,47,93,848	3,74,21,657	28,45,159	-	3,45,76,498
अन्य कार्यक्रम	(35,05,814)	38,24,000	3,18,187	47,43,630	2,69,167	(46,94,611)
फैलोशिप के लिए आईसीएसएसआर से अनुदान	1,75,345	-	1,75,345	96,667	-	78,678
अन्य शोध परियोजनाएं	27847943	6,84,95,038	9,63,42,981	4,51,43,201	5,92,809	5,06,06,971
रिसर्च-1 प्रोजेक्ट्स	4,75,213	-	4,75,213	-	-	4,75,213
योग क:	9,81,07,632	28,73,77,588	38,54,85,220	19,70,15,664	6,38,28,899	12,46,40,657
जोड़ें: डेबिट बैलेंस यानी अनुदान प्राप्त:	2,77,97,040	-	-	-	-	-
31.03.2021 तक अनुपयोगी अनुदान शेष:	12,59,04,672	28,73,77,588	38,54,85,220	19,70,15,664	6,38,28,899	16,74,61,280
(ख) विदेशी अनुदान	35,14,146	57,829	35,71,975	18,50,211	-	17,21,764
कुल योग क+ख	12,94,18,818	28,74,35,417	38,90,57,195	19,88,65,875	6,38,28,899	16,91,83,044

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची-4

चालू देयताएँ

	31.03.2021	31.03.2020
	को	को
कैंटीन ठेकेदार/मेस शुल्क	3,27,515	5,39,586
एस/स्टाफ और फैकल्टी को देय एएमटी	2,01,302	1,51,482
विविध लेनदार	8,80,529	4,49,624
अन्य देनदारियाँ:		
अन्य देय	3,66,88,078	3,47,58,511
अन्य जमा	25,14,656	25,90,909
देय खर्च	1,58,45,085	1,59,40,705
शुल्क और कर (जीएसटी)	45,90,763	59,81,114
योग	6,10,47,928	6,04,11,931

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची-5 स्थायी परिसंपत्तियाँ

	1.4.2020 लागत (₹)	परिवर्धन (-बिक्री) (₹)	मूल्य हास (₹)	31.3.2021 लागत (₹)
क) अनुदान से खरीदी गई अचल संपत्तियां				
भूमि एवं भवन	1,12,09,007	3,10,70,417	-	4,22,79,424
फर्नीचर, फिक्स्चर	2,11,72,398	3,70,896	19,31,082	-
रेफ्रीजरेटर उपकरण और वाटर कूलर	57,18,884	-	15,14,467	-
फिल्म प्रोजेक्टर और स्टेज उपकरण	54,72,412	-	5,27,018	-
डेटा प्रोसेसिंग उपकरण	1,90,76,075	46,65,256	36,81,005	-
हॉस्टल और मेस उपकरण	29,96,127	-	5,02,456	-
कार्यालय उपकरण	1,94,84,032	1,99,000	13,84,731	-
आंतरिक संचार	19,75,935	-	-	-
पुस्तकालय उपकरण	26,85,529	-	-	-
लाइब्रेरी बुक (कारो)	2,25,82,122	82,784	-	-
	11,23,72,521	3,63,88,353	95,40,759	- 13,92,20,116
सीयूएस-फर्नीचर, फिक्चर और कार्यालय उपकरण	30,07,287	-	-	-
सीयूएस- लाइब्रेरी बुक्स	16,23,503	-	-	-
	46,30,790	-	-	- 46,30,790
अप्पा - पुस्तकालय पुस्तकें	46,41,278	-	-	-
अप्पा-फर्नीचर, फिक्चर और कार्यालय उपकरण	50,55,506	8,98,703	-	-
	96,96,784	8,98,703	-	- 1,05,95,487
सीसीएस-फर्नीचर, फिक्चर और कार्यालय उपकरण	17,44,265	-	-	-
सीसीएस- लाइब्रेरी बुक्स	2,99,501	-	-	-
एनसीएच-फर्नीचर, फिक्चर और कार्यालय उपकरण	85,95,733	2,77,500	-	-
उप-योग	1,06,39,499	2,77,500	-	- 1,09,16,999
नमामि गंगे-इंफास्ट्रक्चर/ऑफिस उपकरण	-	3,47,966	-	3,47,966
भूमि तथा भवन	13,73,39,594	3,79,12,522	95,40,759	- 16,57,11,358
	1.4.2020 लागत (₹)	परिवर्धन (-बिक्री) (₹)	मूल्य हास (₹)	31.3.2021 लागत (₹)
ख) स्थायी परिसंपत्तियाँ -स्वयं निधि				
फर्नीचर, फिक्स्चर, ए.सी. उपकरण आदि।	8,98,498	-	89,850	8,08,648
डेटा प्रोसेसिंग उपकरण	1,10,686	4,43,652	-	1,60,106
कार्यालय उपकरण	19,71,837	1,09,538	-	3,03,991
वाहन	18,72,183	-	2,80,827	15,91,355
योग	48,53,204	5,53,190	-	8,34,775
कुल योग (क+ख)	14,21,92,798	3,84,65,712	95,40,759	8,34,775
ग) स्थायी परिसंपत्तिया -एफसीआरए				
एफसीआरए-फर्नीचर, फिक्स्चर, ए.सी. उपकरण	8,42,449	-	-	8,42,449
योग	8,42,449	-	-	8,42,449
कुल योग	14,30,35,247	3,84,65,712	95,40,759	8,34,775
				17,11,25,426

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची-6

निवेश

	01.04.2020 को शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान नकदीकरण	31.03.2021 को शेष
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
वार्षिक स्कूल पुरस्कार कोष	95,918	44,450	42,667	97,701
भूपेंद्र हूजा मेमोरियल फंड	39,582	39,637	39,582	39,637
कंसल्टेंसी सपोर्ट फंड	15,06,680	12,79,421	11,58,102	16,27,999
निगमित सदस्यता पूँजी कोष	36,05,959	6,42,274	4,14,249	38,33,984
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड	4,58,59,015	2,58,78,030	2,06,66,474	5,10,70,571
जीवन पूँजी सदस्यता कोष	1,38,11,884	18,09,591	-	1,56,21,475
नायुदम्मा मेमोरियल साइंस फाउंडेशन	8,15,666	-	-	8,15,666
प्रो. एस. सरोजा मेमोरियल फंड	5,00,000	-	-	5,00,000
अनुसंधान बंदोबस्ती निधि	44,54,585	18,14,798	14,23,320	48,46,063
श्रीमती कुसुम ताई चब्हाण स्मृति कोष	1,41,046	-	-	1,41,046
कर्मचारी हितैषी कोष	3,88,897	2,02,720	1,80,827	4,10,790
टी.एन. चतुर्वेदी पुरस्कार कोष	94,061	24,417	23,064	95,414
पी.के. उमाशंकर मेमोरियल फंड	-	11,08,980	-	11,08,980
यू.सी. अग्रवाल मेमोरियल फंड	-	22,75,000	-	22,75,000
यूको के साथ एफडीआर	-	26,02,91,728	10,00,00,000	16,02,91,728
योग	7,13,13,293	29,54,11,046	12,39,48,285	24,27,76,054

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची-7

वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम

	31.03.2021	31.03.2020
	को (₹)	को (₹)
विविध देनदार		
आयोजित टीपी से प्राप्य राशि	2,34,22,378	3,16,20,336
जीएसटी प्राप्य	-	17,312
अनुसंधान/प्रशिक्षण के लिए ईमडी	53,92,200	30,28,500
उप-योग	2,88,14,578	3,46,66,148
अन्य परिसंपत्तियां		
टीडीएस प्राप्य	1,31,26,618	1,11,55,314
जीएसटी पर टीडीएस	3,18,214	3,48,357
कर्मचारियों/विक्रेताओं को ऋण और अग्रिम	5,88,50,725	1,38,01,814
जमा (डेसू, डीडीए आदि के साथ) और अन्य प्राप्य	6,42,210	6,42,210
एनआईडीएम से प्राप्य किराया (20 प्रतिशत)	2,17,37,800	2,17,37,800
अर्जित ब्याज अदेय सावधि जमा /बॉन्ड	16,34,146	13,59,761
एचबीए पर अर्जित ब्याज	74,191	6,70,215
प्राप्य किराया	2,37,870	2,37,870
पूर्वभुगतान बीमा	42,652	39,108
प्रीपेड खर्च (प्रीमियम)	9,99,275	6,84,000
जीएसटी संचय इनपुट/जीएसटी पर टीडीएस	-	3,48,357
अग्रिम कर	6,23,574	
प्राप्य राशि		
पेंशन निधि	99,19,689	-
सी.पी. निधि	97,85,000	-
अन्य	66,03,463	4,713
उप-योग	12,45,95,427	5,10,29,518
नकद और बैंक शेष (प्रबंधन द्वारा प्रमाणित)		
नकद रोकड़	4,917	-
अग्रदाय राजस्व स्टाम्प	200	200
उप-योग	5,117	200
अनुसूचित बैंकों के साथ शेष राशि		
यूको बैंक चालू खाते	14,51,326	12,75,751
यूको बैंक बचत खाता	3,89,93,342	17,20,17,818
भारतीय स्टेट बैंक	2,62,547	2,62,547
यूको बैंक - एफसीआरए - बचत खाता।	17,21,764	35,14,146
यूको बैंक पीएफएमएस खाता	4,43,501	2,99,163
यूको बैंक परियोजना खाता	15,72,163	22,01,657
यूको बैंक - उपभोक्ता पीएफएमएस खाता	85,43,218	1,61,98,804
यूको बैंक - सीयूएस पीएफएमएस खाता	48,673	12,50,071
उप-योग	5,30,36,534	19,70,19,957
योग	5,30,41,651	19,70,20,157
कुल योग	20,64,51,656	28,27,15,823

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची-8

सदस्यता अंशदान/सदस्यता निधि पर ब्याज

	वर्ष 2020-21 के लिए	वर्ष 2019-20 के लिए
	(₹)	(₹)
उप. - सहयोगी	90,228	71,107
उप. - निगमित	10,000	80,000
उप. - छात्र सदस्यता	5,200	800
उप. - साधारण	11,900	44,900
ब्याज पर :	-	-
कॉर्पोरेट सदस्यता पूँजी कोष	1,33,198	1,65,237
आजीवन सदस्यता पूँजी कोष	6,28,155	6,62,366
	योग	10,24,410
	8,78,681	

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची-9

विविध प्राप्तियाँ

	वर्ष 2020-21 के लिए	वर्ष 2019-20 के लिए
	(₹)	(₹)
ब्याज पर:		
- अल्पावधि जमा	28,50,002	20,31,072
अन्य आय		
सेवा शुल्क	16,11,790	6,78,354
सदस्यता प्रपत्रों की बिक्री	2,11,402	31,66,456
सीजीएचएस वसूली	13,762	29,170
	योग	6,09,850
	52,96,806	65,26,852

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची-10

	वर्ष 2020-21	वर्ष 2019-20
	के लिए	के लिए
	(₹)	(₹)
(क) वेतन तथा भत्ते-कोर		
लेखा एवं पेंशन प्रकोष्ठ	79,27,170	70,98,660
प्रशासन	1,78,90,843	1,75,83,827
कंप्यूटर केंद्र	13,34,924	7,35,182
संकाय और संलग्न कर्मचारी	2,83,93,670	3,04,69,203
छात्रावास	10,22,988	10,62,611
पुस्तकालय	1,10,74,889	1,22,26,310
रखरखाव	1,17,39,227	1,09,28,421
सदस्यता	29,88,287	28,18,320
शैक्षणिक गतिविधियों का कार्यालय	1,06,78,201	1,11,36,721
प्रशासन	50,73,785	49,34,877
आर एंड सी इकाई	6,42,608	7,07,941
ओवरटाइम्स	-	9,582
	9,87,66,592	9,97,11,655
(ख) सेवानिवृत्ति लाभ		
	योग (क + ख)	21,08,86,908
	30,96,53,500	22,06,77,988

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची-11
परिसर रख-रखाव

	वर्ष 2020-21	वर्ष 2019-20
	के लिए	के लिए
	(₹)	(₹)
मरम्मत एवं रख रखाव	18,67,980	13,98,958
छात्रवास सामान्य रख रखाव	5,79,709	23,77,332
किराया, दरें और कर	10,20,558	10,20,559
पानी और बिजली शुल्क	72,15,459	93,12,626
सुरक्षा व्यवस्था	40,00,606	41,40,781
हाउस कीपिंग चार्ज		
छात्रावास	36,97,946	60,21,766
मुख्य भवन	53,10,024	47,93,631
योग	2,36,92,282	2,90,65,653

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची-12

प्रशासनिक और विविध व्यय

	वर्ष 2020-21	वर्ष 2019-20
	के लिए	के लिए
	(₹)	(₹)
यात्रा खर्च		
1. संकाय/संस्थान और कर्मचारियों के लिए	24,320	34,701
2. ई.सी. और उसकी समितियों की बैठक के लिए	-	2,86,717
3. शाखाओं के पदाधिकारियों और अन्य के लिए	14,160	1,81,873
स्टाफ के लिए सुख-सुविधाएं	1,66,850	1,27,670
वार्षिक रिपोर्ट	90,168	1,04,106
बैंक शुल्क	3,651	51,887
निबंध/केस स्टडी पुरस्कार	22,000	43,820
वार्षिक आम बैठक के लिए खर्च	42,567	7,00,610
सम्मेलन के लिए व्यय	10,500	1,52,205
लेखा परीक्षकों को शुल्क	1,20,000	1,20,000
विशेषज्ञों को मानदेय	88,500	53,400
मेस कैंटीन के लिए आईजीएल गैस	1,60,324	2,98,479
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय केंद्र सदस्यता	77,838	61,360
कानूनी शुल्क	78,250	2,28,000
स्थानीय यात्रा व्यय	24,540	3,06,402
बैठक व्यय	41,735	2,36,673
विविध व्यय	18,95,999	6,45,045
मोटर कार व्यय	1,68,898	2,83,873
डाक और टेलीग्राम	1,04,389	2,62,560
डिजिटल सामग्री की तैयारी	14,39,260	-
छपाई और स्टेशनरी	4,04,687	7,10,244
मरम्मत, रखरखाव, फोटोकॉपी मशीन/ए.एम.सी.	3,07,697	2,25,861
टेलीफोन व्यय	4,64,546	5,57,087
योग	57,50,879	56,72,573

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची-क

भारत सरकार और आंतरिक आय से सहायता अनुदान प्राप्तियां और भुगतान खाता

	वर्ष 2020-21	वर्ष 2019-20
	के लिए	के लिए
	(₹)	(₹)
प्राप्तियाँ:		
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से सहायता अनुदान -वेतन	9,50,00,000	8,50,00,000
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से सहायता अनुदान -सामान्य	8,00,00,000	6,00,00,000
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग -पूँजी से सहायता अनुदान	10,50,00,000	3,50,00,000
सदस्य सदस्यता	8,78,681	10,24,410
प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए शुल्क	1,83,06,694	20,79,10,199
ओवरहेड शुल्क सहित अनुसंधान कार्यों से शुद्ध आय	2,11,60,972	1,92,69,117
उपयोगकर्ता शुल्क	46,91,725	1,32,97,573
प्रकाशनों की बिक्री	25,305	3,48,570
विविध प्राप्तियां	52,96,806	67,27,034
	योग	42,85,76,902
भुगतान :		
वेतन और भत्ते	10,94,98,639	10,22,60,471
पेंशन	7,00,80,311	6,00,00,000
पूँजी व्यय	-	
आईआईपीए भवन आदि	10,50,00,000	3,50,00,000
प्रशिक्षण कार्यक्रम	1,04,89,806	19,47,73,898
प्रकाशनों	6,40,809	5,42,862
पुस्तकालय पुस्तकें, पत्रिकाएं, बाध्यकारी और उपकरण शुल्क	4,49,308	5,18,609
शाखा संवर्धन गतिविधियाँ	1,18,565	4,75,904
परिसर रखरखाव	2,40,92,911	2,92,80,055
प्रशासनिक और विविध शुल्क	51,47,916	56,67,136
स्वयं के फंड से खरीदी गई संपत्ति	5,53,190	25,15,571
सीजीएचएस को भुगतान किया गया	15,98,272	10,94,647
जीएसटी/प्रीमियम व्यय	1,59,822	85,500
भा. लोक प्रशा. संस्थान रिजर्व फंड में स्थानांतरित	21,11,574	-
रिसर्च एन्डाउमेंट फंड में स्थानांतरित	2,34,252	-
	Total	43,22,14,652
वर्ष के दौरान भुगतान से अधिक प्राप्तियां	33,01,75,375	1,84,808
पिछले वर्ष प्राप्तियों पर भुगतान की अधिकता	(3637751)	(733326)
भुगतान से प्राप्तियों की कुल अधिकता	(548518)	(733326)

उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली से वर्ष 2020-21 के दौरान रु. 28,00,00,000/- सहायता अनुदान वेतन/सामान्य/पूँजी के रूप में प्राप्त हुए थे, जिसका वर्ष के दौरान का पूरी तरह से उपयोग किया गया है।

इसके अलावा, इस संस्थान ने वर्ष 2020-21 के दौरान 5,03,60,183/- रुपये का आंतरिक राजस्व प्राप्त किया है और 7,33,326/-रुपये के भुगतान से अधिक प्राप्त किया गया है, जिसे पिछले वर्ष यानी 2019-20 से आगे ले जाया गया था।

जैसा कि प्राप्तियाँ और भुगतान खातों की अनुसूची संख्या ए में दर्शाया गया है, वर्ष 31-3-2021 को प्राप्ति से अधिक भुगतान की शेष राशि 5,48,518/- रुपये की राशि को अगले वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान समायोजन के लिए ले जाया गया है।

जी.एस.ए. तथा सहयोगी एल.एल.पी.
चर्टरित लेखापाल
एफ.आर.एन. सं. 00257एन/एन500339

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची-ख

निधियों, जमा एवं अग्रिमों की प्राप्तियों एवं भुगतान का लेखा

	वर्ष 2020-21	वर्ष 2019-20
	के लिए	के लिए
प्राप्तियाँ		
वार्षिक स्कूल पुरस्कार कोष	5,293	6,552
भूपेंद्र हृजा मेमोरियल फंड	2,475	2,355
कंसल्टेंसी सपोर्ट फंड	75,237	1,01,297
इंफास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड	37,73,585	2,08,145
न्यादुम्मा मेमोरियल फंड	42,721	12,08,566
प्रो. एस. सरोजा मेमोरियल फंड	32,500	19,07,753
अनुसंधान बंदोबस्ती निधि	3,35,369	45,074
श्रीमती कुसुमताई मेमोरियल फंड	8,816	24,533
कर्मचारी हितैषी कोष	35,853	2,89,658
टी.एन. चतुर्वेदी पुरस्कार कोष	5,565	6,612
पी.के. उमाशंकर मेमोरियल फंड	12,50,000	-
यूसी अग्रवाल मेमोरियल फंड	25,00,000	-
कॉर्पोरेट सदस्यता पूँजी कोष	2,28,985	1,96,855
आजीवन सदस्यता पूँजी कोष (उप)	24,83,943	5,059
स्टाफ/संकाय से प्राप्य अग्रिम	1,87,42,755	4,17,23,823
अग्रिम किराया	17,057	17,057
पार्टियों से प्राप्य राशि	-	-
एएमटी कर्मचारियों को देय (देयता)	49,820	15,876
बैंक के साथ सावधि जमा	12,39,48,285	1,83,26,014
जीएसटी इनपुट संचय	1,07,37,611	2,04,19,132
वर्तमान संपत्ति अन्य	34,83,267	1,07,524
एचबीए पर अर्जित ब्याज	16,104	16,104
मेस शुल्क	29,079	5,81,850
अन्य जमा (संपत्ति)	-	500
अन्य जमा (देयता)	10,98,191	24,15,629
अन्य देनदारियाँ	3,78,69,777	6,15,31,001
अन्य देयताएं (विविध लेनदारों)	14,01,159	15,67,443
विविध देनदार	94,54,958	2,05,13,018
टीडीएस प्राप्य	19,32,880	-
जीएसटी पर टीडीएस	6,01,010	-
कुल योग	22,01,62,295	17,12,37,430

भुगतानः

वार्षिक स्कूल पुरस्कार कोष	-	-
निगमित सदस्यता पूंजी कोष	6,865	1,65,237
आजीवन सदस्यता पूंजी कोष (उप)	68,869	6,62,366
आईआईपीए रिजर्व फंड	-	-
इंफास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड	92,690	-
प्रो. एस. सरोजा मेमोरियल फंड	-	21,140
अनुसंधान बंदोबस्ती निधि	10,295	1,99,755
कर्मचारी हितैषी कोष	6,000	-
न्यादुम्मा मेमोरियल फंड	7,765	76,575
टी.एन. चतुर्वेदी कोष	10,000	7,490
पी.के. उमाशंकर मेमोरियल फंड	26,219	-
यूसी अग्रवाल मेमोरियल फंड	2,40,623	-
स्टाफ/संकाय से वसूली योग्य अग्रिम	70,91,666	4,75,03,775
वर्तमान संपत्ति अन्य	70,42,177	1,39,037
वर्ष के दौरान देय व्यय	63,41,797	1,10,70,784
बैंक के साथ सावधि जमा	29,54,11,046	2,00,24,339
जीएसटी इनपुट संचय	47,68,310	1,92,35,863
जीएसटी आउटपुट संचय	73,59,653	-
मेस शुल्क	2,41,150	4,05,979
अन्य जमा (संपत्ति)	-	2,500
अन्य जमा (देयता)	11,74,444	24,42,918
अन्य देनदारियाँ	3,75,88,313	9,20,66,056
अन्य देयताएं (विविध लेनदारों)	9,70,254	20,65,898
विविध देनदार	29,33,700	5,37,312
टीडीएस प्राप्य	39,04,184	42,50,736
जीएसटी पर टीडीएस	5,70,867	3,48,357
अग्रिम कर	6,23,574	-
धनराशि सीपीएफ से प्राप्य	97,85,000	-
धनराशि पेशन फंड से प्राप्य	99,19,689	-
कुल योग	39,61,95,150	20,12,26,117

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुलग्नक-1
(संदर्भ अनुसूची-3)

शोध परियोजनाओं का प्राप्ति एवं भुगतान लेखा (एफ.सी.आर.ए. अनुदान को छोड़कर)

	वर्ष 2020-21	वर्ष 2019-20
	के लिए	के लिए
	(₹)	(₹)
प्राप्तियाँ :		
शहरी अध्ययन केंद्र के लिए आवास और शहरी मामलों और रोजगार मंत्रालय से अनुदान (प्रकाशन की बिक्री सहित)	3,34,39,342	3,20,75,248
अप्पा विदेश और क्षेत्र का दौरा	1,47,93,848	2,68,39,816
अन्य कार्यक्रम	38,24,000	98,42,990
उपभोक्ता मामलों के लिए केंद्र	-	3,46,07,000
अन्य शोध परियोजना / अध्ययन	6,84,95,038	4,64,79,405
अनुसंधान-I असाइनमेंट	-	-
आईसीएसएसआर एफ/जहाज रसीद	-	96,667
अप्पा I	2,18,25,360	3,77,48,676
आईसीजीआरएस -एनसीएच	4,00,00,000	4,16,00,000
प्रांतस्था	-	28,16,000
कुल	18,23,77,588	23,21,05,802

भुगतान :

शहरी अध्ययन केंद्र	2,42,25,783	2,71,57,342
अप्पा विदेश और क्षेत्रीय दौरा	28,45,159	97,33,991
अन्य कार्यक्रम	47,43,630	93,45,132
उपभोक्ता मामले केंद्र	2,36,69,829	2,67,69,928
अनुसंधान परियोजना/स्टडी	4,51,43,201	2,85,92,270
अनुसंधान-1 असाइनमेंट	-	28,169
आईसीएसएसआर भाड़ा/शिपिंग व्यय	96,667	3,27,890
अप्पा 1	55,89,841	78,92,792
आईसीजीआरएस एनसीएच	3,88,83,022	4,74,12,870
कॉर्टक्स	35,18,532	32,59,529
भुगतान पर प्राप्तियों की अधिकता	3,36,61,924	7,15,85,307
कुल	18,23,77,588	23,21,05,802

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुलग्नक-2

(संदर्भ अनुसूची-3)

सीयूएस के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से प्राप्त अनुदान प्राप्ति एवं भुगतान खाता

	वर्ष 2020-21	वर्ष 2019-20
	के लिए	के लिए
	(₹)	(₹)
प्राप्तियाँ		
वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	3,34,31,431.0	3,20,64,060
सीयूएस प्रकाशनों की बिक्री	7,911.0	11,188
योग	3,34,39,342.0	3,20,75,248
भुगतान		
वेतन एवं भत्ते	2,08,15,818	2,34,49,696
आधारभूत संरचना	24,682	-
यात्र व्यय	5,41,746	4,94,068
पुस्तकालय पुस्तकों और पत्रिकाएं	5,98,118	1,215
प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	-	-
विविध और आकस्मिक व्यय	2,93,584	1,35,089
छपाई और स्टेशनरी	1,34,149	2,01,028
परिसर रखरखाव	6,38,979	8,40,644
प्रकाशन का मुद्रण	77,586	67,553
पानी और बिजली	4,13,565	5,96,151
ओवरहेड शुल्क	22,70,410	29,04,808
योग	2,58,08,637	2,86,90,252
वर्ष के दौरान भुगतान से अधिक प्राप्तियाँ	76,30,705	33,84,996
पिछले वर्ष प्राप्तियों पर भुगतान की अधिकता	(1,09,96,325)	(1,43,81,321)
योग	(33,65,620)	(1,09,96,325)

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुलग्नक-3

(संदर्भ अनुसूची-3)

उपभोक्ता अध्ययन केंद्र के लिए उपभोक्ता मामले मंत्रालय से प्राप्त अनुदान प्राप्ति एवं भुगतान खाता

	वर्ष 2020-21	वर्ष 2019-20
	के लिए	के लिए
	(₹)	(₹)
प्राप्तियाँ		
वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान		3,46,07,000
योग		3,46,07,000
भुगतानः		
संचार	1,63,452	1,86,270
आधारभूत संरचना	3,12,367	95,636
पुस्तकालय की, पुस्तकें	1,07,308	-
विविध खर्च	3,09,056	2,29,488
वेतन और भत्ते	1,29,35,386	1,00,81,286
प्रकाशन	6,35,815	8,69,268
प्रकाशन अनुदान से व्यय	-	-
शोध अध्ययन	1,37,693	5,28,260
संगोष्ठी/कार्यशाला	22,60,126	18,90,523
प्रशिक्षण कार्यक्रम	29,59,694	74,65,000
यात्रा व्यय	51,979	3,35,363
ओवरहेड शुल्क	44,80,863	59,07,629
योग	2,43,53,739	2,75,88,723
वर्ष के दौरान भुगतान से अधिक प्राप्तियाँ	(2,43,53,739)	70,18,277
पिछले वर्ष प्राप्तियों पर भुगतान की अधिकता	1,17,38,347.0	47,20,070
योग	(1,26,15,392)	1,17,38,347

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुलग्नक-4

(संदर्भ अनुसूची-3)

एनसीएच के माध्यम से एकीकृत उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली के लिए उपभोक्ता मामले मंत्रालय से अनुदान की प्राप्ति एवं भुगतान खाता

	वर्ष 2020-21	वर्ष 2019-20
	के लिए	के लिए
	(₹)	(₹)
प्राप्तियाँ		
वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	4,00,00,000	4,16,00,000
और पिछले वर्ष अव्ययित अनुदान	-	1,43,01,946
ब्याज	-	-
	योग	4,00,00,000
		5,59,01,946
भुगतान		
अनु. सहित सहित संचार व्यय	79,34,333	1,09,51,952
अनु., सहित अवसरंचना व्यय	9,10,411	21,72,731
श्रम	2,51,23,359	2,43,52,560
विविध खर्च	2,15,868	1,31,260
अनु.. सहित प्रिंटिंग और स्टेशनरी	1,73,515	79,609
नवीनीकरण का काम	-	23,17,978
कर्मचारी कल्याण	1,58,372	3,44,472
प्रशिक्षण	5,00,000	55,719
अनु. सहित यात्रा व्यय	12,703	38,316
वेबसाइट व्यय	-	6,937
संस्थागत शुल्क	76,00,627	94,97,650
	योग	4,26,29,188
	(26,29,188)	-
पिछले वर्ष प्राप्तियों पर भुगतान की अधिकता	59,52,762	59,52,762
	योग	33,23,575
		59,52,762

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची-13

लेखा परीक्षा का हिस्सा बनने वाली महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा नीतियां एवं टिप्पणियां

1. पृष्ठभूमि

सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित भारतीय लोक प्रशासन का उद्घाटन संस्थान के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा मार्च 29, 1954 को किया गया था। इस संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ऐसी अकादमिक गतिविधियों को क्रियान्वित करने से है जिनके माध्यम से सरकारी और अन्य सार्वजनिक सेवा संगठनों के अधिकारियों की नेतृत्व योग्यता और प्रबन्धनीय क्षमता को बढ़ाया जा सके।

2. लेखा परीक्षा करने की पद्धति

संस्थान का वित्तीय विवरण “संग्रहण आधार” पर तैयार किया गया है जो सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षक सिद्धांतों के अनुरूप है। दिल्ली कार्यालय में लेन-देन संबंधी वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी आधार पर तैयार किए जाते हैं जब तक कि अन्यथा कहा न गया हो।

क. अचल संपत्तियां

- 31 मार्च, 2012 तक, अपने स्वयं के स्रोतों से प्राप्त संपत्तियों को बैलेंस शीट में संपत्ति निधि खाते में संबंधित प्रविष्टि के साथ लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया गया था। हालांकि, 2012-13 में लेखांकन प्रणाली को नकद से संग्रहण में परिवर्तित करने के समय, स्वयं से स्रोत से अर्जित संपत्ति को पूंजीगत वस्तु के रूप में माना गया है और अचल संपत्तियों के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। पूंजीकरण (कॉपिटलाइजेशन) के लिए कट-ऑफ तिथि को पांच वर्ष के रूप में लिया गया है यानि 1 अप्रैल 2008 से स्वयं से अर्जित संपत्ति का पूंजीकरण किया है। 31 मार्च 2013 को वित्तीय रिकॉर्ड से भूमि और भवन और पुस्तकों का मूल्य लिया गया है। अनुदान से सृजित परिसंपत्तियों को प्रायोजित परियोजनाओं और कार्यक्रम की प्राप्त निधियों से प्राप्त निधि, जहां ऐसी परिसंपत्तियों का स्वामित्व संस्थान में निहित है, को संस्थान की अचल संपत्ति के रूप में माना जाता है, साथ ही परिसंपत्ति निधि में जमा किया जाता है। हालांकि, ऐसी परिसंपत्तियों पर कोई मूल्यांकन का दावा नहीं किया जाता है जिन्हें निधियों से प्राप्त किया जाता है।

क. अनुदान सहायता

- आवर्ती व्यय के लिए प्राप्त सहायता अनुदान वर्तेन और सामान्य आय को आय, जैसे भी और जब भी प्राप्त हो, के रूप में लिया जाता है।
- पूंजीगत व्यय के लिए अनुदान सहायता जैसे कि अचल संपत्तियों को पूंजी निधि में स्थानांतरित किया जाता है।
- निर्दिष्ट सौंपे गए कार्य के लिए अनुदान सहायता का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाता है जिसके लिए वह प्राप्त होता है और अप्रयुक्त अनुदानों को आगे बढ़ाया जाता है और बैलेंस शीट में इन्हें आर्थिक देनदारी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे किसी मामले जिसमें, व्यय प्राप्त अनुदान

की तुलना में अधिक है, इसे प्राप्य अनुदान के रूप में दर्शाया जाना है।

- अनुसंधान परियोजनाओं/कार्यों पर अधिशेष/घाटे को अनुसंधान परियोजनाओं/कार्यों के पूरा होने पर आय और व्यय खाते में शामिल किया जाता है।
 - चल रहीं प्रायोजित परियोजनाओं, अनुसंधान परियोजनाओं और कार्यक्रम के संबंध में, ऐसी परियोजना का व्यय ऐसी निर्दिष्ट परियोजना से नामे लिखा (डेबिट कर लिया) जाता है। परियोजनाओं से बचने वाले अतिरिक्त शुल्क को संस्थान की आय के रूप में माना जाता है।
- ख. प्राप्त होने वाली जीवन/सहकारी सदस्यता फीस को आय नहीं माना जाता और इसकी बजाय इसे निर्दिष्ट निधियों जैसे कि जीवन/सहकारी सदस्यता पूँजी निधि में स्थानांतरित किया जाता है।
- ग. जीवन/सहकारी सदस्यता पूँजी निधि के निमित्त किए गए निवेश से प्राप्त ब्याज को संबंधित निधियों में स्थानांतरित किया जाता है और आय के रूप में नहीं लिया जाता है जबकि सामान्य निधि पर प्राप्त ब्याज का 50 प्रतिशत भाग आय में स्थानांतरित किया जाता है और शेष 50 प्रतिशत को शाखाओं को देयता के रूप में दर्शाया जाता है।
- घ. गृह निर्माण और अन्य अग्रिमों के लिए कर्मचारियों को दिए जाने वाले ब्याज वाले अग्रिमों पर आय की गणना को संग्रहण आधार के रूप में की जाती है, हालांकि, ब्याज की वास्तविक वसूली मूलधान के पूर्ण भुगतान के बाद शुरू होती है।
- ऋ. पूँजी निधि से संबंधित आय और व्यय को संबंधित पूँजी निधि में क्रेडिट (जमा)/डेबिट (काट लिया) किया जाता है।
- च. प्राप्त अनुदानों से सृजित परिसंपत्तियों, प्रायोजित परियोजनाओं की निधियां और कार्यक्रम, जहां ऐसी परिसंपत्तियों का स्वामित्व संस्थान में निहित है, को पूँजी निधि में इसे क्रेडिट (शामिल) करते हुए संस्थान की अचल संपत्ति के रूप में माना जाता है। हालांकि, ऐसी परिसंपत्तियों पर मूल्यद्वास का दावा नहीं किया जाता, जो निधियों से प्राप्त की जाती हैं।
- छ. आयकर महानिदेशक से दिनांक 20 दिसम्बर 2010 से प्राप्त कर छूट प्रमाण पत्र को देखते हुए आयकर के किसी प्रावधान पर विचार नहीं किया गया है।
- ज. विदेशी मुद्रा लेन-देन का संदर्भ लेने-देन की तिथि पर प्रचलित दर के आधार पर लिया जाता है। हालांकि, साल के अंत तक चलने वाले मौद्रिक लेन-देन की व्याख्या वर्ष की अंतिम दर के आधार पर की जाती है।
- ज. निम्नलिखित को छोड़कर, विभिन्न गतिविधियों से प्राप्त होने वाली आय और व्यय की गणना संग्रहण आधार पर की जाती है।
- सदस्यता फीस रसीद, की गणना जैसे भी और जब भी प्राप्त के आधार पर की जाती है।
 - छात्रावास कक्ष की रसीद की गणना नकद आधार पर की जाती है।
 - अवकाश यात्र अनुदान पर व्यय की गणना नकद आधार पर की गई है।
 - शाखाओं को दी गई वित्तीय सहायता की गणना भुगतान के वर्ष में व्यय आधार पर की जाती है।
 - आवेदन पत्र की बिक्री की गणना नकद आधार पर की जाती है।
 - प्रकाशनों की बिक्री पर प्राप्त रॉयलटी

3. अचल परिसंपत्तियां

- अचल परिसंपत्तियों की व्याख्या अधिग्रहण की लागत छागत भाड़ा, शुल्क, कर और अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष व्यय सहितऋ कम सचित मूल्यहास आधार पर की जाती है
- प्राप्त अनुदानों से सृजित परिसंपत्तियों, प्रायोजित परियोजनाओं की निधियां और कार्यक्रम, जहां ऐसी परिसंपत्तियों का स्वामित्व संस्थान में निहित है, को पूंजी निधि में इसे क्रेडिट (शामिल) करते हुए संस्थान की अचल संपत्ति के रूप में माना जाता है। हालांकि, ऐसी परिसंपत्तियों पर मूल्यहास का दावा नहीं किया जाता, जो निधियों से प्राप्त की जाती हैं।

4. अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास

- प्राप्त अनुदानों/प्रायोजित निधि से अधिग्रहित परिसंपत्तियों को छोड़कर मूल्यहास की गणना आयकर अधिनियम में निर्दिष्ट दरों पर निम्नलिखित आधार पर की जाती है, वे हैं:
 - वाहन 15 प्रतिशत
 - कार्यालय उपकरण 15 प्रतिशत
 - कंप्यूटर 40 प्रतिशत
 - फर्नीचर 10 प्रतिशत
- 30 सितम्बर के बाद अधिग्रहित परिसंपत्तियों के मामले में मूल्यहास लागू दर का 50 प्रतिशत लिया जाता है
- 5000/- से कम लागत वाली संपत्ति का अधिग्रहण वर्ष में पूरी तरह से मूल्यहास किया जाता है

(ख) लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां

- i. संस्थान द्वारा गठित समिति द्वारा अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है। वित्तीय विवरण के प्रयोजन के लिए, अचल संपत्तियों के बुक बैलेंस को अचल संपत्तियों के अंतर्गत माना गया है।
- ii. सेवा कर दायित्व के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गा है और इसके लिए आगे कोई परामर्श नहीं लिया गया है।
- iii. कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम खर्चे पुष्टि के अधीन है। वित्तीय विवरण के उद्देश्य के लिए, वित्तीय पुस्तिकाओं के अनुरूप वसूली योग्य राशि को प्राप्त माना गया है। कर्मचारी सदस्यों/संकाय सदस्यों से शेष राशि की प्राप्ति पुष्टि की प्रक्रिया में है।
- iv. भुगतान के समय टीडीएस की कटौती की गई है।
- v. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं आवश्यक हो, पुनर्वर्गीकृत, पुनः निरपेक्षित और पुनः व्यवस्थित किया गया है।

कार्यकारिणी परिषद के लिए

एस.एन. त्रिपाठी

के.के. पांडेय

अमिताभ रंजन

महानिदेशक

सदस्य

कुल सचिव

सदस्य सचिव

कार्यकारिणी परिषद

(मुख्य लेख परीक्षक अधिकारी)

तिथि: 27/09/2021

स्थान: नई दिल्ली

यूडीआईएन 21083899AAAADM7638

लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

सदस्यों को

पेंशन निधि, भा.लो.प्र.सं.

हमने 31 मार्च, 2021 तक भारतीय लोक प्रशासन संस्थान-पेंशन निधि के संलग्न तुलन पत्र और उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के आय-व्यय लेखा परीक्षक जांच की है। ये वित्तीय विवरण निधियों के प्रबन्धन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारे लेखा परीक्षक के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक विचार व्यक्त करना है।

हमने भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षक संबंधी मानकों के अनुरूप अपना लेखा (ऑडिट) किया। उन मानकों के लिए यह आवश्यक है कि हम इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय विवरण भौतिक रूप से गलत विवरण से मुक्त हैं। एक लेखा परीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों का समर्थन करने वाले साक्ष्य की जांच करना शामिल है। ऑडिट (वित्तीय लेखा) में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबन्धनों द्वारा व्यक्त किए गए महत्वपूर्ण अनुपानों का आकलन करने के साथ-साथ समर्ग वित्तीय विवरण प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारा ऑडिट हमारे विचार के लिए एक उचित आधार प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, हम प्रतिवेदन करते हैं कि:

1. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुरूप हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे;
2. हमारी राय में, संस्थान द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकों रखी गई हैं, जहां तक उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है;
3. इन रिपोर्टों के आधार पर निपटाए गए तुलन पत्र और आय तथा व्यय लेखा, लेखा की पुस्तिकाओं के अनुरूप हैं;
4. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुरूप और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त खातों की लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों (अनुसूची-3) के साथ संदर्भ में व्याख्या की जाती है, जिससे आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक उचित और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्राप्त होता है:-
 - क. तुलन पत्र के मामले में, 31 मार्च, 2021 को निधि के मामलों की स्थिति; तथा
 - ख. आय और व्यय लेखा परीक्षा के मामले में, उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए अधिशेष का।

जीएसए और एसोसिएट्स के लिए

(चर्टरित लेखापाल)

सुनील अग्रवाल

सहभागी

एम. नम्बर 083899

16, डीडीए फ्लैट, पंचशील पार्क, नजदीक मालवीय नगर

नई दिल्ली-1100017

तिथि: 27/09/2021

यूडीआईएन 21083899AAAADN5632

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

पेंशन निधि

31 मार्च, 2020 को तुलन पत्र

	अनुसूची	31.3.2021 तक	31.3.2020 तक
		(₹)	(₹)
उत्तरदायित्व			
कोष	1	9,46,73,474	8,35,63,582
दीर्घावधि उत्तरदायित्व		1,21,99,00,000	1,09,24,36,418
आईआई को देय राशि		99,19,689	
	कुल	1,32,44,93,163	1,17,60,00,000
परिसंपत्ति			
निवेश	2	6,01,93,774	2,29,66,574
प्राप्त योग्य टीडीएस		9,989	9,989
एसबीआई के पास शेष		4,43,89,400	6,05,87,019
आईआईपीए से प्राप्त योग्य राशि		1,21,99,00,000	1,09,24,36,418
	कुल	1,32,44,93,163	1,17,60,00,000

लेखांकन नीतियां और खातों के लिए टिप्पणियां 3

अनुसूची 1 से 3 लेखा परीक्षा एक अभिन्न भाग के रूप में शामिल हैं

एक समान तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

जी.एस.ए. तथा सहयोगी

(चर्टरित लेखापाल)

एफ.आर.एन. 000257एन/एन500339

(सुनील अग्रवाल)

सहभागी

एम.नम्बर 083899

16 डी.डी.ए. फ्लैट्स,

पंचशील पार्क,

नियर मालवीय नगर

नई दिल्ली-110017

दिनांक : 27.9.2021

यू.डी.आई.एन.सं. 21083899AAAADN5632

सदस्य सचिव

कुल सचिव

अध्यक्ष

महानिदेशक

सदस्य

कार्यकारी परिषद, भा.लो.प्र.सं.

सदस्य

भा.लो.प्र.सं. कर्मचारी संघ

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

पेंशन निधि

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष का आय तथा व्यय लेखा

	31.3.2021 को समाप्त वर्ष (₹)	31.3.2020 को समाप्त वर्ष (₹)
आय		
डीओपीटी से प्राप्त रकम	7,00,80,311	6,00,00,000
भालोप्रसं से प्राप्त रकम	31,24,399	1,01,64,891
ब्याज से आय		
वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	62,98,461	32,35,903
कुल योग - अ	7,95,03,171	7,34,00,794

व्यय		
(जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है)		
पेंशन का परिवर्तित मूल्य	48,95,842	18,01,370
मासिक पेंशन का भुगतान	6,51,84,469	5,88,94,040
बैंक शुल्क	778	3,043
प्रीमियम	39,66,800	
कुल योग - ब	7,40,47,889	6,06,98,453
वर्ष के लिए अधिशेष	(अ - ब)	54,55,282
(घाटा)पिछले वर्ष से अधिशेष		1,27,02,341
तुलन-पत्र में ले जाया गया		(23,85,235)
लेखांकन नीतियां और खातों के लिए नोट्स - 3		(1,50,87,576)
अनुसूचियां 1 से 3 खातों का एक अभिन्न अंग है		
समान तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार		
कृते जीएसए और एसोसिएट्स		
चर्टरित लेखापाल		
एफ आर एन - 000257 एन / एन 500339		

सुनील अग्रवाल	सदस्य सचिव	सभापति
भागीदार	कुलसचिव, भा.लो.प्र.सं.	महानिदेशक, भा.लो.प्र.सं.
एम. नं. 083899		

16, डीडीए “फ्लैट्स, पंचशील पार्क, मालवीय नगर के पास, नई दिल्ली-110017	सदस्य कार्यकारी परिषद	सदस्य भा.लो.प्र.सं. स्टाफ एसोसिएशन
--	----------------------------------	---

दिनांक: 27/09/2021

यू डी आई एन 21083899एएएडीएन5632

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

पेंशन निधि

अनुसूची-1

कॉर्पस

	31.3.2021 को समाप्त वर्ष	31.3.2020 को समाप्त वर्ष
	(₹)	(₹)
सरकारी अनुदान	5,50,71,000	5,50,71,000
बकाया के लिए प्राप्त अनुदान	73,27,000	73,27,000
नियोक्ता के हिस्से का हस्तांतरण		
सीपीएफ से -- बी एफ	1,72,70,529	
जोड़ें : पेंशन अंशदान प्रतिनियुक्त वाले	1,19,34,898	2,92,05,427
कर्मचारियों के बारे में		
जोड़ें: आय और व्यय खाते		
से स्थानांतरित किया गया	30,70,047	(23,85,235)
कुलयोग	9,46,73,474	8,92,18,192

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
पेंशन निधि

अनुसूची-2
निवेश

	31.3.2021 को (₹)	31.3.2020 को (₹)
(क) विशेष जमा योजना, एस.बी.आई., आई.पी. एस्टेट	68,774	68,774
(ख) केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियाँ		
10.25: भारत सरकार 2021	34,00,000	34,00,000
8.15: भारत सरकार एफ.सी.आई. विशेष बांड 2022	5,45,000	5,45,000
8.20: भारत सरकार ऑयल विशेष बांड 2024	5,15,000	5,15,000
8.20: भारत सरकार ऑयल विशेष बांड 2024	20,00,000	20,00,000
8.20: भारत सरकार ऑयल विशेष बांड 2024	10,25,000	10,25,000
8.26: भारत सरकार 2027	40,00,000	40,00,000
8.64: यूनियन बैंक प्रेप.बांड निवेश	1,00,00,000	-
8.25: बैंक आफ बड़ौदा पर्प बांड	1,10,00,000	-
9.15: पीएनबी पर्प बांड	2,00,00,000	-
कुलयोग (अ)	5,25,53,774	1,15,53,774
(ग) राज्य सरकार के बांड (15% श्रेणी)		
8.31% राज्य विकास ऋण राजस्थान 2020	-	6,00,000
8.88% राज्य विकास ऋण गुजरात 2021	7,50,000	7,50,000
कुलयोग (ब)	7,50,000	13,50,000
(घ) सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं आदि के बांड (40% श्रेणी)		
9.45% एसबीआई लोअर टियर-2 2026	28,90,000	28,90,000
9.75% ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड 2021	-	31,72,800
9.75% ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड 2021	40,00,000	40,00,000
कुलयोग (स)	68,90,000	1,00,62,800
कुलयोग (अ+ब+स)	6,01,93,774	2,29,66,574

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

पेंशन निधि

अनुसूची-3

लेखांकन नीतियाँ और खातों के लिए टिप्पणियाँ

अ. लेखा नीतियाँ

1. निधि का खाते नकद आधार पर तैयार किया गया है।
2. निवेश अंकित मूल्य पर बताए गए हैं।
3. निवेश पर ब्याज की गणना प्राप्ति के आधार पर की जाती है।
4. भुगतान किए गए प्रीमियम या निवेश पर अर्जित छूट को अधिग्रहण के वर्ष में लाभ और हानि खाते के माध्यम से भेजा जाता है।

ब. खातों के लिए टिप्पणियाँ

पिछले वर्ष के आँकड़ों को जहाँ आवश्यक समझा गया, पुनर्व्यवस्थित या पुनः समूहित किया गया है।

सदस्य सचिव

(कुलसचिव, भा.लो.प्र.सं.)

सभापति

(महानिदेशक, भा.लो.प्र.सं.)

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सदस्य-गण

अंशदायी भविष्य निधि, भा.लो.प्र.सं.

हमने 31 मार्च, 2021 को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान-अंशदायी भविष्य निधि के संलग्न तुलन-पत्र और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय-व्यय खाते की भी लेखापरीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण फंड के प्रबंधान की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करें।

हमने भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा-परीक्षण मानकों के अनुसार अपनी लेखा-परीक्षा की है। उन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा-परीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय विवरण ठोस गलत विवरण से मुक्त हैं। लेखा-परीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों का समर्थन करने वाले साक्ष्यों का परीक्षण के आधार पर परीक्षण करना शामिल है। लेखा-परीक्षा में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करने के साथ-साथ समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हम मानते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती है।

आगे, हम सूचित करते हैं कि:

- (1) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;
- (2) हमारी राय में, संस्थान द्वारा कानून न अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकों रखी गई है; यह उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है;
- (3) इन रिपोर्ट द्वारा बनाए गए तुलन-पत्र और आय और व्यय खाते, खाते की किताबों के अनुरूप हैं;
- (4) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त खाते को खातों की टिप्पणियों (अनुसूची - 3) के साथ पढ़े जाने पर, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृश्य प्रदान करते हैं : -
 - (अ) तुलन पत्र के मामले में, 31 मार्च, 2021 को फंड के मामलों की स्थितीय तथा
 - (ब) आय और व्यय खाते के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष।

कृते जीएसए और एसोसिएट्स

चर्टरित लेखापाल

एफ आर एन - 000257 एन / एन 500339

16 डी डी ए फ्लैट पंचशील पार्क

मालवीय नगर के समीप, नई दिल्ली-110017

दिनांक : 27.9.2021

यू.डी.आई.एन.सं. 20083899ए.ए.ए.डी.पी.7660

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अंशदायी भविष्य निधि

31 मार्च, 2021 को तुलन-पत्र

	अनुसूची को (₹)	31.3.2021 को (₹)	31.3.2020 को (₹)
देयताएं			
संचित शेष	1	807433	21382191
अवितरित ब्याज		(1654011)	(42,98,660)
जीपी को देय राशि फंड		2960000	10,89,444
भा.लो.प्र.सं. को देय राशि		9785000	-
	कुल	1,18,98,422	1,81,72,975
संपत्तियां			
निवेश	2	11430000	11430000
एसबीआई में बैलेंस		468422	6742975
	कुल	1,18,98,422	1,81,72,975
लेखांकन नीतियां और खातों के लिए नोट्स अनुसूचियां 1 से 3 खातों का अधिन्न अंग हैं समान तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार	3		

कृते जीएसए और एसोसिएट्स एलएलपी

चर्टरित लेखापाल

एफआरएन - 000257एन एन500339

सुनील अग्रवाल

भागीदार

एम. नं. 083899

16, डी डी ए फ्लैट, पंचशील पार्क,

मालवीय नगर के पास,

नई दिल्ली-110017

सदस्य सचिव

कुलसचिव, भा.लो.प्र.सं.

सदस्य
कार्यकारी परिषद्

सदस्य

भा.लो.प्र.सं. स्टाफ एसोसिएशन

सभापति

महानिदेशक, भा.लो.प्र.सं.

दिनांक : 27.9.2021

यू.डी.आई.एन.सं. 20083899ए.ए.ए.डी.पी.7660

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अंशदायी भविष्य निधि

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा

	31.3.2021 को समाप्त वर्ष (₹)	31.3.2020 को समाप्त वर्ष (₹)
आय		
ब्याज	3877873	1284889
	कुल	38,77,873
		12,84,889

व्यय

(अ) ब्याज जमा किया गया:

- सदस्यों का योगदान	861257	1068159
- नियोक्ता का योगदान	371367	407228
(ब) बैंक और डाक शुल्क	599	3699
	कुल	1233223
	26,44,650	(1,94,197)
वर्ष के दौरान अतिरेक/(घाटा)		
गत् वर्ष से अवितरित ब्याज	(42,98,660)	(41,04,463)
अवितरित ब्याज ले जाया गया	-1	
कुल तुलन पत्र को अग्रेषित करें	कुल	(16,54,011)
लेखांकन नीतियां और खातों के लिए नोट्स 3	3	(42,98,660)

अनुसूचियां 1 से 4 खाते का एक अधिन अंग हैं

समान तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते जीएसए और एसोसिएट्स एलएलपी

चर्टरित लेखापाल

एफआरएन - 000257एन एन500339

सुनील अग्रवाल
भागीदार
एम. नं. 083899
16 डी डी ए फ्लैट पंचशील पार्क
मालवीय नगर के समीप, नई दिल्ली-110017

सदस्य सचिव
कुलसचिव भा.लो.प्र.सं.

सदस्य
भा.लो.प्र.सं. स्टाफ एसोसिएशन

सदस्य
कार्यकारी परिषद

सभापति
महानिदेशक भा.लो.प्र.सं.

दिनांक : 27.9.2021

यू.डी.आई.एन.सं. 20083899ए.ए.ए.डी.पी.7660

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अंशदायी भविष्य निधि

अनुसूची-1

संचित पात्रता

	सदस्यों का अंशदान	नियोक्ता का अंशदान	31.3.2021 को समाप्त वर्ष का कुल	31.3.2020 को समाप्त वर्ष का कुल
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
प्रारंभिक शेष	1,52,12,972	61,69,219	2,13,82,191	1,84,08,095
वर्ष के दौरान योगदान	12,52,000	8,48,380	21,00,380	21,34,560
ब्याज क्रेडिट	8,61,257	3,71,367	12,32,624	14,75,387
कुल:	1,73,26,229	73,88,966	2,47,15,195	2,20,18,042
घटाएः अंतिम भुगतान	(1,68,70,144)	(70,37,618)	(2,39,07,762)	(6,35,851)
शेष	4,56,085	3,51,348	8,07,433	2,13,82,191

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
अंशदायी भविष्य निधि

अनुसूची-2

निवेश

	31.3.2021 को	31.3.2020 को
	(₹)	(₹)
(अ) अन्य निवेश		
10.25% भारत सरकार 2021	3,00,000	3,00,000
8.15% भारत सरकार एफ.सी.आई. विशेष बांड 2022	2,00,000	2,00,000
8.20% भारत सरकार ऑयल विशेष बांड 2024	6,25,000	6,25,000
8.20% भारत सरकार ऑयल विशेष बांड 2024	2,50,000	2,50,000
8.20% भारत सरकार ऑयल विशेष बांड 2024	3,75,000	3,75,000
8.26% भारत सरकार 2027	10,00,000	10,00,000
9.56% एसबीआई पैपा बांड	70,00,000	70,00,000
कुल (अ)	97,50,000	97,50,000
(ब) राज्य सरकारी बांड (15:)		
8.11% एसडीएल राजस्थान 2020	2,00,000	2,00,000
8.88% एसडीएल गुजरात 2021	5,20,000	5,20,000
कुल (ब)	7,20,000	7,20,000
(स) सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं आदि के बांड (40% श्रेणी)		
9.45% एस.बी.आई. लोअर II 2016	9,60,000	9,60,000
8.92% यूको बैंक 2020	-	-
कुल (स)	9,60,000	9,60,000
कुल योग अ+ब+स	1,14,30,000	1,14,30,000

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अंशदायी भविष्य निधि

अनुसूची-३

लेखा नीतियाँ और खातों के लिए टिप्पणियाँ

अ. लेखा नीतियाँ

1. निधि के खाते नकद आधार पर तैयार किए गए हैं।
2. निवेश अंकित मूल्य पर बताया गया है
3. निवेश पर ब्याज की गणना प्राप्ति के आधार पर की जाती है।
4. भुगतान किए गए प्रीमियम या निवेश पर अर्जित छूट को अधिग्रहण के वर्ष में लाभ और हानि खाते के माध्यम से भेजा जाता है।

ब. लेखा टिप्पणियाँ

1. संस्थान मूल बेतन के 10% की दर से नियोक्ता के योगदान के लिए योगदान दे रहा है।
2. सदस्य मूल बेतन का न्यूनतम 10% योगदान कर रहे हैं।
3. वित्त, भारत सरकार के आदेश के अनुसार ब्याज का भुगतान किया जा रहा है।
4. सदस्यों को अग्रिम की शेष राशि पुष्टि के अधीन है।
5. पिछले वर्ष के आँकड़ों को जहाँ आवश्यक समझा गया, पुनर्व्यवस्थित या पुनर्समूहित किया गया है।

सदस्य सचिव
(कुल सचिव, भा.लो.प्र.सं.)

अध्यक्ष
(महानिदेशक, भा.लो.प्र.सं.)

लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

सदस्यों के लिए

सामान्य भविष्य निधि, भा.लो.प्र.सं.

हमने 31 मार्च, 2021 को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान - सामान्य भविष्य निधि के संलग्न तुलन-पत्र और उस तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के आय-व्यय खाते का लेखा-जोखा किया है। ये वित्तीय विवरण फंड के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करें।

हमने भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा-परीक्षण मानकों के अनुसार अपनी लेखा-परीक्षा की है। उन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा-परीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय विवरण ठोस गलत विवरण से मुक्त हैं। लेखा-परीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों का समर्थन करने वाले साक्षों का परीक्षण के आधार पर परीक्षण करना शामिल है। लेखा-परीक्षा में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करने के साथ-साथ समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हम मानते हैं कि हमारी लेखा-परीक्षा हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती है।

इसके अलावा, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- (1) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।
- (2) हमारी राय में, संस्थान द्वारा कानूनन अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकों रखी गई हैं, यह उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।
- (3) इन रिपोर्ट द्वारा बनाए गए तुलन-पत्र और आय और व्यय खाते, खाते की किताबों के अनुरूप हैं।
- (4) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त खाते खातों की टिप्पणियों (अनुसूची - 3) के साथ पढ़े जाने पर, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृश्य प्रदान करते हैं:-
 - क) तुलन-पत्र के मामले में, 31 मार्च, 2021 को फंड के मामलों की स्थिति। तथा
 - ख) आय और व्यय खाते के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष।

कृते जीएसए और एसोसिएट्स

चर्टरित लेखापाल

एफ आर एन - 000257 एन / एन 500339
16 डी डी ए फ्लैट पंचशील पार्क
मालवीय नगर के समीप, नई दिल्ली-110017

दिनांक : 27.9.2021
यू.डी.आई.एन.सं. 21083899ए.ए.ए.डी.ओ.9049

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
सामान्य भविष्य निधि

31 मार्च, 2021 को तुलन-पत्र

	अनुसूची	31.3.2021 को	31.3.2020 को
	(₹)	(₹)	
<u>देयताएँ</u>			
संचित पात्रता	1	10,88,41,945.00	9,58,67,867
अवितरित व्याज		(74,60,487.00)	(88,94,248)
(आय और व्यय खाते के अनुसार)			
	कुल	10,13,81,458.00	8,69,73,619
<u>संपत्तियां</u>			
निवेश	2	8,52,99,356.00	6,83,20,316
एसबीआई में शेष		1,20,05,294.00	1,68,75,192
सदस्यों को अग्रिम		9,25,540.00	4,97,399
टीडीएस प्राप्त		1,91,268.00	1,91,268
सीपी फंड से प्राप्त राशि		29,60,000.00	10,89,444
	कुल	10,13,81,458.00	8,69,73,619

लेखांकन नीतियां और खातों के लिए नोट्स 3

हमारी समान तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

अनुसूचियां 1 से 3 खातों का अभिन्न अंग हैं

कृते जीएसए और एसोसिएट्स एलएलपी

चर्टरित लेखापाल

एफ आर एन - 000257 एन / एन 500339

सुनील अग्रवाल

सदस्य सचिव

सदस्य

भागीदार

कुलसचिव, भा.लो.प्र.सं.

भा.लो.प्र.सं. स्टाफ एसोसिएशन

एम नंबर 083899

16 डी.डी.ए फ्लैट पंचशील पार्क

सदस्य

सभापति

मालवीय नगर के समीप,

कार्यकारी परिषद

महानिदेशक, भा.लो.प्र.सं.

नई दिल्ली-110017

दिनांक : 27.9.2021

यू.डी.आई.एन.सं. 21083899ए.ए.ए.डी.ओ.9049

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

सामान्य भविष्य निधि

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा

	31.3.2021 को समाप्त वर्ष (₹)	31.3.2020 को समाप्त वर्ष (₹)
आय		
ब्याज	1,02,47,018.00	65,49,574
	कुल 1,02,47,018.00	65,49,574
व्यय		
(i) सदस्यों के अंशदान में ब्याज जमा किया	67,94,304.00	68,06,492
(पप) बैंक शुल्क	135.00	2,088
(iii) प्रीमियम	20,18,800.00	26,25,000
(iv) डीमैट शुल्क	618.00	
	कुल 88,13,857.00	94,33,580
वर्ष के लिए अधिशेष या घाटा	14,33,161.00	(28,84,006)
पिछला वर्ष कम या अधिक	600.00	
पिछले वर्ष से अवितरित ब्याज शेष	(88,94,248)	(60,10,242)
कुल अवितरित ब्याज		
तुलन-पत्र के लिए अग्रेषित किया गया	कुल (74,60,487)	(88,94,248)

लेखांकन नीतियां और खातों पर टिप्पणियां - 3
हमारी समान तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
अनुसूचियां 1 से 3 खातों का अभिन्न अंग हैं
एफआरएन - 000257एन एन500339

कृते जीएसए और एसोसिएट्स एलएलपी
चर्टरित लेखापाल
एफ आर एन - 000257 एन / एन 500339

सुनील अग्रवाल	सदस्य सचिव	सदस्य
भागीदार	कुलसचिव, भा.लो.प्र.सं.	(भा.लो.प्र.सं. स्टाफ एसोसिएशन)
एम नंबर 083899		
16 डी डी ए फ्लैट पंचशील पार्क	सदस्य	सभापति
मालवीय नगर के समीप, नई	कार्यकारी परिषद	(महानिदेशक, भा.लो.प्र.सं.)
दिल्ली-110017		

दिनांक : 27.9.2021
यू.डी.आई.एन.सं. 21083899ए.ए.ए.डी.ओ.9049

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
सामान्य भविष्य निधि

अनुसूची-1

संचित सदस्यों की पात्रता

	31.3.2021 को समाप्त वर्ष (₹)	31.3.2020 को समाप्त वर्ष (₹)
प्रारंभिक शेष	9,58,67,867	8,52,85,985
वर्ष के दौरान सदस्यता	1,48,73,498	1,30,38,100
ब्याज क्रेडिट	67,94,304	68,06,492
कुल	11,75,35,669	10,51,30,577
घटाएं		
सदस्यों के खातों का निपटान	8,28,724	44,14,710
अंतिम निकासी	78,65,000	48,48,000
कुल	10,88,41,945	9,58,67,867

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
सामान्य भविष्य निधि

अनुसूची 2

निवेश

	31.3.2021 को (₹)	31.3.2020 को (₹)
(अ) विशेष जमा योजना एस.बी.आई.आई.पी.एस्टेट	8724356	8724356
अन्य निवेश		
10.25% भारत सरकार 2021	3,00,000	3,00,000
8.15% भारत सरकार एफसीआई विशेष बाँड 2022	12,55,000	12,55,000
8.20% भारत सरकार ऑयल विशेष बाँड 2024	9,70,000	9,70,000
8.20% भारत सरकार ऑयल विशेष बाँड 2024	20,00,000	20,00,000
8.20% भारत सरकार ऑयल विशेष बाँड 2024	30,00,000	30,00,000
8.98% पीएफसी प्रीपुटल बाँड	1,00,00,000	1,00,00,000
9.50% एसबीआई प्रीपुटल बाँड	70,00,000	70,00,000
9.45% एसबीआई प्रीपुटल बाँड	1,00,00,000	1,00,00,000
(ब) राज्य सरकार के बाँड (15% श्रेणी)		
8.11% एसडीएल राजस्थान 2020	-	18,00,000
8.88% एसडीएल गुजरात 2021	10,50,000	10,50,000
(स) सार्वजनिक वित्तीय संस्थान आदि बांड		
8.95% आईआरएफसी 2025	40,00,000	40,00,000
9.35% पीजीसी 2023	40,00,000	40,00,000
9.75% आरईसी 2021	20,00,000	20,00,000
9.75% आरईसी 2021	-	22,20,960
8.28% नाबार्ड 2028	1,00,00,000	1,00,00,000
8.25% बैंक ऑफ बड़ौदा पर्प बांड	1,10,00,000	
9.15% पीएनबी पर्प बांड	1,00,00,000	
	कुल	8,52,99,356
		6,83,20,316

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

सामान्य भविष्य निधि

अनुसूची-3

लेखांकन नीतियाँ और खातों की टिप्पणियाँ

अ. लेखा नीतियाँ

1. निधि के खाते नकद आधार पर तैयार किए गए हैं।
2. निवेश अंकित मूल्य पर बताया गया है।
3. निवेश पर ब्याज की गणना प्राप्ति के आधार पर की जाती है।
4. भुगतान किए गए प्रीमियम या निवेश पर अर्जित छूट को अधिग्रहण के वर्ष में लाभ और हानि खाते के माध्यम से भेजा जाता है।

ब. खातों की टिप्पणियाँ

1. सदस्यों को अग्रिम की शेष राशि पुष्टि के अधीन है।
2. फंड के सदस्य मूल वेतन के न्यूनतम 6% की दर से सदस्यता ले रहे हैं।
3. भारत सरकार के आदेशों के अनुसार सदस्यों की सदस्यता और नियोक्ता के योगदान पर ब्याज का भुगतान किया जाता है।
4. जहां कहीं आवश्यक समझा गया, पिछले वर्ष के आंकड़े को पुनर्व्यवस्थित या पुनः समूहित किया गया है।

सदस्य सचिव

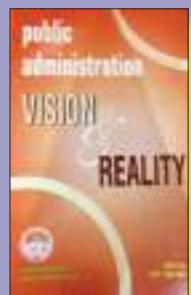
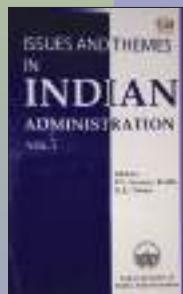
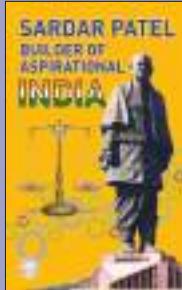
(कुलसचिव, भा.लो.प्र.सं.)

सभापति

(महानिदेशक, भा.लो.प्र.सं.)



IIPA PUBLICATIONS



FOR PURCHASE OF BOOKS KINDLY CONTACT:-

Assistant Publication Officer, Indian Institute of Public Administration,
Indraprastha Estate, Ring Road, New Delhi – 110002

Phone +91-11-23468300 | Fax +91-11-23702440
Email: helpdesk.iipa@gmail.com | iipa.org.in

Editorial Board

Editor in Chief

Surendra Nath Tripathi

Editor

Amitabh Ranjan

Joint Editor

Mithun Barua

Asstt. Editor

Meghna Chukkath



भारतीय लोक प्रशासन संस्थान
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली- 110002
iipa.org.in

Printed at: New United Process, 9811426024